राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 02] सोलहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का दसवां दिवस [संख्या: 05

शुक्रवार,

12 जुलाई 2024

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल। श्री चन्द्रभान सिंह चौहान।

राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त पद

39. **श्री चन्द्रभान सिंह चौहान** (चित्तौड़गढ़): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष व शारीरिक शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत व कितने रिक्त हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला चित्तौड़गढ़ के राजकीय महाविद्यालयों में उक्त पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

उच्च शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेम चन्द बैरवा): (1) प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में 555 पुस्तकालयाध्यक्ष एवं 555 शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक (पी.टी.आई.) के पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 535 पुस्तकालयाध्यक्ष एवं 540 शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक (पी.टी.आई.) के पद रिक्त हैं।

(2) जिला चित्तौड़गढ़ के राजकीय महाविद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक (पी.टी.आई.) के रिक्त पदों का तिथिवार विवरण परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(3) जी हां। पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक

(उच्च शिक्षा मंत्री)

(पी.टी.आई.) के 247-247 (कुल 494) पदों की भर्ती का विज्ञापन राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया जाकर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है। चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर नियमानुसार रिक्त पदों को भरा जा सकेगा। (व्यवधान)

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय, उत्तर में जो लिखा है, पहले उसको पढ़ लें। माननीय सदस्य, पूरक प्रश्न।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि पिछले 15 वर्षों से लैब टेक्नीशियन हो, पी.टी.आई.हो, सभी कालेज में जीरो संख्या है, भर्ती नहीं हुई है। पहली बात तो भर्ती कब कर लेंगे और कब तक लगा देंगे?

दूसरा प्रश्न, मेरे यहां ऐसे बहुत से लॉ कालेज है, वहां एक भी, सिंगल टीचर नहीं है। मेरे यहां घोसुण्डा में कालेज है, पर वहां पर एक भी टीचर नहीं है और बस्सी में एक भी कालेज नहीं है। मेरे यहां पी.जी. महाराणा प्रताप कालेज बहुत बड़ा कालेज है, उसमें केवल 10 प्रतिशत टीचर्स की संख्या है। गर्ल्स कालेज में भी 10 प्रतिशत संख्या है। एक बार आप यह पूरा बता दें कि जहां जीरो संख्या है वहां आप टेम्परेरी के रूप में लॉ कालेज में लगवाएं, बस्सी कालेज में लगवाएं, घोसुण्डा कालेज में लगवाएं। पी.टी.आई. और पुस्तकालयाध्यक्ष की संख्या वास्तव में सभी जगह जीरो है, तो यहां पर तो कम से कम एक-एक पद भरने की कोशिश आप करें। यहां पर पिछले 15 साल से भर्ती नहीं हो रही है। पहले वालों ने क्या कुछ किया, नहीं किया, उसकी तुलना अपन नहीं करें। अब अपन क्या करेंगे, उसके बारे में आप एक बार डिटेल में बताएं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, उत्तर आने दीजिए।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): हमारे 1,936 पदों की भर्ती रेगुलर कालेज में आ रखी है, दो-तीन महीने में वे सारे पद आ जायेंगे तो आपके रेगुलर कालेज में लगा दिया जायेगा। जो सोसायटी बैच के कालेज हैं, उनमें हमने विद्या सम्बल योजना के तहत वेकेंसी निकाली हुई है, निश्चित रूप से जल्दी आपके इन पदों पर लगा दिये जायेंगे।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी एक विनती है।

श्री अध्यक्ष: आपका और कुछ रह गया?

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): हां। जहां जीरो है, वहां पर आप डेपुटेशन कितनी तारीख तक कर देंगे? मेरे यहां लॉ कालेज में बिलकुल, एक भी सिंगल टीचर नहीं है। जैसे बस्सी है, जैसे घोसुण्डा है, वहां पर एक-एक टीचर की भी व्यवस्था हो जाये जिससे उस कालेज को संभालने वाला भी हो जाये। लॉ कालेज में आप कब तक व्यवस्था कर देंगे? +++

श्री अध्यक्ष: यह प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है। माननीय सदस्य वह प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है। वह हटा दीजिए।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): आपके यहां एक भी जीरो रिक्त पद नहीं रहेगा। आपके यहां व्यवस्था कर दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री संजीव कुमार।

आपका हो गया। दो क्वेश्चन हो गये, आप बैठिए। श्री संजीव कुमार। आप बैठिए। इन्होंने कह दिया न, तुरन्त लगा देंगे।

भादरा शहर में पेयजल आपूर्ति

40. श्री संजीव कुमार (भादरा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भादरा शहर में पेयजल आपूर्ति को दुरुस्त करने हेतु 'संवर्धन शहरी जल प्रदाय योजना भादरा' को स्वीकृत किया गया था? यदि हां, तो कितनी राशि की एवं कब? योजना की प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्वीकृत योजना का कार्य अब तक प्रारम्भ नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) सरकार उक्त योजना का कार्य कब तक प्रारम्भ करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री) (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री के स्थान पर): (1) भादरा शहर में पेयजल आपूर्ति को दुरुस्त करने हेतु संवर्धन शहरी जल प्रदाय योजना भादरा की स्वीकृति वित्त समिति की बैठक क्रमांक 842 दिनांक 14.03.2023 द्वारा राशि रुपये 95.64 करोड़ की जारी की गई। कार्य की संशोधित तकनीकी स्वीकृति तकनीकी समिति की बैठक

(श्री सुरेश सिंह रावत)

क्रमांक 752 दिनांक 22.08.2023 द्वारा राशि रुपये 78.49 करोड़ की जारी की गई थी। विवरण परिशिष्ट 'अ' व 'ब' पर संलग्न है।

(2) शहरी जल योजना भादरा के संवर्धन कार्य की निविदा अतिरिक्त मुख्य अभियंता क्षेत्र बीकानेर की निविदा संख्या 09/2023-24 द्वारा राशि रुपये 78.49 करोड़ की आमंत्रित की गई थी। प्राप्त निविदा में आर.टी.पी.पी. नियमों की पालना के अभाव में दिनांक 14.12.2023 को उक्त निविदा निरस्त की जा चुकी है। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 22.12.2023 द्वारा 15.12.2023 से पूर्व के स्वीकृत कार्यों को क्रियान्वित नहीं किये जाने के निर्देशों के दृष्टिगत उक्त स्वीकृत कार्य की नवीन निविदा जारी नहीं की गई है। कार्य की निविदा नहीं होने से कार्य शुरू नहीं हुआ है।

(3) जी हां। दिनांक 15.12.2023 से पूर्व के स्वीकृत कार्यों को प्रारम्भ करने के लिए राज्य सरकार स्तर से समीक्षा की जाकर योजना कार्य की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता का आकलन करते हुए उचित निर्णय लिया जाकर तदनुसार योजना कार्य की नवीन निविदा आमंत्रित की जा सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, भादरा शहर की जो जलप्रदाय योजना है, वर्तमान में अमरसिंह सिंचाई सिस्टम से उसमें पानी की आपूर्ति होती है और अमरसिंह सिंचाई सिस्टम में 15 दिन पानी चलता है। 15 दिन पानी चलने के बाद लगातार भादरा शहर को और इस शहर की जलप्रदाय योजना से करीब 19 राजस्व ग्राम भी जुड़े हुए हैं तो इन लोगों को लगातार पानी की भारी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो इसके लिए संवर्धन शहरी जलप्रदाय योजना स्वीकृत की गयी थी। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि इस स्कीम के लिए आप कब तक टेंडर आमंत्रित कर लोगे और इसका कार्य कब तक चालू करवा दोगे? यह बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): भादरा से आने वाले माननीय सदस्य की चिंता जायज है। इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि इस योजना के कार्य की आवश्यकता का वर्तमान परिदृश्य में समीक्षा कर शीघ्र उचित निर्णय लिया जाकर कार्य प्रारम्भ करने का प्रयास किया जायेगा।

श्री संजीव कुमार (भादरा): नहीं, समीक्षा नहीं, आप तो यह बताओ कि स्वीकृत करके कब तक चालू कर दोगे?

श्री अध्यक्ष: आपका दूसरा प्रश्न। दूसरा सवाल पूछो।

श्री संजीव कुमार (भादरा): मेरा दूसरा सवाल है। एक तो आप स्पष्ट उत्तर दें कि कब तक आप इसमें निविदा आमंत्रित कर लोगे और कब तक चालू कर दोगे? यह साफ तो बताओ। अब यह समीक्षा का क्या है?

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): जल्दी ही कर लेंगे।

श्री संजीव कुमार (भादरा): मेरा दूसरा सवाल यह है कि 22.08.2023 को यह स्कीम स्वीकृत की गयी और 14.12.2023 को वह निविदा RTPP नियमों की पालना के अभाव में निरस्त हुई, तो इस वजह से लगातार योजना में विलम्ब भी हुआ, लोगों को परेशानी भी हुई, तो इसमें RTPP नियमों की पालना के अभाव में जब यह निरस्त हुई तो इसमें विभागीय लापरवाही हुई है।

श्री अध्यक्ष: आप तारीख पूछिए। वह आपका अधिकार है।

श्री संजीव कुमार (भादरा): मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने लापरवाही की है, उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करोगे? आप कार्यवाही करोगे तो कब तक करोगे?

श्री अध्यक्ष: आ गया, बैठिए आप।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, दोषी अधिकारी के विरुद्ध मुख्य अभियंता, बीकानेर को कारण बताओ नोटिस दिनांक 19.07.2024 को जारी कर दिया गया है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय मंत्रीजी की कोई गलती नहीं है। इसकी अगर आप गहराई में जाओगे तो आपको खण्ड (2) में जो जवाब मिला है कि, वित्त विभाग के आदेश दिनांक 22.12.2023 द्वारा 15.12.2023 से पूर्व के स्वीकृत कार्यों को क्रियान्वित नहीं किये जाने के निर्देशों के दृष्टिगत उक्त स्वीकृत कार्यों की निविदा जारी नहीं की गयी है। यह आर्डर जब तक नहीं हटेगा, तब तक मंत्रीजी निविदा जारी नहीं कर पायेंगे। यह टैक्निकल विषय है और यह कोई एक विभाग पर लागू नहीं हो रहा है। यह नियम पूरे राजस्थान पर लागू है और यह गैर-संवैधानिक नियम है कि आप एक लैटर के माध्यम से पूरे राजस्थान की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, जितने भी विभागों की चल रही हैं, सब पर रोक लगा दें। आप, अध्यक्षजी, व्यवस्था दें कि इस आर्डर को निरस्त करें तो और विभागों में भी काम हो सके। यह हकीकत है।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी का उत्तर आने दें।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नेता, प्रतिपक्ष को बताना चाहता हूं कि यह आपके टाइम में भी होता आया है। जब सरकार बनती है तो पुराने कार्यों की समीक्षा होती है और क्योंकि...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नो-नो, उत्तर आने दीजिए। आप उत्तर सुनिए।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): टेंडरों के अन्दर घोटाला हुआ। बिना RTPP नियमों की पालना करते हुए टेंडरों को अपलोड कर दिया गया। इस कारण से यह टेंडर निरस्त हुआ है।

श्री अध्यक्ष: श्री जुबेर खान।

सिलीसेढ़ व जयसमन्द बांध (अलवर) के भराव क्षेत्र में अवैध निर्माण

41. श्री जुबेर खान (रामगढ़): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला अलवर की सिलीसेढ़ एवं जयसमन्द बांध व झीलों के भराव क्षेत्र एवं वेस्ट वेयर के बहाव क्षेत्रों में अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किये गये हैं? यदि हां, तो उक्त अवैध निर्माणों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवैध निर्माणों को रोकने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्या सरकार लापरवाही बरतने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त अवैध अतिक्रमणों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (श्री सुरेश सिंह रावत): (1) वर्तमान में जयसमन्द बांध के भराव व वेस्ट वेयर के बहाव क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नहीं है। सिलीसेढ़ बांध के भराव क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नहीं है, लेकिन बहाव क्षेत्र में 16 अतिक्रमण चिह्नित किये गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) सिलीसेढ़ एवं जयसमन्द बांध के भराव/बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण विधि सम्मत कार्यवाही कर हटाये गये हैं तथा हटाने की कार्यवाही की जा रही है। इस सम्बन्ध में यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो जांच कर कार्यवाही की जावेगी।

(जल संसाधन मंत्री)

(3) सिलीसेढ़ के उपरा (Waste Weir) से बहने वाले पानी के बहाव क्षेत्र के 16 अतिक्रमण निजी खातेदारी में दर्ज होने के कारण इन्हें राजस्व विभाग से समन्वय कर हटाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पूरक प्रश्न पूछें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने कहा है कि वर्तमान में जयसमन्द बांध के भराव व वेस्ट वेयर के बहाव क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिला प्रशासन ने जांच करके एक लिस्ट जारी की कि जयसमन्द बांध के बहाव क्षेत्र में जिन गांवों की जमीन आती है, मंत्रीजी, नोट कर लीजिए, लिवारी में 200, अलापुर माचड़ी में 50, भराव क्षेत्र में अतिक्रमण हैं, जिनमें से कार्यवाही करते हुए एक अतिक्रमण हटा दिया गया है तो आपका उत्तर असत्य है।

दूसरी बात मैं करना चाहूंगा, आपने कहा है कि सिलीसेढ़ भराव क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नहीं है। सिलीसेढ़ के बांध की भराव क्षमता 28.9 इंच है। यहां अलवर के मंत्री भी बैठे हैं, अलवर के नेता, प्रतिपक्ष भी बैठे हैं। जब 28.9 इंच पानी भरेगा तो आप एक कमेटी बना दीजिए आज, कितने होटल उसमें चल रहे हैं, अगर वे होटल भराव क्षेत्र में, पानी में नहीं भरते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा विधान सभा से, नहीं तो आप क्या करेंगे, आप बताइए? आप अधिकारियों के कहने से यहां असत्य उत्तर दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अभी आपकी आवश्यकता विधान सभा को है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): जुबेर भाई, बहुत दिनों में आये हो विधान सभा में, इस तरह की बात मत करो।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए, माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): इस्तीफा दूंगा तभी तो आपकी सरकार गिरेगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछिए। प्रश्न पूछो।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं आपसे कहना चाहूंगा कि, मंत्रीजी, सिवाय चक जमीन चली गई यू.आई.टी. में, यू.आई.टी. के नाम चढ़ गई। यहां सिंचाई विभाग के नाम भी जमीन है, यहां वन विभाग के नाम भी जमीन है, यहां बागात विभाग के नाम भी जमीन है,

(श्री जुबेर खान)

यहां मत्स्य विभाग के नाम भी जमीन है। जिसको कहो, यह हमारी नहीं है, यह हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आती। क्यों नहीं आप एक जोइंट टीम, कोई सर्वे टीम या कोई भी टीम कलक्टर की अध्यक्षता में बनाएं जिसमें सब विभाग के अधिकारी हों और वे यह तय करें कि सरकारी जमीनों पर कहां-कहां लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, अतिक्रमण कर रखा है, इसकी जांच करके उचित कार्यवाही करें। दूसरा, जब वेस्ट वेयर चलेगी...

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिए कि करेंगे या नहीं करेंगे?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सिलीसेढ़ की वेस्ट वेयर हर दो-तीन साल में चलती है, जब वेस्ट वेयर चलेगी...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, भाषण नहीं, प्रश्न पूछो।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मैंने जो एक-दो सवाल पूछे हैं भराव क्षेत्र के और जयसमन्द के, आप उनके बारे में बता दीजिए।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी जो चिंता है, एक तकनीकी टीम बनाकर, इसका भौतिक सर्वे करवाकर इस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द प्रसाद। (व्यवधान) हो गया। जो मांगा उसका उत्तर दे दिया। (व्यवधान)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर मामला है, बड़ा गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर तो आया ही नहीं।

श्री अध्यक्ष: आपका हो गया, आपने जो आश्वासन मांगा, दे दिया कि कमेटी बनाकर जांच कराएंगे। हो गया आपका।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने जवाब में दिया है ..(व्यवधान) आपने यह कहा कि जयसमन्द के भराव क्षेत्र में और जो पानी आ रहा है उसमें कोई अतिक्रमण नहीं है। विभाग द्वारा एक महीने पहले नोटिस दिए गए, उस नोटिस की वजह से एक गरीब-दलित व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। सिर्फ इस बात पर कि उसको नोटिस दिया गया, वह अतिक्रमण में था या नहीं, उसको नोटिस क्यों

(श्री टीकाराम जूली)

दिया गया और यह सबके संज्ञान में है, पूरे प्रशासन के संज्ञान में है तो उस गरीब-दलित परिवार की सरकार कोई मदद करने की इच्छाशक्ति रखती है या नहीं? जब आप मान रहे हो कि कोई अतिक्रमण नहीं है तो फिर उसको नोटिस कैसे दे दिया?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सिलीसेढ़ बांध के भराव व...

श्री अध्यक्ष: जयसमन्द का पूछा है।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): क्या कह रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: जयसमन्द का।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): जयसमन्द का।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): हां, हां, जयसमन्द का ही कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ये जवाब नहीं दे पाएंगे। ..(व्यवधान)... रिकॉर्ड में ही नहीं आया। ..(व्यवधान)... मंत्रीजी जवाब इसलिए नहीं दे पाएंगे कि इन्होंने अतिक्रमण माना ही नहीं है।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): नहीं-नहीं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): जब इन्होंने अतिक्रमण नहीं माना तो अधिकारियों ने उसको अतिक्रमण मानकर नोटिस कैसे दे दिया? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इनका कहना है कि अतिक्रमण हटाने के कोई नोटिस महीने भर पहले दिये हैं। उसमें एक व्यक्ति ने आत्महत्या की है। क्या जिसने आत्महत्या की, उसका एरिया अतिक्रमण में आता है या नहीं? (व्यवधान) इतना ही प्रश्न है आपका? (व्यवधान) बैठे-बैठें न बोलें, उत्तर सुनें।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मामले की मैं पूरी जांच करवाकर नेता, प्रतिपक्ष को अवगत करवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द प्रसाद।

मनोहर थाना में संचालित उचित मूल्य की दुकानें

42.श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गोविन्द प्रसाद)

(1) विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में उचित मूल्य की दुकानें कहां-कहां संचालित हैं? संचालनकर्ता के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में उचित मूल्य की नवीन दुकानें खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में खाद्य सुरक्षा में नये नाम जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री सुमित गोदारा): (1) विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में संचालित राशन की दुकानों का स्थानवार एवं संचालनकर्ता के नाम सहित विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विभागीय निर्देश दिनांक 07.04.2010 एवं 26.12.2019 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत चयनित 500 राशनकार्डों अथवा 2,000 यूनिट पर नवीन उचित मूल्य दुकान खोले जाने के मापदण्ड निर्धारित हैं।

वर्तमान में नवीन उचित मूल्य दुकान हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं एवं न ही कोई प्रस्ताव विचाराधीन है।

(3) वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रदेश की वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थियों को चयनित करने की सीलिंग 4.46 करोड़ की गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानानुसार सुसंगत प्रकाशित जनसंख्या अनुसार सीलिंग तय है। राज्य के कवरेज में कोई भी संशोधन अगली जनगणना के जनसंख्या अनुमान आंकड़े प्रकाशित होने के बाद सम्भव हो सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर के खण्ड संख्या (2) पर, अंत्योदय योजना, बी.पी.एल., स्टेट बी.पी.एल. एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत चयनित राशन कार्डों की संख्या 500 एवं 2,000 यूनिट का मानदंड निर्धारित है। ऐसे बहुत से जिले हैं, जिनमें निर्धारित मानदंडों से ज्यादा यूनिट की उचित मूल्य की दुकानें चल रही हैं।

श्री अध्यक्ष: आप मनोहर थाना की पूछें।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि अगर प्रस्ताव दिए जाते हैं तो क्या आप नई दुकान खोलने का विचार रखते हैं?

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विधायक महोदय, मनोहर थाना को आश्वस्त करूंगा कि आबंटन सलाहकार समिति बन रही है, उसके बाद आप अपने क्षेत्र के जो भी प्रस्ताव भेजेंगे, उन पर बिलकुल विवेकपूर्ण निर्णय कर आपके दुकानें खोल दी जाएंगी।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रताप लाल भील।

गोगून्दा के वन क्षेत्र में वृक्षारोपण

43. श्री प्रताप लाल भील (गोगून्दा): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगून्दा में विगत तीन वर्षों में सामरा, गोगून्दा, देवता रेंज में कितने हैक्टेयर में किस-किस योजना में कितनी राशि व्यय कर वृक्षारोपण करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में वृक्षारोपण में से कितने पौधे वर्तमान में जीवित हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, वन (श्री संजय शर्मा): (1) गोगून्दा विधान सभा क्षेत्र की रेंज सायरा, गोगून्दा, देवला में विगत तीन वर्षों में करवाये गये वृक्षारोपण एवं व्यय की गई राशि का योजनावार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उप वन संरक्षक उदयपुर (उत्तर) से प्राप्त सूचना अनुसार वर्तमान में जीवित पौधों की संख्या का विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में समाहित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री प्रताप लाल भील (गोगून्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2021-22 में आपने 73 प्लांटेशन की सूचना प्रेषित की है, इसमें विशेषकर देवला रेंज में आपने वृक्षारोपण किया था, उसमें कहीं 58 परसेंट रहा, कहीं 61 परसेंट, इसका क्या कारण रहा? जो वृक्षारोपण किया गया था, वो वास्तव में किया गया या नहीं किया गया? वर्तमान में इन्होंने जो पौधों की संख्या बताई है वो वहां पर है या नहीं, इसकी जांच कराएं।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्षजी, गोगून्दा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पौधारोपण को लेकर, विशेष रूप से 2021-22, 2022-23 और 2022-23 के अलग-अलग और रेंज देवला को लेकर जो चिंता जताई है, उसके बारे में कहना चाहूंगा कि पौधारोपण को लेकर एक रेंज से दूसरे रेंज के अधिकारी द्वारा जांच की जाती है। डी.सी.एफ. और सी.सी.एफ. के माध्यम से भी जांच कराई जाती है। थर्ड पार्टी के द्वारा भी जांच कराई जाती है। उसके साथ-साथ भारत सरकार द्वारा सैटेलाइट के माध्यम से हर वर्ष कितना फोरेस्ट बढ़ा और कितना घटा, उसकी जांच भी भारत सरकार द्वारा कराई जाती है, लेकिन जो चिन्ता माननीय सदस्य ने सदन में व्यक्त की है, माननीय सदस्य मुझे लिखकर दे दें, किस-किस जगह उन्हें लगता है कि पौधारोपण कम हुआ है या कोई गड़बड़ है, निश्चित रूप से तीन सदस्यीय कमेटी बनाकर उसकी जांच करा ली जायेगी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, आप बात समझें। गौर से देखें, जो जीवित पौधों की संख्या बता रखी है, 10 हजार में से 9 हजार, 10 हजार में से साढ़े 8 हजार, 20 हजार में से 8,400, 10 हजार में 9,100, 9,200, 9,400, तो ये ऐसी क्या संख्याएं हैं जो पूरी राउंड फिगर में ही आ रही हैं? जब इन्होंने जांच करवायी है तो यह तो हो नहीं सकता कि वे फुलफ्लैज्ड सौ में से सौ ही जीवित हैं या 100 में से 80 हैं, कहीं 89, 99, 98, 97 भी हो सकते हैं तो ये जो आंकड़े हैं, ये गुमराह करने के हैं। मैं यह कहूंगा, इनकी जांच करायी जाए और मंत्री जी एक्चुअल स्थिति स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: जांच के लिए कहा है उन्होंने।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता, प्रतिपक्ष को हर प्रश्न पर खड़े होने की आदत-सी हो गयी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह काम मेरा है। (व्यवधान)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आदत नहीं, यह मेरा अधिकार है। अधिकार, अधिकार, अधिकार। (व्यवधान) उंगली और कर रहे हैं मंत्री। अध्यक्ष जी, मंत्री मेरी तरफ उंगली कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिए। मैं हूं व्यवस्था देने वाला। हरिमोहन जी, आप अपनी सीट पर भी नहीं हैं। बौहरा जी, आप अपनी सीट पर जाइए। आगे जाकर बैठिए। (व्यवधान) यह काम मेरा है। मैंने कह दिया जो कहना था। बैठिए। (व्यवधान) आपको खड़े होने की आदत है क्या? मुझे व्यवस्था देनी थी,

(श्री अध्यक्ष)

मैंने दे दी। सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, व्यवस्था मेरे जिम्मे है। (व्यवधान) आपको क्या हो गया, आप अस्वस्थ हैं? आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं आएंगे फिर। आपका प्रश्न नहीं लूंगा, ज्यादा करेंगे तो। तमाशा कर रहे हैं। चलिए, आगामी, श्री जसवन्त सिंह यादव।

न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद के केन्द्र

44. डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा किसानों की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है? यदि हां, तो किन-किन फसलों को किस दर पर? विगत दो वर्षों में सरकार द्वारा खरीदी गयी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की दर सहित विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में तहसील स्तर पर फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए केन्द्र स्थापित किये गये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री गोतम कुमार): (1) जी हां। सहकारिता विभाग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य दर पर दलहन-तिलहन की खरीद की जाती है। विभाग द्वारा गत दो वर्षों में की गयी दलहन-तिलहन खरीद का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा गेहूं की समर्थन मूल्य खरीद की जाती है। रबी सीजन वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा किसानों को समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी दिया गया है। खाद्य विभाग द्वारा गत दो वर्षों में की गयी गेहूं खरीद का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जी हां। सहकारिता विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर दलहन-तिलहन की खरीद हेतु प्रत्येक सीजन में सम्बन्धित जिला कलक्टर की अनुशंसा के अनुसार क्रय/विक्रय ग्राम सेवा सहकारी समितियों के स्तर पर क्रय केन्द्र स्थापित किये जाते हैं। ये क्रय केन्द्र सम्बन्धित तहसील से मैप किये जाते हैं।

(राज्य मंत्री, सहकारिता)

वर्ष 2024-25 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों/चना की खरीद हेतु स्थापित किये गये क्रय केन्द्रों की सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

खाद्य विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद हेतु गत वर्षों के अनुभव व जिला प्रशासन एवं क्रय एजेन्सियों से प्राप्त मांग के आधार पर क्रय केन्द्र स्थापित किये जाते हैं। वर्ष 2024-25 में गेहूं खरीद हेतु स्थापित किये गये क्रय केन्द्रों की सूची परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री महोदय का जवाब मेरे पास आ गया है, मुझे एक-दो चीजें पूछनी हैं, वे बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न पूछें। (व्यवधान) जो सदस्य ज्यादा डिस्टर्ब करेगा, उसका उत्तर फिर रुक जायेगा। उसे उत्तर ही नहीं चाहिये तो फिर मैं काहे को दिलवाऊं? प्रश्न काल शान्ति से चलने दीजिए, उत्तर आ रहे हैं। आपके नेता को अनुमति दे रहा हूं। इससे ज्यादा क्या चाहिए? (व्यवधान) आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, बैठे-बैठे बोलना मना है। खड़े होकर बोलें। नियमों में आएंगे तो ही अनुमति दूंगा। (व्यवधान) प्रश्न काल में डिस्टर्बेंस मैं बिलकुल नहीं होने दूंगा। प्रश्न काल में कोई नहीं खड़ा होगा, बैठिए। (व्यवधान) कोई नहीं खड़ा हो रहा है, आप क्यों खड़े हो रहे हैं जब मैं आपके नेता को अनुमति दे रहा हूं तो? फिर मुझे आपके नेता को भी अनुमति देना बंद करना पड़ेगा यदि इस तरह आप सब खड़े होंगे तो। यहां तमाशा बना रहे हैं सदन को।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र हरियाणा से बिलकुल जुड़ा हुआ है। किसान के भविष्य का एक सवाल है। हरियाणा में जो भी सरसों बिक्री केन्द्र पर लायी जाती है, वह पूरी खरीद ली जाती है। मैं मंत्री जी से स्पेसिफिक बात पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: थोड़ा माइक के नजदीक होकर बोलिए।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मैं माननीय मंत्री महोदय से एक बात पूछना चाहता हूं कि हरियाणा में सरसों की पूरी फसल को खरीद लिया जाता है...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिए।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ऐसे में आपने किसान की फसल को खरीदने में कितने क्विंटल की लिमिट बना रखी है? क्या हरियाणा की तर्ज पर सारी सरसों को खरीदने की कोई सम्भावना है या नहीं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): भारत सरकार द्वारा नियमों में 25 क्विंटल की अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी थी और हमने इस बार प्रयास किया, पिछली बार भी वह 40 क्विंटल खरीदी गयी थी, इस बार भी हमने पत्र लिखा था इसे 40 क्विंटल करने के लिए, लेकिन आचार संहिता की वजह से वह 40 क्विंटल नहीं हो पायी।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय मंत्री महोदय, मैं यह पूछ रहा हूं आपसे कि भारत सरकार का कानून तो हरियाणा में भी लागू होता है। जब हरियाणा में ऐसा कर सकते हैं तो हम राजस्थान में क्यों नहीं कर सकते?

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): भारत सरकार द्वारा कुल उत्पादन का 25 परसेंट खरीदा जाता है और 25 क्विंटल अभी अनुमति दी जाती है। हम राजफैड के माध्यम से खरीद करते हैं। हम अगली बार निश्चित रूप से भारत सरकार से कहकर प्रयास करेंगे कि किसानों की अधिकतम उपज को खरीदा जाए।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या अब जो कपास और बाजरा आयेगा, उसे खरीदने की भी कोई योजना है? क्या उन्हें भी खरीदने का कोई केन्द्र स्थापित कर रहे हैं? चूंकि आप खरीदते नहीं हैं तो क्या इस बार खरीदने की तैयारी है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): निश्चित रूप से हम इस बार प्रयास करेंगे। आपका प्रस्ताव निश्चित रूप से भारत सरकार को भेजकर हम इस बार कपास और उसको भी खरीदने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री रामनिवास गावड़िया।

सफाई कर्मचारियों की भर्ती

45. **श्री रामनिवास गावड़िया** (परबतसर): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों की भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी की गयी थी? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्रवाई की गयी? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) उक्त भर्ती के सम्बन्ध में क्या नियम बनाये गये थे? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(श्री रामनिवास गावड़िया)

(3) क्या सरकार सफाई कर्मचारियों के पद बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री झाबर सिंह खर्रा): (1) जी हां। विगत सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों की भर्ती हेतु विज्ञप्ति संख्या 1/2023 दिनांक 09.06.2023 एवं 2/2023 दिनांक 6.10.2023 को जारी की गयी थी।

पूर्व में जारी इन दोनों विज्ञप्तियों को प्रत्याहारित करने एवं सम्यक संशोधन उपरान्त एक नवीन विज्ञप्ति संख्या 01/2024 दिनांक 01.03.2024 को जारी की गयी है।

उक्त विज्ञप्ति के क्रम में राज्य के विभिन्न नगरीय निकायों में 24,797 सफाई कर्मचारियों के पदों के विरुद्ध कुल 9,20,442 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी भर्ती हेतु लाटरी किये जाने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से एक "लाटरी पोर्टल" बनवाये जाने का कार्य प्रगतिरत है।

(2) उक्त सफाई कर्मचारी भर्ती राज्य में प्रभावी राजस्थान नगरपालिका (सफाई कर्मचारी सेवा) नियम, 2012 एवं इन्हीं नियमों में समय-समय पर किये गये सम्यक संशोधन के अन्तर्गत की जा रही है। नियमों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। क्योंकि उक्त सफाई कर्मचारी भर्ती में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत निर्धारित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार अधिकतम पद स्वीकृत हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जवाब आ गया है, मैं कुछ सप्लीमैंटरी प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न पूछिए।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि इस भर्ती को समय-समय पर सम्यक संशोधन के अन्तर्गत किया जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न है कि क्या वर्तमान में जो बदलाव किये गये, इन्हीं के आधार पर इस भर्ती को किया जायेगा या इसमें बदलाव करने का विचार है?

दूसरा प्रश्न यह है, क्या सरकार द्वारा उक्त भर्ती को पूर्ण करने हेतु कोई कैलेंडर निर्धारित किया गया था? यदि हां, तो उसके अनुसार भर्ती क्यों

(श्री रामनिवास गावड़िया)

नहीं की गयी? कारण स्पष्ट करें। क्या सरकार उक्त भर्ती हेतु कोई नया कैलेंडर जारी करने का विचार रखती है एवं कब तक उसे पूरा करने का विचार रखती है? मंत्री जी, कृपया बताने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि सफाई कर्मी की भर्ती के लिए 2012 में नियम बने थे। नियम (6) में शुरुआत में दो साल का सफाई अनुभव नगरपालिका का था। उसके बाद उसमें 05.07.2023 में संशोधन किया गया और उसमें निजी संस्थान और व्यक्तिगत रूप से जारी किये गये अनुभव प्रमाण पत्र को भी मान्यता देने का प्रावधान किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद 11.04.2018 को एक संशोधन बीच में और हुआ था, जिसमें शुरुआत में नियम (6) के अनुसार जो दो साल का अनुभव था, उसे घटाकर एक साल का अनुभव किया गया और साथ में दो बच्चों का प्रावधान जोड़ा गया। मूल नियमों में परीक्षा और साक्षात्कार थे, क्योंकि उसमें दो साल का नगरपालिका के अनुभव का प्रावधान था। 23.01.2024 को लाटरी के माध्यम से भर्ती करने का प्रावधान जोड़ा गया और उसके बाद 08.06.2023 को प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान जोड़ा गया। हमारे 9,20,442 आवेदन प्राप्त हुए हैं। पहली विज्ञप्ति 13,184 की 09.06.2023 को निकली थी। दूसरी विज्ञप्ति 24,797 की 06.10.2023 को निकली, जिसमें साक्षात्कार का प्रावधान किया गया था। तीसरी विज्ञप्ति 01.03.2024 को निकाली गयी, जिसमें 24,797 फार्म चले गये, उसमें प्रायोगिक परीक्षा जोड़ी गयी।

इसी दौरान तीसरी विज्ञप्ति के बाद 100 से ज्यादा रिट याचिकाएं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गईं। मेरी जानकारी के अनुसार कल माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने सभी रिट याचिकाओं का निस्तारण कर दिया है। आज शाम तक माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले की प्रमाणित प्रति हमें मिल जायेगी। उसका विधिक परीक्षण कराने के बाद हमें जो कुछ करना है, हम यथासम्भव बहुत जल्दी इस भर्ती को पूरा करने का प्रयास करेंगे।

इसी बीच मैं आपसे एक निवेदन और कर दूं, 12 जून, 2024 को एक सफाई कर्मचारी 1 लाख 75 हजार रुपये एक आवेदक की भर्ती करवाने की गारंटी के साथ प्राप्त करते हुए एसी.बी. के हत्थे चढ़ा। इस प्रकार की

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

शिकायतें हमें बहुत मिली थीं, लेकिन उनमें से एक ही व्यक्ति जाल में फंसा, बाकी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं।

दूसरा, मैं निवेदन करता हूं कि सफाई कर्मचारियों की एक हड़ताल हुई थी, उनकी मांग थी कि दिनांक 05.07.2023 को जो संशोधन करके निजी संस्थान, व्यक्तियों द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र का प्रावधान किया गया है, उसमें फर्दकारी की बहुत सारी आशंकाएं हैं, इसलिए इसमें आप संशोधन करें। इसीलिए, हमने 15 मार्च, 2024 को शर्तों में संशोधन किया, जिसमें नगर निकाय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा, अगर वह संविदा पर रहा है, ठेकेदार ने जो प्रमाण पत्र दिया है, उसको अधिप्रमाणित करने का या नगरपालिका में वह दैनिक मजूदरी पर रहा है तो उसका प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान किया गया था।

श्री अध्यक्ष: बस उत्तर आ गया है, और देना है?

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): साथ ही, मैं निवेदन कर दूं कि मूल नियमों में एक हजार पदों पर चार पदों का प्रावधान है और उसी के आधार पर हमने यह किया है। फिर भी, मैं चाहूंगा कि इस भर्ती में कोई भी माननीय सदस्य या नेता, प्रतिपक्ष कोई भी सकारात्मक सुझाव देंगे, जिससे यह भर्ती पूर्ण रूप से पारदर्शी तरीके से सम्पन्न हो सके, हम उस सुझाव का स्वागत करेंगे।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, हो गया। इससे बढ़िया उत्तर क्या होगा? श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): और उनको नियमों में शामिल करने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेंगे।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मंत्री जी कह रहे हैं, न्यायालय ने सारे रिटधारियों की समस्याओं का निस्तारण कर दिया तो, माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे सिम्पल-सा सवाल है कि 9,20,442 आवेदन इसमें आये हुए हैं तो यह बताने की कृपा करें कि कब तक इस भर्ती को पूरा कर दिया जायेगा?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठिए। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। उन्होंने अगला प्रश्न पूछ लिया है। इससे बढ़िया उत्तर क्या होगा?

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): 000

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय का परीक्षण करवाने के बाद जितनी जल्दी हो सकेगा, हम इस भर्ती को पूरा करने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: इससे अच्छा जवाब क्या होगा? आपके सुझाव मांगे हैं, परीक्षण करने के बाद करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। टू द पाइंट उत्तर आ गया।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

आयुर्वेद महाविद्यालयों की स्थापना

46. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत तीन वर्षों में आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी एवं यूनानी के महाविद्यालय कहां-कहां पर खोलने की घोषणा की गई थी?

(2) उक्त घोषित महाविद्यालयों की प्रगति की क्या स्थिति है? उक्त में से किन-किन में अध्ययन एवं प्रशिक्षण कार्य कब से प्रारम्भ हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

आयुर्वेद मंत्री (डॉ. प्रेम चन्द बैरवा): (1) आयुष विभागान्तर्गत विगत 03 वर्षों में-

• वर्ष 2021-22 में जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, कोटा एवं सीकर में आयुर्वेद एवं योग व नैचुरोपैथी के एकीकृत महाविद्यालय तथा उदयपुर व जोधपुर में योग व नैचुरोपैथी महाविद्यालय,

• वर्ष 2022-23 में तारानगर (चूरू) में आयुर्वेद महाविद्यालय एवं

• वर्ष 2023-24 में नाथद्वारा (राजसमन्द) में आयुर्वेद एवं योग व नैचुरोपैथी का एकीकृत महाविद्यालय, भरतपुर में होम्योपैथी महाविद्यालय तथा जोधपुर में यूनानी महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई।

(2) सम्पूर्ण विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगी कि इन महाविद्यालयों के प्रगति की इसमें अभी भी कोई सूची नहीं है, भूमि का

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

आबंटन कहां हुआ? भवन के निर्माण की क्या स्थिति है और प्रत्येक सत्र में कितने बच्चे पढ़ने आ रहे हैं? कितने विद्यार्थी एडमिशन ले रहे है? और जो पद हैं, उनकी स्थिति के बारे में विवरण दें।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जिन्हें खोला गया है, उन्हें दो साल पूरे नहीं हुए हैं। इनको 50 बेड के हास्पिटल से सम्बद्ध किया जाता है। वह कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है। वह होते ही ये चालू हो जायेंगे और इनके दो निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। आप वाले में अभी बजट आने के बाद शुरू हो जायेगा।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से एक और प्रश्न पूछना चाहूंगी कि क्या यह सही है कि जहां पर योग और प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय खुले हैं, वहां पर आयुर्वेद के शिक्षकों को लगाया जा रहा है? जबकि, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के योग्यताधारी शिक्षकों को नहीं लगाया जा रहा है।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): जहां पर ये औषधालय खोले गये हैं, वहां पर योग के, नैचुरोपैथी के और आयुर्वेद तीनों के रिक्त पद भरे जाते हैं।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ऐसी समस्या आई है, तो आप इसको एक बार दिखवाएं कि जो योग्यताधारी चिकित्सक हैं, प्राकृतिक चिकित्सा और योग के, आप उनको प्रायोरिटी देकर इसमें लगवाएं। मेरा आपसे यही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

छबड़ा में स्वीकृत कछावन पेयजल योजना

47. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तहसील छबड़ा के ग्राम कछावन में कछावन पेयजल योजना स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो कब व किन-किन गांवों हेतु?

(2) क्या यह सही है कि स्वीकृत की गई उक्त पेयजल योजना बंद कर दी गई है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त पेयजल योजना को पुन: स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (श्री सुरेश सिंह रावत) (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री के स्थान पर): (1) जी हां। तहसील छबड़ा के 16 ग्राम व 3 ढाणियों हेतु कछावन पेयजल परियोजना की स्वीकृति वित्त समिति की 747वीं बैठक दिनांक 03.08.2018 में राशि रुपये 50.76 करोड़ की जारी की गई थी। योजना की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता (विशिष्ट परियोजना) द्वारा दिनांक 28.08.2018 को राशि रुपये 21.00 करोड़ की जारी की गई थी। योजना में सम्मिलित ग्रामों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त 16 ग्राम व 3 ढाणियों को प्रस्तावित वृहद् पेयजल परियोजना परवन-अकावद में शामिल करने के कारण मंत्रीस्तरीय समिति द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में वित्त समिति की 761वीं बैठक दिनांक 26.11.2019 द्वारा उक्त परियोजना की स्वीकृति निरस्त की गई थी, जिसका विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) कछावन पेयजल परियोजना के 16 ग्राम व 3 ढाणियों को सम्मिलित करते हुए कोटा, बारां एवं झालावाड़ जिलों के कुल 1402 ग्रामों की वृहद् पेयजल परियोजना परवन-अकावद की स्वीकृति एस.एल.एस.एस.सी. की 27वीं बैठक में दिनांक 03.09.2021 को राशि रुपये 3523.16 करोड़ की जारी की गई है, जिसका विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): साहब, जवाब तो आ गया है।

श्री अध्यक्ष: जवाब आ गया। ठीक है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): मंत्री जी, उप मुख्य मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद। आपने सिंचाई में छबड़ा का ध्यान रखा। आपने कछावन का एनिकट मंजूर किया, उसके लिए मैं आपको स्पेशियली धन्यवाद देता हूं। साथ ही, निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो कछावन पेयजल योजना है, वह 2018 में स्वीकृत हुई थी। उसके बाद यह 03.09.2021 को कांग्रेस सरकार के समय रद्द कर दी गई। इसकी लागत 21 करोड़ रुपये थी। इस योजना से 16 गांव और 3 ढाणी को पेयजल मिलता।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न करें।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): एक तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसको बंद करने के क्या कारण रहे? आपने कहा है कि परवन सिंचाई परियोजना या परवन डैम से पेयजल स्कीम तीन-चार हजार करोड़ की बनी है, उससे हम इनको जोड़ेंगे। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि परवन डैम बनने

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

में ही अभी काफी समय लगेगा। कब तो पेयजल की लाइनें खिचेंगी और कब गांवों तक पानी पहुंचेगा। ये बिलकुल टेल पर गांव हैं। किशनगंज, शाहबाद से और अटरू प्रोपर से लगे हुए गांव हैं, इसलिए आप इस योजना को तो अलग से मंजूर करें। इसलिए करें कि इसमें आपने एनिकट तो दे ही दिया है। पी.एच.ई.डी. का पैसा भी कम खर्च होगा, खाली लाइन डालनी है।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): इसमें बताया है कि 2021 में हमने स्वीकृति जारी कर दी है परवन डैम से, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि 2021 से पहले...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए। अभी भाषण नहीं देना है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): एक मिनट, साहब। यह 2018 में सैंक्शन हुई, 2021 में निरस्त हुई। इसको चालू कर दो, इतना ही निवेदन है। आपने जो सिंचाई में पैसा दिया, उसके लिए मुख्य मंत्री जी का, उप मुख्य मंत्री जी का और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, विराजिये। माननीय मंत्री जी, कुछ कहेंगे?

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, छबड़ा से आने वाले वरिष्ठ विधायक महोदय को बताना चाहता हूं कि इस योजना में 16 ग्राम व ढाणियों को प्रस्तावित वृहद् पेयजल परियोजना परवन-अकावद में शामिल करने के कारण मंत्री स्तरीय समिति द्वारा लिए गये निर्णय के क्रम में वित्त समिति की 761वीं बैठक दिनांक 26.11.2019 द्वारा उक्त योजना की स्वीकृति निरस्त की गई थी, जिसका विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है, इनको भिजवा दिया गया है।

दूसरा, योजना की निविदाएं वर्तमान में प्रक्रियाधीन हैं एवं पैकेज चार, जिसमें उक्त 16 ग्राम सम्मिलित हैं कि प्री-क्वालीफिकेशन बिड दिनांक 25.06.2024 को निर्णीत करते हुए..

श्री अध्यक्ष: उनके प्रश्न का उत्तर दीजिए।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): वित्तीय बिड प्रक्रियाधीन है। योजना के कार्यादेश जारी करने के उपरान्त 20 माह में योजना में प्रभावी समस्त कार्यों को पूर्ण कर पेयजल उपलब्ध कराया जाना लक्षित है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कुछ पूछना है?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): साहब, मेरा यही है कि इसको अलग से सैंक्शन करके इसका काम, जितना जल्दी हो, चालू करवाएं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

सादुलपुर में यमुना का पानी लाने हेतु एमओ.यू.

48. श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य व केन्द्र सरकार के मध्य यमुना का पानी पाइप लाइन द्वारा विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में लाने हेतु एम.ओ.यू. हुआ था? यदि हां, तो एम.ओ.यू. की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना से कितने गांव व कितना क्षेत्रफल सिंचित होगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त परियोजना का कार्य कब से प्रारम्भ कर कब तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

श्री अध्यक्ष: आपका प्रश्न स्थगित हुआ है। आपका बाद में लगायेंगे।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): आपकी व्यवस्था से हम संतुष्ट हैं, आपने जो दे दी, लेकिन सरकार की इतनी बड़ी क्या मजबूरी होगी। यमुना जल का बहुत बड़ा एमओ.यू. था। इस प्रश्न का सरकार जवाब देना नहीं चाह रही है। आपने इसे स्थगित किया।

श्री अध्यक्ष: यह प्रश्न स्थगित है। इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। यह प्रश्न स्थगित है। माननीय सदस्य, प्रश्न चिह्न नहीं होता। माननीय सदस्य, व्यवस्था पर प्रश्न चिह्न नहीं होता। अंकित नहीं होगा, बैठिए। आप प्रश्न पूछिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): 000

श्री अध्यक्ष: श्रीमती इन्द्रा।

अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को देय छात्रवृत्ति

49. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में विभाग की कितनी योजनाएं संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती इन्द्रा)

(2) क्या सरकार विदेश जाकर पढ़ाई करने वाले छात्रों को देय छात्रवृत्ति को बंद करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा रही है? यदि हां, तो विगत एक वर्ष का जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अविनाश गहलोत): (1) विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) विदेश में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों हेतु संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं को बंद करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) सरकार द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों हेतु निम्न छात्रवृत्ति योजनाएं संचालित की जा रही हैं:-

1. पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति
2. उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति
3. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति
4. विधवा/परित्यक्तता मुख्यमंत्री (बी.एड) सम्बल योजना मे छात्रवृत्ति
5. बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना में अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति
6. बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण जनजाति के प्रतिभावान छात्राओं को छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है।

उक्त छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 में योजनावार जिलेवार लाभार्थियों का विवरण परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जवाब आ गया है। आप चाहें तो मैं पूछूं?

श्री अध्यक्ष: आप पूरक प्रश्न पूछिए।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्योंकि कल भी जवाब में ही पूरा हो गया और यहां भी महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, +++

श्री अध्यक्ष: आप पूरक प्रश्न करें।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): आप यदि मंत्री जी से जवाब दिलवाओ तो मैं पूछूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछोगे, जवाब देना उनके हाथ का है।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): +++

श्री अध्यक्ष: कल दिलवाया था। आसन की व्यवस्था पर आप नहीं कह सकते हैं। हटा दीजिए। आसन की व्यवस्था पर प्रश्न चिह्न न करें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा-सा यह गलत आ गया है कि यहां पर महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। कृपया, यह रिकार्ड पर नहीं आवे।

श्री अध्यक्ष: चलिए। हो गया आपका।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगी मंत्री महोदय से कि विदेश में पढ़ने वाले, जो खण्ड (2) में मैंने सवाल पूछा है, विदेश में पढ़ने जो बच्चे जा रहे हैं, उनके लिए जो यूनिवर्सिटीज चयन की गई हैं, उनमें वो कितनी यूनिवर्सिटीज हैं और कौन-कौनसी चिकित्सा की, इंजीनियरिंग की, सामान्य जो हैं अलग-अलग वो कितनी हैं और उनके मापदंड क्या हैं और उसके अलावा उनमें कोई कांट-छांट की गई है क्या अभी कुछ दिन पहले, जिससे कि विद्यार्थियों को नुकसान होगा? मैं यह पूछना चाहती हूं मंत्री महोदय से।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बामनवास से आने वाली माननीय सदस्या ने जो प्रश्न पूछा, प्रश्न का खण्ड (2) है जिसमें आपने पूछा, उसका उत्तर है, 'विदेश में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों हेतु संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं को बंद करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।'

अब माननीय सदस्या ने जो पूछा है उसका उत्तर मैं आपसे निवेदन करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह सवाल हायर एजुकेशन से सम्बन्धित है, लेकिन फिर भी मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। पूर्व में इस योजना का नाम राजीव गांधी स्कालरशिप योजना था। हमारी सरकार बनने के बाद में हमने इसका नाम स्वामी विवेकानन्द के नाम पर रखा। पहले इसमें प्रावधान था कि लगभग पांच सौ के करीब हमारे छात्र विदेश में पढ़ने के लिए

(श्री अविनाश गहलोत)

जायेंगे कोचिंग के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि राजस्थान के सरकारी कालेजों में आठ लाख से ज्यादा के करीब विद्यार्थी अध्ययनरत हैं आज की तारीख में और जिन पांच सौ के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं, उसके बाद में हमने तीन सौ इसलिए किया, क्योंकि जिन पांच सौ बच्चों का जो बजट होता है वह राजस्थान के कालेजों में पढ़ने वाले आठ लाख बच्चों से ज्यादा का बजट होता है। आप यह तय करिए कि राजस्थान के कालेजों में जो आठ लाख बच्चे पढ़ते हैं उनका भविष्य भी सुधारना जरूरी है या सिर्फ उन पांच सौ बच्चों को, इसलिए बजट के मामले में अगर हम लोग देखें तो आठ लाख का जो बजट है उसके बराबर तीन सौ बच्चों का बजट है, इसलिए हमने इसमें थोड़ा संशोधन किया है और आने वाले समय में मेरिट के आधार पर यह तय होगा कि किन बच्चों को हम लोग भेजेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा, इस स्कालरशिप योजना के अन्दर राजस्थान का आम गरीब व्यक्ति पहुंच नहीं पाता है। बड़े रसूखदार व्यक्ति जो होते हैं वो अपने बच्चों को विदेश में भेजते हैं। आज आपके विधान सभा क्षेत्र का कोई छात्र पढ़ने के लिए उस स्तर पर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उनके पास अप्रोच नहीं होती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह जो योजना है यह साथ में उन आठ लाख बच्चों के भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए चलायी जानी चाहिये, क्योंकि उनका पूरा बजट इन तीन सौ बच्चों के बराबर होता है। आप यह बताएं कि क्या आठ लाख बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल सकते हैं हम लोग, इन तीन सौ बच्चों को विदेश भेजने के नाम पर? कोई गांव का गरीब व्यक्ति अपने बेटे को विदेश में भेज सकता है क्या पढ़ाई के नाम पर आज? नहीं भेज सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस योजना को और संशोधित करना चाहिये और राजस्थान के आठ लाख विद्यार्थियों के भविष्य के साथ जोड़ा जाना चाहिये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले सवाल में एक सवाल और पूछा था कि कौनसे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनको आपने और सलेक्ट किया है और कुछ को काटा है जिनकी रैंकिंग कम है उनको सलेक्ट कर लिया और बाकी जो अच्छी रैंकिंग वाले हैं उनको काट दिया है। ऐसा प्रकरण अगर है तो आप सदन को बताएं।

(श्रीमती इन्द्रा)

दूसरा एक और पाइंट है मेरा राजस्थान के बारे में कि राजस्थान में पिछले पांच सालों के अन्दर छात्रवृत्तियां बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल पायीं। बहुत सारी पेंडेंसी चल रही है, तो केन्द्र सरकार की तरफ से पैसा नहीं आया। पिछले पांच साल जिस तरीके से चला, क्या अभी भी उसी प्रकार चलेगा या आप कन्टीन्यू बनायेंगे उसको?

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि जो स्कालरशिप योजना है वह मैंने आपको सारी उत्तर में दे दी है, वैसे पूरा बंडल मेरे पास पड़ा है, मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा।

विशेष रूप से आपने पूछा एस.टी. का। अब मैं आपको निवेदन करता हूं कि जो एससी./एस.टी./ओ.बी.सी. की स्कालरशिप है, इसमें सिर्फ एस.टी. का बताता हूं मैं। एसटी. के अन्दर केन्द्र प्रवृतित योजना का अंश 75 प्रतिशत है और हमारी स्टेट गवर्नमेंट का 25 प्रतिशत है। अब हमारी सरकार को बने हुए छह महीने हुए हैं, इससे पहले जब आपकी सरकार थी तो आपने इससे पहले जो एस.टी. के बच्चों की स्कालरशिप बकाया थी, उसमें ऐसा कोई प्रयास नहीं किया सेन्ट्रल से पैसे लाने का। अब हम यह बता रहे हैं कि वर्ष 2023-24 में सम्भावित आवेदन जो हमारे पास थे, उसमें 401.39 करोड़ रुपये एवं इससे पहले के बकाया जो थे 257.42 करोड़ रुपये, की कुल राशि समेत 658.81 करोड़ रुपये के प्रस्ताव जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किये गये थे, जिनमें से हमने 220 करोड़ रुपये अभी तक प्राप्त कर लिए हैं और वो हमारे छात्रों के खाते में हमने दे दिये हैं और यह जो 257 करोड़ रुपये थे, ये आपकी सरकार में आपने कोई प्रयास नहीं किया था, इसलिए आ नहीं पाये। हमारी सरकार को छह महीने हुए हैं और इन छह महीनों में इस बकाया बजट को लाने के लिए ...(व्यवधान) एक मिनट सुनिये, इस बजट को लाने के लिए हमारे राजस्थान के एस.टी. समुदाय के जितने भी छात्र-छात्राएं, जो स्कालरशिप का लाभ लेते हैं उनको यह बकाया राशि देने के लिए राजस्थान सरकार के माध्यम से मैंने स्वयं ने पत्र लिखा है। हमारे जो ए.सी.एस. हैं उन्होंने पत्र लिखा है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने पत्र लिखा है। (व्यवधान) एक मिनट सुनिए आप।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो पूछ रही हूं उसका जवाब मंत्री महोदय दे नहीं रहे हैं। दोनों सवालों के जवाब, पहले जो मैंने पूछे हैं रिप्लाई के समय उनका आप जवाब दे दीजिए। क्या विश्वविद्यालय में चैंजेज किया है, रैंकिंग के आधार पर क्या विश्वविद्यालय घटाये-बढ़ाये हैं, जिनका चयन आपने किया है कि इन विद्यालयों में जायेंगे तो ही हम स्कालरशिप देंगे?

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो दूसरा सवाल पूछा था तब मैंने एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. के बारे में बताना चाहा, आपने कहा कि मुझे एस.टी के बारे में बतायें।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): वह जवाब आ गया है।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अब जब मैं आपको बताना चाह रहा हूं हमने पत्र लिख दिया है, सम्भवत: इसी जुलाई महीने के अन्दर या इसके आस-पास में हमारी बची हुई राशि 438.81 करोड़ जैसे ही आती है एस.टी. समुदाय के प्रत्येक छात्र के खाते में छात्रवृत्ति चली जायेगी।

दूसरा, आपने जो इन विश्वविद्यालय/कालेज के बारे में पूछा है, मैंने पहले ही, माननीय सदस्या, आपको निवेदन किया था कि यह हायर एजुकेशन का विषय है। हमारी जो विदेश में पढ़ने वाली योजना है, स्वामी विवेकानन्द जी के नाम से हमने जो की है यह उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में फिर भी अगर आप मुझे बतायेंगे तो व्यक्तिगत रूप से मैं उच्च शिक्षा के विभाग से इसकी सम्पूर्ण जानकारी लेकर आपको उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, एक मिनट। एक तो माननीय मंत्री जी ने जो यहां जवाब दिया है वो यहां रिकार्ड हो रहा है कि पिछली सरकार ने प्रयास नहीं किये। अगर प्रयास किये हुए होंगे तो यहां मंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा सदन के अन्दर, सबसे पहली बात।

मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं कि यह जो एसटी. की और ओ.बी.सी. की छात्रवृत्ति जो बकाया है कब से बकाया है और भारत सरकार क्यों नहीं दे रही है? वह आप बताएं।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बता दिया था कि हमने हमारे छह महीने के इस कार्यकाल में समय-समय पर, मैं आपको यही निवेदन कर रहा हूं, हमने यह पत्र...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप तो डिटेल दिलवाओ, साहब, भाषण नहीं। आप डिटेल दिलवा दो कब से बकाया है, कितनी बकाया है? यह बता दें आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपकी ओर से प्रश्न पूछा है, आने दीजिए।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2023-24 का जो बकाया है मैं आपको इसकी डिटेल दे देता हूं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): स्पेसिफिक जो बकाया है वह बता दो। स्पेसिफिक जवाब दिलवा दो।

श्री अध्यक्ष: फिर आप अलग से आइए।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैंने इसमें यह उत्तर दिया है कि अभी तक 438.81 करोड़ रुपये बकाया है, वह हमारे पास इसी जुलाई के अन्दर, कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से आचार संहिता के कारण, नया मंत्री परिषद् बनने के कारण नहीं आये हैं। इसके लिए हमने, पहले से ही माननीय मुख्य मंत्री जी ने, मैंने और हमारे विभाग ने पत्राचार करके और व्यक्तिगत हमारी टीम को हमने भेजा है सेन्टर में, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से वह नहीं हुआ, लेकिन मैंने बताया कि इसी जुलाई माह के अन्दर सम्भवत: अभी हमारी लेटेस्ट बात हुई है, हम लगातार प्रयास करेंगे कि वह जल्दी ही हमारे एस.टी. के छात्रों के खाते में आ जाएं।

श्री अध्यक्ष: श्री लक्ष्मण।

उचित मूल्य के दुकानदारों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

50. श्री लक्ष्मण (बस्सी): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में विगत एक वर्ष में उचित मूल्य के दुकानदारों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में उक्त अवधि में कितने उचित मूल्य के दुकानदारों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई तथा उक्त पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार राशन वितरण व्यवस्था में अनियमितताओं को रोकने व सुधार हेतु ग्राम पंचायत के माध्यम से राशन वितरण कराने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री सुमित गोदारा): (1) प्रदेश में विगत एक वर्ष में उचित मूल्य के दुकानदारों के विरुद्ध कुल 1,560 शिकायतें प्राप्त हुई जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में विगत एक वर्ष में कुल 02 राशन डीलरों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई उक्त शिकायतों में राशन डीलरों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है-

क्रम संख्या	नाम डीलर	विभागीय कार्यवाही
1.	श्री नन्दकिशोर मीणा	प्राधिकार पत्र निलम्बित
2.	श्री भगवान सहाय	नोटिस जारी किया गया है।

(3) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री लक्ष्मण (बस्सी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि यह जो एग्जिस्टिंग शोप्स हैं राशन की, उनके अलावा भी कोई और नयी दुकानें खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है या नहीं?

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मैंने पूर्व में यह जवाब दिया कि हम आबंटन सलाहकार समिति का गठन करने के बाद, यदि आपके भी विधान सभा क्षेत्र में कहीं आपको आवश्यकता है तो आप जरूर सुझाव दीजिए, हम उस पर जरूर अमल करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री उदयलाल भडाणा।

माण्डल में संचालित कोयले के अवैध भट्टे

51. श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र माण्डल में कितने तथा किस-किस स्थान पर कोयला बनाने के अवैध भट्टे संचालित हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भट्टों से क्षेत्र में प्रदूषण हो रहा है तथा आस-पास के गांवों में फसलों तथा पेड़-पौधों को भी काफी नुकसान हो रहा है? यदि हां, तो उक्त अवैध भट्टों को हटाने तथा प्रदूषण की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री उदयलाल भडाणा)

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कोयला भट्टों द्वारा आस-पास के पेड़ों को काटकर कोयला बनाया जाता है? यदि हां, तो इसकी रोकथाम हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, पर्यावरण (श्री संजय शर्मा): (1) विधान सभा क्षेत्र माण्डल में बिलानाम एवं चरागाह भूमियों पर 215 अवैध कोयला भट्टियां संचालित थीं, जिनमें से 82 अवैध कोयला भट्टियों को मौके पर बंद करवा दी गई हैं एवं शेष के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है (सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।) तथा निजी खातेदारी भूमियों पर अवैध कोयला भट्टियों के सम्बन्ध में सर्वे करवाया जा रहा है।

(2) जी हां। कोयला भट्टियों से होने वाले प्रदूषण से फसलों तथा पेड़ पौधों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

वन विभाग एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को अवैध कोयला भट्टियों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर राजस्व विभाग एवं सम्बन्धित जिला कलक्टर द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

विधान सभा क्षेत्र माण्डल में बिलानाम एवं चरागाह भूमियों पर 215 अवैध कोयला भट्टियां संचालित थीं, जिनमें से 82 अवैध कोयला भट्टियों को मौके पर बंद करवा दी गई हैं एवं शेष के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है (सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।)

(3) जी हां। सामान्यत अंग्रेजी बबूल व अन्य पेड़ों से कोयला बनाया जाता है।

पेड़ों की अवैध कटाई के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर राजस्व विभाग, सम्बन्धित जिला कलक्टर एवं उप वन संरक्षक द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

वन मण्डल भीलवाड़ा के अधीन वन कर्मियों द्वारा नियमित रूप से सतत् गश्त करते हुए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि वन क्षेत्र के आस पास कोई कोयले की भट्टी संचालित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जैसा आपने बताया 215 भट्टियां संचालित हैं, लेकिन माण्डल विधान सभा क्षेत्र में ही करीब 5,000 कोयले की अवैध भट्टियां संचालित हैं और पूरे भीलवाड़ा जिले में करीब 20 हजार के पास भट्टियां हैं। आप सभी माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि पिछले 7-8 महीने पहले एक अवैध कोयला भट्टी वालों के द्वारा वहां बहन +++ का बलात्कार कर के निर्मम हत्या कर भट्टी में जला दिया गया था। ये भट्टी वाले गलत तरीके से अवैध काम करते हैं।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिए।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): मैं जब विधायक नहीं था, तब मैंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में आवाज उठाई, तब मेरे ऊपर भी करीब 700 लोगों ने, लुहारिया गांव के भट्टी वालों ने मेरे पर जानलेवा हमला किया, लेकिन गनीमत रही और भगवान का आशीर्वाद रहा कि मैं उस जानलेवा हमले में बच गया। अगर गलत काम की आवाज उठाना गलत है, तो सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिए।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): यह 215 नहीं, पूरी 5,000 भट्टियां हैं। एक तरफ प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी कहते हैं कि एक पेड़ मां के नाम लगाकर...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, भाषण नहीं, प्रश्न पूछिए।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): यह 215 भट्टियां नहीं, यह 5,000 भट्टियां हैं, इनको कब तक ध्वस्त कर दिया जायेगा?

श्री अध्यक्ष: हां, यह प्रश्न हुआ। मंत्री महोदय।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह प्रश्न राजस्व विभाग से सम्बन्धित है, चूंकि मेरे नाम नामित हुआ है मैंने माननीय सदस्य के प्रश्न को और इनकी भावना को देखते हुए वहां के कलेक्टर साहब से बात की है और कलेक्टर साहब ने मुझे आश्वस्त किया है कि एक महीने के अन्दर-अन्दर जो भी अवैध भट्टियां हैं, उनको तोड़ कर, भट्टियों से उन्मूलन करके उस क्षेत्र को मुक्त कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री मनीष यादव।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाभान्वित परिवार

52. श्री मनीष यादव (शाहपुरा): क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सभी गरीब परिवारों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है? यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रदेश में अब तक कितने गरीब परिवारों को चयनित कर उक्त योजना से लाभान्वित किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के तहत वर्ष 2024-25 में कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) (राज्य मंत्री, सहकारिता के स्थान पर): (1) खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत चयनित पात्र लाभार्थियों को जनवरी, 2023 से दिसम्बर 2028 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है/कराया जावेगा।

नवीन सरकार के गठन के पश्चात् खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किये जाने हेतु नवीन आवेदन प्राप्त नहीं करके पूर्व में प्राप्त कुल 19.58 लाख आवेदन में से लम्बित आवेदन लगभग 13.9 लाख में से परीक्षण पश्चात् नाम जोड़ने की कार्यवाही विभागीय स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

(2) वर्तमान में वर्ष 2024-25 में संकल्प पत्र में पृथक् से लक्ष्य निर्धारित नहीं है।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): उत्तर प्राप्त हो गया है। मैं पूरक प्रश्न पूछने की इजाजत चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, पूरक प्रश्न पूछिए।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022 में 19.58 लाख आवेदन खाद्य सुरक्षा के प्राप्त हुए हैं। इनमें से 13.90 लाख अभी भी लम्बित हैं तथा उसके बाद भी लगभग 15 लाख ऐसे गरीब परिवार हैं जो खाद्य सुरक्षा से वंचित हैं, जो अभी भी खाद्य सुरक्षा पोर्टल खुलने का इंतजार कर रहे हैं। पिछले दो वर्ष से केन्द्र सरकार तथा राज्य में सात महीने से आपकी सरकार है, आपकी सरकार ने इनके खाद्यान्न की क्या व्यवस्था की? आपने उत्तर में इस सारे मसले को प्रक्रियाधीन बताया है, जबकि अब तक सात माह में एक भी नये परिवार को आपने राशन नहीं दिया है। कृपया उत्तर दें।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 4 करोड़ 46 लाख की राजस्थान की जो सीलिंग है, उसमें 4 करोड़ 35 लाख लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। आपने जो साढ़े दस लाख वंचित स्थान बताये हैं, उसमें सरकार ने आते ही 1 लाख 66 हजार जो सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी विशेष योग्यजन हैं, उनका नाम जोड़ दिया है। डी.ओ.आई.टी. में अगले 2-4 दिन में ही वह सूचीबद्ध हो जायेंगे और भारत सरकार के निर्देश से जो सहरिया जनजाति है, जो PVTG पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं, उनके नाम जोड़ने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। लगभग दो लाख नाम जुड़ रहे हैं और जो 44,374 विशेष योग्यजन हैं, जिन्होंने आधार कार्ड/जनाधार से अभी तक ई.के.वाई.सी. नहीं कराया है, वह करायेंगे तो लगभग डेढ़ लाख लोग वे भी नये जुड़ेंगे। आप जो साढ़े दस लाख बता रहे हो, उसमें सात लाख स्थान हमारे पास रिक्त रहेंगे। इनके लिए 13 लाख 90 हजार आवेदन प्राप्त हैं, उनको जोड़ने की प्रक्रिया जारी है और जल्दी ही उनको जोड़ दिया जायेगा।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक एक भी नया परिवार नहीं जोड़ा गया है।

मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि आपने संकल्प पत्रानुसार पांच वर्षों के लिए राजस्थान के सभी गरीब परिवारों को मुफ्त राशन देने की घोषणा की थी। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी कह रहे हैं कि हमने गरीब कल्याण को आधार बनाया है और हम सत्ता का माइंड सैट नहीं, सेवा का माइंड सैट लेकर आये हैं। ऐसे में मैं जानना चाह रहा हूं कि दो वर्षों से ऐसे गरीबों को उनका हक क्यों नहीं मिल पा रहा है? आप घोषणा पत्र में तो कह रहे हैं कि सभी गरीब परिवारों को राशन देंगे। ऐसे में आपका संकल्प पत्र/घोषणा पत्र असत्य है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिए, भाषण नहीं।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): ...(व्यवधान) मैं प्रश्न पूछ रहा हूं।

आपने संकल्प पत्रानुसार पांच वर्षों के लिए सभी गरीब परिवारों को मुफ्त राशन देने की घोषणा की है, जबकि आपने प्रश्न संख्या दो के जवाब में कहा है कि वर्तमान में 2024-25 में संकल्प पत्र में पृथक् लक्ष्य निर्धारित नहीं हैं। ऐसे में आपका संकल्प पत्र असत्य है।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिए, आप ही जवाब दे रहे हो। प्रश्न पूछो, नहीं मैं अगला प्रश्न पुकार रहा हूं।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): मैंने प्रश्न ही पूछा है। गांवों में लोग इंतजार कर रहे हैं, खाद्य सुरक्षा का पोर्टल कब खुलेगा?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा कि वास्तव में आपने प्रधान मंत्री जी की प्रशंसा ही की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 82 करोड़ देशवासियों को और आगामी पांच सालों में 12 लाख करोड़ की घोषणा की गई ...(व्यवधान) आप जवाब सुनिए... (व्यवधान) माननीय जुबेर जी, भाभी जी अच्छा जवाब देती थीं, आप बैठिए... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए, आप विराजिए। (व्यवधान) बिना अनुमति के नहीं, हो गया। (व्यवधान)

श्री गोपाल शर्मा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, सिम्पल-सी बात है, पोर्टल की तारीख बता दें कब खुलेगा? पूरा राजस्थान त्रस्त है, गरीब त्रस्त हैं। गरीब कल्याण की बात हो रही है, पोर्टल कब खोलोगे? तारीख बता दो, तारीख।

श्री अध्यक्ष: श्री गोपाल शर्मा।

जयपुर में मैट्रो के विस्तार हेतु सर्वे

53. श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाइन्स): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा जयपुर की बढ़ती जनसंख्या के दृष्टिगत जयपुर मैट्रो रेल के विकास तथा विस्तार के लिए कोई सर्वे करवाया गया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जयपुर मैट्रो रेल हैड सर्वे करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन (श्री झाबर सिंह खर्रा): (1) जी हां। जयपुर मैट्रो फेज-1 के विस्तार के लिए विभिन्न सर्वे करवाने के उपरान्त एवं मैट्रो रेल पालिसी-2017 के दिशा-निर्देशों अनुसार, फेज-1सी (बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर) एवं फेज-1डी (मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहा) की डी.पी.आर. तैयार करवाई गई थी। अनुमोदन उपरान्त परियोजना पर कार्य प्रगति पर है। सम्बन्धित ट्रैफिक स्टडी सर्वे की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन)

जयपुर मैट्रो के विस्तार हेतु वर्ष 2014 एवं वर्ष 2020 में जयपुर मैट्रो फेज-2 (सीतापुरा से अम्बाबाडी) की डी.पी.आर. तैयार करवाई गई थी, जो आदिनांक तक अनुमोदित नहीं है।

तदुपरान्त जयपुर मैट्रो फेज-2 डी.पी.आर. वर्ष 2020 (सीतापुरा से अम्बाबाड़ी) के Updation एवं Revision, लेखानुदान 2024-2025 अनुसार फेज-2 के अम्बाबाड़ी से विद्याधर नगर तक विस्तार के लिए सर्वे कार्य प्रस्तावित है।

(2) जी हां। उपरोक्तानुसार सम्भावित मार्गों पर विस्तार हेतु सर्वे/ डी.पी.आर. के लिए ट्रैफिक-ट्रांसपोर्ट सलाहकार की नियुक्ति हेतु दिनांक 06.07.2024 को निविदा जारी की गई है। सलाहकार द्वारा सर्वे उपरान्त, Feasible मार्गों पर डी.पी.आर. तैयार करवाई जायेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाइन्स): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से पूरी तरह से संतुष्ट हूं, तथ्य परक जवाब है। मेरा एक पूरक प्रश्न है कि 2014 से मैट्रो फेज-2 का विषय चल रहा है। 2014 में, 2000 में इसके लिए डी.पी.आर. तैयार हुई, लेकिन अभी तक अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका, क्योंकि पिछली सरकार को तीन वर्षों तक अनुमोदन करने के लायक विषय नहीं मिला था, जो जवाब में है।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछो।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाइन्स): मेरा प्रश्न यह है कि जब इस वर्तमान सरकार ने अम्बाबाड़ी से स्कीम को विद्याधर नगर तक बढ़ा दिया है, तो क्या पिछली डी.पी.आर. के अनुसार कुछ काम आगे बढ़ेगा या नये सिरे से सारा विचार किया जायेगा?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सदन को अवगत कराना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बोलिए। (व्यवधान) अंकित नहीं हो। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, ...(व्यवधान) आप उत्तर दीजिए।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): हमको हर चीज का मालूम है, आप जो भी पूछेंगे, उसका सम्पूर्ण जवाब मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: आपका प्रश्न लगे तब आप पूछ लेना।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): यहां किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय विधायक और सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि जयपुर मैट्रो ने सम्भावित मार्गों के विस्तार हेतु सर्वे डी.पी.आर. के लिए ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट सलाहकार की नियुक्ति हेतु दिनांक 06.07.2024 को निविदा जारी कर दी है। सलाहकार द्वारा सर्वे उपरान्त फिजिबल मार्गों पर डी.पी.आर. तैयार करवाई जायेगी और इस बीच माननीय जन-प्रतिनिधियों द्वारा जो भी सकारात्मक सुझाव हमें मिलेंगे, उनको भी हम डी.पी.आर. में शामिल करवाने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेंगे।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाइन्स): बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त।

(शेष तारांकित व समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें।)

(समय: 12.00 बजे)

अनुपस्थिति अनुमति

किरोड़ी लाल, श्री, मंत्री, को सम्पूर्ण सत्रकाल के लिए

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री किरोड़ी लाल, सदस्य विधान सभा द्वारा सोलहवीं राजस्थान विधान सभा के द्वितीय सत्र में अपरिहार्य कारणों से सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए? (व्यवधान)

(स्वीकृत)

दिनांक 12 जुलाई, 2024 को यह अनुमति प्रदान की गयी।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में बीमा कम्पनी द्वारा मनमाने तरीके से आपत्तियां दर्ज कर बीमा क्लेम का भुगतान बाधित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में स्वीकृत महाविद्यालय के भवन का निर्माण एवं कार्मिकों की नियुक्ति नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री हरिमोहन शर्मा एवं 13 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में राजस्थान पंचायत सरपंच संघ की लम्बित मांगों का निस्तारण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री गणेश घोगरा, सदस्य की ओर से नानाभाई खांट राजकीय जनजाति बालक आश्रम छात्रावास का भवन जर्जर अवस्था में होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री रविन्द्र सिंह भाटी, सदस्य की ओर से प्रदेश के स्थानीय युवाओं को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में रोजगार न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री ललित यादव, सदस्य की ओर से प्रदेश में छात्र संघ चुनावों पर लगी रोक न हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री चन्द्रभान सिंह चौहान, सदस्य की ओर से नरेगा अन्तर्गत कार्मिकों के नियमितीकरण एवं दुर्घटनाग्रस्त होने पर राहत नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री पूसाराम गोदारा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के नवीन क्रमोन्नत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पदों का सृजन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(9) श्री हरीश चौधरी, सदस्य की ओर से जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के इंजीनियरिंग संकाय को अलग कर एम.बी.एम. विश्वविद्यालय बनाने के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री थावर चन्द, सदस्य की ओर से प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों के उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को विगत 03 वर्षों से छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री घनश्याम एवं 11 अन्य सदस्यों की ओर से करौली जिले के

(श्री अध्यक्ष)

मासलपुर-आगरा रोड के ग्राम भोजपुर स्थित वन विभाग की चौकी में 09 वर्षीय मूक-बधिर बालिका के साथ किये गये अमानवीय कृत्य की जांच सी.बी.आई. से करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री मनीष यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा एवं पूरे प्रदेश में बन्दरों के आतंक से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए। अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री हरीश चौधरी, श्री थावर चन्द, श्री घनश्याम एवं श्री मनीष यादव को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री रामबिलास, सदस्य की ओर से जयपुर डेयरी में कार्यरत ठेकाकर्मियों को संविदाकर्मी मानते हुए नियमित भर्ती में बोनस अंक दिये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्रीमती गीता बरवड़, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के ग्राम नांदड़ा खुर्द में हुई हत्याओं एवं बिलाड़ा के ग्राम रावनियाणा में दलित नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

(3) श्रीमती कल्पना देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के नगर निगम कोटा उत्तर एवं दक्षिण के अन्तर्गत आने वाले नालों की सफाई नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में पानी की कमी के कारण हो रहे किसानों के पलायन को रोकने हेतु ठोस कार्ययोजना बनाकर जलापूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री सुरेश गुर्जर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खानपुर के ग्राम लड़ानिया के टोल बूथ से स्थानीय निवासियों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(6) श्री हरिसिंह रावत, सदस्य की ओर से प्रदेश में निजी संस्थाओं के माध्यम से नरेगा के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्य को वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(7) श्री हाकम अली खां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के रामगढ़ कस्बे से गुजरने वाले एन.एच. 52 पर अण्डर-पास का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(8) डा. ऋतु बनावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बयाना के उप खण्ड रूपवास में जल-जीवन मिशन योजनान्तर्गत हर घर जल योजना का कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री राम सहाय वर्मा (रेगर), सदस्य की ओर से प्रदेश में अवैध बजरी खनन के लिए जिम्मेदार ठेकेदारों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में।

(10) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा शहर में नमामि गंगे योजनान्तर्गत करवाये गये सीवरेज कार्य में हुई अनियमितताओं की जांच करवाकर कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में जल जीवन मिशन योजना की पाइप लाइनें डालने से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत करवाए जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री विद्याधर सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के किशनगढ़-रेनवाल कस्बे के गन्दे पानी की निकासी हेतु समुचित बजट आबंटित किए जाने के सम्बन्ध में।

(13) श्री राजेन्द्र, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र महवा के उकरूंद में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों द्वारा कनेक्शन जारी करने में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(14) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की विद्युत लाइनों को व्यवस्थित किये जाने के जाने के सम्बन्ध में।

(15) श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से प्रदेश में कुआं शिफ्ट योजना पुन: प्रारम्भ करवाये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 12 जुलाई, 2024 को शून्यकाल में बोलने हेतु 42 पर्चियां प्राप्त हुईं जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नानुसार हैं:-

(श्री अध्यक्ष)

क्र. सं.	मा. सदस्य का नाम	विषय
1.	श्री कालीचरण सराफ	बाईस गोदाम सुदर्शनपुरा एवं करतारपुरा औद्योगिक क्षेत्र को आबादी से अन्यत्र स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में।
2.	श्री डूंगरराम गेदर	सूरतगढ विधान सभा क्षेत्र में खातेदारी एवं चकबंदी करने बाबत।
3.	श्री केसाराम चौधरी	प्रदेश में हो रहे नाबालिग एवं बालिका-बच्चियों के मुकदमे एवं गुमशुदगी से समाज में फैल रहे असंतोष के सम्बन्ध में।
4.	श्री छगनसिंह राजपुरोहित	सियाणा को उप तहसील बनाने के सम्बन्ध में चर्चा।

श्री हरीश चौधरी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहूंगा और आसन एवं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछले कुछ समय से प्रदेश के अन्दर पंचायती राज और नगरपालिका के जो चुनाव हैं, उनके अन्दर प्रशासन के द्वारा...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय, यह नियम है। जैसे ही जीरो ऑवर समाप्त होगा, सबसे पहले आपको अनुमति दूंगा।

माननीय हरीश चौधरी।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): माननीय अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए, मैंने पुकार लिया है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): पूरे राजस्थान में पंचायती राज... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मुझे पता है। आपका स्थगन नहीं आ सकता। आपका सप्ताह में एक बार आ चुका है। एक सप्ताह में एक ही मिलता है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): 000

श्री अध्यक्ष: नहीं, बोलने का नहीं। आप बैठिए। इनका अंकित नहीं हो। आपके सदस्य बोल रहे हैं, बैठिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): 000

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संकाय को अलग कर एम.बी.एम. विश्वविद्यालय बनाने के उद्देश्यों की अप्राप्ति

श्री हरीश चौधरी (बायतू): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 50 के अन्तर्गत बोलने की इजाजत दी, उसके लिए धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, 2021 में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से अलग एम.बी.एम. विश्वविद्यालय बनाने का फैसला सरकार ने लिया। अध्यक्ष महोदय, उसी विश्वविद्यालय की जमीन के दो टुकड़े करके, उसी भवन के दो टुकड़े करके, जो संकाय जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में थे, वही के वही संकाय एम.बी.एम. विश्वविद्यालय में खोलने की अनुमति देना किसी भी प्रकार का कोई भी न्यायोचित तर्क नहीं था। जो एम.बी.एम. विश्वविद्यालय खोला गया, उसमें यह कुतर्क दिया गया कि सेंटर आफ एक्सीलेंसी बनाया जायेगा। यह भी कुतर्क दिया गया कि जो एम.बी.एम. कालेज की जो एल्युमिनाई एसोसिएशन है, वह वित्तीय तौर पर सहायता करेगी।

अध्यक्ष महोदय, आज उस विश्वविद्यालय के तीन वर्षों के बाद क्या हालात बने हुए हैं? दोनों के दोनों विश्वविद्यालयों के अन्दर 99 प्रतिशत शिक्षकों से कोई भी जाकर पता कर ले कि वे दोनों के दोनों विश्वविद्यालय आज अंतिम सांसें ले रहे हैं। विश्वविद्यालय के अन्दर उन कक्षाओं में सन्नाटा ही नहीं है, हमारे युवाओं के भविष्य का सन्नाटा, इस प्रदेश के भविष्य का सन्नाटा है, क्योंकि वहां कोई कक्षाएं भी नहीं लग रहीं। अध्यक्ष महोदय, जो वहां के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, उन प्रोफेसर को आज पेंशन नहीं मिल रही है। आज हमारे राष्ट्र के निर्माण, राज्य के निर्माण के लिए सबसे अहम भूमिका किसी की हो सकती है तो उन प्रोफेसर्स की हो सकती है। उन रिटायर्ड प्रोफेसर्स को फुटपाथ पर लाकर हमने बिठा दिया है। वे अनशन कर रहे हैं। वे प्रोफेसर फुटपाथ पर नहीं आये हैं, हम लोगों का भविष्य फुटपाथ पर आया हुआ है। आज विश्वविद्यालय का मूल कार्य शोध है। उस मूल शोध कार्य की सहायता के लिए शैक्षणिक कार्य होता है और शैक्षणिक कार्य का आकलन करने के लिए

(श्री हरीश चौधरी)

परीक्षा होती है। उन विश्वविद्यालयों के अन्दर आज किसी भी प्रकार की, दोनों विश्वविद्यालयों में शोध कार्य नहीं हो रहा है। दोनों के अन्दर आज कोई शैक्षणिक कार्य नहीं हो रहा है। सिर्फ परीक्षा के नाम पर ये संस्थाएं आज चल रही हैं।

मेरा आपसे निवेदन है कि किसी भी प्रकार का दोषारोपण करने की जगह हम एम.बी.एम. विश्वविद्यालय एक्ट, 10/2021 को विलोपित कर आवश्यक अधिनियम इस विधान सभा में लेकर आएं। धन्यवाद। जय हिन्द। राम-राम सा।

श्री अध्यक्ष: श्री थावर चन्द (अनुपस्थित)।

श्री घनश्याम। अपनी सीट से।

करौली में मूक-बधिर बालिका के साथ अमानवीय कृत्य की सी.बी.आई. से जांच

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का जो अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव दादनपुर की +++ मूक-बधिर के साथ जो घटना हुई, पहले उसके साथ बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या हुई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक महीने से ज्यादा का प्रकरण है। एक महीने से इसमें कई जगह हिंडोन में, करौली जिला हैडक्वार्टर पर सब जगह धरना-प्रदर्शन दिया गया, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जयपुर में भी शहीद स्मारक पर उनके परिवारजनों और आदिवासी लोगों के द्वारा कई बार धरने दिये गये। बच्ची के साथ जिस तरह की घटना हुई है, उसको नीचे से जलाया गया है। अगर कोई व्यक्ति जलता है तो उसके हाथ जलते हैं, ऊपर के हिस्से जलते हैं। इस घटना को देखते हुए ऐसा लगता है कि जो लोग इसमें लिप्त हैं, दोषी हैं, उन्होंने उसको पकड़ कर बांध कर जलाया है। बच्ची के गुप्तांग और नीचे का जो स्थान है, पूरी तरह से जला दिया गया है। पुलिस के बयान जो आ रहे हैं, वे बार-बार भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। तीन बार पुलिस ने प्रेसनोट जारी किया है। एक बार कहा है कि बच्ची तेजाब से जली है। दूसरी बार पुलिस ने प्रेसनोट जारी किया कि वह पेट्रोल से जलायी गयी है। तीसरी बार आई.जी. का जो प्रेसनोट आया है, उसमें कहा गया है कि बच्ची की जहर देने से मृत्यु हुई है।

(श्री घनश्याम)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा और आपके माध्यम से सरकार से यह चाहता हूं कि इस मामले में +++ को न्याय मिले और सी.बी.आई. से जांच होनी चाहिए। हम लोगों ने वहां करौली में बहुत सारे, हजारों लोगों ने धरना दिया और कहा कि जिला कलक्टर ने सरकार को यह लिखित में भी दिया है कि इस मामले की सी.बी.आई. जांच होनी चाहिए। सरकार को क्या परेशानी है इसकी सी.बी.आई. जांच कराने में? एक आदिवासी बच्ची जो मूक-बधिर है, बोल सकती नहीं, सुन सकती नहीं, ऐसी स्थिति में सरकार को कौनसी परेशानी है कि इस मामले में सी.बी.आई. की जांच नहीं करायी जा रही है। आदिवासियों से इतनी नफरत क्यों है? इस सरकार को इतनी ईर्ष्या क्यों है? आदिवासियों के कोई प्रकरण का मामला हो, चाहे कोई और प्रकरण में देख लीजिए, आप आदिवासियों के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं दे रहे हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): ये जो बोला गया है, इसको एक्सपंज कराया जाये। ये गलत बोला गया है। (व्यवधान) गलत बोला गया है। गलत बोल रहे हैं आप। (व्यवधान) ऐसी गैर-जिम्मेदाराना बात मत करिए।

श्री अध्यक्ष: श्री मनीष यादव। हो गया विषय आपका। आपकी बात रिकार्ड में आ गयी है। मनीष यादव। मैंने नाम पुकार लिया है। बैठिए।

प्रदेश में बन्दरों का आतंक

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 50 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव पर प्रदेश में बन्दरों के काटने एवं जनहानि व लोगों में भयंकर आतंक विषय पर आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में नगरपालिका क्षेत्र हो या हमारी जो ग्राम पंचायतें हों, वहां या फिर पूरे प्रदेश में भी कई जगह पर, अभी मैंने जब साथी विधायकों से राय की तो सबने बताया कि बन्दरों का जिस प्रकार का आतंक मेरे विधान सभा क्षेत्र में भले ही महिलाएं हों, भले ही बच्चे हों, भले ही बुजुर्ग हों, हर व्यक्ति बन्दरों के आतंक से परेशान है। ऐसे हालात, ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि कई बार बच्चे विद्यालय में जा रहे होते हैं, उन पर छीना-झपटी बन्दरों की टोलियां बनाकर की जाती है। बुजुर्ग जो छत पर टहल रहे

(श्री मनीष यादव)

होते हैं, महिलाएं जो छत पर टहल रही होती हैं, कई केसों में तो ऐसी स्थिति आयी है कि किसी की छत से गिरकर जान भी जा चुकी है। ऐसे हालात मेरे क्षेत्र में बने हुए हैं। जहां पर भी हम जाते हैं, पानी, बिजली की जनता बात करती है, लेकिन बन्दर की समस्या के बारे में, इस विषय पर ज्यादा बात करती है।

श्री अध्यक्ष: इस पर चर्चा नहीं होती। (व्यवधान) आपको अगली बार देंगे। इसमें एक ही व्यक्ति बोलता है। नहीं बैठिए, No I said, no किसी को अनुमति नहीं है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 000

श्री अध्यक्ष: उनका स्थगन लगा है, उनको बोलने दीजिए।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): मैं आपका ध्यान आकर्षित इसलिए करना चाह रहा हूं कि मैं एक रिकार्ड बताऊं कि वर्ष 2023 में मेरे विधान सभा क्षेत्र के राजकीय अस्पताल जितने भी हैं, उनमें बन्दर के काटने के कारण 695 लोगों को एंटी रेबीज का टीका लगाया गया है। आप देखेंगे कि 2024 में एक जनवरी से 30 जून तक 516 लोगों को मेरे विधान सभा क्षेत्र में एंटी रेबीज का टीका लगाया गया है। आश्चर्यजनक रूप से इस समय, क्योंकि यह ऐसा मौसम है कि इनमें बहुत वृद्धि हुई है तो मेरा सदन से आग्रह है कि इस सम्बन्ध में राज्य के हित में कोई ठोस नीति बनायी जाए, कार्ययोजना बनायी जाए, जिससे आम जनता को बन्दरों के आतंक से मुक्ति मिल सके, राहत मिल सके। साथ ही कोई ऐसी नीति बनायी जाए, जिसमें बन्दरों के संरक्षण पर भी ध्यान दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: यह समस्या पूरे राजस्थान की है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इसका संज्ञान लेकर कोई उपाय करें। (व्यवधान)

श्री रामबिलास। आप बैठिए। श्री रामबिलास। कितने मंत्री बैठे हैं, जितने पहले बैठते थे, उनसे ज्यादा हैं। बैठिए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप डायरेक्शन दीजिए।

श्री अध्यक्ष: आपको दिखाई नहीं दे रहा है। 9 लोग बैठे हैं।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

जयपुर डेयरी में कार्यरत ठेकाकर्मियों को भर्ती में बोनस अंक

श्री रामबिलास (लालसोट): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के

(श्री रामबिलास)

नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से माननीय डेयरी मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर अनुरोध करता हूं कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी विभागों में कार्यरत ठेका कर्मियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए राज्य सरकार द्वारा ठेका प्रथा खतम करने के आदेश हमारे मुख्य मंत्री महोदय द्वारा जारी किये गये हैं। इन सबके बावजूद राज्य में दुग्ध उत्पादक संघों, दुग्ध प्रोडक्टों के प्रोसेसिंग व बनाने में जयपुर डेयरी संघ सहित राज्य के सभी दुग्ध संघों में ठेका कर्मियों द्वारा पिछले 30 वर्षों से कार्य पूरी ईमानदारी व पूर्ण निष्ठा से सम्पादित किया जा रहा है। इनके साथ जयपुर दुग्ध संघ की कार्य व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित किया जा रहा है। इन ठेका श्रमिकों को संविदा कर्मी कब माना जाएगा? इन ठेका श्रमिकों ने अपना पूरा जीवन जयपुर डेयरी की सेवा में समर्पित कर दिया है, जो 15-22 वर्षों से दुग्ध संघ की सेवा में लगे हुए हैं, उन्हें संविदा कर्मी आज दिनांक तक नहीं माना। यह तो जयपुर डेयरी में कार्यरत ठेका श्रमिकों के साथ अन्याय है। अतः जयपुर डेयरी में भर्ती नहीं होने तक इन कर्मियों को संविदा कर्मी माना जाए तथा नियमित भर्ती में इन्हें बोनस अंक दिए जाएं तथा आयु सीमा में छूट का प्रावधान किया जाए, क्योंकि इस संस्था में कार्य करते हुए ओवरएज हो गये हैं। माननीय, इन ठेका कर्मियों के साथ न्याय हो सके, इस हेतु मैं पुनः माननीय डेयरी मंत्री महोदय एवं सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय से सादर अनुरोध करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती गीता बरवड़।

नांदड़ा खुर्द (भोपालगढ़) में हत्या एवं रावनियाणा ग्राम (बिलाड़ा) में दलित नाबालिग के साथ दुष्कर्म प्रकरणों में कार्रवाई

श्रीमती गीता बरवड़ (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में ग्राम नांदड़ा खुर्द में हृदय विदारक घटाना के सन्दर्भ में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के ग्राम नांदड़ा खुर्द में स्वर्गीय मांगीलाल जाट की धर्मपत्नी व इनकी पुत्री की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर देने तथा दो बच्चों को भी पानी के टांका में डालकर हत्या कर देने की हृदय विदारक घटना है। इस घटना को संज्ञान में लेकर इसका गहनता से अनुसंधान कर दोषियों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्यवाही करावें। श्रीमान्, अभी सारा गांव मथुरा दास माथुर की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठा है। इनको न्याय दिया जावे। साथ ही,

(श्रीमती गीता बरवड़)
श्रीमान्, मेरे विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के पास ही बिलाड़ा विधान सभा के ग्राम रावनियाणा में 26.06.2024 की रात को एक दलित नाबालिग लड़की को अपराधी घर से उठा ले गये और उनके साथ सामूहिक बलात्कार कर उसे अलसुबह घर के बाहर सड़क पर घायल अवस्था में फेंकने की घटना निंदनीय है। श्रीमान्, लोक लाज के भय से पीड़िता ने कीटनाशक पी लिया, जिससे उसकी हालत और बिगड़ गई। पीड़िता गम्भीर अवस्था में मथुरादास माथुर चिकित्सालय में उपचाराधीन है। यह जघन्य अपराध है, अमानवीय कृत्य है। घटना के कारण क्षेत्र के कई लोगों एवं अनुसूचित जाति समाज में रोष है। श्रीमान्, दुष्कर्म के आरोप में नामजद है एवं उसके साथियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही करें। श्रीमान्, प्रदेश में दिनों दिन बढ़ते अपराध बहुत ही चिंता का विषय हैं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती कल्पना देवी।

लाडपुरा के नगर निगम कोटा उत्तर एवं दक्षिण क्षेत्रों के नालों की सफाई

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि लाडपुरा विधान सभा के शहरी क्षेत्र में नगर निगम कोटा उत्तर एवं दक्षिण में बरसात से पूर्व नालों की सफाई कराने हेतु नगर निगम को कई पत्रों एवं मौखिक रूप से अवगत कराया गया था, किन्तु मानसून पूर्व नाले साफ नहीं होने से एक ही बारिश में नाले उफन पड़े, बस्तियों एवं दुकानों में पानी भराव की समस्या सामने आई है। शहर में प्री-मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है लेकिन विभाग द्वारा नालों की सफाई का कार्य पूरा नहीं हों सका है। अधिकारी केवल काग़ज़ों में ही नाली व नालों की सफाई कर रहे है। नाले चौक होने की समस्याएं प्रतिदिन आ रही हैं। कालोनी में जल भराव की स्थिति होने से संक्रामक बीमारियां फैलने की भी सम्भावना है। यदि समय रहते नालों की सफाई नहीं की जाती है तो सड़कों एवं बस्तियों में पानी भरना तय है, जिससे क्षेत्रवासियों की जान-माल के नुकसान होने की भी सम्भावना रहेगी।

मेरा निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के नाले बोरखेड़ा से नयानोहरा, देवली अरब, बोरखेड़ा पेट्रोल पम्प से बक्शी स्कूल, बोरखण्डी, मानपुरा, सूरसागर, प्रेमनगर, गिरधरपुरा, रोटेदा मेन रोड से नयागांव कच्ची बस्ती तक, सोगरिया से चंद्रेसल, कोटड़ी, बजरंग नगर, अक्षरधाम कालोनी,

(श्रीमती कल्पना देवी)

छावनी रामचन्द्रपुरा तथा अटवाल नगर बोरखेड़ा, थेगड़ा, जय श्री विहार, सूरसागर आदि के नालों की सफाई अतिशीघ्र करवाने का श्रम करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जब्बर सिंह।

पानी की कमी के कारण किसानों का पलायन

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र आसीन्द हुरडा में पिछले 35 से 40 साल से अकाल पड़ रहा है। वर्षा की कमी के कारण यहां के किसानों, व्यापारियों की स्थिति बहुत खराब है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के आम मजदूर, आम किसान पलायन कर चुके हैं। गुजरात, महाराष्ट्र व अन्य प्रदेशों में जाकर मजदूरी करने को विवश है। यहां पर खारी बांध है, जिस पर खारी नदी है तथा मानसी व नेरवाड़ी नदी सहित तीन नदियां हैं जो पिछले कई वर्षों से सूखी पड़ी हैं।

मेरा मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि क्षेत्र की जनता की इस वाजिब मांग को मानते हुए इन तीनों नदियों को ईआर.सी.पी. में या अन्य किसी भी डैम से जो सरप्लस पानी होता है उसमें जोड़कर क्षेत्र की जनता को अकाल से निजात दिलाने की कृपा करावें।

खारी नदी राजसमन्द के दिवेर के पास से शुरू होती है, जो देवगढ़ के सोपरी डैम को भरते हुए खारी डैम से होते हुए गुलाबपुरा, विजयनगर सहित हजारों गांव, ढाणी, मजरों, खेड़ों को प्रभावित करती है।

अतः मुख्य मंत्री जी से क्षेत्र की जनता की ओर से नम्र निवेदन करता हूं कि आपने कुछ ही माह में जनहित के कई महत्वपूर्ण कार्य किये हैं तथा कई योजनाओं को धरातल पर उतारा है। आप एक संवेदनशील एवं विकास पुरुष मुख्य मंत्री हैं।

अतः आपसे नम्र निवेदन है कि आप इसी बजट में या आपकी अन्य किसी भी योजना में आसीन्द हुरडा विधान सभा की नदियों को जोड़कर आम जनता को राहत देकर आशीर्वाद प्रदान कराने का श्रम कराने की कृपा करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेश गुर्जर।

लड़ानिया (खानपुर) के टोल बूथ से स्थानीय निवासियों को कारित परेशानी

श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विधान सभा क्षेत्र खानपुर की जनता से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। झालावाड से बारां मेगा हाईवे की लम्बाई लगभग 78 किलोमीटर है, जिस पर विधान सभा क्षेत्र खानपुर के ग्राम लड़ानिया पर टोल बूथ लगा कर टोल संग्रहित किया जाता है। यह टोल बूथ नियमानुसार निर्धारित दूरी पर नहीं लगाया जाकर ऐसे स्थान पर लगा दिया गया, जहां से खानपुर की दूरी मात्र 8 किलोमीटर, झालावाड़ की दूरी 28 किलोमीटर है। ऐसे में खानपुर क्षेत्र के निवासियों को 28 किलोमीटर की यात्रा के लिए पूरे 78 किलोमीटर की यात्रा का टोल शुल्क देने को विवश होना पड़ता है। टोल संवेदकों द्वारा स्थानीय नागरिकों को जिनका व्यापार अथवा खेती किसानी के लिए रोजाना झालावाड़ जाना होता है उनके मासिक पास भी जारी नहीं किये जा रहे हैं। इतना ही नहीं, राहगीरों को बिना उनकी सहमति के रिटर्न जर्नी की पर्ची काट दी जाती है।

मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि इस विसंगति को अविलम्ब दूर करके खानपुर की जनता को पूरे 78 किलोमीटर लम्बे मेगा हाईवे के टोल शुल्क वसूले जाने से निजात दिलायी जाए। इसके लिए सम्बन्धित निर्माण एजेंसी के अधिकारियों को निर्देशित करके टोल बूथ को या तो सेन्टर पोइंट पर शिफ्ट किया जाए अथवा दो बूथ बना कर टोल शुल्क आधा-आधा किया जाए। साथ ही स्थानीय नागरिकों के मासिक पास नहीं बना कर जबरन अधिक शुल्क वसूलने वाले संवेदक के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए।

श्री अध्यक्ष: हरिसिंह रावत।

निजी संस्थाओं के माध्यम से वृक्षारोपण कार्य का नरेगा के अन्तर्गत वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलन

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत नरेगा के अंतर्गत पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण को वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित करवाए जाने के सम्बन्ध में निवेदन है कि आज भारतवर्ष ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व जलवायु नियंत्रण को लेकर

(श्री हरिसिंह रावत)

चिंतित है। वर्तमान परिदृश्य को मध्य नजर रखते हुए भी यह देखना पड़ रहा है कि आज हम जो जलवायु परिवर्तन देख रहे हैं, यदि अभी भी हम सजग नहीं रहे तो आने वाला समय हमारे लिए दुष्परिणाम लेकर आएगा। उक्त मुद्दे पर लोगों द्वारा सिर्फ बात ही की जा रही है, परन्तु जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। उक्त जलवायु परिवर्तन को कैसे सुरक्षित रखा जाए उसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने अपने पहले टर्म में ही ग्रामीण महिलाओं द्वारा जंगल एवं खेत खलिहानों से गृह कार्य हेतु लकड़ी नहीं काटी जाए, इस हेतु उज्जवला योजना के माध्यम से गैस चूल्हों का वितरण कर एक नेक कार्य करते हुए एक तीर से दो शिकार किये, जिस कारण पर्यावरण भी सुरक्षित रहा एवं महिलाओं को धुएं से निजात मिली एवं पेड़ पौधे नहीं कटने से पर्यावरण भी सुरक्षित हो रहा है।

माननीय, वर्तमान में नरेगा योजना अन्तर्गत ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में खड्डे खुदवा कर वृक्षारोपण करवाया जाता है तो उक्त जलवायु परिवर्तन से निजात मिल सकेगी। उक्त कार्य को करने के लिए वर्तमान में विभिन्न ऐसी कई संस्थाएं हैं, जिनमें भारत विकास परिषद् जैसी संस्था सम्पूर्ण राजस्थान में पौधारोपण के लिए अपनी सेवा दे रही है। उक्त एजेंसी द्वारा वर्तमान में वृक्षारोपण का कार्य सम्पूर्ण भारतवर्ष में किये जाने का कार्य किया जा रहा है।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं कि निजी संस्था/परिषद् के माध्यम से नरेगा के अंतर्गत पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वृक्षारोपण को वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित किया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हाकम अली खां।

फतेहपुर के रामगढ़ कस्बे से गुजरने वाले एन.एच. 52 पर अण्डरपास का निर्माण

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के विशेष उल्लेख प्रस्ताव नियम 295 के अन्तर्गत सूचना।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के रामगढ़ कस्बे के किसान लगभग पिछले 70-72 दिनों से एन.एच.

(श्री हाकम अली खां)

52 पर धरने पर बैठे हैं। उल्लेखनीय यह है कि किसानों के घर हाईवे से पूर्व दिशा की ओर हैं तथा इनकी कृषि भूमि पश्चिम दिशा की ओर है। उक्त किसानों को अपने-अपने खेतों में कृषि कार्य एवं मवेशियों के चारा एवं अन्य कार्य के लिए हाईवे को पार करना पड़ता है, जिसके कारण किसानों द्वारा हाईवे को पार करने के दौरान आये-दिन जान-माल एवं अन्य दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

अतः उक्त किसानों की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए मेरा सरकार से निवेदन है कि वहां पर एक अण्डरपास बनाया जाए, जिससे किसानों को कृषि एवं अन्य कार्य करने के लिए हाईवे को पार नहीं करना पड़े तथा ग्राम हौदसर के पास एवं फतेहपुर के राजकीय महाविद्यालय एवं राजकीय आवासीय महाविद्यालय के पास भी एक-एक यू-टर्न बनाया जाए, जिससे जान-माल एवं अन्य दुर्घटनाएं न हों। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: डा. ऋतु बनावत।

रूपवास (बयाना) में जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत हर-घर-जल योजना के कार्य की निर्धारित अवधि में पूर्णता

डा. ऋतु बनावत (बयाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचने हेतु प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव रखती हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना-रूपवास में हर घर जल पहुंचाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही हूं। केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना को अक्टूबर, 2024 तक पूर्ण करना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, रूपवास उप खण्ड के 72 गांव चम्बल परियोजना से जुड़े होने के कारण गर्मियों में 3-4 दिन में कुछ मिनटों के लिए ही पानी की सप्लाई होती है। इन गांवों में 8-10 चम्बल पाइन्ट से गांव की पूरी आबादी को पानी उपलब्ध कराया जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्षेत्र की जीवनदायिनी गम्भीरी नदी में पांचना बांध से पानी नहीं छोड़े जाने के कारण पूरे इलाके में भूजल का स्तर बहुत नीचा चला गया गया है। साथ ही इलाके में खारा पानी होने से वह पीने योग्य भी नहीं है। यही कारण है कि पूरी आबादी, जिसमें ग्राम पंचायत

(डा. ऋतु बनावत)

मिल्सवा, मेरथा, नयागांव इब्राहिमपुर चौकोरा, शक्करपुर, सिघावली, खान सूरजापुर, नौहरदा, सज्जावास, पुरा मौलोनी, जटमासी, बिनऊआ, जौतरौली औडेलगदड़ी, दौरदा, महलपुर काछी, दाहिना, निमेरा, मंडौली, महपुर-चूरा, पहाड़पुर के 72 गांव पानी के लिए चम्बल परियोजना पर ही निर्भर हैं। इन सभी गांवों में पीने योग्य पेयजल को शीघ्र से शीघ्र चम्बल परियोजना के माध्यम से जल जीवन मिशन योजना में हर घर जल योजना को निर्धारित अवधि अक्टूबर, 2024 तक कार्य की धीमी गति को बढ़ाकर शीघ्र पूर्ण कराएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राम सहाय वर्मा।

अवैध बजरी खनन के लिए जिम्मेदार ठेकेदारों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, टोंक जिले में बजरी खनन और पत्थर खनन का काम बहुत जोरशोर से है और उसके लिए 02 तारीख को टोंक के अन्दर जो सभापति हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इसमें जो लिखा हुआ है केवल वह ही पढ़ना है।

श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) (निवाई): जी।

प्रदेश में खनन माफियाओं का विस्तृत जाल फैला हुआ है। खनन माफियाओं का आतंक इस हद तक है कि टोंक में अवैध बजरी माफियाओं ने ट्रैक्टर से गश्त के दौरान कार्यरत हैड कांस्टेबल को कुचलकर मार दिया, जिसके दुःख से परिवारजन उबर नहीं पाये हैं। विभागीय अधिकारियों, सभापति एवं नगर परिषद् के अधिशासी अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध ठेका पर्ची सिस्टम बना रखा है, इन्हीं की सरपरस्ती से अवैध बजरी के ट्रक शहर के व्यस्ततम मार्ग पर बेरोकटोक गुजर जाते हैं। ट्रैक्टर में टेप लगाकर ऊंची आवाज में ये चलाते हैं, जिससे ये आवाज सुनते नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: इसमें यह नहीं है। यह वाक्य नहीं है जो आप बीच में बोल रहे हो।

श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) (निवाई): उनियारा में तो बजरी माफियाओं

(श्री राम सहाय वर्मा) (रेगर)

द्वारा वनकर्मी को भी बेहरमी से पीटा गया है। सरकार इन अवैध बजरी खनन के ठेकेदारों एवं कथित भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध जांच करने एवं कठोर कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान करे।

श्री अध्यक्ष: श्री संदीप शर्मा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हालत है। सरकार के विधायक उठा रहे हैं इन मामलों को।

श्री अध्यक्ष: मामले तो उठेंगे। बैठिए। आपको क्या हो गया? विराजिए। श्री संदीप शर्मा, आप पढ़िये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): सरकार पारदर्शिता से एवं निष्पक्षता से सबके भले के लिए कार्य कर रही है। आपकी तरह पक्षपात नहीं करती है हमारी सरकार।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप मान रहे हो न कि आपके राज में अवैध खनन बजरी माफिया सक्रिय है और कांस्टेबल को कुचल कर मारा जा रहा है? यह मान रहे हो न? आप मान रहे हो न? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। श्री संदीप शर्मा। आपको अनुमति नहीं दी है। आप विराजिए। आप 295 के बाद में बोलिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): व्यवधान कर रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउस को कण्ट्रोल में लाइये।

श्री अध्यक्ष: आप कण्ट्रोल में हो क्या? आप आज पांचवीं बार खड़े हुए हो। आप कौनसे कण्ट्रोल में हो? आप कण्ट्रोल में पहले रहो, मैं उनको भी करूंगा। आप बैठिए। माननीय मंत्री महोदय। श्री संदीप शर्मा, आप बोलिए।

कोटा में नमामि गंगे योजनान्तर्गत सीवरेज कार्य में हुई अनियमितताओं की जांच

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आभार। नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा नमामि गंगे योजना में कोटा शहर में सीवरेज पाइप लाइन डालने में हुई अनियमितता व लापरवाही के कारण लोगों को हुई परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा।

मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी

(श्री संदीप शर्मा)

नियम 295 के तहत राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा शहर में नगर विकास न्यास कोटा द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा गंदे पानी के निकास हेतु प्रदत्त नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत कोटा शहर में सीवरेज की पाइप लाइन का कार्य प्रारम्भ किया गया। इस योजना के अन्तर्गत 81 करोड़ रुपये की लागत से 68 किलोमीटर की सीवरेज पाइप लाइन डाली गयी, परन्तु पूर्ववर्ती सरकार द्वारा इस योजना के पैसे का दुरुपयोग किया गया तथा इस योजना में प्रयुक्त संवेदक द्वारा लापरवाही बरतते हुए सम्पूर्ण कोटा शहर के मुख्य मार्ग एवं गली मोहल्ले की सड़कों को खोद दिया गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए, मंत्रीजी खड़े-खड़े बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: खड़े-खड़े बात नहीं। यह सदन है।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): साहब, इन दोनों को बाहर निकालिए।

श्री अध्यक्ष: पहले आपको भी निकालना पड़ेगा। आप बैठिए। बिना अनुमति के खड़े हो। आप भी बिना अनुमति के खड़े हो, आप बैठिए। उनको बैठा दिया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इनको पार्टी से निकाल दिया, सदन से तो मत निकालो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बार-बार आपको क्या हो गया? सामने से नहीं। माननीय सदस्य, सामने से नहीं आते हैं।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): साहब, ये लोग बोलने में बार-बार व्यवधान कर रहे हैं। विषय इतना गम्भीर है, साहब, इनकी पुरानी सरकार का ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इसमें जो लिखा है वह ही पढ़ो।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): शहर में एक के बाद एक लोग दुर्घटना का शिकार बने और कई लोग अकारण मौत का शिकार हुए जिसके परिणाम स्वरूप कोटा शहर हादसों का शहर बन गया। संवेदक ने कहीं भी नियमों का पालन नहीं किया, कहीं सीवरेज के चैम्बर सड़क से ऊंचे उठा दिये तो कहीं गड्ढे में छोड़ दिये। कहीं पर सीवरेज के पाइप को आपस में जोड़े बिना ही ऊपर से सीसी कर दिया गया। अनेक स्थान तो ऐसे हैं जहां पर कम ढलान व

(श्री संदीप शर्मा)

अपर्याप्त आकार के पाइपों के कारण पानी का निस्तारण ही नहीं हो पा रहा। पहली बरसात में ही पानी घरों में भर गया और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संवेदक द्वारा कोटा में सीवरेज पाइप लाइनें डाली गयी हैं, वे निर्धारित मापदंडों की उपेक्षा कर कम गुणवत्ता की पाइप लाइनें बिछाई गई हैं। इस सम्बन्ध में अधिकारियों ने आंखें बंद की हुई थीं जो भी एक जांच का विषय है। केन्द्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजना करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है।

अतः मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि कोटा शहर में नगर विकास न्यास द्वारा डाली गई सीवरेज पाइप लाइन डालने में हुई अनियमितता और लापरवाही की जांच करवाकर संवेदक व संलिप्त अधिकारियों की जांच करवाना महती आवश्यक है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मनोज कुमार।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): नया कोटा बनाने के लिए धारीवालजी को धन्यवाद तो दे दो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हरिमोहनजी। माननीय सदस्य, आप विराजें। हर मामले में बिना अनुमति के खड़े होना ठीक नहीं है।

सादुलपुर में जल जीवन मिशन योजना की पाइपलाइन डालने से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के अंतर्गत निवेदन है कि मेरे सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र में गत वर्षों से जल जीवन मिशन योजना की पाइपलाइन बिछाने का कार्य लम्बे समय से जारी है। उक्त कार्य में कार्यकारी एजेंसी ने राजगढ़ नगरपालिका क्षेत्र तथा विधान सभा क्षेत्र के गांवों में सभी मुख्य सड़क मार्गों सहित छोटी-मोटी सभी सड़कों को तोड़ डाला है। उक्त एजेंसी द्वारा जहां पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूर्ण कर दिया जाता है वहां इन सड़कों की पुनः मरम्मत का कार्य राम-भरोसे छोड़ दिया जा रहा है। नगरपालिका क्षेत्र के सम्पूर्ण वार्डों सहित मुख्य बाजार के सारे सड़क मार्ग टूटी-फूटी अवस्था में पड़े हुए हैं। लोगों का वार्डों से मुख्य बाजार तथा आसपास के ग्रामीणों का तहसील मुख्यालय, विभिन्न कार्यालयों व अस्पतालों तक पहुंचना दूभर हो गया है। सड़कें गड्ढों में समा गयी हैं।

(श्री मनोज कुमार)

मानसून के इस मौसम में शहर में जगह-जगह पानी भरा पड़ा है। आवागमन की स्थिति अति दयनीय हो गई है। साधनों का संचालन दूभर हो गया है। टैक्सी चालकों का धंधा ठप हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों की भी यही दशा है। पंचायतों की अनुमति के बिना ही सड़कों को तोड़कर पाइपलाइन डाली जा रही है। तोड़ी गई इन सड़कों के पुनः निर्माण की कोई व्यवस्था न होने के कारण स्थिति गम्भीर होती जा रही है। जल जीवन मिशन की फर्म द्वारा इन तोड़ी गई सड़कों को उनकी जिम्मेदारी तय करते हुए इन सड़कों का निर्माण पाइपलाइन बिछाने के साथ-साथ ही करवाया जावे, अन्यथा यह फर्म पाइपलाइन का कार्य पूर्ण कर, सड़कों की मरम्मत का कार्य अधूरा छोड़ रवाना हो जाएगी। यह फर्म प्रशासनिक सिस्टम से सेटिंग कर सड़कों के निर्माण कार्य को अधर में छोड़ बजट उठाकर चली गई तो शहर व गांवों में यातायात सम्बन्धित नई व गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी।

अतः अध्यक्ष महोदय उक्त प्रकरण में विशेष उल्लेख की मार्फत मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान मेरे क्षेत्र में उत्पन्न उक्त गम्भीर समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि मामले की जांच करवाकर जल जीवन मिशन की फर्म द्वारा तोड़ी गई सभी सड़कों को तुरन्त प्रभाव से ठीक करवाया जाए तथा उक्त कार्य पूर्ण होने से पहले सड़कों को तोड़ने वाली फर्म को पूर्ण राशि का भुगतान न किया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री विद्याधर सिंह।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): धारीवाल जी बैठे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: बैठिए, बैठिए। विद्याधर सिंह जी।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): इनसे आप जवाब दिलाओ।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): चम्बल का पानी पी रहे हो।

श्री अध्यक्ष: मुझे आपकी तबीयत की चिंता है। माननीय धारीवाल साहब, आपकी तबीयत की मुझे चिंता है। बैठिए, बैठिए। आपको क्या हो जाता है? अभी पर्चियां भी हैं।

किशनगढ़-रेनवाल (फुलेरा) के गन्दे पानी की निकासी हेतु बजट आबंटन

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष

(श्री विद्याधर सिंह)
उल्लेख प्रस्ताव के अन्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के अन्तर्गत किशनगढ़-रेनवाल में पिछले 70 वर्षों से कस्बे के बीच में घनी आबादी वाले क्षेत्र कसाई मोहल्ले से सरकारी अस्पताल होते हुए डम्पिंग यार्ड तक कच्चा गन्दा नाला गुजर रहा है।

श्री अध्यक्ष: इसमें जो लिखा है, वही पढ़िये।

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): डम्पिंग यार्ड से आगे ग्राम पंचायत मुण्डली रणजीतपुरा की सीमा आने के कारण गन्दे पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, जिससे किशनगढ़-रेनवाल के पूरे कस्बे में बदबू के कारण वातावरण दूषित हो रहा है। उक्त नाले में कई प्रकार के छोटे जीव-जन्तु एवं संक्रमित मच्छर पनप रहे हैं। दूषित वातावरण की वजह से कस्बे के लोगों में अनेक संक्रमित बीमारियां हो रही हैं, जिससे कस्बे की जनता में भारी आक्रोश है।

मेरा यह सुझाव है कि गन्दे नाले के पानी की निकासी के लिए सूखी मेढ़ा नदी में मिला दिया जाए तो किशगनढ़-रेनवाल का ड्रैनेज सिस्टम सुदृढ़ हो सकता है, जिस पर मात्र चार करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। इसके साथ ही कस्बे में रेलवे फाटक के बाहर से कृषि मंडी तक पानी की निकासी के लिए कच्चे गन्दे नाले का निर्माण कराया जाना भी अति आवश्यक है, जिस पर मात्र एक करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। यदि स्वायत्त शासन विभाग द्वारा दोनों कार्य किशनगढ़-रेनवाल में करवा दिए जाएं तो ड्रैनेज सिस्टम में सुधार हो सकता है।

अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन विभाग मंत्री से मेरा निवेदन है कि इस उक्त परेशानी को ध्यान में रखते हुए कच्चा गन्दा नाला निर्माण के लिए पांच करोड़ रुपये बजट आबंटित कर इस कार्य को करवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: हो गया। श्री राजेन्द्र।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): बिना लिखा हुआ पढ़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: वह अंकित नहीं होगा। जो लिखा है वह पढ़ें।

उकरूंद (महवा) में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों द्वारा कनेक्शन जारी करने में अनियमितताएं

श्री राजेन्द्र (महवा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा

(श्री राजेन्द्र)

के प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र महवा में अधिकारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में निवेदन है कि महवा के उकरूंद (रामकुटी) स्थित पेट्रोल पम्प पर दिये गये विद्युत कनेक्शन में अधिकारियों ने दबाव में आकर पेट्रोल पम्प मालिक को लाखों रुपयों का आर्थिक लाभ पहुंचाया है, जिससे सरकार को राजस्व की हानि हुई है।

पुराना 33/11 के.वी. फीडर मण्डावर से महवा को खुर्द-बुर्द कर दिया गया है। पेट्रोल पम्प के कनेक्शन में लगभग 20 पोल का चार्ज लगना था, लेकिन अधिकारियों ने केवल चार पोल का चार्ज लेकर विभाग ने कनेक्शन जारी कर लाखों रुपये का विद्युत विभाग को राजस्व घाटा पहुंचाया है। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर विद्युत कनेक्शन को बंद कर नियमानुसार कनेक्शन दिया जाये।

श्री अध्यक्ष: श्री अमृतलाल मीणा ...(व्यवधान) नहीं हैं? अगला, तो खड़े हो जाएं न।

सलूम्बर की विद्युत लाइनों को व्यवस्थित रूप

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के अंतर्गत निम्न प्रकार निवेदन है:-

1. मेरे विधान सभा क्षेत्र के सलूम्बर के अधिशासी अभियंता कार्यालय के अन्तर्गत सलूम्बर अरबन, सलूम्बर रुरल, लसाड़िया, विरपुरा, सराड़ा, सेमारी आदि सहायक अभियंता कार्यालय आते हैं, जिनमें करीब 1,50,000 के करीब उपभोक्ता हैं। साथ ही अधिशासी अभियंता कार्यालय, सलूम्बर से 70 किमी. की दूरी होने से आम उपभोक्ता के कार्य बाधित होते हैं। अतः अधीक्षण अभियंता कार्यालय सलूम्बर में खोला जाए।

2. सलूम्बर नगर के अंदर जाने वाली विद्युत की 11 केवी. लाइन को अंडरग्राउन्ड कर आमजन को जन हानि से बचाया जाए।

3. पुरानी और डिस्मेंटल लाइन 33 के.वी., जो आबादी क्षेत्र में गुजर रही है. उसे हटाया जाए। सलूम्बर जी.एस.एस. से सेमारी जाने वाली 33 के.वी. लाइन के तार आमजन के घरों पर छूकर जा रहे हैं, जिसे हटाया जाए। उक्त लाइन लम्बे समय से बंद पड़ी है।

(श्री अमृतलाल मीणा)

4. डींगरी गांव के मध्य से गुजरने वाली 11 के.वी. व 33 के.वी. लाइन को बस्ती से दूर हटाया जाए। डगार फीडर जी.एस.एस. जाने वाली लाइन रामनगर, केकोडीया, जेमनपुरा, आमलिया, एमनिया पाडला, तलाई, बोड़का फला आदि 30 से 40 किमी. लम्बी घूमती हुई जा रही है, जिससे लाइन में बार-बार फॉल्ट आने पर सभी गांव प्रभावित होते हैं। अगर 6-7 पोल लगाएं तो लाम्बी डूंगरी, एमनीया पाउला, सुहावतो का गुढ़ा, बोडका, बांदनवाड़ा, दैबली आदि गांवों को बिजली की समस्या से निजात मिल सकती है।

5. जयसमन्द स्थित धार्मिक स्थल कला जी विकास सेवा संस्थान के ऊपर से गुजरने वाली 33 के.वी. व 11 के.वी. लाइन को हटाने हेतु कई बार अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता कार्यालय व प्रबन्ध निदेशक महोदय को लिखित रूप से देने के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः उक्त लाइन को हटाने के आदेश करावें, जिससे भविष्य में होने वाली दुर्घटना से बचा जा सकेगा।

6. खरका गांव से जाने वाले 11 के.वी. फीडर की लाइन को आबादी क्षेत्र से बाहर निकालकर अन्यत्र जगह शिफ्ट कराने की व्यवस्था करावें, जिससे आमजन को दुर्घटना से बचाया जा सके।

7. बस्सी व ईटाली खेड़ा में 11 के.वी. जी.एस.एस. बनवाने बाबत सलूम्बर विधान सभा के बस्सी गांव सलूम्बर सहायक अभियंता कार्यालय का सबसे अधिक उपभोक्ता का गांव है, जिससे अलग-अलग फीडर होने के कारण से व छितरी बस्ती होने से दो नये जी.एस.एस. (11 के.वी. लाइन) बनाने की व्यवस्था करावें। उक्त गांव में सलूम्बर जी.एस.एस. से सप्लाई मिलती है, जिससे लाइन लम्बी होने से पूरा गांव विद्युत बंद होने से प्रभावित रहता है। उदयपुर अधीक्षण अभियंता के अधीनस्थ 27 सहायक अभियंता कार्यालय हैं जो बहुत अधिक हैं, जबकि 16 सहायक अभियंता के अन्तर्गत एस.सी. कार्यालय सलूम्बर में खोला जाए, जिससे आमजन को लम्बी दूरी तय नहीं करनी पड़े।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री श्रवण कुमार।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि 15 दिन के बाद हमारा माइक तो खुला।

श्री अध्यक्ष: अब आप पढ़िये। इसको पढ़िए, आपका माइक चालू है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): धन्यवाद। चालू आज ही हुआ है।

श्री अध्यक्ष: जो लिखा है, वह पढ़िए माननीय। जो लिखा है, वही पढ़ो न।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं दूसरा नहीं पढ़ूंगा। मुझे मालूम है आप मास्टर रहे हो न।

श्री अध्यक्ष: अगर आपको पढ़ना नहीं है तो मैं आगे बढ़ूं?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): दूसरा नहीं पढ़ूंगा।

श्री अध्यक्ष: तो पढ़िए न।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप दूसरा पढ़ने नहीं देते हो।

श्री अध्यक्ष: आप पढ़िए।

प्रदेश में कुआं शिफ्ट योजना का पुनः प्रारम्भ

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के विशेष उल्लेख प्रस्ताव के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में पानी की भारी किल्लत है और गांवों में कुएं सूख गये हैं। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा कुछ कुएं भी मंजूर किये गये थे, किन्तु उक्त स्वीकृत कुएं आज दिनांक तक नहीं खोदे गये हैं। उल्लेखनीय यह है कि पूर्व में कुओं पर स्थगन भी किया गया था। कुएं टेंडर प्रक्रिया का पानी भी आज दिनांक तक धरातल पर नहीं आया है। टेंडर प्रक्रिया करवाने के बाद भी वर्तमान में सरकार का वादा था कि समस्त राजस्थान प्रदेश में कुआं शिफ्ट योजना को चालू करवाया जावेगा, किन्तु छह माह का दीर्घ समय व्यतीत हो जाने के उपरांत आज तक भी इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र की जनता प्यास से त्रस्त है। अगर पानी की किल्लत का समाधान नहीं हुआ तो जनता आन्दोलन कर सकती है। (व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: इसमें यह लिखा है कि मेरा इस सदन में, इसको पूरा पढ़ो। जो लिखा है, वह पूरा पढ़ो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं यह परीक्षा ही ले रहा था।

मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जनहित के उक्त कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करवाने का श्रम करें।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री कालीचरण सराफ।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब पर्ची आयेगी। 295 में पढ़ने के बाद कुछ और नहीं बोला जाता। आप बैठिए। श्री कालीचरण सराफ। (व्यवधान) आप बैठिए। 295 पूरा हो गया आपका। आप बिराजो। कालीचरण जी, आप शुरू करिये।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

बाईस गोदाम, सुदर्शनपुरा एवं करतारपुरा औद्योगिक क्षेत्रों का आबादी से अन्यत्र स्थानान्तरण

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से माननीय उद्योग मंत्रीजी का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले बाईस गोदाम, सुदर्शनपुरा, सुदर्शनपुरा विस्तार और करतारपुरा औद्योगिक क्षेत्र के बारे में आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, रीको ने 90 साल की लीज पर 1965 में इन चारों औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया था। करतारपुरा में 180 इकाइयां 28.85 एकड़ में लगायी थीं। सुदर्शनपुरा में 95 इकाइयां 17.60 एकड़ में लगी थीं और सुदर्शनपुरा विस्तार में 150 इकाइयां 14.71 एकड़ में लगी थीं। बाईस गोदाम में 184 इकाइयां 30 एकड़ में लगी थीं। इन औद्योगिक क्षेत्रों में हर औद्योगिक इकाई को 200 वर्गगज से 600 वर्गगज तक भूखण्ड आबंटित किये गये थे। 60 वर्षों से ये बड़ी सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। परन्तु जैसे-जैसे जयपुर शहर का विस्तार हुआ, आज स्थिति यह है कि सभी औद्योगिक क्षेत्र सघन आबादी क्षेत्र में आ गये हैं। इन औद्योगिक क्षेत्रों के चारों ओर सैंकड़ों कालोनियां बस गयी हैं। हजारों नागरिक यहां पर निवास कर रहे हैं। सघन आबादी क्षेत्र में आने के कारण भारी वाहनों का आवागमन पूरे दिन प्रतिबंधित रहता है और रात्रि को 11.00 बजे से सुबह 5.00 बजे तक केवल यह खुलता है, जिसके कारण कच्चे माल को लाने का और जो माल तैयार हो जाता है, उसको बाहर भेजने में बड़ी कठिनाई होती है। आज कुशल और अकुशल श्रमिक ज्यादातर बाहर से आते हैं। इन औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्ड छोटे होने के कारण उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए कर्मचारी स्थायी नहीं रहते और वे चले जाते हैं। इसके कारण वहां पर स्किल्ड लेबर नहीं मिल पाती। आज बढ़ते हुए औद्योगिक परिवेश में इकोनोमिक वायबिलिटी के लिए लार्ज स्केल पर उत्पादन समय की मांग है, पर छोटे भूखण्ड होने के कारण उत्पादन क्षमता का विस्तार करना सम्भव नहीं है। रीको की लापरवाही से...(व्यवधान) (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: विराजें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): दो मिनट, साहब।

श्री अध्यक्ष: दो मिनट की जगह चार मिनट हो चुके हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): रीको की लापरवाही से यहां सड़कों की चौड़ाई भी कहीं पर 10 फीट और कहीं पर 12 फीट रह गयी है। पिछले कुछ साल पहले वहां पर आग लगी थी एक रसायन फैक्टरी में, तो वहां पर फायर ब्रिगेड को आने में तीन घंटे लगे और उसके कारण पांच मजदूर घायल हो गये और आस-पास की चार फैक्टरियां भी उससे क्षतिग्रस्त हुईं। मेरा कहना यह है कि तंग गलियों के कारण यहां आबादी के बीच में आ जाने के कारण स्थानीय निवासी.. (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) दो मिनट और, बात तो पूरी होने दो। एक मिनट और लूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से पीड़ित हैं। कई बार स्थानीय नागरिकों में और उद्यमियों में टकराव की स्थिति भी हो जाती है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि इन औद्योगिक इकाइयों को जो नई औद्योगिक इकाइयां जयपुर में विकसित हो रही हैं, उनमें स्थानांतरित किया जाए। मैं आपके माध्यम से यह भी मांग करना चाहूंगा कि इनको प्राथमिकता के आधार पर उन औद्योगिक इकाइयों में रियायती दर पर जमीन मिले और कम से कम बड़े भूखण्ड आबंटित हों और इनको कन्सेशन रेट पर मिलें, और इस एरिया को डिनोटिफाई करके इनको कामर्शियल में कन्वर्ट कर दिया जाए। इससे राजस्व की भी प्राप्ति होगी। मैं अनुरोध करना चाहूंगा ...(व्यवधान) (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: फिर पर्ची लगाने का लाभ क्या? उत्तर आ जाने दीजिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): बहुत-बहुत धन्यवाद।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कालीचरण जी ने जो बात सदन में उठायी है, मैं उनकी भावना समझ रहा हूं और इन्होंने यह बात पहली बार नहीं उठायी, यह पहले भी इस बात को उठा चुके हैं। बहुत-से शहर ऐसे हैं जहां पर पुराने औद्योगिक क्षेत्र शहर के बीच आ गये, शहर का विस्तार हो गया। मैं सदन को यह बतलाना चाहूंगा कि बाईस गोदाम, सुदर्शनपुरा और करतारपुरा के अन्दर उद्योग की जो इकाइयां हैं, वे ग्रीन वाइट और कुछ ओरेंज में आती हैं। मैं संक्षिप्त में कहता हूं। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। आसपास रिहायशी क्षेत्र हैं जो वर्कर्स हैं, वे हैं, जिनकी इकाइयां खुद की लगी हुई हैं रॉ-मैटेरियल लाने वाले सब लोग हैं।

(कर्नल राज्यवर्धन राठौड़)

इनके अन्दर एक बहुत बड़ी हमारे सामने चुनौती है। यह जमीन खुद लीज पर आती है रीको के पास में, हम इसके मालिक नहीं हैं क्योंकि हमारे पास लीज पर आती है, हमारे ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन है कि कितने का हम लैण्ड यूज चेंज कर सकते हैं। साथ में सुप्रीम कोर्ट का भी एक अराफात केस करके है जिसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ रीको के ऊपर लैण्ड यूज चेंज करने के ऊपर, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि हमें राजस्थान को आगे बढ़ाना है और उसके लिए जितनी ऐसी जगहें हैं, उनको पूरी तरह से हम एग्जामिन करेंगे सभी स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रखते हुए।

श्री अध्यक्ष: श्री डूंगरराम गेदर।

सूरतगढ़ में खातेदारी एवं चकबंदी

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद। सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्दर किसानों की खातेदारी को लेकर और चकबंदी को लेकर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। सूरतगढ़ के किसान 45 से 50 वर्षों से जमीन जोत रहे हैं, ट्यूबवैल बना रखे हैं, ढाणियां बना रखी हैं और सारी की सारी किश्तें जमा करवा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको खातेदारी नहीं दी जा रही है और साधारण तरीके से टी.सी. आबंटन भूमि में खातेदारी नहीं मिलने की वजह से भूमाफिया पनप रहे हैं जो गलत नाम और फर्जी तरीके से खातेदारी लाकर और विवाद पैदा करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, चकबंदी नहीं होने की वजह से किसानों में सीमा सम्बन्धी विवाद होते हैं और सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में एक ऐसी तहसील है जहां जमीनों के टायर लगते हैं जो गरीब लोग हैं, उनकी जमीनें हाईवे से दूर चली जाती हैं और जो भूमाफिया हैं उनकी जमीनें हाईवे पर आ जाती हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गरीब लोगों को सूरतगढ़ से 20 किलोमीटर दूर भी आज खातेदारी नहीं मिलती है, लेकिन भूमाफिया सूरतगढ़ के अन्दर जहां 30-35 सालों से आबादी बसी हुई है, वहां पर भी खातेदारी ले आते हैं। मेरी मांग है कि जमीनों की खातेदारी में सरलीकरण करके खातेदारी जारी की जावे। सूरतगढ़ तहसील की सारी जमीनों की चकबंदी की जावे, ताकि किसानों को अपना हक मिले व किसानों के आपसी झगड़े खतम हों। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: कोई बोलेंगे? एक मिनट है। 1.00 बजे अवकाश करना है। 2.00 बजे वापस मिलेंगे। अभी दो पर्चियां और हैं।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में टी.सी. भूमि व पुख्ता आबादी होने के सम्बन्ध में गैर खातेदारी के कुल 5,208 प्रकरणों में 4,151 प्रकरणों में खातेदारी दी जा चुकी है और शेष 1,057 प्रकरण हैं। गैर खातेदारी से खातेदारी के सम्बन्ध में पैरिफेरी क्षेत्र उपनिवेशन क्षेत्र व राजस्व क्षेत्र सम्बन्धी कतिपय ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह कन्टीन्यू करेंगे। दो पर्चियां और हैं। कार्यवाही 2.00 बजे तक स्थगित कर दें?

सदन की कार्यवाही 14.00 बजे तक भोजनावकाश के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.00 बजे 14.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

(समय: 14.00 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: श्री केसाराम चौधरी। (व्यवधान)

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा रह गया था।

श्री अध्यक्ष: आपका हो गया था। जब समय हो जाता है तो पूरा हो जाता है। अब अगली बार।

पर्ची।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

नाबालिग एवं बालिका-बच्चियों के मुकदमे एवं गुमशुदगी से समाज में व्याप्त असंतोष

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में पर्ची के माध्यम से एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहा हूं जो हर घर-परिवार की एक सच्चाई है। मां और बाप अपनी बेटी को लाड़ और प्यार, लालन-पालन करते हैं। उसकी पढ़ाई-लिखाई कराते हैं, अरमान सजाते हैं कि मेरी बेटी उच्च शिक्षा प्राप्त कर उच्च पद पर पदासीन होगी। उसके सुखी जीवन के लिए माता-पिता उसको सुखद, सम्पन्न दाम्पत्य जीवन में बांधने के

(श्री केसाराम चौधरी)

लिए सब कुछ, अपने जीवन की कमाई पुत्री के लिए दांव पर लगा देते हैं, लेकिन उस समय उनके अरमानों का सपना चूर-चूर हो जाता है, जब उनको पता चलता है कि मेरी पुत्री किसी के साथ भाग गई है। परिवार को इस बात का पता चलता है तो पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। थाने में नाबालिग बच्ची होती है तो मुकदमा दर्ज होता है और बालिग होती है तो गुमशुदगी दर्ज होती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में केवल दो साल की बात करूं तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे चार थानों में, खिंवाड़ा में 17 मुकदमे दर्ज हुए और गुमशुदगी के 53, सिरियारी में 41 और गुमशुदगी के 158, रानी में 27 मुकदमे और गुमशुदगी के 44, मारवाड़ जंक्शन में 37 और गुमशुदगी के 77 मुकदमे, करीब 122 मुकदमे नाबालिगों के हुए और 372 मुकदमे बालिग लड़कियों के दर्ज हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो साल में अगर इतने मुकदमे दर्ज होते हैं तो पूरे प्रदेश में कितने मुकदमे दर्ज हुए होंगे और कितने मां-बापों ने अपनी जीवन लीला उन बच्चियों के लिए होम कर दी होगी? यह कल्पना इसी से लगाई जाती है कि पूरे प्रदेश में कितनी बच्चियां अपने पिता का, पुलिस में मुकदमे दर्ज होने के बाद में पुलिस उनको पकड़कर लाती है और जब बच्ची से न्यायालय में पूछा जाता है, मां-बाप अपनी बच्ची को कहते हैं, बेटी, मैं तेरा पिता हूं तो वह कहती है कि मैं आपको नहीं पहचानती, आप कौन हैं? उनके ये वचन सुनकर मां-बाप रोते-बिलखते, उनके पैर पकड़ते हैं, मगर बच्ची टस से मस नहीं होती और वह यही कहती है कि मैं आपको पहचानती भी नहीं, तो उस समय उस पिता के ऊपर जो गुजरती है वह हर व्यक्ति महसूस कर सकता है कि एक बाप अपनी बेटी को कितने अरमानों से बड़ी करता है और बड़ी होकर वह अपने पिता और परिवार को पहचानने से मना करती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी सूरत में मैं आप सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि इस विषय में अपन सब मिलकर, पक्ष और विपक्ष मिलकर कोई ऐसे कानून में संशोधन करें, ताकि ऐसे केसों में, पूरे देश-प्रदेश में यह बीमारी इतनी फैल गई है कि पुलिस भी परेशान रहती है। जब तक बच्चियां नाबालिग हैं, उनको नहीं पकड़ते हैं, कोर्ट और हाईकोर्ट भी माता-पिता को परेशानी में डालते हैं। ऐसी सूरत में अपन सभी मिलकर इस विषय पर चिंतन करके कोई न कोई कानून ऐसा लाएं कि मां-बाप की बिना स्वीकृति

(श्री केसाराम चौधरी)

के वह बच्ची अपनी मर्जी से किसी के साथ न भागे, ऐसी कोई न कोई व्यवस्था करने की मैं आपके माध्यम से इस बात के लिए मांग करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हम सब मिलकर पूरे प्रदेश में इतनी घटनाएं हो रही हैं, अब तो कोई सीमा ही नहीं रह गई है। इसलिए, बंधुओं, आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हम सभी मिलकर, प्रदेश की जनता के लिए, प्रत्येक मां-बाप के लिए इस कानून को संशोधित किया जाए। (व्यवधान) ऐसा ही कानून गुजरात के अन्दर बना है, उसकी तर्ज पर अपन सब कोई ऐसी व्यवस्था करें, ताकि बच्चियों को और परिवार को सम्बल मिले। यही निवेदन करते हुए, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विषय बहुत गम्भीर है और चिंताजनक भी है। इसमें समाज को, परिवार के लोगों को और हम सबको मिलकर इस प्रश्न का हल ढूंढना पड़ेगा। सरकार भी इस पर विचार करे और बाकी हम सब लोग भी क्या कर सकते हैं, इस पर अपन कंक्रीट किसी बात पर आएं, ताकि निर्णय हो।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिना कानून के, बिना संशोधन के सम्भव नहीं है, चाहे अपन सब हाथ खड़े कर दें। कानून मंत्री इस बात को बिलकुल स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: यह कानून के अलावा सामाजिक बुराई अधिक है।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): बिलकुल सही है।

श्री अध्यक्ष: इसमें समाज का और मां-बाप का ज्यादा रोल है कानून के साथ-साथ।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): मैं केसारामजी की बात का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: आगे, श्री छगनसिंह राजपुरोहित। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप कानून बनाकर लाएं...(व्यवधान) मैं आर.एस.एस. के लोगों से कहना चाहूंगा कि भारतीय संस्कृति पर ज्यादा जोर दो, हिन्दू-मुस्लिम पर ज्यादा जोर मत दो। (व्यवधान)

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): यह सबके लिए बात रखी है, हिन्दू-मुस्लिम के लिए नहीं है। बच्चियों के लिए बड़ी समस्या है, यह सबके लिए विषय है।

श्री अध्यक्ष: श्री छगनसिंह राजपुरोहित।

सियाणा का उप-तहसील में क्रमोन्नयन

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विषय छोटा-सा है। राजस्व मंत्री यहां विराजे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बागड़ा-सियाणा आर.आई. सर्कल में उप-तहसील की अति आवश्यकता है जो काफी लम्बे समय से मांग चल रही है। सियाणा, मेळा उपरला, चांदणा, काणदा, रायपुरिया, समणा, देवाड़ा, आरवाड़ा, भेटाला, आकोळी, देवदळी ऐसे गांव हैं जिनकी तहसील मुख्यालय से दूरी 30 से 35 किलोमीटर है। आज की स्थिति में हमेशा तहसील पर काम पड़ता है आमजन का, तो मैं राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि जो विषय उप-तहसील का है सियाणा में, वहां उप-तहसील बनाएं, जिससे आम जन को सुविधा मिले और जिससे अपने लोगों को यह लगे कि वास्तव में अब प्रशासन अपने द्वार पर आ गया। कैसे आ गया कि यदि उप-तहसील अपने क्षेत्र में हो गई तो मुझे विश्वास है कि वहां की जनता को लाभ मिलेगा। सियाणा उप-तहसील बहुत आवश्यक है, और 30 से 35 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। मैं राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसको गम्भीरता से लें, जब माननीय उप मुख्य मंत्रीजी जवाब दें तो इसको भी सब्मिट कराएं और सियाणा को उप-तहसील बनाएं।

श्री अध्यक्ष: सदन मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

पहले प्रतिपक्ष के नेता कुछ बात कहना चाहेंगे।

सूचना

स्थानीय निकायों में बहुमत परिवर्तन के प्रकरणों के प्रति प्रशासनिक उदासीनता के प्रकरण

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, पिछले दिनों में कुछ घटनाएं हुई हैं। भरतपुर में जिला प्रमुख का पद खाली है, चुनाव नहीं कराये जा रहे हैं। अलवर में जिला प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पार्षदों ने दे दिया है, दस दिनों से तारीख नहीं दी जा रही है। सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि भादरा में दूसरा चण्डीगढ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। (व्यवधान) भादरा में चुनाव की तारीख डिसाइड हो गई और सुबह 10 बजकर 10 मिनट पर दोनों पक्ष के पार्षद, कांग्रेस के भी और बी.जे.पी. के भी, दोनों ही पक्षों के वहां पहुंच गये

(श्री टीकाराम जूली)

और पहुंचने के बाद तीन घंटे तक वे वहां पर इंतजार करते रहे और एक बजे ए.डी.एम. वहां पर आते हैं और वे कहते हैं कि चुनाव स्थगित कर दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा, कहना चाहूंगा, मेरा सवाल है इस सरकार से कि जब तारीख निर्धारित थी तो कलक्टर ने चुनाव के दिन अधिकारियों को छुट्टी कैसे दी? दूसरा, चुनाव अधिकारी के ऐसी क्या बीमारी हो गई, क्यों अचानक छुट्टी चले गये? तीसरा, निर्वाचन अधिकारी के 11 दिन बाद में भी यह पता नहीं चला कि उनके बीमारी क्या है? क्या सरकार उनका बोर्ड से परीक्षण करवाना चाहती है या नहीं करवाना चाहती है? जब वहां मौके पर कलक्टर पहुंच गये तो उन्होंने चुनाव जैसे गम्भीर विषय को क्यों नहीं कराया?

श्री अध्यक्ष: आप पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के रूप में आये हो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्षजी, हम आसन से एक व्यवस्था चाह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आपने पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के लिए कहा, इसके लिए अनुमति दी है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इस प्रकार से हम चण्डीगढ़ क्यों बनाना चाह रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की हत्या की जा रही है, अध्यक्षजी।

श्री अध्यक्ष: आपने इन्फोर्म कर दिया। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): कांग्रेस के राज में भी ऐसा ही होता था। (व्यवधान)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप व्यवस्था दीजिए, अध्यक्षजी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): 000

श्री अध्यक्ष: अधिसूचनाएं, श्री झाबर सिंह खर्रा। (व्यवधान) पाइंट आफ इन्फोर्मेशन पर इन्फोर्मेशन देनी होती है। इन्फोर्मेशन आपने दे दी। (व्यवधान) इस पर आप कभी आधे घण्टे की चर्चा बुलवाइए, करेंगे। (व्यवधान) आपको क्या हो गया? आप बैठिए। मैंने इनको अनुमति दी है।

(श्री अध्यक्ष)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं। श्री झाबर सिंह खर्रा।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

नगरीय विकास विभाग

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार नगरीय विकास विभाग की 17 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्याः प.10 (48) नविवि/3/2000, दिनांक 04.03.2024 जिसके द्वारा कुशलगढ़ मास्टर प्लान-2023 की समयावधि दिनांक 31.12.2023 को समाप्त हो चुकी है, को एतदद्वारा 01 वर्ष/दिनांक 31.12.2024 अथवा नया मास्टर प्लान प्रारूप के प्रकाशन होने तक जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाया गया है;

(2) अधिसूचना संख्याः प.11 (14) नविवि/3/2023, दिनांक 04.03.2024 जिसके द्वारा बीकानेर मास्टर प्लान-2023 की समयावधि दिनांक 31.12.2023 को समाप्त हो चुकी है, को एतदद्वारा 01 वर्ष/दिनांक 31.12.2024 अथवा नया मास्टर प्लान प्रारूप के प्रकाशन होने तक जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाया गया है;

(3) अधिसूचना संख्याः प.10 (15) नविवि/3/2003, दिनांक 04.03.2024 जिसके द्वारा पीलीबंगा मास्टर प्लान-2023 की समयावधि दिनांक 31.12.2023 को समाप्त हो चुकी है, को एतदद्वारा 01 वर्ष/दिनांक 31.12.2024 अथवा नया मास्टर प्लान प्रारूप के प्रकाशन होने तक जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाया गया है;

(4) अधिसूचना संख्याः प.11(5)नविवि/ऋषभदेव (उदयपुर)/2024, दिनांक 09.03.2024 जिसके द्वारा ऋषभदेव (जिला उदयपुर) के नगरीय क्षेत्र का सिविक सर्वेक्षण करने एवं क्षितिज वर्ष-2043 तक के लिए मास्टर प्लान बनाया गया है;

(5) अधिसूचना संख्याः प.11(8) नविवि/खाजूवाला/2024, दिनांक 12.06.2024 जिसके द्वारा खाजूवाला (जिला अनूपगढ़) के नगरीय क्षेत्र का

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

सिविक सर्वेक्षण करने एवं क्षितिज वर्ष-2043 तक के लिए मास्टर प्लान बनाया गया है;

(6) अधिसूचना संख्याः प.11(6) नविवि/फलौदी/2024, दिनांक 12.06.2024 जिसके द्वारा अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व) राजस्थान जयपुर को फलौदी (जिला फलौदी) के नगरीय क्षेत्र का सिविक सर्वेक्षण करने एवं क्षितिज वर्ष-2043 तक के लिए मास्टर प्लान तैयार करने हेतु नियुक्त किया गया है;

(7) अधिसूचना संख्या: प.10 (16) नविवि/3/1998, दिनांक 13.06.2024 जिसके द्वारा सूरतगढ़ मास्टर प्लान-2023 की समयावधि दिनांक 31.12.2023 को समाप्त हो रही है, को एतदद्वारा, दिनांक 31.12.2024 अथवा नया मास्टर प्लान प्रारूप का प्रकाशन होने तक जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाया गया है;

(8) अधिसूचना संख्याः प.11 (10) नविवि/टिब्बी (हनुमानगढ़)/ 2024, दिनांक 13.06.2024 जिसके द्वारा टिब्बी (जिला हनुमानगढ़) के नगरीय क्षेत्र का सिविक सर्वेक्षण करने एवं क्षैतिज वर्ष-2043 तक के लिए मास्टर प्लान तैयार करने हेतु वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर को नियुक्त किया गया है;

(9) अधिसूचना संख्याः एजेजेड/1120/एमपी/डेगाना/24, दिनांक 18.06.2024 जिसके द्वारा डेगाना (जिला नागौर) के नगरीय क्षेत्र मास्टर प्लान 2041 का प्रारूप तैयार कर जनता से आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु धारा 5 (1) की अधिसूचना जारी की गई है;

(10) अधिसूचना संख्याः प.10 (47) नविवि/3/1998 पार्ट, दिनांक 18.06.2024 जिसके द्वारा फलौदी मास्टर प्लान-2023 की समयावधि क्षितिज वर्ष-2023 को समाप्त हो रही है, को एतदद्वारा 01 वर्ष की अवधि अथवा नवीन मास्टर प्लान प्रारूप के प्रकाशन होने तक जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाया गया है;

(11) अधिसूचना संख्याः टीपीआर/एनसीआर/मास्टर प्लान, दिनांक 24.06.2024 जिसके द्वारा रूपवास (जिला भरतपुर) के नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान-2041 का प्रारूप तैयार कर आम जनता से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु धारा 5(1) की अधिसूचना जारी की गई है;

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

(12) अधिसूचना संख्याः प.11 (7) नविवि/2021, दिनांक 24.06.2024 जिसके द्वारा खाटूश्यामजी मास्टर प्लान-2041 की धारा 3(1) में संशोधन किया गया है;

(13) अधिसूचना संख्याः एजेजेड/1120/एमपी/देवली/24, दिनांक 25.06.2024 जिसके द्वारा देवली (जिला टोंक) के नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान-2045 का प्रारूप तैयार कर आम जनता से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु धारा 5(1) की अधिसूचना जारी की गई है;

(14) अधिसूचना संख्या: टीपीआर/1120 (एमजी)/खाटूश्यामजी/2018, दिनांक 27.06.2024 जिसके द्वारा खाटूश्यामजी (जिला सीकर) के नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान-2041 का प्रारूप तैयार कर आम जनता से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु धारा 5(1) की अधिसूचना जारी की गई है;

(15) अधिसूचना संख्याः प.11 (3) नविवि/इटावा/2015, दिनांक 28.06.2024 जिसके द्वारा इटावा शहर के नगरीय क्षेत्र का सिविक सर्वेक्षण करने एवं वर्ष-2041 तक के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा को नियुक्त किया गया है;

(16) अधिसूचना संख्याः प.19 (2) नविवि/2023 दिनांक 12.06.2024 जिसके द्वारा दी रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एण्ड डवलपमेंट) में सदस्य की नियुक्ति की गई है:

(17) अधिसूचना संख्याः प.19 (1) नविवि/2022 दिनांक 12.06.2024 जिसके द्वारा राजस्थान रियल एस्टेट अपीलान्ट ट्रिब्यूनल में सदस्य की नियुक्ति की गई है;

श्री अध्यक्ष: श्री ओटा राम देवासी।

प्रतिवेदन एवं लेखे

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राजस्थान का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (वर्ष 2022-23)

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा-12(3)(एफ) के अन्तर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राजस्थान का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन। श्री जोगेश्वर गर्ग।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्र.सं. 5)

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के पंचम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 11 जुलाई, 2024 को मध्याह्न पश्चात् 4:00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि बुधवार, दिनांक 24 जुलाई, 2024 से सोमवार, दिनांक 29 जुलाई, 2024 तक सदन में लिए जाने वाले कार्य का नियतन निम्न प्रकार किया जाए:-

बुधवार, दिनांक 24 जुलाई 2024 गुरुवार, दिनांक 25 जुलाई 2024 शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई 2024	परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2024-25 से सम्बन्धित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।

(परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2024-25 से सम्बन्धित अनुदान की शेष मांगें मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर दिनांक 26 जुलाई, 2024 को मतदान हेतु प्रस्तुत की जाएंगी।)

शनिवार, दिनांक 27 जुलाई 2024 रविवार, दिनांक 28 जुलाई 2024	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 29 जुलाई 2024	1. राजस्थान वित्त विधेयक, 2024 एवं 2. राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2024 -पर विचार एवं पारण।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के पंचम प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के पंचम प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2024-25 पर सामान्य वाद-विवाद।

श्री हरीश चौधरी।

आय-व्ययक

परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2024-25 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री हरीश चौधरी (बायतू): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया। सवाल यह खड़ा होता है कि यह बजट होता क्या है? यह सवाल इसलिए खड़ा होता है, क्योंकि तीन घंटों में जो उन्होंने वाचन किया, उसमें बजट को समय कितना दिया और दूसरी बातों को समय कितना दिया? यह बजट का अधिकार हमें संविधान के आर्टिकल 202 से मिलता है। उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में राज्य विधान मण्डल के सदन या सदनों के समक्ष उस वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का विवरण रखाएंगे, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है।

क्या यह इस सदन में हुआ? नहीं हुआ। बड़ा दुखदायी है, अगर यह हुआ है, कोई भी इसका अध्ययन कर ले, अध्ययन नहीं किया। कोई तो कह ले, 25 प्रतिशत यह हुआ है और 75 प्रतिशत समय इस प्रदेश का दूसरी बातों में व्यर्थ किया गया। बजट नीतियों की घोषणा करने का वक्त नहीं होता है। यह बातें करने का वक्त नहीं होता। राज्यपाल के अभिभाषण में आप आने वाले समय की अपनी रूप-रेखा रख सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस लोकतंत्र की हत्या देश में हो रही है, पर इस सदन में भी यह महसूस किया जाता है। यह सरकार है क्या? यह सरकार कैबिनेट है। जब मैं मंत्री था, तब यदि कोई प्रश्न करता था कि सरकार क्या, तो मैं स्वीकार करता था, "मैं सरकार" और मुझे इस सदन में दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे खुद के कैबिनेट के सदस्य भी यह महसूस नहीं कर रहे हैं। "भजन लाल सरकार", भजन लाल जी सरकार नहीं हैं, यह आपकी जिम्मेवारी है, कैबिनेट की जिम्मेवारी है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): आप कहते थे, "मैं सरकार हूं", इसीलिए हटा दिये गये।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): आप कैबिनेट मंत्री नहीं हैं, आपकी यह झुंझलाहट पड़ोसी के नाते मुझे भी महसूस हो रही है। कैबिनेट मंत्रियों में से एक मुख्य मंत्री होते हैं। यह बजट किसके लिए था? राजस्थान के लिए था, किसान के लिए था, गरीब के लिए था, किसके लिए था? तीन घंटे तक हम लोगों ने जब सुना तो यह महसूस हुआ.(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बोलें नहीं।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): नहीं, आप बोलें, आपकी इच्छा जितनी हो, उतना बोलिए। चिल्लाओ, बोलो, टोको, रोको।

श्री अध्यक्ष: आप अपना कन्टीन्यू कीजिए। आसन को सम्बोधित कीजिए।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): इस लोकतंत्र में हम लोगों को अधिकार दिया गया है। हम अपनी बात रखेंगे। आपके रोकने-टोकने से विचलित नहीं होंगे। यह महलों और किलों के लिए, पूर्व राजा-महाराजाओं के लिए और पूंजीपतियों के लिए बजट था। यह मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। बजट में जो तमाम घोषणाएं हुई हैं, आम लोगों के लिए क्या हुई हैं, किसान के लिए क्या हुई हैं, गांव के लिए क्या हुई हैं, पूरा देश और दुनिया जानती है। प्रदेश भी महसूस कर रहा है। आपकी मजबूरी है, इसमें आपको तो यही बोलना पड़ेगा।

इस बजट से प्रदेश नकारात्मकता से आगे नहीं बढ़ पायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हद तो तब हो गयी, जब शुरुआत ही नकारात्मकता से हुई। जो पहली शुरुआत हुई "विरासत में दी गयी गलत नीतियों और कमजोर वित्तीय स्थिति", एक तरफ तो अपनी विरासत का महिमामण्डन, अपनी विरासत के लिए हजारों करोड़ रुपये खर्च कराने की घोषणा इसी बजट में वित्त मंत्री कर रही हैं, दूसरी तरफ लोकतंत्र की संविधान के माध्यम से जो विरासत मिली है, उसके लिए इस तरह के नकारात्मक शब्द इस देश के लिए ही नहीं, प्रदेश के लिए बहुत बड़ी चिन्ताजनक चीज हैं। इसे महसूस करें।

इस संविधान के माध्यम से बड़ी मुश्किल से हम लोगों को यह हक और अधिकार मिला है सबको बराबरी का। अब कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। उन तमाम विरासतों को कुचल दिया गया, जिस दिन यह संविधान इस देश में हम लोगों को मिला। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। इस सोच को

(श्री हरीश चौधरी)

बदलना चाहिये। इस सोच की वापस पुनर्स्थापना करने की इजाजत यह लोकतंत्र नहीं देता, नहीं देता। और तो और, हमने पिछली सरकार में घटित युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने के लिए पेपर लीक जैसी बातें देखीं। क्या यह बजट के अन्दर करने की चीज थी? यह पेपर लीक के सन्दर्भ में जो बातें हुईं, यह अमृत काल की बात हुई, यह बजट सिर्फ एक वर्ष के लिए है। यह महसूस नहीं करें, यह चढ़ना-उतरना, किसी का पद पर रहना-नहीं रहना, आपको पूरे पांच वर्ष दिये गये हैं।

हम लोग भारतीय जनता पार्टी की मोदी की ट्रेनिंग लिए हुए नहीं हैं कि लोकतंत्र की हत्या करने की सोच रहे हैं। आप आराम से पूरे पांच वर्षों में अपना काम करें, हम टीकाराम जी जूली के नेतृत्व में अपनी विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): टीकाराम जी जूली ने क्या कहा है बजट के बारे में? उन्होंने तारीफ की है बजट की।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): आप नीचे बैठें, अगर आपको इजाजत देते हैं तो मैं नीचे बैठ जाऊंगा और आपको सुन लूंगा। अध्यक्ष महोदय आपको इजाजत दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: चेयर को सम्बोधित कीजिए।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): यह अमृत काल खण्ड। 350 मिलियन इकोनॉमी पांच वर्षों में। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपनी बात सदन में दर्ज कराना चाह रहा हूं, जिस दिन पांच वर्ष पूरे होंगे, 350 मिलियन के ये जो नारे, नरेन्द्र मोदी जी तो क्या कह रहे हैं, वह अलग बात है कि नरेन्द्र मोदी जी की खुद की गारंटियां, जो विधान सभा चुनावों के दरम्यान आप "मोदी की गारंटी", "मोदी की गारंटी", "मोदी की गारंटी" कर रहे थे, जैसे ही लोक सभा के नतीजे निकले, वह मोदी की गारंटी अब बिलकुल बंद हो गयी। मजबूरी भी हमें समझ में आ रही है कि और लोकप्रियता के कारण अब मोदी की जगह और किसी की गारंटी। इस सदन में हम लोगों ने देखा, जो भारतीय जनता पार्टी, भैरोंसिंह जी, जिन्होंने राजस्थान में स्थापना की, उनका नाम यहां नहीं ले रहे थे, क्योंकि उस कुर्सी के प्रति निष्ठा ज्यादा हो जाती है। लेना तो उस कुर्सी के माध्यम से ही होता है। ऐसे में अब मोदी जी की जगह और किसी की बात। सम्मान, शायद किसान परिवारों के आर्थिक सशक्तीकरण, किसानों का हक और अधिकार, इस बजट के अन्दर वह गला आप लोगों ने

(श्री हरीश चौधरी)

घोंटा है। आने वाले तीस मिनट, जो मुझे मिले हैं, उसमें बताऊंगा, प्रदेश को बताऊंगा। अध्यक्ष महोदय, मानव संसाधन विकास के अन्दर हमने हमारे खुद के प्रदेश के मानव संसाधन की क्या स्थिति कर दी है। हम लोग हमारे मानव संसाधन को आगे बढ़ा पा रहे हैं या नहीं बढ़ा पा रहे हैं? हम जिन कालेजों और विश्वविद्यालयों की बात कर रहे हैं, ये कालेज और विश्वविद्यालय शिक्षा, संस्कार की संस्थाएं हैं या नहीं हैं? अगर ईमानदारी से कोई यह प्रश्न अपने आप से करेगा तो उसको उत्तर मिलेगा नहीं, नहीं, नहीं। यह दोषारोपण नहीं है। मैं कल यह महसूस कर रहा था। यहां कई मंत्री यह कह रहे थे कि भा.ज.पा. की सरकार, आपके कांग्रेस की सरकार, ये लोकतंत्र को भूल रहे हैं। सरकार लगातार सतत चलने वाली सरकारें रहती हैं। जो भी गलत किया, सही किया, उसको सुधारने के लिए आप लोगों को राजस्थान की जनता ने अधिकृत किया है, सिवाय दोषारोपण से अपनी जिम्मेदारी से दूर नहीं रह सकते हो। कई गलतियां की होंगी, जब काम करेंगे तो गलतियां भी होंगी। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, एम.बी.एम. विश्वविद्यालय की गलती, मैंने उस वक्त के तत्कालीन मुख्य मंत्री जी को भी कहा कि आप यह गलत कर रहे हो और आज भी वह बात मैं दोहरा रहा हूं कि जो विश्वविद्यालय बनाने की गलती की, आज आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप उसको सुधारो, प्रदेश दोषारोपण से आगे नहीं बढ़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, इन कालेजों और विश्वविद्यालयों के हालात क्या हैं। आप खुद शिक्षक रहे हैं। आप हमारी प्रतिद्वंद्वी विचारधारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् में भी कार्य कर चुके हैं। उस वक्त के कालेज और विश्वविद्यालय और आज के कालेज और विश्वविद्यालय, ये कालेज और विश्वविद्यालय लाक्षागृह हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, लाक्षागृह हैं। उनमें चन्द छात्र बच जाते हैं, वरना उन प्रतिभाओं के लिए हम क्या कर रहे हैं? कालेज और विश्वविद्यालय सिर्फ डिग्री लेने के स्थान नहीं हैं, सिर्फ किताबें पढ़ने के लिए नहीं हैं, जो शैक्षणिक सिलेबस हम उनको दे रहे हैं, उनके लिए ये कालेज और विश्वविद्यालय नहीं हैं। राजस्थान में ईमानदारी से कितने कालेज और विश्वविद्यालय चल रहे हैं? 95 प्रतिशत कालेज और विश्वविद्यालयों में, जो उनका मूल कार्य है, वह नहीं हो रहा है। कितना रिसर्च का कार्य हो रहा है? आज बच्चे नहीं पढ़कर खुश हो रहे हैं। हद तो तब हो जाती है, जब ये प्राइवेट कालेजेज, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी पैसे ले

(श्री हरीश चौधरी)

रहे हैं। हम सबको पता है, हमारे सबके विधान सभा क्षेत्र के बच्चों का शोषण हो रहा है? हम लोग इस बात की चिन्ता करके, इस बात की व्यवस्था नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भविष्य के राजस्थान को सुधारने की जिम्मेदारी किसकी है? इस सदन की है। हमने परिवार को क्या दिखाया है? हर सरकार लगातार राजस्थान के नौजवानों के साथ क्या कृत्य कर रही है, उनको क्या दिखाया जा रहा है? क्या स्वप्न, क्या सब्जबाग दिखाये जा रहे हैं? हकीकत क्यों नहीं बता रहे हैं? यह किसकी जिम्मेदारी है?

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि एक सत्र आप इसी के लिए बुलाओ कि राजस्थान के नौजवान कैसे आगे बढ़ सकते हैं, शैक्षणिक व्यवस्था कैसे हो सकती है, कालेज और विश्वविद्यालय में कैसे हो सकती है। हम लोग बातें कर रहे हैं, ढिंढोरा पीट रहे हैं, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी पाने के लिए राजस्थान के तमाम परिवार अपने बच्चों को कहां धकेल रहे हैं? कालेज और विश्वविद्यालय हमने बंद कर लिए और उन कोचिंग संस्थाओं के लाक्षागृहों के अन्दर हम धकेल रहे हैं।

यह मैं नहीं, कल हमने गुलाब चन्द कटारिया जी का स्वागत करते हुए सभी ने तालियां बजाईं, पक्ष और विपक्ष ने तालियां बजाईं। पक्ष और विपक्ष ने तालियां क्यों बजाईं, क्योंकि उन्होंने विपक्ष के नेता रहते वक्त कई ऐसी बातें कीं और स्वीकार भी कीं। उन्होंने यह बात स्वीकार की, हम लोगों की सरकार हो या हम लोगों की तरफ अंगुली करके उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार हो, ये पेपर लीक होते क्यों हैं? ये पेपर लीक विद्यार्थी नहीं करते हैं, अभ्यर्थी नहीं करते हैं। पेपर लीक के पीछे गुलाब चन्द कटारिया जी ने जो बात की, उससे मैं भी सहमत हूं और आप सब भी सहमत हों। आपकी मजबूरी है, आप मौन रहेंगे कि उनके पीछे कौन हैं। उनके पीछे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। आप वह गुलाब चन्द कटारिया जी से पूछ लो, नहीं तो मेरे पास आकर आप कर लो। आप इतनी गम्भीर बात को हल्के में ओढ़ोगे तो इतिहास माफ नहीं करेगा। कौन-सा है, वह आप लोगों को भी पता है और मुझे भी पता है, पर अपन दोषारोपण करने की जगह, व्यवस्था कौन परिवर्तित करेगा, हम लोग करेंगे, यह जिम्मेदारी हमारी है। कई एक कोचिंग संस्थाओं को बंद करना या दो कोचिंग संस्थाओं को चलाने से, इस व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। मूल प्रश्न यह है कि शैक्षणिक व्यवस्था, जो उच्च शैक्षणिक व्यवस्था है, कालेज और विश्वविद्यालय में, उसमें हम परिवर्तन करके कैसे उसका मूल स्वरूप करें

(श्री हरीश चौधरी)

और परीक्षा के पैटर्न में हम क्या तब्दीली करें, लम्बी चर्चा की आवश्यकता है, सदन पूरा बैठा है, चर्चा करे कि हम लोग किस तरह से यह कर सकते हैं।

नीट में क्या हुआ, एन.ई.ई.टी. में क्या हुआ, परीक्षा में क्या हुआ? मैं सबको कह रहा हूं। रीट के अन्दर क्या हुआ? इसकी जिम्मेदारी उन दोषियों को जेल तक पहुंचाने की आप लोगों की है। मैं सदन के अन्दर स्वीकार करता हूं कि बहुत सक्षम अधिकारी को लगाया है जो वी.के. सिंह को लगाया है, पर उनके हाथ नहीं बांध देना, क्योंकि ऐसे सक्षम अधिकारियों के हाथ कोई नहीं बांधता, हम लोग सदन में बैठे हुए लोग ही उनके हाथ बांधते हैं।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): हमने तो उस टाइम कहा था कि आप सी.बी.आई. को दे दो। आप लोगों ने सी.बी.आई. में जाने से रोका और धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी सरकार को कि ऐसे अधिकारी को बैठाया, जो सलाखों के पीछे डाल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: यह लाइव जा रहा है। माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): अध्यक्ष महोदय, ये बहुत चिल्लाते थे, सी.बी.आई. में देने के लिए, अब सी.बी.आई. को दे दो, आपको कौन रोकता है? पुष्पेन्द्र सिंह जी, आपके पास तो अधिकार नहीं है। आप तो मेरे जैसे एक सामान्य विधायक हो, पर इस कैबिनेट के पास तो है। आप भी इनको गुजारिश कर लो, मैं भी गुजारिश कर लूं कि सी.बी.आई. को दे दें। काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, वह अपन सब लोगों को पता है, तो यह वी.के. सिंह जी के माध्यम से।

अध्यक्ष महोदय, हम हमारे नौजवानों को क्या दिखा रहे हैं? सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी; राजस्थान में कितनी सरकारी नौकरी है, सिर्फ 8 लाख। राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, 8 करोड़ 21 लाख, एक प्रतिशत सरकारी नौकरी है। एक प्रतिशत सरकारी नौकरी है, उसमें भी वैकेंसीज हैं, राजस्थान के बाहर के लोगों की भी यहां पर है। यह सच्चाई हम हमारे प्रदेश के नौजवानों, छात्रों को क्यों नहीं कहते हैं कि सरकारी नौकरी के अलावा बहुत कुछ है दुनिया के अन्दर, 99 प्रतिशत के लिए बहुत कुछ है।

आप योग्य बनो। आप कृषि के माध्यम से, पशुपालन के माध्यम से, स्वरोजगार के माध्यम से आगे बढ़ सकते हो। सिर्फ सरकारी नौकरी के माध्यम से, ये सपने अपन दिखा रहे हैं, वाहवाही लूटने के लिए, यह वाहवाही लूटने की हम लोगों ने भी बहुत कोशिश की, पर जब लूट रहे थे, तो पीछे जैसे

(श्री हरीश चौधरी)

जीवाराम जी या अन्य टेबलें थपथपा रहे थे, तो हम तमाम लोग टेबलें थपथपाते थे, पर राजस्थान बहुत जागरूक है। राजस्थान का नौजवान बहुत जागरूक है। उन्होंने हमको हमारी जगह दिखा दी। कल आपको हमारी जगह नहीं दिखा दें, इसके लिए भी मैं आपको आज ही सावचेत करता हूं। आप इनको इस तरह के सब्जबाग नहीं दिखाओ।

अध्यक्ष महोदय, और तो और, इन सरकारी नौकरियों के अन्दर सबसे ज्यादा अन्याय किसी के साथ होगा, किस वर्ग का होगा, लगातार सरकारें करती आ रही हैं, एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और अब वापस यह अन्याय आप लोग करोगे। आपकी मंशा हम लोग जानते हैं। छह महीने के अन्दर जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया कि ई.डब्ल्यू.एस. रिजर्वेशन ओ.बी.सी. के अन्दर नहीं डाल सकते हो, कोड आफ कंडक्ट के अन्दर ही आप लोगों ने राजस्थान के अन्दर आर.ए.एस. की परीक्षा का परिणाम निकाल दिया।

(समय: 14.29 बजे)

(श्री अर्जुन लाल जीनगर, सभापति, पदासीन)

इस बजट के अन्दर आपने जले पर और नमक छिड़का। पैरा 85 में आपने क्या लिखा, इसी क्रम में ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग के युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार, बालिकाओं के सम्बलन एवं परिवारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए 150 करोड़ रुपये। धन्यवाद, आपने ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग के लिए दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, पर उसके अगले पैरा 86 के अन्दर आपने 15 प्रतिशत के लिए तो 150 करोड़ और 85 प्रतिशत के लिए कितना? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकास निगम, अन्य पिछड़ा विकास निगम, अल्पसंख्यक विकास निगम के माध्यम से एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., सफाई कर्मचारी, अल्पसंख्यक समुदाय, दिव्यांगजन के जरूरतमंद परिवार को रियायती दर पर, वह भी क्या? ऋण, और कितना? 100 करोड़। 15 प्रतिशत के लिए तो डेढ़ सौ करोड़ और 85 प्रतिशत के लिए सौ करोड़। कहानी यहीं खतम नहीं होती है। उसी के आगे दूसरे में आपने क्या किया कि ई.डब्ल्यू.एस. के लिए और 25 प्रतिशत तक ऋण। यह आप लोगों की मंशा है।

सभापति महोदय, सबसे ज्यादा अगर कुप्रचार इस देश में हो रहा है तो आरक्षण के लिए हो रहा है। नौजवान बच्चों के बीच में गलत तथ्यों के

(श्री हरीश चौधरी)

आधार पर जहर भर दिया गया है कि आरक्षण से योग्यता को खतम कर दिया गया है। आरक्षण से आपके हक को खा गये। हकीकत उसके विपरीत है। कोई भी परीक्षा, आज देश में कोई भी परीक्षा ले लो आरक्षण के सन्दर्भ में आंकड़े देख लो तो आपको हकीकत पता चल जायेगी। देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा अगर कोई है तो वह है यू.पी.एस.सी. की। इसमें तो कोई दोराय नहीं है या इसमें भी दोराय है? इसमें भी बी.जे.पी.-कांग्रेस आ गई? उस परीक्षा के अन्दर भी पिछले पांच-छह सालों के आप आंकड़े निकाल कर देख लो।

सभापति महोदय, उन आंकड़ों में आपको साफ अन्याय झलकेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े यह कहानी अपने-आप बयान कर रही है। ई.डब्ल्यू.एस. की कट आफ परसेंटेज में रिटन में ओ.बी.सी. की कट आफ ज्यादा है, सिर्फ ओ.बी.सी. की ही नहीं, एस.सी./एस.टी. की भी। ये इन्टरव्यू में जो खेला हो रहा है वह किसलिए हो रहा है, वह भी देश को अगर बतायेंगे तो पता चलेगा कि इन्टरव्यू से पहले आपका वर्ग उस अभ्यर्थी के सामने अंकित नहीं होता और जैसे ही इन्टरव्यू होता है, इन्टरव्यू के अन्दर आपका वर्ग पता चल जाता है कि यह एस.सी. का है, यह एस.टी. का है, यह ओ.बी.सी. का है। इसलिए इन्टरव्यू में जान-बूझकर, यह मैं नहीं कह रहा हूं यह आंकड़े कह रहे हैं, इन्टरव्यू में जान-बूझकर नम्बर कम दिये जाते हैं, जिसके कारण यह स्थिति है। उसके बावजूद भी तमाम आंकड़े, इतना मेरे पास समय नहीं है, एक साल के आंकड़े आपको 2019 के ओ.बी.सी. के, ई.डब्ल्यू.एस. में क्या हैं, जो फाइनल लिस्ट है ई.डब्ल्यू.एस. में 909 कट आफ थी और ओ.बी.सी. के अन्दर 925 और इसके अन्दर भी इन्टरव्यू और रिटन की अगर आप देखोगे तो इन्टरव्यू में ओ.बी.सी. को कम से कम दस प्रतिशत नम्बर कम हैं, और एस.सी. के अन्दर 898, सिर्फ तीन-चार प्रतिशत और एस.सी. को इन्टरव्यू में कितना कम मिल रहा है, कम से कम 15 से 20 प्रतिशत और एस.टी. में कितना, 893, ये हालात हैं। इस तरह का अन्याय हम लोगों के साथ हो रहा है और सब मिलकर कर रहे हैं।

मेरा यह निवेदन है कि इस तरह का अन्याय इन नौकरियों के अन्दर किसी के साथ नहीं करें। इसका प्रयास हम लोग करें। समय कम है, वरना इस सन्दर्भ में और भी कई आंकड़े मैं इस सदन में रखना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि यह अन्याय करना बंद करो। हक और अधिकार सबको मिलना चाहिये। यह जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते हो, इसलिए नहीं कराना चाहते

(श्री हरीश चौधरी)

हो कि यह काछ हम सबको देखनी पड़ जायेगी। यह कुप्रचार किया जाता था और बड़े-बड़े सिर्फ सियासी फायदा लेने के लिए, मूल ओ.बी.सी., अति पिछड़ी ओ.बी.सी. वोट लेने के लिए ये बातें की जाती थीं। उनके साथ जो ओ.बी.सी. के साथ अन्याय हो रहा है, आज वे लोग जो वोटों के लिए नारे देते थे, जहर फैलाते थे, वे लोग आज यह नहीं बोलेंगे। मैं उसमें कांग्रेस और बी.जे.पी. की बात नहीं कर रहा हूं। उस स्कूल के अन्दर दोनों पार्टियों के छात्र हैं जो संविधान की मूल भावनाओं में विश्वास नहीं रखते हैं, वे तमाम लोग उसके अन्दर हैं।

सभापति महोदय, स्टेट बजट में सबसे पहली प्राथमिकता किसको मिलनी चाहिये? दुनिया में कायदा है सबसे पहली प्राथमिकता प्राकृतिक आपदा में मिलनी चाहिये। क्या हमारे बजट में सबसे पहली प्राथमिकता स्टेट बजट में प्राकृतिक आपदा में मिली? नहीं। मेरे खुद के विधान सभा क्षेत्र में कई लोग, लू बोल लो, गर्मी बोल लो, हीट वेव बोल लो, उससे उनकी मृत्यु हुई। चलो मेरे प्रति तो आप लोगों की क्या सोच है, वह मैं भी महसूस कर रहा हूं इस बजट में और मेरे अलावा कई आप लोग भी। कालीचरण जी सराफ के प्रति भी आपकी क्या सोच है, वह भी पूरी दुनिया देख रही है, पर एस.एम.एस. अस्पताल के आंकड़ों के प्रति तो आप कोई दुर्भावना नहीं रखो। आपकी खुद की सरकार के आंकड़े हैं। 29.05.2024 को कितनी डेड बॉडीज आयी हैं, 50 और 30.05.2024 को 51, 31.05.2024 को 54, ये हालात पूरे प्रदेश में थे। 52-53 डिग्री तक तापमान प्रदेश में था। उस लू के कारण हम लोगों के परिवारों के कितने लोग खतम हुए? अपन लोग तो एयर कंडीशन में बैठे हैं, अपन लोगों के पास तो सब व्यवस्था है। 'हां पक्ष' के पास भी अच्छी खासी व्यवस्था है, 'ना पक्ष' के पास भी व्यवस्था है। उनके पानी की व्यवस्था, छांव की व्यवस्था, गर्मी से निजात की व्यवस्था थी? नहीं थी, हजारों लोग इस प्रदेश में लू से खतम हुए हैं। हमारा दुर्भाग्य है इस राजस्थान का दुर्भाग्य है, कि सरकार ने उसको प्राकृतिक आपदा भी महसूस नहीं किया।

मेरा निवेदन है कि इसको प्राकृतिक आपदा महसूस करो, क्योंकि लम्पी में भी यही हुआ। मोदी-मोदी करते गये और मोदी जी ने लम्पी को प्राकृतिक आपदा नहीं मानी। कोविड के अन्दर भी क्या चीज हुई? वह भी देश ने महसूस किया है। आप कितना ही चिल्लाओ और चिल्लाओ और बोलो, पर जो हकीकत है, उसको आप दबा नहीं सकते हो। हकीकत तो हकीकत रहेगी 'सत्यमेव जयते'।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): कोरोना में फाइव स्टार होटल में आप लोग ही थे।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): हम तो फाइव स्टार होटल नहीं, सेवन स्टार होटलों में भी जाते हैं, क्योंकि हमारे परिवार ने खून-पसीने से हमको इस तरह से योग्य बनाया है। आप रोक सको तो रोक लो हमें सेवन स्टार होटलों से। (व्यवधान) आप छोड़ो। सेवन स्टार होटल में भी जाते थे और जायेंगे। आपके अन्दर अगर ताकत है तो रोक लो, क्योंकि उस होटल में जाने के लिए किसी की जरूरत है तो सिर्फ आर्थिक ताकत की जरूरत है। अगर जेब में पैसा होगा तो सेवन स्टार होटल में भी जायेंगे। आपके मिर्ची लगने की जरूरत नहीं है। यह वह समय नहीं है। देश आजाद हो चुका है। हमको संविधान की मार्फत यह योग्यता मिल गई है। एक वक्त था, जिस वक्त हमको दो वक्त की रोटी नहीं मिलती थी। तन पर कपड़ा नहीं मिलता था। छत नहीं मिलती थी, कृपलानी जी। आज योग्य हो चुके हैं, आप फाइव स्टार होटलों की बात छोड़ो, सेवन स्टार में और यहां ही नहीं, दुनिया के किसी भी होटल में जायेंगे तो आप रोक नहीं सकते हो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मैं मना नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री हरीश चौधरी (बायतू): आप मना करो तो भी रुकेंगे नहीं। ये महलों की बात करने वाले हैं, महलों की मानसिकता रखने वाले हैं। ये हमारी तकलीफ क्या जानेंगे? (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): हजारों-करोड़ रुपये आपने इन महलों के लिए दिये हैं। टूरिज्म के नाम से दिये हैं, विरासत के नाम से दिये हैं। किन-किन नामों से यह लूट की? गांवों को कुचल रहे हो। किसान को कुचल रहे हो। रिवाज से आवाज को दबाना चाहते हो यह आवाज नहीं दबेगी। कितनी भी ताकत लगा लो, यह आवाज नहीं दब सकती है। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो? हमारे विधान सभा क्षेत्र में आप विकास नहीं दे सकते हो। विकास पहले बहुत करवा दिया और हमारे पास ताकत होगी तो और विकास करवा देंगे, आप रोक लो। आपके पास रोकने का अधिकार सिर्फ पांच साल तक है, उससे ज्यादा आपके पास अधिकार नहीं है, राजस्थान की जनता के पास है। मैं यह कहने के लिए इसलिए कह रहा हूं...(व्यवधान) चिल्लाओ और चिल्लाओ, क्योंकि चिल्लाने के अलावा आपके पास सत्यता नहीं है, सच्चाई

(श्री हरीश चौधरी)

नहीं है, दर्द नहीं है। जवाब उनसे मिलेगा, तब आप बात कर लेना। सच्चाई आप लोगों के पास नहीं है।

मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, दो घोषणाएं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक घोषणा की कि बायतू में बस स्टैंड। सभापति महोदय, चर्चा तो कर लेते, ये अधिकारी ही कर लेते फाइनेंस वाले, अगर बड़े लोगों के पास समय नहीं है तो। बड़े लोगों के पास तो आप लोगों के लिए भी समय नहीं, पर वहां बायतू के अन्दर सरकारी जमीन एक इंच भी नहीं है तो वह बस स्टैंड कहां बनेगा? वह तो जन सहयोग से अगर कोई जमीन मुहैया करेंगे, पहले भी अस्पताल बने तो वह जन सहयोग से बने और जमीन की उपलब्धता है या नहीं है, नहीं है। दूसरी है कि ...(व्यवधान) मना कर लें, आप लोगों से पूछा नहीं है, मना करना होगा तो हम कर लेंगे। ताकत है, ताकत किसकी? लोगों की। ताकत किसकी? अपनी अपनायत की। आपके गुरूर के, आपके अहंकार के सामने झुकने वाले नहीं हैं। लोगों की ताकत है इसलिए आंख से आंख मिला कर पूरी ताकत से हम लोग यहां बात करने के लिए आये हैं। आप इस बात के लिए दबा नहीं सकते हैं।

सभापति महोदय, जो कुचले जा रहे हैं, ये गांव में रहने वाले हैं। ये अपनी इस पीड़ा को महसूस नहीं कर रहे हैं। ये धन के नीचे खड़े हैं। उनको लग रहा है उस धन में से कुछ न कुछ मिलेगा, पर जिस गांव में ये खुद रह रहे हैं उस गांव के साथ जो अन्याय हो रहा है, वह अन्याय किसी विचारधारा के माध्यम से नहीं, किसी धर्म के माध्यम से नहीं, किसी जाति के माध्यम से नहीं, क्या हो रहा है, इन्होंने पढ़ा नहीं, यह सिर्फ तालियां बजा रहे थे, आगे-पीछे ही घूम रहे थे, बधाइयां ही दे रहे थे। पंचायती राज संस्थाओं को, स्टेट फाइनेंस कमीशन को पिछली सरकार 5,000 करोड़ वार्षिक दे रही थी, उसको 1,000 करोड़ कम करके 4,000 करोड़ कर दिया। यह महलों को ताकत देने का गांव-ढाणियों में रहने वाले लोग भुगत रहे हैं। यह तकलीफ है, वह तकलीफ यहां जाहिर कर रहे हैं। आप उस तकलीफ को महसूस नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप किसी और लाइन में लगे हुए हो, इसलिए वह तकलीफ आपको अहसास नहीं हो रही है। सभापति महोदय, स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी ने बहुत चलाया।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): विश्व लीडर हैं।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): विश्व लीडर हैं या क्या हैं, वह आपको भी

(श्री हरीश चौधरी)

पता है। स्वच्छ भारत मिशन में 1,140 करोड़ रुपये पिछली सरकार देती थी, उसको 1,000 करोड़ कर दिया। गांव में स्वच्छता नहीं रहनी चाहिये, महलों में रहनी चाहिये, महानगरों में रहनी चाहिये। गांव तो हिन्दुस्तान से अलग हैं, आप लोग एक दूसरा हिन्दुस्तान बनाना चाह रहे हो। पिछली सरकार ने जिला परिषद् के माध्यम से गांवों के लिए 341 करोड़ रुपये दिये, उसको कम कर के 316.77 करोड़ कर दिया।

लोन, लोन, या तो इन मोदी जी का नाम लेना छोड़ दो। (व्यवधान) प्रदेश को लोन लेने के लिए...(व्यवधान) सभापति महोदय, भारत सरकार ने कोविड के समय कहा, भारत सरकार की नाकामी थी, कोविड में जब वित्तीय संकट था, भारत सरकार ने एक पैसे का भी सहयोग नहीं किया और सिर्फ यह कहा कि आप लोन उठाओ ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। हरीश जी, विराजो।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): आप हमारे नेता से पूछ लो, हमारा समय है।

श्री सभापति: दे दिये 30 मिनट।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): हमारे समय से ज्यादा समय नहीं लेंगे।

श्री सभापति: पूरे 30 मिनट हो गये। (व्यवधान)

श्री हरीश चौधरी (बायतू): सभापति महोदय, नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने राजस्थान को विवश किया लोन उठाने के लिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिए।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): कोविड के वक्त में मदद के लिए उन्होंने हाथ खड़े कर दिये और राजस्थान को लोन लेने के लिए विवश किया, यह सच्चाई है। आपको नहीं पता तो कुछ पढ़ लो, सिर्फ नारों से नहीं होगा।

सभापति महोदय, महलों के लिए, पूंजीपतियों के लिए यह खेला क्या हो रहा है? 156 पैरा में आप देखो, Captive Power प्रयोग करने वाले उपक्रमों को राहत देने के लिए उपक्रम हेतु उपयोग ली गई ऊर्जा से सम्बन्धित Auxiliary Power पर इलेक्ट्रिक ड्यूटी समाप्त करती हूं और जो बचा हुआ है 10 प्रतिशत में सैटल करना। कितने हजारों करोड़ का यह खेला हुआ, जवाब देते वक्त वित्त मंत्री इस प्रदेश को बतायेंगी। सभापति महोदय, इससे ज्यादा क्रूर मजाक 175 पैरा में की गई।

श्री सभापति: अब आप विराजिए।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): हमारा खुद का समय है। सभापति महोदय, तीन-तीन घंटे उनको दिये हैं तो जवाब भी सुनो। हमारे समय से ज्यादा नहीं ले रहे हैं। आप हमारे नेता से पूछ लो।

श्री सभापति: आपको 30 मिनट का समय दिया गया है, 35 मिनट हो गये हैं।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): रीको में आपने क्या किया? रीको में हमारे किसान की जमीन को हड़पा। हमारे किसान को नो प्रोफिट ...(व्यवधान) उद्योग के नाम पर हड़प कर, आज उन्हीं उद्योगपतियों को इजाजत दे रहे हैं कि वहां कामर्शियल तौर पर या रेजीडेंशियल तौर पर, उस किसान की जमीन को सरकार के माध्यम से रीको ने हड़पा है। क्या किसान का हक और अधिकार नहीं है? यह आपकी पालिसी है?

सभापति महोदय, अगर ये सुनें, गांव-ढाणी की सुनें तो अंत में मैं दो निवेदन करना चाहता हूं। 200 तक की आबादी का मूल काम तो प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना का था। उसमें पिछले पांच साल में केन्द्र सरकार विफल रही। राजस्थान सरकार ने ढाई सौ तक की आबादी के गांव जोड़े। मेरा सरकार से निवेदन है कि जो 200 तक की आबादी की सड़कें वंचित हैं, उन ढाणियों को भी हक और अधिकार है। मैं धन्यवाद भी देता हूं, सड़कों में राजस्थान में जो काम हुआ है, उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सड़कों में अच्छा काम हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि हर चीज में कमी है।

दूसरा, बिजली के डोमेस्टिक कनेक्शनों में जो योजना स्वीकृत है, उनके मैटेरियल सप्लाई करके उसको करें।

अंत में जो जे.जे.एम. के बारे में बोल रहे हैं, जे.जे.एम. में जिसको लटकाना हो, लटकाओ। सबको लटकाना है, लटकाओ। जो भी चोर हैं, सबको लटकाओ। जे.जे.एम. की जितनी भी इनक्वायरी करनी हो, करो। जे.जे.एम. की दो-तीन मूल बातों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप करो तो करो, नहीं करो तो मत करो। (व्यवधान) आप बैठ जाओ, आप में कोई स्प्रिंग लगी हुई है क्या? पहला, इस स्कीम में कोई टूंटियां लगी हुई हैं उसको देखो। दूसरा, सोर्स में जबरदस्त कमी है, इसमें बहुत बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। सोर्स की कमी को हम लोग कैसे दूर कर सकें? उदाहरण के तौर पर जोगाराम जी, आई.जी.एन.पी. की जोधपुर में जो स्कीम है, उसका थर्ड फेज स्वीकृत हो चुका है। वह थर्ड फेज जल्दी से जल्दी पहुंचाइए, उससे भी अपना

(श्री हरीश चौधरी)

नहीं होगा। भविष्य में आई.जी.एन.पी. के समानान्तर एक दूसरी नहर, क्योंकि जमीन तो एक्वायर की हुई है, अपने पास संसाधन हैं। इन्दिरा गांधी नहर के समानान्तर नहर नहीं लेकर आयेंगे तो यह अपनी पूरी की पूरी स्कीमें फेल हो जायेंगी। बाड़मेर में मोहनगढ़ से बाड़मेर की जो स्कीम आ रही है, उसमें भी क्लोजर के समय पानी को स्टोरेज के लिए डिग्गी स्वीकृत कर दी गई है, वह काम भी बहुत धीमा चल रहा है। बिजली की उपलब्धता नहीं होने के कारण 9 पम्पों में से केवल एक या दो चल रहे हैं। सोर्स नहीं होगा तो सिर्फ आप नारेबाजी कर सकोगे, दोषारोपण कर सकोगे, लेकिन ढाणियों में रहने वाले लोग भी उतना ही अधिकार रखते हैं, जितना आपने इन पूंजीपतियों व राजा-महाराजाओं या परिवार के लिए किया। (व्यवधान) राज राजस्थान के लोगों का रहा है। यह आपकी सामंती सोच है ...(व्यवधान) संविधान में अधिकार दिया है ...(व्यवधान) न राज आपका है और न राज हमारा था, राज राजस्थान की जनता का था। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए, विराजिए।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): ...(व्यवधान) जब तक संविधान रहेगा ...(व्यवधान) जय-जय संविधान, जय-जय संविधान, धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय कैलाश चन्द वर्मा। (व्यवधान) प्लीज विराजिए, प्लीज विराजिए।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): माननीय सभापति महोदय, आपने मेरे को बजट 2024-25 पर विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। लगभग 125 पेज का यह बजट, जिसमें 193 बिन्दु हैं। इन 193 बिन्दुओं में गांव, गरीब, किसान की आत्मा बसती है। मेरे यह समझ में नहीं आ रहा ...(व्यवधान) देखिए, बीच में बोलोगे तो कभी नहीं बोल पाओगे। तेज आवाज में बोल कर नहीं दबा सकते। यह क्या परम्परा है? हम अभी आपको सुन रहे थे न। फालतू की बात करने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय विपक्ष के नेता, प्लीज आप अपने सदस्यों को रोकिए। अच्छा नहीं लगता। (व्यवधान)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप मेरी बात सुनिए, यह बराबर का काम है, बराबर का पाला है, इधर से बोलते हैं, जब ये कैसे खड़े होते हैं? (व्यवधान) ये खुद डिस्टर्ब करते हैं। (व्यवधान) जब आपका मैम्बर बोले, वे

(श्री टीकाराम जूली)

जवाब दे दें, बीच में क्यों खड़े होते हो? ये चार-पांच लोग तो ऐसे हैं जिनके स्प्रिंग लग रही है।

श्री सभापति: आप विराजिए, विराजिए।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): मेरा पाइंट आफ आर्डर है, आप सुन लें।... (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): कोई पांइट आफ आर्डर नहीं होता, वे बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): जिसमें गांव, गरीब, किसान की आत्मा बसती है। (व्यवधान)

श्री सभापति: इनके भाषण के बाद बता देना। हरीश जी, विराजिए। (व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस बजट की जितनी प्रशंसा करूं, वह प्रशंसा कम है। आज राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत से उन गांव-ढाणियों के अन्दर आवाज जायेगी और उन गांव ढाणियों के अन्दर बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक महिला, प्रत्येक युवा, प्रत्येक बेरोजगार इस बात पर पूरी तरीके से टकटकी लगाये हुए देख रहा है कि राजस्थान की विधान सभा के अन्दर माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया और कांग्रेस हमेशा इसके ऊपर क्या लांछन लगाती रही कि यह बजट क्यों लेकर आ गये? इससे पहले तो केन्द्र सरकार का आना चाहिए था। ऐसा बजट तो सरकार का जब अन्तिम साल होता है, तब आता है। भई, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? (व्यवधान) आप सुनने का माद्दा रखें। इन 20 पेज के अन्दर आपका पूरा चिट्ठा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आसन को सम्बोधित करें।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): जबकि कांग्रेस हमेशा इस बात का आरोप लगाती रही कि ऐसा बजट तो अन्तिम कार्यकाल के अन्दर आता है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा सोच रखी कि जब-जब इनकी सरकारें रही, राजस्थान की जनता के साथ में धोखा करके लूट और असत्य की सरकार राजस्थान प्रदेश के अन्दर इन्होंने चलायी। बजट के अन्दर, हमारे स्वर्गीय भैरोंसिंह जी शेखावत, जो कि अन्त्योदय लेकर आये, उनका इस बजट के अन्दर विजन है। हमारी पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी का इस बजट के अन्दर विजन है और

(श्री कैलाश चन्द वर्मा)

माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार का इस बजट के अन्दर विजन है। (व्यवधान) हार के विपक्ष में।

श्री सभापति: यह सदन चल रहा है। यह सदन है। आप इसकी गरिमा नहीं समझ रहे हैं। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आपसे विनती है कि अपने सदस्यों को रोकें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति जी, मैं फिर कह रहा हूं। यह सदन ऐसे नहीं चलेगा। आप हाउस को कंट्रोल में लेकर आएं। इनको भी डायरेक्शन दें कि जो वक्ता हैं ...(व्यवधान) अब, आप देख लें।

श्री सभापति: ...(व्यवधान) हमीर सिंह जी, यह अच्छी बात नहीं है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने कल भी एक बात कही थी कि कोई भी सदस्य अपनी बात रखे तो गरिमा से रखे। दूसरा, किसी भी पक्ष को जवाब देना हो तो उसके बाद बोलने का नम्बर आता है। वह उसका जवाब दे दे।

श्री सभापति: आपस में कोई किसी पर बात नहीं करेगा, सीधा आसन को सम्बोधित करें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ये बैठे-बैठे टोकते हैं। मैंने कल भी बताया था। ये चार-पांच लोग हैं, जो पूरे सदन को डिस्टर्ब करते हैं, चार-पांच ही हैं।

श्री सभापति: आप अपने लोगों को भी समझाएं, मैं इधर बात करता हूं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय नेता प्रतिपक्ष, उधर भी देख लें। हमारा एक विधायक बोल रहा है और आपके विधायक बार-बार खड़े हो रहे हैं। यदि आप इस तरह से करेंगे तो फिर आपका एक भी आदमी नहीं बोल पायेगा, यह आप नोट कर लेना। फिर आप भी नहीं बोल पायेंगे। (व्यवधान)

श्री हरीश चौधरी (बायतू): ...(व्यवधान) यह अच्छी परम्परा नहीं है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप धमकी मत दो, हम धमकी से डरने वाले नहीं है। धमकी मत दो। यह सदन आपस में सहयोग से ही चलेगा। सहयोग आप भी करें और सहयोग हम भी करें। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ...(व्यवधान) आप इनको बाहर कर दें, सदन को हम चला लेंगे।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के लोगों को कहना चाहूंगा कि-

"हार के विपक्ष में बैठ गये तो क्या है,
बजट तो अच्छा है, मुस्कुराना तो होगा।"

हमारी सरकार का विजन और माननीय मुख्य मंत्री जी का विजन:-

"मंजिल से जरा कह दूं, पहुंचा नहीं हूं,
मुश्किलें जरूर हैं, मगर ठहरा नहीं हूं।"

आपकी सरकार का विजन, पिछले पांच साल के अन्दर जो लूट मचाई, बन्दरबांट की और लास्ट के अन्दर तो थाली भी ले जाओ, प्याली भी ले जाओ, साड़ी भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, वह भी ले जाओ, उसके लिए, किसी ने बहुत अच्छा लिखा है,

"हमको बहुत बड़ी जागीर मिली,
मगर उस जागीर को हम सब भूल गये।
घोंसला बनाने में तो हम मशगूल हो गये,
उड़ने को पंख भी थे, यह भी भूल गये।"

जो राजस्थान की जनता के साथ किया। विपक्ष हमेशा बार-बार इस बात का तंज कसता आया कि पर्ची की सरकार, पर्ची की सरकार। जब केन्द्र से एडवाइजरी जारी हुई, हमने कम से कम हमारे आलाकमान की बात को तो बड़ी मजबूती के साथ तो रखा। यह पर्ची की नहीं है, यह विजन की सरकार है, यह मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आने वाले समय के अन्दर इसका पूरा लेखा-जोखा, जो इस बजट के अन्दर 2047 का विजन देखकर पेश किया है, वह आपके सामने होगा। आपका बताऊं, पर्ची का हाल क्या है? जब दिल्ली से पर्ची आयी थी, आधे जैसलमेर, आधे मानेसर, आधे सिविल लाइन, आधे कौनसे बंगलों के अन्दर। (व्यवधान) सुनने का माद्दा रखो। आपके सामने एक-एक चीज खोलकर रखूंगा। आपकी सरकार के जितने मंत्री थे, मैं एक पुराना गीत कहना चाहूंगा। एक पुराना गीत कुछ नये रूप में गूंजता है, 'लेकर तरह-तरह के भ्रष्टाचार जादू नगरी से आया है, कोई जादूगर'।

प्रदेश में सत्ता भ्रष्टाचार पहली बार ऐसे मुकाम पर आया कि हर काम में, हर कर्म में आपके मंत्रीगण लिप्त हैं, हम सुनते, पढ़ते, मानते आये हैं, धरती हमारी माता है, धरती हमारा धन है, मैंने सुना सियासत में सिंहासन बचाने के लिए राजा ने कई मंत्री बनाये उनमें से:-

(श्री कैलाश चन्द वर्मा)

"खनिज मंत्री ने सिद्ध किया, धरती हमारी लूट का धन है,
एक मंत्री ने सिद्ध किया, मिड-डे-मील हमारी लूट का धन है,
एक मंत्री ने सिद्ध किया, पोषाहार हमारी लूट का धन है,
एक मंत्री ने सिद्ध किया, कौशल रोजगार हमारी लूट का धन है,
एक मंत्री ने सिद्ध किया कि शिक्षा नाथी का बाड़ा है।
एक मंत्री ने सिद्ध किया, नौकरी-परीक्षा हमारी लूट का धन है,
एक मंत्री ने सिद्ध किया, खेल-आयोजन हमारी लूट का धन है,
एक मंत्री ने सिद्ध किया, दवा-चिकित्सा हमारी लूट का धन है,
सब लूट की होड़ मची हुई थी, राजा बांसूरी बजा रहा था,
रोम जल रहा है, वह नीरो और कोई नहीं था, यही था।"

आपकी हकीकत बहुत बेहतर तरीके से राजस्थान प्रदेश की जनता समझ गयी है। आपकी सरकार बहुत आटोमेटिक हो गयी। उस ट्रांजेक्शन बेस्ड ट्रांसफर का फार्मूला अपनाया, जो सरकार नौकरी देने के लिए पैसों का खेल रचती थी, वह पोस्टिंग देने के लिए भला क्या ईमानदार हो सकती है। जो सरकार ठीक से पदस्थापन नहीं कर पायी, वह सुशासन क्या देगी? अब आगे-आगे देखते जाइये। आपके जादूगर की पर्ची निकली, उसके अन्दर सरकार के वर्तमान विधायकों का लोकतंत्र के अन्दर ...(व्यवधान) मैं उसी के ऊपर भी आऊंगा। मैं आपके ऊपर भी आऊंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इनके विधायकों के फोन और इनके मंत्रियों के फोन टेप कराने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी गयी थी? लोकेश शर्मा इन्हीं के ओ.एस.डी. थे, जिन्होंने टेपिंग करायी। फिर पेट में दर्द क्यों हो रहा है? माननीय सभापति महोदय, बार-बार माननीय प्रधान मंत्री जी का नाम लिया जाता है। आप लोग तो 99 के फेर में ही फंसे हुए हैं। राजस्थान और हिन्दुस्तान की जनता है कि ऐसे व्यक्ति को प्रधान मंत्री बना दें तो हिन्दुस्तान का हाल क्या होगा, मैं किसी सदस्य का नाम नहीं ले रहा हूं। आपके पेट में दर्द होगा, मिर्ची लगेगी, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। टीवी के अन्दर एक एड आया है, एक छोटा बच्चा अपने पिताजी से कहता है। वह ऐश्वर्या राय का एड था। वह बोलती है कि मेरी सुन्दरता का राज लक्स, छोटा बच्चा कहता है कि इनसे मेरी शादी करा दो तो पिताजी बोलते हैं कि शादी तो

(श्री कैलाश चन्द वर्मा)

करा देंगे, मगर तू कर क्या लेगा? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग तो 99 के फेर फंसे हुए हो। 99 से बाहर नहीं निकले।

(समय: 15.00 बजे)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): बजट पर तैयारी करके आएं और बजट पर बोलें। (व्यवधान) ये टेलीविजन पर लक्स का एड चलाकर बजट बताना चाह रहे हैं क्या? यही है इनका बजट। ये संस्कार हैं इनके ...(व्यवधान) ये सिर्फ यूट्यूब और फेसबुक पर इसको डालने के लिए, सस्ती लोकप्रियता उठाने के लिए इस तरह की भाषा का यूज कर रहे हैं। आप सदन के अन्दर आये हैं, बजट में राजस्थान का विजन क्या है, वह बताइए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ये इधर-उधर की बात बता रहे हैं, बजट की बात क्यों नहीं बता रहे हैं? (व्यवधान) सम्बोधित आप को करेंगे, इधर नहीं करेंगे। यह क्या तरीका है? आप बताइए, ये कांग्रेस की क्या दशा बता रहे हैं? ये बताइए बजट में क्या है?

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): इनके कार्यकाल में ...(व्यवधान) परस्पर कुर्सी को लेकर ...(व्यवधान) छिपा हुआ नहीं है। 2018-19 के अनुसार 31 मार्च, 2019 को राज्य का 3,11,374 करोड़ का ऋणभार था। (व्यवधान) प्रति व्यक्ति भार 40,300 रुपये था। बजट की अनुशंसा 2023-24 के अनुसार 31 मार्च, 2024 को ...(व्यवधान) ऋण अनुमानित था तथा प्रति व्यक्ति ऋणभार बढ़कर 70,800 रुपये होना अनुमानित है।

श्री सभापति: आप सब बैठिए। सभी विराजिए।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): यह तो वही बात हो गयी कि

"चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोय,

दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय"।

इसीलिए बिना वित्तीय प्रबन्धन जिस तरीके से आपने थोथी घोषणाएं कीं। मैं भारतीय जनता पार्टी की घोषणाओं की बात करना चाहूंगा, प्रदेश की भा.ज.पा. सरकार का यह बजट इस बात का प्रमाण है कि योजनाओं का, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम इनका शिलान्यास भी करेंगे और हमारी भारतीय जनता पार्टी की इतनी ताकत है कि इसका लोकार्पण भी हम ही करेंगे। जब ही तो आपके पाली, चौमूं और रानीवाड़ा और अभी बायतू वाले माननीय विधायक जी बता रहे थे कि बजट में सड़कें तो हमारे को भी मिली हैं। पहले बोल रहे थे कि कुछ नहीं मिला, पहले तो ये बोल रहे थे कि आप

(श्री कैलाश चन्द वर्मा)

आवाज को नहीं दबा सकते। दूसरी बार बोले कि हमारे को सड़कें तो मिली हैं। कुछ तो आपको मिला है, इसीलिए आपने इस बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा की है।

पूर्व मुख्य मंत्री कहते रहे कि आप मांगते-मांगते थक जाओगे, मैं देता-देता नहीं थकूंगा। यह अहंकार, जो अहंकार था इनका, अभी बोल रहे थे कि आप अहंकार में हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारा अहंकार नहीं था, अहंकार इनका था। बिना किसी एडवाइजरी के, बिना किसी रोडमैप के, लोग घरों के अन्दर सो रहे थे, सुबह जब अख़बार पढ़ा तो उन्होंने कहा कि, साहब, 39 से 50 जिले हो गये। अब किसी को तो यह पता नहीं कि मैं कौनसे जिले की ढाणी में हूं, किस कस्बे में हूं, मैं कहा रहता हूं, गली में हूं, मोहल्ले में हूं और अभी तक पता नहीं है। (व्यवधान) इसीलिए, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय विधायक, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि राजाखेड़ा से आने वाले माननीय विधायक कल बड़ा आंकड़ों की दुहाई दे रहे थे कि इतना प्रतिशत यह हो गया, इतना करोड़ यह हो गया। क्यों भाई, जब आपने जिलों की आनन-फानन के अन्दर बन्दरबांट की थी तब आपको नहीं दिख रहा था कि हजारों-करोड़ों रुपये का प्रावधान एक जिले के लिए होता है? जब कहां गये थे आप लोग? जो बातें आपके अन्दर आयीं, तब ये निकलकर क्यों नहीं आयीं?

माननीय सभापति महोदय, जब सरकार का अंतिम वर्ष था, ऐसा बजट लेकर आये जिस बजट का प्रावधान कहीं हुआ नहीं। आज भी मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर चलकर आप लोगों को दिखा दूं, 10 आपके ऐसे पत्थर लगे हुए हैं जहां पर कंकरीट तो दूर की बात, मिट्टी भी ठीक नहीं है और उनका लोकार्पण आप लोगों ने किया। शर्म आनी चाहिए। लास्ट के अन्दर 125 करोड़ तो विज्ञापनों के अन्दर उड़ा दिये। योजनाओं के जो होर्डिंग्स लगे थे, उन होर्डिंग्स का जिस दिन लगे, दूसरे दिन पता नहीं रहा, क्योंकि दूसरे वाले व्यक्ति, दूसरा पक्ष ये नहीं चाहता था कि सरकार की योजनाओं का यहां प्रचार-प्रसार हो। और तो और, भारी मात्रा के अन्दर जो पैम्फ्लेट कागज बने, आज मेरे साथ कोई भी जाना चाहे तो मैं बता दूं छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ के जितने भी ठेले हैं, उन पैम्फ्लेटों के अन्दर लोग कचोरी-समोसा खा रहे हैं। ये तो योजनाएं थीं सरकार की। आप लोगों को बताते हैं तो बोलते हैं कि आवाज दबा रहे हैं। आपको बताते हैं तो, साहब, हमको बोलने नहीं दे रहे। भाई, कौन रोक रहा है आपको? बोलिए, आपको कोई नहीं रोक रहा।

(श्री कैलाश चन्द वर्मा)

राजाखेड़ा से आने वाले विधायक को कहना चाहूंगा कि are you getting my point? इस बात को समझ लें, अच्छी तरीके से समझ लें कि विगत सरकार ने सिर्फ भा.ज.पा. सरकार की योजनाओं का नाम बदलने का काम किया। अन्नपूर्णा योजना, अन्नपूर्णा मां के नाम से था, उसको इंदिरा रसोई कर दिया। आज बगरू के अन्दर जाकर बताऊं इस इंदिरा रसोई की सच्चाई, एक गंदे नाले के अन्दर इंदिरा रसोई चल रही है। कहीं शराब के ठेकों के सामने चल रही हैं। भामाशाह योजना, जिसमें तीन लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त होता था, उसको चिरंजीवी योजना कर दिया। आपने क्या किया, रामलाल को श्यामलाल। इससे ज्यादा तो कुछ किया ही नहीं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठजन योजना थी, उसको मुख्यमंत्री वरिष्ठ योजना कर दी। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन, राजीव गांधी, भाई, नाम तो बदल दिया, कोई बात नहीं, सभापति महोदय, मगर इसको चलाते तो सही। और तो और, नाम बदलकर आप तो फाइव स्टार, सेवन स्टार होटलों के अन्दर बड़ी मौज से मस्ती कर रहे थे।

युवाओं के लिए रोजगार के नये अवसर प्रदान करने वाली ये सरकार, जो कहती थी कि मैं युवाओं के लिए प्रतिबद्ध हूं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, चांद-तारे तोड़ लाएंगे। हमारी सरकार ने एक वर्ष में एक लाख भर्तियां प्रस्तावित कीं। आगामी चार साल के अन्दर चार लाख भर्तियां। अभी बायतू से आने वाले माननीय विधायक बोल रहे थे कि हमारे को पक्ष-विपक्ष को मिलकर इस चीज की कोई न कोई योजना निकालनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विगत वर्षों के अन्दर स्पेशल इकोनोमिक जोन (सेज) जैसी योजनाएं राजस्थान के अन्दर लेकर आयी। उनमें सभी सरकारी थे क्या? प्राइवेट सेक्टर के भी लोग लगते हैं, स्किल डवलपमेंट से जुड़े लोग भी उनके अन्दर लगते हैं।

अभी जो सदन के अन्दर बता रहे थे, उस बात को कम बोला, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि युवाओं के साथ में जब अत्याचार हो रहा था, तब इसी सदन के माननीय सदस्य, जो आज आसाम के महामहिम हैं, उनकी आंखों के अन्दर आंसू आये थे, माननीय सभापति महोदय, कि युवाओं के सपने चकनाचूर हो रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, वे युवाओं के साथ लूट-खसोट कर रहे हैं। तब कहां गयी थी आपकी सरकार? थी न आपकी सरकार, बहुमत में थी, करते कार्यवाही। आज आपको छह महीने के अन्दर ही सब-कुछ दिख गया। ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसीलिए हमारी सरकार ने जिस

(श्री कैलाश चन्द वर्मा)

तरीके से लगाम करने का काम किया, आपकी कांग्रेसी नेता के करीबी प्रदीप पाराशर और उसके साथ में 100 लोगों को गिरफ्तार करके उन युवाओं के आंसू पोंछने का काम किया, जो आने वाले समय के अन्दर इस राजस्थान की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम करेंगे।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): नीट पर तो बोलिए।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): मैं नीट का भी जवाब दे दूंगा। आपकी हर बात का जवाब दूंगा। आप नीट का भी लेंगे तो उसका भी दे दूंगा।

जल जीवन मिशन, केन्द्र सरकार की योजना के तहत प्रदेश सरकार हर घर तक जल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध थी। मगर जल शक्ति मंत्री राजस्थान के होते हुए इन्होंने कभी एनओ.सी. देने का बहाना, कभी विधायकों को योजना को राजस्थान के अन्दर लागू नहीं होने देना, क्यों? केन्द्र की योजना थी। और तो और, यह योजना विगत सरकार के भ्रष्टाचार की जो भेंट चढ़ी है, राजस्थान की जनता इस बात से अनभिज्ञ नहीं है। राजस्थान की जनता इस बात को जानती है। जहां पर पाइप लाइन डाली, ऐसा नहीं है यहां की आवाज गांव, गरीब, किसान तक नहीं जायेगी, पाइप था वहां पानी नहीं है, पानी था वहां पाइप नहीं है। जिस तरीके से पानी की टंकियां बनीं, उनमें जितना भ्रष्टाचार हुआ, मैं तो माननीय हमारे मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि इनका काला चिट्ठा सदन की मेज पर आए, ताकि राजस्थान की जनता के सामने इनका चेहरा जा सके।

दूसरा, किसान कल्याण। ये बार-बार दुहाई दे रहे थे कि किसानों के लिए क्या किया? प्रधानमंत्री सम्मान निधि 6 हजार से बढ़ाकर 8 हजार रुपये माननीय भजन लाल जी की सरकार ने इसी सदन के अन्दर की, ...(व्यवधान) जिसकी आवाज गांव, गरीब, किसान तक गयी। हर घर, खेत तक निर्बाध बिजली आपूर्ति करने का भी काम किया।

श्री सभापति: आप विराजिए।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): आप एक बार सुन लीजिए। आप लोगों की बात का भी जवाब दे देंगे। बार-बार आप माननीय प्रधान मंत्री जी का नाम ले रहे थे। आपके शहज़ादे यहां पर आये थे। माननीय सभापति महोदय, एक तो बहुत बड़ा दृश्य हो जाता यहां। पिछली जब सरकार थी, उनको किसी कांग्रेसी नेता ने जाकर बोला कि, साहब, एक तक गिनती बोलनी है। उन्होंने कहा कि मैं एक तक गिनती, एक मूवी आयी थी, एन. चन्द्रा डायरेक्टर थे उस

(श्री कैलाश चन्द वर्मा)

समय, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, वह तेरह तक चली गयी थी, किसी ने रोक लिया, नहीं तो 13 तक डांस करते इनके शहजादे पप्पू। (व्यवधान) इसीलिए जिस तरीके से।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप नये हैं, आप विराजिए। ये सब देख लेंगे। आप रिलेवेंट बोलिए।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): जिस तरीके से ...(व्यवधान) राजस्थान की जनता के साथ में एक से दस तक गिनती बोलकर जो किसानों का कर्जा माफ करने का असत्य नाटक किया।

श्री सभापति: आप सुनिए।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): नाटक तो इन्होंने किया। हमने तो किसानों की आर्थिक स्थिति बढ़ाने का काम किया। महिला सुरक्षा एवं सम्मान, महिला सुरक्षा सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजन लाल जी की सरकार आज भी कटिबद्ध है। पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब भी कटिबद्ध थी। आने वाले समय में भी कटिबद्ध रहेगी। महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण, गैस सिलेंडर 450 रुपये में। आपकी सरकार में, महिला अत्याचार दुष्कर्म में राजस्थान क्यों एक नम्बर पर आ गया? क्यों नहीं बोलते? इन्हीं के एक मंत्री ने कहा था कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार तो होते रहेंगे। नारी शक्ति वन्दन किसने लागू किया? कांग्रेस ने कितने समय तक उसको अटकाये रखा। प्रदेश के अन्दर भ्रष्टाचार की जीरो टोलरेंस की नीति पर भारतीय जनता पार्टी काम करना चाह रही है। सभी विभागों की प्रभावी मॉनिटरिंग, पारदर्शिता, क्यों भ्रष्टाचार के अन्दर गांव, गरीब, किसान की नीति बनती है, योजना बनती है, उन सचिवालय के दफ्तरों में अलमारियों के अन्दर सोना और पैसे मिलते हैं, फिर सुशासन की बात करते हो।

वन एवं पर्यावरण विभाग के माध्यम से 5 जून, 2024 में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। प्रदेश में 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया, 'हरियालो राजस्थान' के तहत 5 वर्षों में 4 हजार करोड़ की राशि प्रत्येक ज़िले में 'मातृ वन', और आपने अवैध खनन से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, वन्य जीव अभयारण्यों की उपेक्षा की। बजरी खनन का नंगा नाच जो आपके राज में हुआ, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है।

प्रदेश की शिक्षा नीति। भा.ज.पा. सरकार के अन्दर नवीन नियुक्तियां

(श्री कैलाश चन्द वर्मा)

प्रदान कर शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने का काम किया। कक्षा 8, 10, 12 के लिए 33 हजार विद्यार्थियों को नि:शुल्क टेबलेट देने का काम किया। 20 संस्कृत महाविद्यालयों के भवनों की घोषणा की। आपने क्या किया, यह भी सुन लो। बिना स्टाफ, बिना सुविधा अंग्रेज़ी माध्यम के विद्यालय खोल दिये। जहां पर हिन्दी के चल रहे थे, आनन-फानन में ऐसी क्या जल्दी हो रही थी कि रातों-रात अंग्रेज़ी के विद्यालय खोल दिये? अब हिन्दी वाले को अंग्रेज़ी नहीं आती। (व्यवधान) प्रदेश के छात्र न तो अंग्रेज़ी पढ़ पाये, न ही हिन्दी पढ़ पाये। कोई संसाधन नहीं, कोई टीचर नहीं। और तो और इन्हीं की सरकार के अन्दर, जब इनके माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी ने पूछा कि ट्रांसफरों के अन्दर पैसा लगता है क्या? तो शिक्षकों ने हाथ खड़े करके बोला 'हां'। यह क्या था? फिर सुशासन की बात करते हो।

माननीय सभापति महोदय, इनकी बात का, लोकतंत्र की बात का मैं आपके माध्यम से जवाब भी दूंगा। मगर बाबा साहब अम्बेडकर आदर्श विकास योजना प्रारम्भ की जाएगी। माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार टी.एस.पी. और एस.सी., एस.टी. के सशक्तीकरण हेतु 1,500 करोड़ रुपये की बजट घोषणा, टी.एस.पी. क्षेत्र के लिए गोविन्द गुरु जनजाति क्षेत्रीय विकास योजना, बजट 75 करोड़। आपने क्या किया, विगत सरकार में दलितों के साथ अत्याचार हुआ, वह किसी से छिपा हुआ है क्या? थानागाजी किसी से छिपा हुआ है? बाड़मेर किसी से छिपा हुआ है? भीलवाड़ा किसी से छिपा हुआ है? आपने तो मातृ शक्ति को भट्टी तक नहीं छोड़ा और फिर सुशासन की बात करते हो। दलित बालक द्वारा मटके का पानी पीने से जो विवाद हुआ, वह पूरे राजस्थान से छिपा हुआ है क्या?

चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार। भा.ज.पा. सरकार में आमजन की सेहत की चिंता करते हुए 27,600 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान, सम्पूर्ण बजट का लगभग 9 परसेंट चिकित्सा सेवा में खर्च होगा। प्रत्येक विधान सभा में आयुष्मान मॉडल सी.एच.सी. की स्थापना, एस.एम.एस., आर.यू.एच.एस. में करीब 400 करोड़ रुपये के कार्य। आपने क्या किया, चिकित्सा व्यवस्था बेपटरी रही। कोरोना जैसी महामारी में, अभी आपके ही पूर्व मंत्री बोल रहे थे कि हम तो फाइव स्टार में जाएं, सेवन स्टार में जाएं, जाओ न, आपको कौन मना कर रहा है, आप जाइए। माननीय सभापति महोदय, मरीज अस्पतालों के बाहर दम तोड़ रहे थे और यह सरकार कुर्सी बचाने के लिए होटलों के अन्दर ऐशो-आराम

(श्री कैलाश चन्द वर्मा)

कर रही थी, और आज सुशासन की बात करते हैं। नवजात बालकों को चूहे एवं कुत्ते द्वारा काटने की ख़बरें, आये दिन मुख्य पृष्ठ के बिन्दु बने हुए थे, जब राजस्थान के ...(व्यवधान)

श्री सभापति: तीन मिनट बाकी हैं।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): जब राजस्थान के अन्दर जिस तरीके का बन्दरबांट हुआ।

कृषि बजट। सिंचाई एवं जल संचयन 50 हजार करोड़ का बजट और 550 करोड़ रुपये की राशि से 100 एनिकट्स का निर्माण व मरम्मत कार्य, 1,400 करोड़ रुपये इंदिरा गांधी नहर परियोजना योजना में कार्य। आपने क्या किया? आपके टाइम तो किसान यूरिया के लिए भी भटकता रहा, लाइनों के अन्दर लगा रहता था। उस किसान की सुध नहीं ले पाये। अभी बड़ा ज्ञान दे रहे थे, हम तो यहां 'हां पक्ष' में, 'ना पक्ष' में ए.सी. के अन्दर बैठे हैं। यहां पर लगभग 70 से 80 परसेंट लोग किसान परिवार से ही आते हैं।

इस विधान सभा में बार-बार बात उठती है, लोकतंत्र को खतरा है। इनके पूर्व मुख्य मंत्री भी बोलते रहे ...(व्यवधान) आप ईमानदारी से बता दो कितने ऐसे लोग हो, जिन्होंने संविधान को पढ़ा है? (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): कितने लोगों ने संविधान को पढ़ा है। माननीय सभापति महोदय, मैं इसमें पांच मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लूंगा। कांग्रेस ने संविधान बदलने का असत्य भ्रम जाल फैलाया। कांग्रेस ने फैलाया न? कांग्रेस ने फैलाया इस बात को। कांग्रेस ने अपने शासन के चार दशकों तक संविधान निर्माता बाबा साहेब को भारत रत्न से सम्मानित नहीं होने दिया, इससे बड़ी क्या शर्म की बात हो सकती है। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वह सम्मान भी 1990 में भा.ज.पा. सरकार ने बाबा साहेब को दिया। बाबा साहेब को लोक सभा चुनाव जीतने से रोका गया। देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ भा.ज.पा. सरकार नहीं कर रही, बल्कि कांग्रेस सरकार ने समय-समय पर किया और आपातकाल जैसी काली करतूत करके संविधान को कलंकित करने का काम किया।

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच, तीन तलाक जैसी कुप्रथा को हटा कर संविधान को संरक्षित करने का काम किया। जबकि कांग्रेस के एक पूर्व प्रधान मंत्री के नेतृत्व में शाहबानो जैसे मामलों के

(श्री कैलाश चन्द वर्मा)

माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक शक्तियों को, संविधान को चुनौतियां देने का काम किया। आप लोग बोल रहे थे, आप संविधान की दुहाई देते हो न? (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, एक माननीय सदस्य उठकर यह बता दें कि मैंने संविधान को पढ़ा है। पढ़ा है तो कितने बिन्दु हैं, बिन्दु में क्या है? क्या है, तो बाबा साहेब ने क्या किया है? अब इनकी एक पोल और खोल देता हूं। देश में पहली बार प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने 2015 से 26 नवम्बर को संविधान दिवस के रूप में शुरू करके संविधान के प्रति जागरूकता पैदा की। 70 साल से कहां गये थे संविधान को मानने वाले? 70 साल से आप कहां गये थे, संविधान को मान रहे थे न?

श्री सभापति: संक्षिप्त करिए।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): कांग्रेस की सरकार में संविधान के साथ क्या हुआ, चारों तरफ एक भ्रम जाल फैलाया गया। आप तो 99 के फेर में हो, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की, एन.डी.ए. की सरकार, 292 से ज्यादा सीटें लाकर हिन्दुस्तान के अन्दर तीसरी बार सरकार बनाई है। तीसरी बार सरकार बनाई है। आपके तो नहीं आये न। आप तो 99 पर ही अटक गये न, अब आपको क्या दिक्कत आ रही है? (व्यवधान) संविधान की सामाजिक समरसता के ताने-बाने को मजबूत करने के लिए संविधान के सपने को साकार करने के लिए पहली बार ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के रूप में मुस्लिम, दूसरी बार रामनाथ कोविंद के रूप में दलित और तीसरी बार द्रौपदी मुर्मू के रूप में पहली आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने यह अहसास कराया कि संविधान के रक्षक हम हैं।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं बजट पर...। जिस तरीके का बजट आया, उससे बगरू भी नहीं बचा। बगरू को भी बहुत कुछ मिला। बगरू के अन्दर उप तहसील को तहसील क्रमोन्नत, 20 किलोमीटर की सड़कें इससे जोड़ी गईं। और तो और, पानी जैसी फ्लैगशिप योजना बीसलपुर योजना थी, पिछले पांच साल तक कांग्रेस सरकार ने न तो डी.पी.आर. बनने दी, न जमीन अलाटमेंट होने दिया, न कोई बजट का प्रावधान था।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): मैं माननीय भजन लाल जी को

(श्री कैलाश चन्द वर्मा)

धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने समय रहते इस बजट प्रावधान में उस योजना को लिया।

अंत में चार लाइनों से मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा।

"अंधेरों पर पार पाकर रहेंगे एक दिन,
रोशनी आंगन में लाकर रहेंगे एक दिन,
धूप को तुम चाहे कितना ही छिपा लो तिजोरी में,
हम प्रदेश की जनता के सपनों का राजस्थान बनाकर रहेंगे एक दिन।"

श्री सभापति: श्री संदीप शर्मा।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): माननीय सभापति महोदय, आपने मेरे को बजट के ऊपर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई। राम-राम सा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, आपका आभार कि आपने मुझे बजट 2024-25 पर बोलने का अवसर दिया। यह परिवर्तित बजट 2024-25 एक संतुलित, महत्वाकांक्षी और प्रदेश के समग्र विकास के हितों वाला बजट है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, एक इधर से और एक इधर से बुलवाइए।

श्री सभापति: आपकी संख्या कम है और इधर से संख्या ज्यादा है। इनके बाद आपका नम्बर आ जायेगा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): प्रदेश के सभी क्षेत्रों, विभागों, वर्गों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला यह परिवर्तित बजट 2024-25 है। यह बजट राजस्थान के भविष्य की खुशहाली का बजट है। प्रदेश की मौजूदा 17 हजार अरब रुपये की अर्थव्यवस्था को 29,230 अरब रुपये तक इन पांच सालों में पहुंचाने का यह परिवर्तित बजट है। यह एक ऐतिहासिक लक्ष्य है, जिसे हम पहुंचाकर रहेंगे पांच वर्षों के अन्दर।

मुख्य मंत्रीजी की सार्थक मेहनत और एक महीने पहले से, माननीय सभापति महोदय, पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक माह पूर्व प्रदेश के प्रबुद्ध जन, उद्योगपति, व्यवसायी, महिला संगठन, युवा संगठन, संस्थाएं सभी को आमंत्रित किया, उनके सुझाव लिए और उनकी राय पर राजस्थान की, प्रदेश की जनता के इस बजट का निर्धारण किया, जो बजट आप लोगों ने सुना, जो आप सहन नहीं कर पा रहे हो।

(श्री संदीप शर्मा)

माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी के उस विकासवादी दृष्टिकोण को, जिसकी सोच के कारण आज राजस्थान छह महीने में एक व्यापक कायापलट की ओर आगे बढ़ने लगा है और आप जिस तरीके से बहुत आतुर हो, आप हमारे से छह महीने का हिसाब पूछते हो और जानना चाहते हो कि इन छह महीनों के अन्दर भजन लालजी की सरकार ने क्या किया। हम तो छह महीने का हिसाब भी दे देंगे, आगे आने वाले साढ़े चार वर्षों का जवाब भी अभी ही दे देंगे कि कैसा राजस्थान होगा। अभी जवाब दे देंगे, पूरा-पूरा दे देंगे, शत-प्रतिशत दे देंगे, लेकिन पिछले पांच साल के आपके काले कारनामों का जवाब भी हमारे सम्माननीय सदस्य पूछ रहे थे, उन काले कारनामों का जवाब कौन देगा? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय श्रवणजी, विराजिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): आपके प्रतिपक्ष के नेता तो चले गये। डोटासरा साहब आ नहीं रहे, तो उन काले कारनामों का जवाब कौन देगा? जनता जनार्दन यह पूछ रही है उस फेल कानून-व्यवस्था का, जो पांच साल तक इस राजस्थान की धरती पर लोगों ने देखी है। महिलाओं के ऊपर होने वाले वे मुकदमे, जो सम्पूर्ण देश में सबसे ज्यादा बलात्कार, उत्पीड़न शोषण के दर्ज हुए और आपके मंत्रियों ने उसके लिए आपके प्रदेश की क्या उपाधि दी, उस बात का हिसाब पहले हमें दे दीजिए। परीक्षाओं में उस नकल का, आपने पराकाष्ठा पार कर दी। 15-15 लाख रुपये में पेपर बिक रहे हैं। उनकी भागीदारी का जो आपने, उन पर नियुक्त किये थे लोग बाग, जिनको आपने वहां पर डेपुट किया था, बैठाया था तो आपकी क्या भागीदारी थी, इस बात का हिसाब भी दे दो। इस बात का हिसाब भी जनता-जनार्दन को चाहिए, यह राजस्थान की जनता मांग रही है। यह हिसाब आपको देने पड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे हिसाब जो आपसे चाहिए, आप दे नहीं पाते।

पिछली बार हम यहां पर बैठे थे, वहां बैठे थे आपकी जगह पर, यहां से गहलोत साहब पांच साल तक लगातार बजट की घोषणाएं करते थे, बड़ी-बड़ी घोषणाएं और बड़े-बड़े वादे। खूब लोकलुभावन, वाह-वाह, ऐसे-ऐसे जादूगरजी के जो वाक्य निकलते थे, यहां पर सम्बोधन करते थे, लेकिन एक भी धरातल पर फलित होने वाली घोषणा और वादे हमने नहीं देखे। लोग-बाग आपकी लोकलुभावन उन घोषणाओं का इंतजार करते रहते थे कि कब चंदा मामा आएंगे, दूध मलाई लाएंगे, पर न तो दूध मलाई आती थी और न चंदा

(श्री संदीप शर्मा)

मामा आते थे और निश्चित रूप से आपके गहलोत साहब द्वारा की गयी सारी घोषणाएं फाइलों में ही सिमट कर रह जाती थीं, फाइलों के अन्दर ही पैक रह जाती थीं। कोई धरातल पर, किसी भी घोषणा पर आप चर्चा कर लेना, कोई भी एक फलित हुई हो तो हमें बता देना। यहां पर उछल-उछल कर कभी आप वैल में आते हो, कभी हमसे पूछते हो, तो हमने तो छह महीने में बहुत कुछ करके दिखा दिया।

धन्यवाद दो उस प्रधान मंत्री के, जिसने इस राजस्थान की धरा पर एक ऐसे मुख्य मंत्री को बैठाया जो किसान पुत्र है, जिसके संकल्प में सेवा है, जिसके हृदय में सेवा है, जिसके मन में सेवा है, जो संवेदनाओं से भरा हुआ है, जो जनता के हित में मेहनत करना जानता है, खड़ा होकर लोगों की समस्याओं को सुनना जानता है। कभी देखा है ऐसा मुख्य मंत्री? आप धन्यवाद दो प्रधान मंत्रीजी को कि आपको ऐसा मुख्य मंत्री मिला है, जो वास्तव में प्रदेश के हित में सोचने वाला है। आपकी भी सुध ली होगी, आपके विधान सभा क्षेत्र में भी काम हुए होंगे, जबकि आपके समय में हमारे साथ तो पक्षपात किया जाता था। पक्षपात होता था, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं किया होगा, क्योंकि यह भजन लालजी की सरकार है। आपको भी कुछ न कुछ मिला होगा। हमारे यहां पर ऐसे पक्षपात नहीं चलते, क्योंकि प्रदेश में जो भी रहने वाला व्यक्ति है, वह हमारा प्रदेशवासी है। सबके विकास की, सबके स्वास्थ्य की, सबकी चिकित्सा की चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, बंधुओं।

माननीय सभापति महोदय, आपकी यह आतुरता देखते ही बनती है। उछल-उछल के पड़ते हैं जो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आपको यह बात बता रहे हैं। पांच साल का ऐसा गुंडा राज, माफिया राज, जहां पर देखो वहीं भू-माफिया, रेत माफिया और ये बता रहे थे कि आपके मंत्री तक उसमें इन्वॉल्व थे और आपके दूसरे जो नेता थे, वे खुले आम उन पर आरोप लगाया करते थे, लेकिन फिर भी खुलकर लूट मची हुई थी। जमकर लूट मची हुई थी। गुंडा राज बन गया था राजस्थान। पूरी तरीके से गुंडा राज बना दिया था। गैंगस्टर यहां पनपने लगे थे। तलवारें खुली लेकर हाथ में चाहे वे किसी की भी गर्दन काटते थे, पूरी राजस्थान की जनता दहशतजदा कर दी थी आपने। उत्तर प्रदेश से योगीजी भगाते थे, आप यहां उनकी आवभगत करते थे। यहां बैठाकर उनकी मेहमाननवाजी करते थे, अतिथि बनाते थे उनको। यू.पी. से गुंडे, उत्तर प्रदेश से गुंडे राजस्थान में आपके मेहमान बनकर आते थे। आपने इस

(श्री संदीप शर्मा)

राजस्थान को मादक द्रव्यों की राजधानी बना दिया था पांच साल में। जितने मादक द्रव्य के केस इस राजस्थान की धरती में युवाओं के ऊपर मादक पदार्थों का सेवन कराने का जो प्रयास, एक कुत्सित भावना के साथ किया गया। पाकिस्तान से लगातार खेप आती थी, तस्करी की खेप आती थी, मादक द्रव्यों की खेप आती थी, तो कोई रोकने वाला नहीं था, लेकिन आप सोचो कि इन छह महीनों के अन्दर एंटी गैंगस्टर फोर्स लगाकर उन गुंडों को नेस्तनाबूद करने वाली सरकार भजन लाल सरकार है। पूरी तरीके से आज गुंडागर्दी बंद हो गयी है राजस्थान में। जो गुंडे सीना तानकर चलते थे, तलवारें फहराते थे, गैंगस्टर गैंग चलाया करते थे, वे गैंग्स कहां गायब हो गयीं आज, यह आपको विचार करना होगा। यह छह महीने का हमारा काम है और यही, नहीं पुलिस की भी भर्ती कर रहे हैं। 5,500 पुलिस वालों की भर्ती कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्रवणजी। माननीय सदस्य।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): जयपुर कमिश्नरेट पर सिक्योरिटी पुलिस फोर्स का गठन कर रहे हैं।

यह दृढ़ इच्छा शक्ति है। श्रवण जी, वह माफिया राज भी खतम हो गया। आपके यहां भी कोई माफिया हो तो बता देना, उसको भी खतम कर देंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्रवण जी, विराजिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): आपके जितने भी गैंगस्टर हों, कोई भी नाम हो, आपको डरा रहा हो, धमका रहा हो, हमें बताना, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबको नेस्तनाबूद कर देंगे। आप निश्चिंत रहो। आपने तो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को ऐसा पार किया, अभी माननीय सदस्य बता रहे थे। अलमारियों में नोट मिल रहे हैं। गजब हो रहा है। खुलकर सोना मिल रहा है। नोट मिल रहे हैं। सब जगह जमकर भ्रष्टाचार, आने दो।

यहां तक कि पाकिस्तान के माफिया, तस्कर ही नहीं, पुलिसकर्मी भी सिंडिकेट बनाकर इन सारे मादक द्रव्यों की तस्करी में लिप्त थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको तथ्यों समेत हम दे देंगे। आपकी सरपरस्ती में वे शामिल होते थे।

इसके अलावा, आपकी जो संस्कृति थी वह रेवड़ी बांटने वाली संस्कृति थी। आपने राजस्थान का क्या हाल कर दिया? मुफ्त में मोबाइल ले जाओ। मोबाइल भी आप सभी को नहीं दे पाये। महिलाओं को भी उसमें से छांट-छांट

(श्री संदीप शर्मा)

करके कि ये इस विधायक की 500 महिला कार्यकर्ता हैं, इनको दे देना। इनको 300 दे देना। आपने काहे को फ्री की रेवड़ियों में पैसे इस तरह से बर्बाद किये? राजस्थान को सर्वाधिक घाटा देकर, सर्वाधिक कर्ज वाला प्रदेश बनाया तो आपने बनाया।

2018 में जब आपने सरकार बनाई थी तब राजकोषीय घाटा 25,342 करोड़ था। उसको पांच साल में आपने बढ़ाकर 58,212 करोड़ कर दिया, जबकि नियमानुसार तीन प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकता। फ्री की योजनाओं से आपने ऐसे कर्जे में इस राजस्थान को डुबो दिया कि 25 हजार करोड़ रुपये का सालाना ब्याज आज भी हमें भरना पड़ रहा है। राजस्थान की जनता को भरना पड़ रहा है। आपने फ्री की जो योजनाएं लगाईं, 2018 में प्रदेश पर 2 लाख 81 हजार करोड़ का कर्जा था, 5 साल में 5 लाख 37 हजार करोड़ का कर्जा आप लोगों ने कर दिया। यह सब आपकी नादानी भरी योजनाओं से हुआ। कुप्रबन्धन से हुआ। आपने कर्ज के इस दलदल में राजस्थान को डुबो दिया। आपने प्रदेश को दिवालिया कर दिया। नम्बर वन घाटे वाला, कर्ज वाला प्रदेश आप लेकर आये। वे हिसाब दे रहे थे। हिसाब यह है, फाइनेंस से पढ़कर आने के बाद वे बता रहे हैं, साफ-साफ मालूम है।

आपने कहा कि यह तो एक रुपया कम किया है पेट्रोल पर, डीजल पर, बस एक रुपया कम हुआ है। पेट्रोल, डीजल पर आप पांच साल तक बहाने बनाते रहे। एक भी पैसा कम किया क्या? अब वे कह रहे हैं कि राजस्थान से हरियाणा का ज्यादा है। मध्य प्रदेश का हमसे कम है। पहली बार हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने, इस छह महीने की सरकार ने पेट्रोल, डीजल, सी.एन.जी., पेट्रोल उत्पादों पर वैट कम करके राजस्थान की जनता को राहत प्रदान की। आप तो नहीं कर पाये न? आप सिर्फ बहानेबाजी करते रहे, टालमटोल करते रहे।

आपने ई.आर.सी.पी. के लिए हमेशा बहाने बनाये, हमेशा टालमटोल करते रहे। धन्यवाद दो कि माननीय मुख्य मंत्री जी के भगीरथी प्रयासों से ई.आर.सी.पी. की आज गंगा रूपी कैनाल का काम भी प्रारम्भ हो गया। एक तिहाई लोगों की प्यास राजस्थान की गंगा रूपी कैनाल बुझायेगी। आप क्यों नहीं कर पाये? आप सिर्फ बहाने बनाते रहे, क्योंकि करने की इच्छा शक्ति नहीं थी, कोई मन में संकल्प नहीं था। अब कैसे ये सारे काम हो रहे हैं? आप 5 साल तक लोगों को बरगलाते रहे। कोई काम आप नहीं कर पाये। कुछ करने

(श्री संदीप शर्मा)

की इच्छा शक्ति होती तो राजस्थान की जनता इस तरीके से आपको नकार कर बाहर नहीं फेंकती। निश्चित रूप से आपका भी सम्मान करती। थोड़े से और विधायक दे देती तो कम से कम और अच्छा विपक्ष होता। अभी तो खाली पड़ा है।

जल जीवन मिशन की ऐसी योजना थी जिसमें माननीय प्रधान मंत्री जी का सपना था कि राजस्थान एक प्यासा प्रदेश है, पानी की कमी है, वहां घर-घर नल से जल पहुंचाएं घर-घर लोगों को जल की उपलब्धता कराएं लेकिन उसमें भी आप कर नहीं पाये। इस योजना को 27 हजार करोड़ रुपये आबंटित किये थे। आपने सारे बर्बाद कर दिये। जितने भी आपने काम किये, जहां वाटर रिसोर्सेज नहीं थे, स्रोत नहीं थे, पानी की उपलब्धता नहीं थी, वहां पाइप लाइन डाल दी। कबाड़ से लाकर के ठेकेदार जी ने डाल दी। आपको भी मालूम है, आपकी आंखों के सामने काम चल रहा था। बहुत धुआंधार भ्रष्टाचार चल रहा था। जे.जे.एम. में गजब कर दिया आप लोगों ने। राजस्थान के लोगों के साथ ऐसी नाइंसाफी आप लोगों ने की है जबकि अब इसी योजना में 55,846 अतिरिक्त गांवों को जोड़कर शुद्ध पेयजल पहुंचाया जायेगा। इस योजना में 20 हजार करोड़ की छह बड़ी पेयजल परियोजनाओं के साथ 183 शहरी क्षेत्रों में भी पेयजल के लिए छह हजार करोड़ की राशि से प्रत्येक प्रदेश वासी को शुद्ध पेयजल उपलब्धता की गारंटी के साथ काम किया जायेगा।

श्री सभापति: विराजिए, माननीय सदस्य।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): बिजली में भी आपने ऐसा ही किया। फ्री बिजली बांट दी। फ्री बिजली देंगे, फ्री बिजली देंगे, उसमें भी लोग-बाग़ चक्कर काटते रहे। स्थिति यह थी कि आपने सब्सिडी के पैसे नहीं दिये। 90 हजार करोड़ रुपये की जो राशि है, वह कम्पनियों को घाटा सहना पड़ा। यह घाटा उन कम्पनियों का नहीं है, राजस्थान के प्रदेशवासियों पर पड़ा है।

आप लोगों ने इन पांच सालों के अन्दर क्या-क्या किया है, यह आप मन से सोचो, हृदय से सोचो। आपको वास्तव में शर्म आनी चाहिए कि किस तरह की शासन व्यवस्था इन पांच सालों की रही है, आपने क्या हालात इस राजस्थान के कर दिये थे? चिकित्सा में आपकी सारी योजनाएं अप्रासंगिक थीं। किस व्यक्ति का, एक व्यक्ति आकर के बता दे कि 25 लाख का किसी का इलाज किया हो। सिर्फ वाहवाही लूट लो, तालियां बजवा लो। एक व्यक्ति का नाम बता दो जिसने 25 लाख रुपये का इलाज करवाया हो।

श्री सभापति: विराजें।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): चिकित्सक आप नहीं लगा पाये। 1,500 चिकित्सक और 5,000 नर्स इस राजस्थान की धरती पर सेवा करेंगे। रफीक भाई, आकर के एक भी नाम बता देना। 1,500 चिकित्सक और 5 हजार स्टाफ नर्स लगेंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, आप समय कम दे रहे हो....

श्री सभापति: पूरा दिया है।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): लेकिन मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। जिस तरह से कांग्रेस सरकार की नीतियां रहीं, प्रशासन रहा, उसको हम भुगत रहे हैं, लेकिन इन पांच सालों के अन्दर हम यह वादा करते हैं जनता से कि जिस तरीके से हमने बजट को प्रस्तुत किया है, वह पूरा इम्पलीमेंट होगा, एग्जिक्यूट होगा।

उद्योगों में भी मैं आपको बता दूं कि आपने कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप नहीं किया, लेकिन आज हमारे द्वारा उद्योगों को लेकर जो काम किये जा रहे हैं, इस प्रदेश में हम उद्योगों के लिए भी लोगों को आमंत्रित करेंगे और लोग स्वयं आकर्षित होकर राजस्थान की धरती पर अपने उद्योग स्थापित करेंगे। माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय नरेन्द्र जी बुडानियां।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, आपने परिवर्तित बजट 2024-25 पर मुझे बोलने के लिए समय दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

सभापति महोदय, मैं कल से बराबर इस बहस को सुन रहा हूं। मुझे बड़ा दु:ख हुआ है, बड़ा अफसोस हुआ है कि हमारा बजट पेश हुआ, पूरे राजस्थान की जनता आस लगाये बैठी थी कि हमारे लिए बजट आयेगा, बजट आया, बजट पर बहस शुरू हुई लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बजट की बहस का जो स्तर है वह सही नहीं है।

पूरा राजस्थान आपको देख रहा है, इस बहस को सुन रहा है। बहस बजट पर हो रही है, चर्चा बजट पर हो रही है। क्या हुआ, क्या होना चाहिए, बजट में क्या चीज रह गई, बजट में क्या चीज अच्छी है, जनता के लिए क्या

(श्री नरेन्द्र बुडानियां)

फायदे की है, ये सब बातें होनी चाहिए थीं, लेकिन जिस प्रकार से यह बहस चालू हुई है, नगरपालिकाओं में भी ऐसी बहस नहीं होती है। बहस बजट की हो रही है और चर्चाएं किसी और चीज की हो रही हैं। ये सारी चीजें हो रही हैं। मैं चेताना चाहता हूं, हाउस हमारा है, राजस्थान के हाउस की एक गरिमा है। पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर राजस्थान की विधान सभा जानी जाती है, लेकिन मैं समझता हूं, जोगाराम जी, यह आपकी सरकार बनी है, यह आपको समझ में ही नहीं आयी कि बनी है कि नहीं बनी अभी तक।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप जो फरमा रहे हैं हमारी सरकार जनता की सरकार है और आप वाली सरकार थी न, वह कभी इधर की, कभी उधर की, कभी होटलों की, कभी बाहर की, वैसी सरकार हमारी नहीं है।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): समय बहुत बलवान होता है। राजनीति में उतार-चढ़ाव सबके आते हैं। भगवान करे आपके जल्दी नहीं आ जाएं, ध्यान रखना आप। मैं यह समझता हूं, माननीय सभापति महोदय, मेरा यह दु:ख था, यह मैंने आपके सामने रखा है। यदि आपको मेरी बात सही नहीं लग रही कि बहस बजट पर होनी चाहिये, उसका एक स्टैण्डर्ड होना चाहिये, जनता हमारे को देख रही है, आपको पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): जो ये कह रहे हैं, वह बिलकुल सही फरमा रहे हैं बस।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, मैं बैठा-बैठा यह महसूस कर रहा था कि यदि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होता तो जो राजनीतिक बातें अभी हो रही हैं, जो बजट के अलावा बातें हो रही हैं, वे सारी बातें उसके अन्दर आ जातीं। पता नहीं किस सलाहकार की सलाह में आकर आपने राज्यपाल महोदय का अभिभाषण नहीं करवाया। आप अभिभाषण करवाते तो राजस्थान की जनता को इसका लाभ मिलता। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण तो नहीं करवाया, लेकिन मैं लम्बे समय से काम कर रहा हूं और केन्द्र से पहले बजट पेश करना, कर सकते हैं, हमारा अधिकार है, लेकिन आपके लिए अच्छा होता, प्रदेश के लिए अच्छा होता, हम सबके लिए अच्छा होता यदि केन्द्र सरकार के बजट के बाद हमारा बजट रखा जाता। आज हमारा शेयर क्या होगा? आज कोई खड़ा होकर बता सकता है कि हमारा शेयर क्या

(श्री नरेन्द्र बुडानियां)

होगा? कोई नहीं बता सकता। इसलिए यदि बाद में बजट रखा जाता तो हम सबके लिए फायदे की बात होती।

माननीय सभापति महोदय, सरकार ने जो बजट रखा है, वह बहुत लम्बा समय लिया। तीन घंटे तक हम बैठे रहे और तीन घंटे तक सुनते रहे। अच्छी बात है, आपने लम्बा भाषण पढ़ा, लेकिन भाषण में आपने बजट में रखा क्या? आपने 3 लाख 34 हजार करोड़ का बजट पेश किया है और राज्य की आमदनी क्या है, 2 लाख 64 हजार, बाकी पैसा कहां से आयेगा? 70 हजार करोड़ रुपये आपको कर्ज लेना पड़ेगा। अभी आप कर्ज की बात कर रहे थे कि उस सरकार ने डुबो दिया। 70 हजार करोड़ रुपये आप कहां से लेंगे? कैसे लेंगे आप? आपने कहीं पर भी इसका स्पष्ट उल्लेख किया कि हम यहां से बजट लेंगे? आपने कहीं भी नहीं किया। (व्यवधान) मैं कह रहा हूं आप भी संसद में रहे हुए हैं माननीय सदस्य, मैं भी आपके साथ एम.पी. रहा हूं। हमारी सालाना आमदनी क्या है? हमारे कर्ज और आमदनी का रेशो क्या है? यह समझना पड़ेगा। आपको आर.बी.आई. ने नोटिस दे रखा है। राजस्थान को आर.बी.आई. ने नोटिस दे रखा है। यह आपको कब ब्लैक लिस्टेड कर देगा, आपको इसका पता नहीं चलेगा।

माननीय सभापति महोदय, वाह-वाह, क्या बात है, आपने तो इसमें घोषणाओं का अम्बार लगा दिया। यह घोषणाओं वाली सरकार जानी जायेगी। 1,005 घोषणाएं हुई हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सदस्य, आपसे एक निवेदन करूं कि कितनी घोषणाएं आपको अच्छी लगती हैं? आपको कितनी घोषणाएं अच्छी लग रही हैं? 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत या 20 प्रतिशत, 100 प्रतिशत।

एक माननीय सदस्य: सारी अच्छी हैं, सब पूरी करोगे तो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): सब पूरी करेंगे। हां, यह बात ठीक है।

एक माननीय सदस्य: पूरी करोगे तो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): पूरी करने के लिए ही घोषणा की है।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): ईश्वर करे आपको इतनी ताकत मिले कि आप इन घोषणाओं को पूरी कर सको, लेकिन, माननीय मंत्रीजी, आप यह

(श्री नरेन्द्र बुडानियां)

घोषणाएं कैसे पूरी करोगे? कुछ बताओ तो सही। कितना पैसा है आपके पास इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए? मात्र 44 हजार करोड़ रुपये हैं। 44 हजार करोड़ रुपये में 1,005 घोषणाएं पूरी कर दो तो मैं आपको सैल्यूट करूंगा। लेकिन नहीं होंगी, ये घोषणाएं थोथी साबित होंगी, मैं आपको आज कह रहा हूं। थोथी घोषणाएं होंगी ये। आपने तो घोषणाओं का अम्बार ही लगा दिया। आपके पास में पैसा है नहीं। आप इनको कहां से पूरी करोगे? वैसे आपका कसूर नहीं है, आप जुमलेबाजी में माहिर हैं। आप इसमें विश्वास रखते हैं। आज भी 10 साल हो गये, लोग 15 लाख रुपये का इंतजार कर रहे हैं। अपना खाता अभी भी टटोल रहे हैं। आपने भी वही काम शुरू कर दिया।

अब आप देखिए, आप बार-बार प्रधान मंत्रीजी का नाम ले रहे हैं। मैं सोच रहा था कि हमारे मुख्य मंत्रीजी बैठे हैं, कितने भले आदमी हैं। मैं बजाता हूं ताली, भले आदमी हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): जितने भले आप हो, भाटी साहब हैं, तो हम स्वीकार करते हैं कि इससे बेस्ट बजट आज दिन तक नहीं आया है।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): वास्तविकता स्वीकार करने में, मैं आपका भी उतना ही रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं, आप बुरा नहीं मानें तो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): नहीं मानेंगे।

(समय: 15.47 बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): आप बार-बार खड़े मत होना।

एक माननीय सदस्य: संसदीय कार्य मंत्री को शोभा नहीं देता।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): मैं हिन्दुस्तान के तीनों सदनों में रहा हूं। बीच में बारबार उठना, मैं समझता हूं एक अच्छे पॉलिटिशियन की पहचान नहीं है और मैं आपको इतना अच्छा मानता हूं। मुझे दुख होता है कि ये बार-बार क्यों खड़े हो रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा यह सुझाव है, इसके लिए बुरा मत मानना आप। मेरे मन में आया तो मैंने बोल दिया। जब बार-बार प्रधान मंत्रीजी का नाम बोल रहे थे तो बीच में कभी मुख्य मंत्रीजी का नाम भी आ

(श्री नरेन्द्र बुडानियां)

रहा था। मैं समझ रहा था कि कभी-कभी दबाव में मुख्य मंत्रीजी को भी याद तो किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, आपने राजस्थान का नजारा देखा? आप 11 सीटें हार गये। आपने 25 का नारा दिया था। हैट ट्रिक की बात कही और मोदीजी तो आपसे कुट्टी हो गये। मोदीजी कुट्टी हो गये, आपने 25 की बात कही और आपने 11 खो दीं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैंने तो अभी शुरू ही नहीं किया।

श्री सभापति: आपका जो समय है, वह समाप्त होने वाला है। एक मिनट में अपनी बात पूर्ण करें प्लीज।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): कोई बात नहीं, हमारे नेता हैं नहीं, मैं इनसे ..(व्यवधान)

श्री सभापति: मैं निवेदन करूं आज 34 वक्ता हैं।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): भले ही होंगे।

श्री सभापति: तो आपको 12.00 बजे तक बैठना पड़ेगा।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): मैं मेरी पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं।

श्री सभापति: ऐसे नहीं हो पाता है। (व्यवधान) ऐसे नहीं हो पाता है कभी भी।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): मैं तो बोला ही नहीं अभी कुछ भी।

श्री सभापति: कृपया आप समाप्त करें। कन्क्लूड कर दें, आप बहुत वरिष्ठ विधायक हैं।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): मैं यह कह रहा था कि प्रधान मंत्रीजी कुट्टी हो गये। वे तो आंध्र प्रदेश और बिहार में उलझे हुए हैं। अब आपको खुश रखेंगे कि उनको खुश रखेंगे? आपको खुश रखेंगे तो वे नाराज हो जाएंगे। वे नाराज हो जाएंगे तो आपका क्या होगा? (व्यवधान)

श्री सभापति: आपका समय पूर्ण हो चुका है।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): समय मेरी पार्टी का है, समय बंटवारा जो इसमें लिखा हुआ है, आपके कहने से नहीं, यह जो समय इसमें लिखा हुआ है। व्यवधान) तो आप इसमें से कम करा दो।

मुझे आधा घंटे के लिए बोला गया है। मेरे को आधा घंटे के लिए बोला गया है।

(श्री नरेन्द्र बुडानियां)

माननीय सभापति महोदय, मैं अभी बोल रहा था, नौजवानों पर अभी बात चल रही थी। मैं भी यही महसूस करता हूं कि नौजवान को आज आवश्यकता है मदद की, आज हमारा नौजवान बहुत नर्वस है, आज नौजवान की नौकरी नहीं है। घोषणाएं होती हैं, कहीं दो करोड़ की होती है, कहीं एक लाख की होती है, लेकिन नौकरियां है कहां? आज हमको सोचना पड़ेगा। हमें इसके साथ-साथ में एम.एस.एम.ई. की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। एम.एस.एम.ई. की क्या हालत हो रही है? एम.एस.एम.ई. की हालत बहुत खराब हो रही है। हमारी उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत गिर गई है। बिजली काट रहे हो। आठ घंटे बिजली दे रहे हो। हमारे बड़े-बड़े उद्योग तो चमक रहे हैं, लेकिन छोटे फेल हो रहे हैं। आपको इस पर ध्यान देना चाहिए, यह मेरा सुझाव है।

माननीय सभापति महोदय, आज कृषि सेक्टर हमारे देश का सबसे बड़ा सेक्टर है। सब कहते हैं, किसान-किसान-किसान, किसान हमारा अन्नदाता है, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। आज किसान की क्या हालत हो रही है? पिछले दस साल के अन्दर किसान की जो हालत हुई है, हिन्दुस्तान का किसान आपको कभी माफ नहीं करेगा। कभी माफ नहीं करेगा। किस प्रकार से वह सड़कों पर पड़ा रहा, किस प्रकार से उनके लोग शहीद हुए..(व्यवधान) दस साल के अन्दर और मैं कहना चाहता हूं और चेतावनी देना चाहता हूं कि यह फिर शुरू होगा। कल पंजाब के अन्दर पूरे भारत की मीटिंग हुई है किसान यूनियन की और उन्होंने फैसला किया है पूरे देश में आंदोलन करने का। इसलिए आप सम्भल जाइए। मैं यह बात कहना चाहता हूं। (व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए। मुख्य मंत्रीजी से मिलकर भी मैं कहूंगा कि हम सब लोग किसान के बेटे हैं ज्यादातर। आज हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। हमको इसकी स्टडी तो करनी चाहिए। मेरा सुझाव है कि केरल की स्टडी करनी चाहिए कि केरल के किसानों के साथ क्या हो रहा है? वहां नारियल के पानी का भी एम.एस.पी. मिलता है, नारियल के पानी का, सब्जियों का। आज हमारे क्या होता है? आपके जिले के टमाटर देख लीजिए, प्याज देख लीजिए, सड़कों पर मिलते हैं। किसान की क्या हालत हो रही है? बाजरी हमारी बम्पर क्रॉप है। राजस्थान की हमारी सारी इकॉनोमी बाजरे के ऊपर ही है। बाजरी खरीद की बात तो चली एम.एस.पी. की अखबारों में कि बजट में आएगा, लेकिन नहीं आया। विचार करना चाहिए इस पर। इस पर विचार करना चाहिए, मैं समझता हूं कि आप जरूर करेंगे।

(श्री नरेन्द्र बुडानियां)

माननीय सभापति महोदय, 01 लाख 45 हजार किसानों को कृषि विद्‌युत कनेक्शन देने की बात की है। यह तो बिलकुल हास्यास्पद है। बिजली कम्पनियों के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए आपके पास पैसा कहां है? क्या हालत है कम्पनियों की? तार के लिए बोलते हैं, पोल के लिए बोलते हैं तो वे नहीं है। ये हालात हैं। यह सोचने की जरूरत है। 3,300 मेगावाट थर्मल पावर की आपने बात कही है। कहां से पूरा करेंगे आप? आपका एग्जिस्टिंग थर्मल पावर है उसके लिए कोयला नहीं है आपके पास। उसके लिए कोयला नहीं मिलेगा आपके पास। (व्यवधान) मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यह कभी पूरा होने वाला नहीं है। (व्यवधान)

साथियों, सरकार के मेरे साथी मित्रों, मैं किसान का बेटा हूं। कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल हमारे एरिये का बहुत बडा..

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): वो तो कुम्भकर्ण कहते थे आपके युवराज।

श्री सभापति: कन्क्लूड करें।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): आपने कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल के लिए 200 करोड़ रुपये दिये, उसकी डिग्गियों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए। उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरी यह मांग थी, मेरी यह पुरानी मांग है। वह इसलिए कि मैंने 20 हजार हैक्टेयर जमीन के लिए नहर बनाकर दी है, पिछले पांच सालों में किसान को, 120 किलोमीटर, राजस्थान में कहीं नहीं होगी, लेकिन तारानगर के अन्दर 120 किलोमीटर नहर है। (व्यवधान)

श्री यूनुस खान (डीडवाना): उसका परिणाम भी तो आया है। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): लेकिन, मंत्रीजी, पिछले बजट में 100 करोड़ रुपये इसी काम के लिए सेंक्शन हुए थे, एक पैसा भी नहीं लगा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): कौनसी सरकार में?

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): नहीं, नहीं, अभी पिछले बजट में।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): हमारी सरकार का बजट तो अब आया है।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): पिछले बजट में। (व्यवधान) आपको छह महीने तो हो गये। (व्यवधान) मैं मेरी सरकार की या आपकी सरकार की

(श्री नरेन्द्र बुडानियां)

बात नहीं करता, मैं किसान की बात करता हूं। मैं किसान की बात कर रहा हूं। किसान के लिए 100 करोड़ रुपये मंजूर हुए, उनमें से एक पैसा नहीं लगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको बहुत सीरियस लेकर किसान के लिए पैसा खर्च करवाइए। मैं उम्मीद करता हूं आपसे। मैं बहुत दुखी हूं कि 2005 में आपका राज था और हमारी इस कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल का सिंचित रकबा काट दिया। किसानों के पेट पर, नौजवानों के पेट पर लात मारी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय अशोक गहलोत को कि मेरे कहने पर 20 हजार हैक्टेयर जमीन की उन्होंने पहले बजट में घोषणा कर दी और उसको पूरा भी कर दिया। वह अब पूर्ण होने के ऊपर है। आज सरदारशहर, तारानगर, राजगढ़ के किसानों, जिनकी सिंचित जमीन का रकबा काट दिया, ये सरदारशहर के एम.एल.ए. हैं, ये राजगढ़ के एम.एल.ए. हैं, ये दोनों ही मेरे मतदाता हैं।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): सौभाग्य है हमारा।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): इन दोनों का गांव मेरे विधान सभा क्षेत्र में है। आज सरदारशहर, राजगढ़ और तारानगर के गांवों की जमीन कट गई है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): तारानगर के वोटर बनेंगे, तभी हम एम.एल.ए. बन सकते हैं वहां से।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि 20 हजार हैक्टेयर रकबा पिछली सरकार ने सिंचित किया, यदि आप किसानों के सच्चे साथी हो तो 20 हजार की घोषणा करवा दो यहां पर। 20 हजार की और घोषणा करवा दो यहां पर। मैं मांग करता हूं।

श्री सभापति: विराजें आप।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, एक बात मैं कहना नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे कितना ही कहो, बिजली पानी के हालात बहुत बुरे हैं। इतना बुरा हाल है पिछले दो महीने के अन्दर, दो महीने के अन्दर जो हालात हुए हैं गरीबों के, किसानों के, गांव में रहने वाले और शहरों में रहने वाले लोगों के, मंत्रीजी, आपको मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि मेरे पास ऐसे-ऐसे फोन आये हैं कि, विधायकजी, बच्चा छोटा है चार दिन का, बिजली नहीं है, मर रहे हैं बच्चे।

श्री सभापति: श्री फूल सिंह मीणा।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): ऐसे हालात हो रहे हैं। ऐसे ही हालात पानी के हैं। ऐसे ही हालात पीने के पानी के हैं। आप सुधारिए इसको। आप सुधारिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज। (व्यवधान) अंकित नहीं हो।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): 000

श्री सभापति: आप विराजें। (व्यवधान) बोलिए, फूल सिंहजी।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, आज आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी मेरे से पहले के वक्ताओं ने जो अपनी मनगढ़ंत बातें रखीं, वे कहीं पर भी धरातल पर नहीं उतरीं।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): 000

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य, आपका समय पूरा हो गया। (व्यवधान) आपका अंकित नहीं होगा।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): 000

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि पूर्व सरकार ने घोषणा के अलावा कुछ भी नहीं किया। घोषणा की घोषणा रह गई। पूर्व में जब हमारी वसुन्धरा राजे जी की सरकार थी तो गौरव पथ हमारी हर पंचायत को दिया था, उसको इन्होंने चेंज करके विकास पथ का नाम लिया, लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पूर्व सरकार के यहां पर जो मेरे भाई बैठे हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही नहीं, हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी के जीतकर आने वाले विधायकों को एक भी विकास पथ नहीं दिया। यही नहीं, इन्होंने पेरिफेरी एरिया के अन्दर हमारी गरीब जनता, चाहे वह किसी भी समाज की हो, बरसों से रह रहे थे, उनको यह कहा था कि 11 नवम्बर, 2011 से पहले का कोई भी प्रमाण लाकर पट्टा ले जाओ, मगर सभापति महोदय, एक आदमी को पट्टा नहीं दिया। वहां

(समय: 16.00 बजे)

हमारे प्रधानमंत्री आवास का एक भी मकान गरीब नहीं बना पाया, क्योंकि पट्टा ही नहीं था। यही नहीं, नन्दी गोशाला खोलने की बात कही थी कि हर पंचायत स्तर पर। "हम पंचायत समिति मुख्यालय पर नन्दी गोशाला खोलेंगे", एक भी

(श्री फूल सिंह मीणा)

गोशाला नहीं खोली। यही नहीं, पंचायती राज में भा.ज.पा. का जो हर समय वोट था, वहां एक पंचायत को तीन-तीन पंचायत समिति का एक सदस्य में बांट दिया, ताकि इनका प्रधान बन जाए। इनकी ऐसी नीति से प्रधान तो बना लिया, मगर ये अपने विधायक को नहीं जिता पाये। यह जनता समझ चुकी है।

यही नहीं, आपको मैं बताना चाहता हूं, विद्यालय में महात्मा गांधी का नाम रखकर अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोल दिया, मगर वहां न तो टीचर था और न ही वहां पर भवन बना हुआ था। ऐसी स्थिति में हमारे गरीब आदिवासियों के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया। यही नहीं, पूर्व सरकार ने जनता क्लिनिक का वादा किया कि हर वार्ड में जनता क्लिनिक खोलेंगे। सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में, गांव में एक भी जनता क्लिनिक नहीं खोली। यही नहीं, पूर्व सरकार ने, हमारे विधायक, जो अभी भा.ज.पा. से जीतकर आये, उन्हें छांट-छांटकर, चाहे डी.एम.एफ.टी. फंड हो, चाहे मेरा विधायक कोष हो, उसे इन्होंने रिलीज नहीं होने दिया। इन्होंने सोचा कि यह विधायक फंड का पैसा भी लग जायेगा तो ये जीतकर आ जायेंगे। डी.एम.एफ.टी. फंड को भी इन्होंने हमारे विधायकों के यहां पर रोक दिया। इनके जो भी विधायक थे, वहां पर भण्डार खोल दिया। फिर भी मैं ग्रामीण विधान सभा की जनता का आभार व्यक्त करता हूं जो उन्होंने रिकार्ड तोड़ मतों से जिताकर विधान सभा में मुझे भेजा। लोक सभा में भी तीसरी बार हमारे सांसद को जिताकर भेजा।

अब मैं विकास की बात करूं तो हमारे बजट में भजन लाल जी की सरकार ने प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में राजस्थान में विकास का डबल इंजन लाकर राजस्थान में विकास और सुशासन स्थापित करने का आगाज कर दिया। आचार संहिता के बावजूद भी 53 परसेंट बजट घोषणाएं और संकल्प पत्र के 45 बिन्दु पूरे किये गये हैं। हमारी माताओं-बहनों को 450 रुपये में सिलेंडर देने का जो वादा किया, वह पूरा किया।

कांग्रेस की पिछली सरकार ने अपनी गलत नीतियों से कमजोर वित्तीय स्थिति छोड़ी, लेकिन हम राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का, राजस्थान के युवाओं के जोश और ज्ञान का सदुपयोग करने के लिए हमने चार लाख भर्तियां करने का संकल्प लिया।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, हमारे वरिष्ठ साथी आसन को पीठ बताकर बैठे हैं। देख लें आप नजारा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, आपके माध्यम से पेपर लीक करने वाले लोगों को वास्तव में डमी पेपर देने वाले और पेपर लीक करने वाले सौ लोगों को गिरफ्तार करके उनके आशियाने पर भी बुलडोजर चलाने का काम भजन लाल जी की सरकार ने किया। 10 लाख से भी अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएंगे। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे इस बजट में प्रावधान किया है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: हो गया समय।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, मैं तो अभी खड़ा ही हुआ हूं। अभी पांच मिनट भी नहीं हुए मुझे 10 मिनट दिये गये हैं।

श्री सभापति: अब चेंज हो गयी है व्यवस्था। अब मैं बता दूं, सबको 7-7 मिनट कर रहे हैं। बोलने वाले वक्ता 35 हैं। सब 7 मिनट में अपनी बात रखें। आप जल्दी अपनी बात को पूरा करें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, मैं बात ही तो कर रहा हूं। मैं इनके काले कारनामों को याद कर रहा था। बजट पर तो अभी आया ही नहीं। इन्होंने क्या दिया हमें?

श्री सभापति: बहुत अच्छा बोल रहे थे, पर समय की सीमा है।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, हमारी सरकार ने आते ही पहले 20-20 हैंडपम्प्स और 10-10 ट्यूबवैल्स देकर हमारे जनजातीय परिवारों को तोहफा देने का काम किया।

श्री सभापति: श्री जीवाराम चौधरी।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, दो मिनट में पूरा कर रहा हूं।

श्री सभापति: यह व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, मैं सरकार का धन्यवाद तो कर दूं। सरकार का धन्यवाद तो करने दें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में नान्देश्वर से रामपुरा तक का जो रोड, देबारी से प्रताप नगर तक एलिवेटेड रोड, पारस तिराहे पर फ्लाईओवर, जड़ाव नर्सरी से कलरवाड़ तक का रोड, नान्देश्वर-जाडोल रोड से कविता तक रिंग रोड, नाई की तहसील बनाने का यह जो सरकार ने हमें दिया, उनका धन्यवाद देता हूं। पांच साल तक हम इन्तजार करते रहे।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री जीवाराम चौधरी।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, एक मिनट। सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पेरिफेरी के अन्दर बसे लोगों को पट्टा दिलाने के लिए मेरी मांग करता हूं।

श्री सभापति: पांच मिनट का समय मिला है आपको।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): सभापति महोदय, थोड़ा-सा तो बोलने दें, चाहे आज वक्ता कम कर दें आप, प्लीज। एक दिन और बढ़ा दीजिएगा चाहे। पांच मिनट में तो वे अपने क्षेत्र पर ही नहीं आ पाये।

श्री सभापति: वक्ता आज भी बहुत हैं, वक्ता कल भी बहुत हैं, परसों मुख्य मंत्री जी रिप्लाई करेंगे। माननीय सदस्य, मेरी बात सुनिए।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): हमारा एक निवेदन सुन लें आप। सबके लिए लागू है। विधायक अपने क्षेत्र की बात ही नहीं कह पा रहे।

श्री सभापति: यह अध्यक्ष जी की व्यवस्था है और अध्यक्ष जी तय कर लेंगे। अभी यह व्यवस्था जो दी गयी है, इसमें अपन कर लेंगे। माननीय सदस्य, बोलें, आपका समय चालू हो गया।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी आपने मुझे 4 बजकर 6 मिनट पर आदेश दिया है। आदरणीय यूनुस जी ने बहुत सही निवेदन किया है। अगली टाइम में आप भले ही हमारा समय पांच मिनट कम कर देना, 10 मिनट कम कर देना और अगर चाहें तो बिलकुल ही कम कर देना, लेकिन आज तो आप बात निकालने दें हमें। काफी दिनों से भरी पड़ी है स्टाक में।

श्री सभापति: जो होशियार वक्ता होते हैं, वे कम समय में भी बहुत अच्छी-अच्छी बात कह देते हैं। जीवाराम जी, आपसे यही अपेक्षा है कि पांच मिनट में आप बहुत अच्छी-अच्छी बात कहेंगे।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): टाइम अब शुरू हुआ है आठ मिनट।

आज के सभी वक्ताओं ने खूब अच्छी-अच्छी बातें कीं, खूब अच्छा-अच्छा अपना सुझाव भी दिया। उसमें मैं भी पार्टिसिपेट करता हूं। सर्वप्रथम, हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय भजन लाल जी, उप मुख्य मंत्री और हमारी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी, हमारे मंत्रिमण्डल के सभी माननीय सदस्य और हाउस में भिन्न-भिन्न विचारधाराओं से जीतकर विराजे हुए सभी माननीय सदस्य, मैं आप सबको खूब-खूब धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं और बधाई भी देता हूं।

(श्री जीवाराम चौधरी)

सभापति महोदय, इस बजट में प्रत्येक विषय को कहीं न कहीं हमारी लोकप्रिय सरकार ने छुआ है, चाहे वह सड़क हो, बिजली हो, सौर ऊर्जा हो, किसान हो। कोई ऐसा सब्जेक्ट, लगभग-लगभग बाकी नहीं रहा, लेकिन बजट पढ़ने के बाद उसमें मुझे कुछ महसूस हुआ जो मैं सुझाव देना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचोर में विश्व की सबसे बड़ी गोशाला है। उसी तरह से पूरे प्रदेश में लगभग हर अल्टरनेट ग्राम पंचायत में लोग गऊ माता की सेवा अपने-अपने स्तर पर करते हैं। वर्तमान सरकार में हम लोग 12 महीने में से 9 महीने का अनुदान गायों के लिए देते हैं।

सभापति महोदय, जिस प्रकार से वर्तमान में चारे की व्यवस्था हो रही है, वह कम है। जो अनुदान दे रहे हैं, उसके माध्यम से 12 महीनों तक उन गायों की सेवा करना थोड़ा मुश्किल होता है। मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि गऊ गोचर के लिए हमारे पूरे प्रदेश में हजारों बीघा जमीन गोचर अवेलेबल है। सरकार क्यों नहीं उनको अधिकार दे? चाहे पंचायत हो, चाहे गोशाला की कमेटी हो, उस गोचर की भूमि में, अभी यह बारिश का समय है, अगर वहां गायों के लिए बाजरे की बुवाई कर दें, जहां पानी की उपलब्धता है, वहां सर्दियों में भी कई प्रकार की घास उगाकर 12 मास गायों के लिए चारे की व्यवस्था हो सकती है। हमारे पास जो गोचर की जमीन पड़ी है, उस पर लोग नाजायज कब्जा कर रहे हैं। वह गोचर भूमि हमारे पूर्वजों ने गायों के लिए ही छोड़ी थी। आज उन गायों को गोशाला में इकट्ठा रखकर सेवा करनी पड़ रही है। यह हमारे लिए बहुत ही दुख का विषय है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार को सुझाव है कि जहां-जहां गोचर भूमि खाली पड़ी है, उस गोचर भूमि में गायों के लिए चारा उगाने के लिए सरकार उनको आदेश दे। उनको परमिट करें, उनको परमिशन दें, लोग अपने आप मेहनत करेंगे, वे उसके बदले में सरकार से कोई धनराशि नहीं मांगेंगे। अपने आप मेहनत करके चारा उगा करके गायों को खिलायेंगे। जो गोचर भूमि खाली पड़ी है, उसकी परमिशन माननीय सरकार दे, तब जाकर इस समस्या का समाधान हो सकता है।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचोर में प्रधान मंत्री मोदी जी द्वारा, केन्द्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन, वैसे तो पूरे प्रदेश में चल रहा है, लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है, प्रत्येक सरकार तो अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा कार्य करने का प्रयास करती है, उसी प्रकार विधायक

(श्री जीवाराम चौधरी)

भी अपने विधान सभा क्षेत्र में अच्छे से अच्छा कार्य करने का प्रयास करता है, ताकि वह अगली बार भी वापस रिपीट हो, लेकिन वह करते-करते भी कुछ न कुछ कमियां, खामियां रह जाती हैं, जिसकी वजह से जनता परिवर्तन करती है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका समय पूर्ण हुआ। श्री घनश्याम जी मेहर।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): जल जीवन मिशन में जिस प्रकार से पाइप लाइनें बिछाई हैं। उन पाइप लाइनों की गहराई..। सभापति महोदय, 7 मिनट पूरे हुए हैं। मैंने अभी तक पूरी बात नहीं कही।

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): मेरा एक सुझाव है, सुझाव तो ले लीजिए।

श्री सभापति: आपके बहुत सारे सुझाव आ गये हैं।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी मैं जिस फ्लैट में रह रहा हूं, उन फ्लैट्स को बनाने वालों को, उस समय की सरकार को, उन सभी इंजीनियरों को, उन सभी मजदूरों को और जिन-जिन ने सहयोग करके ये इतने बढ़िया और सुन्दर फ्लैट बनाये हैं, लेकिन उनकी ईंटों में एक कमी रह गई है, ईंटों में होल नहीं कर सकते हैं, कोई कील लगानी है तो वह कील लगाने के दो-तीन दिन बाद निकल जाती है।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री मुकेश भाकर।...(व्यवधान) घनश्याम जी, बोलो। आपका समय प्रारम्भ हो गया है। अंकित नहीं होगा।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): 000

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, आपने बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की जनता के लिए किस तरह का बजट पेश किया गया है। इससे पूरी जनता को बहुत निराशा मिली है और सिर्फ कागजों में आपने लेखा-जोखा सदन के सामने रखा है, यह जनता को गुमराह करने वाला है।

माननीय सभापति महोदय, मैं टोडाभीम, गंगापुर जिले से आता हूं और पूर्वी राजस्थान में हम गंगापुर जिले से तीन विधायक चुनकर आये हैं।

(श्री घनश्याम)

हम तीनों विधायकों को इस बजट में वंचित रखा गया है, किसी भी प्रकार की कोई सौगात नहीं दी गई है। इससे साबित होता है कि राजस्थान की सरकार, जहां से कांग्रेस के विधायक चुनकर आये हैं, उनके साथ किस तरह से सौतेला व्यवहार कर रही है। हम मानते थे कि पूर्वी राजस्थान से, भरतपुर जिले से माननीय मुख्य मंत्री जी चुनकर आये हैं, जो वहां के रहने वाले हैं। जनता को बहुत आशा थी कि भजन लाल जी पूर्वी राजस्थान में पहली बार मुख्य मंत्री बने हैं तो लोगों को लगा कि विकास के कुछ नये काम वहां स्थापित होंगे, पर एक भी काम पूर्वी राजस्थान, भरतपुर सम्भाग में ऐसा नहीं किया गया है। जहां तक राजा-महाराजाओं के महलों को पैसा दिया गया, हमारे यहां तो मन्दिरों में भी नहीं दिया गया। पूर्वी राजस्थान में कैलादेवी का मन्दिर है, मदन मोहन जी का मन्दिर है, बड़े-बड़े ऐसे धार्मिक स्थल हैं, पर फिर भी उन मन्दिरों को एक रुपया देने का काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग जहां से जीतकर आये हैं, उनको ही पैसा देने का काम किया गया है।

किसान और बेरोजगार युवाओं के लिए इस बजट में किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। हमारी सरकार के दौरान किसानों को जो फसली ऋण मुफ्त ब्याज पर दिया जाता था, आपने उसमें भी कटौती कर दी है। हमारे देश के जवानों के लिए जो आपने अग्निवीर योजना लागू की है, उससे पूरे प्रदेश में बहुत निराशा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में अभी कई अग्निवीर जो शहीद हुए हैं, उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला है। हमारी जब सरकार थी तो उनको 30-30 लाख रुपये का पैकेज दिया जाता था, आज एक रुपये का पैकेज उनको नहीं मिल रहा है। बजट में कह रहे हैं कि 4 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, जबकि बैकलॉग एक लाख 87 हजार ही है। आप 4 लाख नौकरी देंगे कहां से? आप युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। मंत्री जी, आप कहां से देंगे? इसके लिए आपके पास कोई रोडमैप है ही नहीं। आप भर्ती की जगह नहीं निकाल रहे हैं। आप गुमराह करने वाली स्थिति पैदा कर रहे हैं। यह आज का युवा भी समझ रहा है। आप बार-बार कहते हैं कि पेपर लीक हो गये। पेपर लीक तो आपके समय में भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, गुजरात में हो रहे हैं, कौन-से स्टेट में नहीं हो रहे हैं? अब आप सरकार में आ गये हैं तो आप रोकिए।

अभी रीट का पेपर लीक हुआ है। आपके तो एयरपोर्ट लीक हो गये, सड़क लीक हो गई, राम मन्दिर की छत लीक हो गई, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, 13 पुल एक ही दिन में गिर गये।

(श्री घनश्याम)

आपकी सरकार ही लीक हो रही है तो इस बात पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा।

सरकार ने ई.आर.सी.पी. पर बहुत ढिंढोरा पीटा था। ईआर.सी.पी. वर्ष 2016-17 में मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी थीं तो उनके टाइम पर यह योजना लाई गई। ई.आर.सी.पी. पर प्रधान मंत्री जी ने भी अजमेर में, जयपुर में आकर कई बार इस बात पर भाषण दिये और जनता को गुमराह करने का काम किया। हमारी जब सरकार थी, तब उसमें प्रावधान रखा, बजट भी खर्च किया, ईसरदा में भी बहुत सारा काम हुआ और आज उसका नाम चैंज करके..

सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि आपने क्या डी.पी.आर. बनाई है, यह सदन के सामने तो रखें। आप फालतू में ढिंढोराबाजी कर रहे हो और लोगों को ई.आर.सी.पी. के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। लोगों को यही नहीं पता है कि कौन-सा एरिया इसमें जोड़ा है, कौन-से तालाब जोड़े हैं, तो इसकी डी.पी.आर. को एक बार सदन के सामने रखें और हमको भी बताया जाए। विपक्ष के सभी विधायकों को बताया जाए कि हमने यह नई डी.पी.आर. तैयार की है।

मंत्री जी की बात कर रहे हैं। आदिवासियों के साथ बहुत भेदभाव हो रहा है। आदिवासियों के साथ तो करोगे ही, हमारे आदिवासी मंत्री सम्माननीय किरोड़ी लाल जी को ही नहीं बख्शा। आप और आदिवासियों को क्या बख्शोगे? किरोड़ी लाल जी की वजह से यह सरकार सत्ता में आई। आप लोग किरोड़ी लाल जी की वजह से सत्ता में आये। आज उनकी आपने क्या हालत कर दी? उनके काम नहीं हो रहे हैं। उनकी मुख्य मंत्री नहीं सुनता, मंत्री नहीं सुनता। उनको चीफ सेक्रेटरी से काम कराने के लिए जाना पड़ता है। चीफ सेक्रेटरी से उन्होंने कई बार बात की है। जिस तरह के हालात आपने प्रदेश में पैदा किये हैं, आदिवासियों की बात तो बहुत है इस देश के मूल निवासी जो कि आदिवासी हैं...(व्यवधान)

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): अनादिकाल से रहने वाले लोगों से आप बात करते हैं कि आपके डी.एन.ए. की जांच करायेंगे। क्या दुर्भाग्य की बात है। हमारे आदिवासी मंत्री भी यहां बैठे हैं। कभी इन्होंने एक शब्द इसके लिए नहीं कहा। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। राजस्थान की सारी जनता जानती है कि

(श्री घनश्याम)

आप लोग किस तरह का व्यवहार इस प्रदेश में लोगों से कर रहे हैं। मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हां, दीजिए जवाब।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): कांग्रेस ने कितना किया आदिवासियों के लिए, वह भी बता दो, पता लग जायेगा।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): कांग्रेस ने तो जो आदिवासियों के लिए किया है वह इतिहास जानता है और आगे भी कांग्रेस करती रहेगी, पर, मंत्री जी, आपका एक शब्द, आप स्विच आफ हो गये। आपका एक शब्द मुंह से नहीं निकला। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है और आप एरोप्लेन मोड पर बैठे रहते हैं। आपने आदिवासियों में जन्म लिया है तो आपको भी बोलना चाहिये।

श्री सभापति: विराजिए, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): और आपके बगल में बैठने वाले कहते हैं कि इनकी डी.एन.ए. जांच करायेंगे। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। माननीय सभापति, दो-एक पाइंट और हैं मेरे।

श्री सभापति: विराजिए, माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हुआ। अंकित नहीं होगा। श्री अमृतलाल मीणा।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। विराजें।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, बजट 2024-25 के बारे में बोल रहा हूं। मैं उस धरती से आता हूं जहां महाराणा प्रताप की तीसरी राजधानी रही है। मैं उस धरती से आता हूं जहां हाडी रानी ने अपना सर काटा था। मैं उस धरती से आता हूं जहां विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी को, दोनों उप मुख्य मंत्रियों को और पूरे मंत्रि मंडल को धन्यवाद देता हूं। सदन को भी धन्यवाद देता हूं। सबसे हाईएस्ट 14,100 करोड़ रुपये का पानी का जो दिया, वह जो मेवाड़ को माही और जाखम का पानी जयसमन्द में भरने के लिए और माही और सोम, कमला, अम्बा का पानी जयसमन्द में भर करके उदयपुर ले जाने वाली इस महत्वाकांक्षी योजना, जो हमारे असम के राज्यपाल महोदय महामहिम गुलाब चन्द जी कटारिया की वर्षों की योजना थी, मेवाड़ वालों की वर्षों की योजना थी, इस योजना को मुख्य मंत्री ने 14,100 करोड़ रुपये देकर के इस मेवाड़ के

(श्री अमृतलाल मीणा)

आदिवासी एरिये का विकास करने का, पानी की व्यवस्था करने का काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि आपके सामने इसी सलूम्बर नगर में भारी यातायात को सुगम करने के लिए दो-दो बाईपास देने का काम हमारी भजन लाल जी की सरकार, हमारी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने किया। विद्युत व्यवस्था के लिए 220 के.वी. जी.एस.एस. की स्वीकृति मिली है। सलूम्बर के दोनों बाईपास, स्टेट हाईवे 32 से लेकर के 53 तक और दूसरा देवगांव से लेकर के ईसरवास तक, दोनों बाईपास देने का काम किया।

सभापति महोदय, इसी तरह से मैं सदन को बताना चाहूंगा कि हमारे सलूम्बर से उप खण्ड कार्यालय सराड़ा को जोड़ने के लिए टू लेन से जोड़ने की रोड की मंजूरी दी। सलूम्बर से सेमारी उप खण्ड जोड़ने की मंजूरी मिली। तीन-तीन हाई लेवल की पुलिया देने का काम किया। आपका गींगला से सराड़ी पुलिया का और बड़ावली से निचलागुड़ा होता हुआ सेमारी का, और जो यह आदिवासी एरिया है, जहां बहुत बड़ी क्षरुवन नदी पड़ती है, उस एरिया में हाई लेवल का पुल दिया क्षरुवन नदी पर।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है चिकित्सा विभाग में दो सी.एच.सी. देने का काम किया। महामहिम राज्यपाल महोदय की घोषणा थी। उन्होंने शिलान्यास किया था। पचास करोड़ का एक बूलेश्वर एनिकट देने का काम भजन लाल जी की सरकार ने किया। मैं यह कहना चाहूंगा इस क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और नव निर्मित जिला अस्पताल सलूम्बर के भवन निर्माण की घोषणा के लिए काफी भारी मात्रा में पैसा दिया। बीस-बीस हैंडपम्प प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में दिये और दस-दस ट्यूबवैल प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में दिये। प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की मुख्य मंत्री से मेरी अपील है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि गरीब परिवार की महिलाओं को साढ़े चार सौ रुपये में गैस सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार ने किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने का काम किया। बुनियादी सुविधा पानी और बिजली की व्यवस्था करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। पीएम सूर्य घर बिजली योजना, प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम, जल जीवन मिशन, 220 के.वी. जी.एस.एस., विधान सभा क्षेत्र में पांच-पांच करोड़ की सड़कों का और तीन करोड़ अन्य आधारभूत संरचना के लिए, सड़कें सुधारने के लिए दिये हैं।

(श्री अमृतलाल मीणा)

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, गोविन्द गुरू जनजाति क्षेत्र विकास योजना, आर.ए.सी. की आदर्श पद्मिनी कालीबाई और अमृता देवी महिला पुलिस बटालियन की स्थापना करने की घोषणा की। मुख्य मंत्री पशु विकास कोष का गठन, मुख्य मंत्री मंगला पशु बीमा योजना, गरीब वंचित परिवारों के लिए डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी उत्थान योजना, राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन, आयुष्मान मॉडल, प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में सी.एच.सी. बनाने की घोषणा की। इसका मैं समर्थन करता हूं।

किसान परिवारों को आर्थिक शक्ति, 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान की जो शुरुआत की है, बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना हमारी सरकार ने की है। राजस्थान कृषि विकास योजना का गठन, वन धन कार्यक्रम की प्राथमिकता, प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना, इतना ही नहीं, सभापति जी, मेरी मांग है कि चिकित्सा के क्षेत्र में पूरा जनजाति एरिया है, टोड़ा में हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाए, ग्रामड़ापाल में खोला जाए। ईडाणाजी जहां हर शनिवार, रविवार को दस हजार से ऊपर जनता आती है, वहां पी.एच.सी. खोलने की मैं अपील कर रहा हूं सरकार से।

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): जयसमन्द और गींगला उप तहसील है। उनको तहसील का दर्जा दिया जाए। यह मेरी मांग है। इसके अलावा सुरखंड खेड़ा पी.एच.सी. 2017 में बनी। पांच साल कांग्रेस का राज चला गया, लेकिन बजट आबंटन नहीं किया गया है। उसका बजट आबंटन किया जाए। पुलिस चौकी झाड़ोल, सरनीवेन और बड़ावली और महिला थाना सलूम्बर में खोला जाए। यही मेरी मांग है। धन्यवाद। जय हिन्द। जय राजस्थान।

श्री सभापति: श्री छोटूसिंह जी।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे परिवर्तित बजट 2024-25 पर बोलने का अवसर दिया। उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

माननीय, परिवर्तित बजट में हमने पढ़ा, सुना इसमें सबका साथ, सबका विकास पर विशेष जोर दिया गया है। इस बजट में हर क्षेत्र, हर वर्ग के लिए देखने वाला बजट मिला है। मान्यवर, साथ ही किसान, बेरोजगार, युवा,

(श्री छोटूसिंह)

आमजन के लिए इसके साथ राजस्थान में अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को इस बजट में बहुत सारा लाभ देने के लिए प्रावधान किया है। इसके साथ ही पेयजल, बिजली, कृषि के क्षेत्र में विशेषकर पशुपालन के क्षेत्र में आपने इस बजट में बहुत सारी घोषणाएं की हैं। इसलिए आपको और आदरणीय सीएम. साहब को और वित्त मंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। इस बजट में देश और प्रदेश के विकास के लिए 'वोकल फोर लोकल' को निखारने की बात कही गई है। आने वाले पांच सालों में हम सभी श्रेष्ठ राजस्थान में रह कर नये राजस्थान को देखेंगे, इस प्रकार का बजट है। मान्यवर, किसान, युवा, महिला सभी वर्गों के लिए बेहतरीन जीवन होगा। विकसित राजस्थान की तरफ यह बढ़ेगा। भारतीय राजनीति में यह एक ऐतिहासिक वर्ष है, जिसमें आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी को लगातार तीसरी बार भारत को समृद्ध भारत, विकसित भारत बनाने के लिए जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया। माननीय सभापति महोदय, यह हमारे आदरणीय पीएम मोदी जी के विकास की सोच का फल है। आज विदेशी लोग भी भारत को सम्मान की नजरों के साथ देखते हैं, यह सिर्फ पीएम मोदी जी के आयामों का बजट है। आदरणीय मोदी जी की गारंटी पर देश को भरोसा है। इसलिए भारत की जनता ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान कर विश्वास जताया है। आने वाले समय में माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार सुशासन, जन कल्याण की धारणा पर विकसित राजस्थान की दिशा में आगे बढ़ेगी, ऐसी हमारी सोच है।

माननीय सभापति महोदय, इस वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ से ही लोक सभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद में भी 53 प्रतिशत से अधिक बजट घोषणाएं तथा संकल्प पत्र के 45 बिन्दुओं पर कार्यवाही की जा चुकी है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, एल.पी.जी. 450 में, किसान सम्मान निधि जो किसान के लिए जरूरी है, उसको 6,000 से 8,000 करना, विशेषकर आमजन के लिए पैट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करना, गेहूं की एम.एस.पी. पर 125 रुपये का विशेष बोनस देने जैसे बहुत बड़े काम हुए हैं। साथ में पेपर लीक जैसी घटनाओं में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करके 100 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार करना, यह बहुत बड़ा काम हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है।

(श्री छोटूसिंह)

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी एवं वित्त मंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी को धन्यवाद देता हूं कि इस बजट भाषण में आपने मेरे विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के लिए बहुत सारी घोषणाएं की हैं। विशेषकर देखा जाए तो मेरा जिला एक सीमांत जिला है, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए, सुंदरता की दृष्टि से देखा जाए तो मेरा शहर सोने जैसा गोल्डन शहर है। पर्यटन की दृष्टि से हमारा एक छोटा-सा गांव खाभा है, जो पालीवालों की बस्ती का, ब्राह्मण लोगों का था, उसमें पार्क बनवाना, ओपन डोर म्यूजियम बनाना, इसके साथ ही पर्यटन विकास बोर्ड का गठन करना, यह हमारे लिए एवं पूरे प्रदेश के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया, यह स्वागत योग्य है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा क्षेत्र बहुत लम्बा है। अगर किसी गांव से दूसरे गांव जाना हो तो करीब 30-40 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। सिप्तिनयाली गांव में केवल उप तहसील थी, उसको तहसील बनाना हमारे लिए बहुत भाग्य का काम है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस प्रकार का काम किया है। मेरे लिए खुशी की बात है कि आज वह जैसलमेर नहीं है, आज वहां अपार जीरा पैदा होता है। हम सोचते थे कि जीरा लेकर गुजरात जाना पड़ेगा और यही सोच थी कि गुजरात जाकर बेचेंगे, पता नहीं क्या भाव होगा, लेकिन हमारी सरकार ने इस ओर सोचा, माननीय मुख्य मंत्री जी ने एवं माननीय वित्त मंत्री जी ने हमारे जैसलमेर में कृषि के लिए जीरा मण्डी की घोषणा की, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, युवा विकास के लिए पॉलिटेक्निक कालेज है, जिसमें हर बच्चा हुनर सीखता है। उसमें कुछ कमियां हैं। कुछ विषय पूर्ववर्ती सरकार के समय नहीं थे, लेकिन नवीन संकाय खोलने के साथ ही सीटों की वृद्धि करना, बहुत अच्छा काम किया है। एक और बहुत अच्छा काम किया है कि नशा मुक्ति के लिए 25 बेड की क्षमता का केन्द्र बनाना हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। इसके लिए भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ा क्षेत्र है। वहां कई केवी. की लाइटें पैदा होती हैं। हम प्रदेश की भी पूर्ति करेंगे और राष्ट्र की भी पूर्ति करेंगे। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आपने 132 के.वी. की घोषणा डांगरी में की है। वह स्वागत योग्य है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कई कम्पनियां वहां आ गई

(श्री छोटूसिंह)

हैं और वे कम्पनियां केवल इस हिसाब से बैठी हैं कि किसी प्रकार से इस जमीन को हड़पा जाए। हमारे पुरखों ने बहुत मेहनत, मजदूरी करके उस जमीन को संचय करके रखा था। ऐसी सोच नहीं थी कि इस जमीन का कोई दूसरा मालिक था। हमने तो यही सोचा था कि यह लैंड हमारी है और आने वाले समय में हमारे बच्चों की होगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए, विराजिए। श्री अरूण चौधरी।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): आदरणीय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसके लिए एक मिनट लूंगा। आज हमारे बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम चाहते हैं कि उस जमीन पर किसी भी प्रकार का उद्योग खोला जाए, सबसे पहली प्राथमिकता हमारे जिले के निवासियों को दी जाए, ताकि उनको रोजगार मिल सके। यह मेरे लिए और प्रदेश के लिए मुख्य काम है।

श्री सभापति: प्लीज, विराजिए, विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री अरूण चौधरी। विराजिए। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अरूण चौधरी (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे परिवर्तित बजट.

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): 000

श्री सभापति: प्लीज माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, प्लीज, प्लीज। अंकित नहीं हो रहा है। आप बोलें, आपका समय प्रारम्भ हो चुका है।

श्री अरूण चौधरी (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, सर्व प्रथम मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे परिवर्तित बजट 2024-25 पर बोलने का मौका दिया। महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा एवं हमारी उप मुख्य मंत्री दिया कुमारी जी, प्रेम चन्द बैरवा की ट्रिपल इंजन की सरकार को, जिन्होंने राजस्थान को पुन: अग्रणी प्रदेश बनाने के लिए एक रोड मैप इस विधान सभा में रखा है। यह बजट 10 संकल्पों के साथ जिस प्रकार रखा गया है, मुझे पूरा विश्वास है कि यह बजट हमारे इस प्रदेश की दिशा और दशा तय करेगा। जिस प्रकार इस बजट की शुरुआत में रचनाकार निदा फाजली की पंक्तियों को याद किया है,

(श्री अरूण चौधरी)

"सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो।

सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो।"

इस भावना को लेकर चले हैं। मुझे पूरा विश्वास है यह बजट हमारे राजस्थान प्रदेश को वापस अग्रणी प्रदेश बनाने में जरूर मददगार साबित होगा।

मैं मेरे विपक्षी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी स्कूल में जब भर्ती होती है तो तीन टेस्ट, एक अर्ध वार्षिक और फिर फाइनल परीक्षा होती है। यह बजट प्रथम परीक्षा के बराबर है, जिसका मूल्यांकन इस बजट के एक साल बाद होगा। जिस प्रकार आप अभी से चिल्लाते हो कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है, यह गलती किसकी है? स्कूलों में अध्यापक नहीं है, यह गलती किसकी है? यह गलती सिर्फ आपकी है, क्योंकि आपने पांच साल सिर्फ होटलों में राज किया है और इस कारण यह स्थिति पूरे प्रदेश की बनी हुई है। पूरे प्रदेश ने इस गर्मी को झेला है, बिजली की मार के कारण त्रासदी के रूप में यह गर्मी सभी के लिए हुई है। (व्यवधान)

श्री सभापति: बैठे-बैठे कोई नहीं बोलेगा। शांत रहिए।

श्री अरूण चौधरी (पचपदरा): मान्यवर, इस बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए जो घोषणा हुई है, उसके लिए मैं हमारे मुख्य मंत्री जी एवं हमारे दोनों उप मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने रिफाइनरी के आस-पास के क्षेत्र में पैट्रोलियम हब के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। इसके अलावा देव भूमि रणछोड़राय मन्दिर के जीर्णोद्धार के लिए भी जो घोषणा की है। उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। 132 के.वी. के दो जी.एस.एस. दिये, उसके लिए भी धन्यवाद।

सभापति महोदय, मैं कुछ मांग आपके मार्फत सरकार से करता हूं। मेरे क्षेत्र में ग्राम पंचायत असाड़ा और ग्राम पंचायत पारलू की सी.एच.सी. को क्रमोन्नत करावें और आसोतरा, कालूडी देरिया, मूल की ढाणी, ग्वालनाडा, नेवरी कुडी एवं अन्य कई ग्राम पंचायतों में नई पी.एच.सी. खोलें। हमारा जिला सुदूर है और बोर्डर से सटा हुआ है। हमेशा जब बजट होता है तो जयपुर से स्टार्ट करते हैं तो बड़मेर जाते-जाते तो खतम हो जाता है। बाड़मेर और बालोतरा एक सुदूर शहर है। इसके अलावा चांदेसरा एवं थोब ग्राम पंचायत में पी.एच.सी. स्वीकृत है, परन्तु अभी तक भवन निर्माण नहीं हुआ है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसके लिए भी बजट की घोषणा करें। हमारे खेल मंत्री

(श्री अरूण चौधरी)

जी भी बैठे हैं, इनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि हमारे बच्चों का स्टेडियम जो आधा-अधूरा पड़ा है, उसको भी पूरा कराने के लिए मदद करें।

जो बालोतरा शहर है, वह वस्त्र उद्योग के लिए काफी प्रसिद्ध है। इस वस्त्र उद्योग के अन्दर बिठूजा और बालोतरा में नये ट्रीटमेंट प्लांट की घोषणा करायें। इसके अलावा जोधपुर, पाली, बाड़मेर के प्रदूषित पानी को एक नाले के द्वारा कच्छ की खाड़ी में डाले जाने की कोई योजना बनाकर मदद करें। कई विद्यालयों को क्रमोन्नत एवं नये विषय खुलवाने की मदद करें। बालोतरा में रोडवेज डिपो खोलने एवं पचपदरा बस स्टैण्ड आधुनिकीकरण कराने की भी घोषणा करायें। बालोतरा, समदड़ी, पाली सड़क मार्ग का भी पुनर्निर्माण। पादरू, फाटा से जागसा रोड क्षतिग्रस्त है, इस रोड को भी स्टेट हाईवे बनाकर इसका पुनर्निर्माण कराया जाए। इसके अलावा भी कई रोड हैं। रोड़वाखुर्द से गंगावास, कोरणा, जास्ती, आगोलाई और बिपरजॉय में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए आपने जो पैसा दिया है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यह काम अगर हमारे विपक्ष के भाई लोग पहले करते तो शायद इनको उस तरफ बैठने की यह नौबत नहीं आती।

इसके अलावा हमारे स्वायत्त शासन मंत्री बैठे हैं। मैं उनसे भी एक निवेदन करता हूं कि हमारे नगर परिषद् की वित्तीय स्थिति काफी खराब है। वहां की सड़कों को बनाने के लिए आप अलग से पैसा दिलाने की मदद करें। जसौल को पूर्ण तहसील बनाने की घोषणा करायें। सबसे मुख्य बात है कि हमारे प्रवासी भाई जो राजस्थान से बाहर रहते हैं, उनके लिए प्रदेश में कोई विशेष छूट देकर उनको वापस राजस्थान में कैसे बसाया जाए, उनको यहां पर जमीन और उद्योग के टैक्स में छूट देकर राजस्थान में बसाएं, जिससे कि राजस्थान के अप्रवासी हैं, उनको राजस्थान में आने में बहुत ही सहूलियत रहेगी।

मुझे पता है कि जो पिछली सरकार थी, जो अपने आपको जन कल्याणकारी सरकार कहती थी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जन कल्याणकारी नहीं, वह सिर्फ बजरी माफिया, भूमाफिया, नकलमाफिया, वाहन चोर माफिया, पानी चोर माफिया, बिजली चोर माफिया और ठेकेदार माफिया बनकर रह गयी। इसके अलावा मैं धन्यवाद देता हूं कि कल हमारे विपक्षी सदस्यगण भीमराज जी भाटी साहब और चौमूं की हमारी सदस्या बैठी हैं, रतन देवासी जी को भी, जिन्होंने इस सरकार के बजट के ऊपर तारीफ की। मैं उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। अंत में मैं अपनी इतनी-सी बात

(श्री अरूण चौधरी)

कहूंगा कि यह सरकार 24X7 घंटे काम कर रही है। इस सरकार का एक ही ध्येय है, जैसा कि हमारी उप मुख्य मंत्री दिया कुमारी जी ने अपने इन शब्दों के द्वारा अपनी बात कही। संत रैदास जी की पंक्तियों को याद किया।

"सौ बरस लौं जगत मेहिं, जीवत रहि करू काम।

रैदास करम ही धर्म हैं, करम करहु निहकाम।।"

अत: जिस सरकार का कर्म ही मनुष्य धर्म का कार्य करने का हो, उस सरकार को कोई विपक्ष डरा नहीं सकता। आपने जो मुझे मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री मुकेश भाकर।

श्री मुकेश भाकर (लाडनूं): माननीय सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने तीन घंटे बजट पढ़ा और हर कोई सदस्य इस उम्मीद में बैठा था कि अब कुछ न कुछ उनके लिए घोषणा होगी, उनके क्षेत्र को मिलेगा, इस राजस्थान को नया कुछ मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से भा.ज.पा. की सरकारें हमेशा करती आयी हैं, पैसा है नहीं और बजट में किस तरह से राजस्थान की जनता को गुमराह करें, तीन घंटे पढ़ा, उसमें से सिर्फ यही समझ में आया कि एक विधान सभा को 20 हैंडपम्प मिलेंगे, बाकी सब कुछ गोल कर दिया, जो कि हमेशा करती रही है। वित्त मंत्री बजट पढ़ रही थीं। इससे पहले सदस्यों ने कहा कि इनकी यशस्वी पूर्व मुख्य मंत्री, इस राजस्थान की पहली महिला मुख्य मंत्री, जिनका डर ही, जुबान से कुछ सदस्य नाम ले रहे थे, वे सदन में मौजूद नहीं थीं, इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। मेरे से पूर्व सदस्य ने कहा, कबीर का एक दोहा पढ़ा कि दो पाटों के बीच में जो आ गया, वह बचा नहीं, लेकिन आपके पाट तो तीन-तीन हो रहे हैं, आप जरूर बचकर रहना। किसी पाट के नीचे आप लोग नहीं आ जाएं।

सभापति महोदय, इस बजट में सिर्फ मोदी जी और भजन लाल जी, इन दो शब्दों के अलावा, मुझे लगता है कि कुछ भी इस राजस्थान की जनता के लिए नहीं था। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा को लेकर बजट, जो कि इस राजस्थान के लिए हमेशा से एक अच्छी मिसाल पेश हुआ, उस बजट में शिक्षा का नाम ही हटा दिया गया। उसको युवा विकास एवं कल्याण के साथ शामिल कर दिया गया। आप लोगों ने एक लाख नौकरियों की घोषणा की। उसमें कोई वर्गीकरण इस राजस्थान की जनता के सामने, इस सदन में आपने नहीं रखा। आपने यह नहीं बताया कि इन एक लाख नौकरियों में आप संविदा

(श्री मुकेश भाकर)

में देंगे, नरेगा में लगायेंगे, शिक्षा विभाग में लगायेंगे, चिकित्सा में लगायेंगे। यह उसी तरीके की घोषणा है, जैसी घोषणा 15 लाख रुपये की मोदी जी ने लोगों के लिए की थी। इस तरह का चाल-चरित्र भारतीय जनता पार्टी का रहा है कि जनता को गुमराह कर दो। एक लाख नौकरियां देंगे, उसका वर्गीकरण भी तो बताते कि इस विभाग में देंगे, अब देंगे, कब देंगे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस राजस्थान की जनता के लिए एक भीख मांगना चाहूंगा कि ऐसे शिक्षा मंत्री जी, जिनके बनने के बाद कैसे बयान आ रहे हैं? कभी कह रहे हैं कि उलटा लटका दूंगा, कभी डी.एन.ए. टेस्ट करा रहे हैं, कभी किसी के पिताजी का पता मांग रहे हैं और अकबर का नाना कौन था, ऐसे-ऐसे शब्द उन्होंने राजस्थान की जनता के सामने रखे हैं। इस राजस्थान के बच्चों के भविष्य को आप सुरक्षित करें। आप मदन दिलावर जी के लिए अलग डिपार्टमेंट बना दें, ताकि वे बयान देते रहें और आप उनका पक्ष लेते रहें। जिस तरीके के आदिवासियों के लिए उनके शब्द थे, माननीय सभापति महोदय, इससे पहले कोई भी शिक्षा मंत्री इस तरह के बयान नहीं देकर गया। (व्यवधान) आ रहा हूं।

सभापति महोदय, इससे पहले सदस्य बोल रहे थे और मुख्य मंत्री जी ने भी कहा कि हमने गैंगस्टर एक्ट बना दिया, टॉस्क फोर्स बना दी, हमने 100 लोग गिरफ्तार कर लिए। सभापति महोदय, अब तक मछलियां पकड़ी हैं। हम यह कह रहे हैं कि हम भी शामिल हैं तो गिरफ्तार करो। सिर्फ नारों और भाषणों से, जिस वजह से आप लोग सत्ता में आये हैं, जो पेपर लीक के मामले में आप लोग मुद्दा बनाकर सत्ता में आये हैं। आपने प्रदीप पाराशर को पकड़ा है, लेकिन उसको नौकरी पर, उस जगह ड्यूटी देने वाला कौन था? मुझे पता है कि वहां तक आपकी जांच नहीं जायेगी, क्योंकि आर.एल.डी. केन्द्र में आपके साथ सत्ता में भागीदार है। सभापति महोदय, आप लोग जो वादे करके आये हैं, जो नारे आप लोग देकर आये हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी काम करे।

सभापति महोदय, इस बजट को वित्त मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी खड़े होकर राजस्थान की जनता से माफी मांगकर शुरू करते तो मैं समझता हूं कि वे न्याय इस जनता के साथ करते। सभापति महोदय, 50 साल में पहली बार जो बिजली की स्थिति रही, गांव में 20-20 घंटे कटौती और 4 घंटे भी जो बिजली आ रही थी, उसमें वोल्टेज नहीं था। जिस तरीके की व्यवस्था

(श्री मुकेश भाकर)

आपने दी, बिजली में आप पूर्णतया फेल। किसी सरकार के खिलाफ आन्दोलन बनने में साल-दो साल लगते हैं, पहले महीने में ही लोग आपके खिलाफ आ गये। पानी-बिजली को लेकर आप लोगों की जो स्थिति रही, राजस्थान की जनता ने आपको लोक सभा में उसका उत्तर दिया। अभी एक सदस्य संविधान को लेकर खड़े हो रहे थे। जो लोग 400 पार का नारा देकर नया संविधान बनाना चाहते थे, मोदी जी के नाम का संविधान बनाना चाहते थे, उन लोगों को अम्बेडकर जी की याद आयी। यह मैं समझता हूं कि इस जनता ने करके दिखाया। 400 पार, नया संविधान, जो नारा दे रहे थे, उनके कान के पास से निकली है, केवल पार-पार हुए हैं, 400 पार नहीं हो पाये।

सभापति महोदय, इस देश के किसान को, गरीब को, दलित को, अल्पसंख्यक को, जो भा.ज.पा. की डिक्शनरी में नहीं थे, उनको बार-बार याद कर रहे हैं। दिया कुमारी जी ने इस बजट में कम से कम बाबा साहब अम्बेडकर का नाम तो लिया। इससे पहले तो आप लोग भूल ही गये थे कि बाबा साहब ने तो संविधान बनाया ही नहीं, मोदी जी ने संविधान बनाया है। यह स्थिति आप लोगों की है। जे.जे.एम. जो योजना है, हर घर नल।

श्री सभापति: समाप्त करें, आपका समय पूरा हो गया।

श्री मुकेश भाकर (लाडनूं): समय नहीं हुआ, दो मिनट बच रहे हैं। मैं लगाकर पढ़ रहा हूं। दो मिनट बच रहे हैं, पांच मिनट ही हुए हैं।

श्री सभापति: श्री उदय लाल डांगी। अंकित नहीं होगा।

श्री मुकेश भाकर (लाडनूं): 000

श्री सभापति: श्री उदयलाल डांगी। अंकित नहीं होगा। श्री उदयलाल डांगी। श्री गोपीचन्द मीणा। विराजिए, माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा।

श्री मुकेश भाकर (लाडनूं): 000

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, ... (व्यवधान) मुझको बजट 2024-25 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: ऐसे नहीं, सबको सात मिनट मिल रहे हैं। मैं सबको सात मिनट दे रहा हूं, इनको भी और इनको भी। यहां बोलने वाले 28 हैं, इधर बोलने वाले 13 हैं। आप विराजिए, माननीय सदस्य। ऐसे नहीं होता है। आप बोलिए, आपका समय प्रारम्भ हो गया है।

श्री मुकेश भाकर (लाडनूं): 000

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, मुझको बजट 2024-25 पर बोलने का आपने अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी के नेतृत्व में, राजस्थान प्रदेश की उप मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री आदरणीया दिया कुमारी जी के नेतृत्व में 10 जुलाई, 2024 को जो बजट राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किया, उसकी चहुंमुखी बड़ी भारी प्रशंसा हो रही है। प्रदेश का हर एक तबका बजट से संतुष्ट होकर प्रदेश की सरकार को कोटि-कोटि धन्यवाद दे रहा है।

सदन कूप में

(माननीय सदस्य श्री मुकेश भाकर द्वारा स्लोगन लिखी टीशर्ट के साथ सदन कूप में आगमन)

आदरणीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं मेरे भीलवाड़ा जिला एवं शाहपुरा, मेवाड़ क्षेत्र के बजट के लिए जो सौग़ातें दी हैं, उनके लिए मैं हमारे मेवाड़ व जहाजपुर की जनता की ओर से धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं। कांग्रेस सरकार ने आरम्भ से ही भीलवाड़ा और मेवाड़ क्षेत्र की उपेक्षा की। बजट में कुछ भी नहीं दिया गया। कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने हमारे मेवाड़ और भीलवाड़ा के साथ सौतेला व्यवहार किया। यशस्वी मुख्य मंत्री और आदरणीय दिया कुमारी जी ने पिछली सरकार की कमियों की पूर्ति करके, हमारी सरकार ने बजट में भीलवाड़ा जिले को और मेवाड़ को दिया है। भीलवाड़ा जिले में 150 करोड़ रुपये ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, 193 किलोमीटर लम्बाई के जयपुर से भीलवाड़ा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस हाईवे के लिए, मानसरोवर झील, भीलवाड़ा के लिए 12 करोड़ रुपये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भीलवाड़ा नगर परिषद् को नगर निगम बनाये जाने की घोषणा, जो वर्षों पुरानी पुरजोर मांग रही, जिला भीलवाड़ा को वह सौगात मिली।

वस्त्रनगरी भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क के लिए यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल शर्मा जी के द्वारा, आदरणीय दिया कुमारी जी के द्वारा बजट में घोषणा की गयी, इसके लिए मैं हमारे भीलवाड़ा और मेवाड़ की ओर से धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। टेक्सटाइल पार्क से प्रदेश की जीडी.पी. बढ़ने में विशेष योगदान साबित होगा। रोजगार के नये आयाम स्थापित होंगे।

मेरे विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के लिए की गयी बजट घोषणाओं से क्षेत्र में पहली बार बजट प्रसारण के साथ ही दीपावली की तरह पटाखे चलाये

(श्री गोपीचन्द मीणा)

गये, मिठाई बांटी गयी, क्षेत्र की जनता खुश है। यह सब हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी ओर यशस्वी मुख्य मंत्री श्रीमान भजन लाल जी शर्मा और हमारी वित्त मंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के कारण सम्भव हुआ। मेरे क्षेत्र जहाजपुर को बजट में वह सब दिया गया है, जिसकी मेरे क्षेत्र की जनता लम्बे समय से पुरजोर मांग करती आ रही थी। जहाजपुर में कन्या महाविद्यालय स्वीकृत किया गया। जहाजपुर में उप जिला अस्पताल क्रमोन्नत किया गया। जहाजपुर में नगरपालिका क्षेत्र में फल और सब्जी मंडी किसानों के लिए दी गयी। हाई लेवल ब्रिज, नौचोक से चावण्डिया चौराहे तक पुलिया निर्माण, बांदुका जीर्णोद्धार, अमरगढ़ में सब सेन्टर पी.एच.सी. में क्रमोन्नत, जहाजपुर में रीको इंडस्ट्रियल एरिया, ऐसे ऐतिहासिक कार्य किये गये हैं। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी का ओर वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। यह बजट शॉर्ट टर्म बजट नहीं है। हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के आगामी 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार करने हेतु विकसित राजस्थान प्रदेश की परिकल्पना सोच-विचार के खाके को अमलीजामा पहनाने के लिए रूट लेवल पर बहुआयामी कार्यों की नींव डालने का कार्य इस बजट में किया गया है।

हमारी सरकार घोषणाओं को धरातल पर उतारने का विश्वास रखती है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में जो घोषणाएं कीं, वे थोथी घोषणाएं हुईं। उन्होंने बजट में प्रावधान कर दिया, लेकिन एक ईंट तक नहीं लगी। दो साल, चार साल तक काम चालू नहीं हुए लेकिन हमारी सरकार शिलान्यास भी करेगी और लोकार्पण भी इसी समय होगा। विधान सभा के सदस्यगण इस बात से भलीभांति परिचित हैं।

बजट में ग्रामीण एवं शहरी विकास को बराबर महत्व दिया गया है। बजट में पानी, बिजली, सड़क के बुनियादी विकास को ध्यान में रखकर प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिए बिना भेदभाव के बजट घोषणाएं की गयीं। बजट में किसान, मजदूर, माता, बहनों, गृहिणियों, प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा वर्ग के छात्र-छात्राओं, बेरोजगार, युवा वर्ग, व्यापारी, आर्थिक रूप से पिछड़े, अनुसूचित जाति-जनजाति, ओ.बी.सी. वर्ग, कर्मचारी-अधिकारी वर्ग, पेंशनर्स आदि सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ डिमांड्स हैं, वे रखना चाहता हूं। मेरे जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में

(श्री गोपीचन्द मीणा)

कोटड़ी उप खण्ड मुख्यालय में राजकीय महाविद्यालय खोलने की मांग रखता हूं। हमारे सवाईपुर में नेशनल हाईवे 758 निकला हुआ है, आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं तो वहां पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने की मैं मांग करता हूं। कोटड़ी चारभुजानाथ नगर में आये दिन श्रद्धालुभक्तजन आते रहते हैं, वहां बाईपास रोड, रिंग रोड स्वीकृत करने की मैं मांग करता हूं। जहाजपुर में ए.डी.जे. कोर्ट खोलने की मैं मांग करता हूं। पारोली उप तहसील में ग्राम खजूरी उप तहसील मुख्यालय पर खेल स्टेडियम बनाये जाने की मांग करता हूं। घाटारणी माताजी के मन्दिर से ऊपर तक सड़क निर्माण, चौड़ाईकरण व रोपवे का निर्माण कराने की मैं मांग करता हूं। हमारे लुहारीकलां सैनिकों का गांव है, 15 हजार की आबादी का गांव है, उप तहसील खोलने की मांग करता हूं। जहाजपुर कृषि गौण मंडी को स्वतंत्र मंडी बनाने की मैं मांग करता हूं। हमारे क्षेत्र में कोटड़ी कृषि मंडी, जो भीलवाड़ा की गौण मंडी है, उसको विकसित करने की मांग करता हूं। जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कों को एम.डी.आर. घोषित करने की मांग करता हूं। सीमा बूंदी जिले से देवाखेड़ा से लुहारीकलां, मेड़ीया शकरगढ़, बांकराखजूरी, आमल्दा पारोली कोटाज तक जोड़ने वाली सड़क को मैं एम.डी.आर. घोषित करने की मांग करता हूं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में मेज नदी है। वहां ठेलेश्वर महादेव के पास में हजारों बीघा जमीन की सिंचाई के लिए मैं बांध बनाने की मांग करता हूं। जो मेज नदी का पानी है, वह गुढ़ा बांध में जाकर चम्बल नदी में चला जाता है। उस अतिरिक्त पानी को रोकने के लिए एक बांध निर्माण करने की मांग करता हूं। आपने मेरे को बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री शत्रुघन गौतम।

श्री शत्रुघन गौतम (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपको ह्रदय के अंतःकरण से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत-बहुत साधुवाद देता हूं। 2018 से 2023 की सरकार, राजस्थान की सरकार सबने देखी है। उस सरकार में आमजन का जीना दुर्भर हो गया था। चाहे वह नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो और दलितों पर किसी भी तरह से अत्याचार हुआ हो, लेकिन 2023 में राजस्थान की जनता ने नरेन्द्र मोदी नाम के व्यक्ति की गारंटी पर भरोसा करते हुए राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार बनायी। सरकार बनने के बाद

(श्री शत्रुघन गौतम)

जिस तरह से राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री, एक किसान का बेटा, एक गरीब का बेटा, एक संगठन की संरचना करने वाला व्यक्ति, जिसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं राजस्थान का प्रतिनिधित्व करूंगा, राजस्थान की सरकार का नेतृत्व करूंगा, ऐसे व्यक्ति को राजस्थान का मुख्य मंत्री बनाने का अवसर, राजस्थान की जनता ने और भारतीय जनता पार्टी के 115 विधायकों ने दिया है।

सभापति महोदय, आत्मचिंतन, विपक्ष के लोग आते हैं, इन्होंने भी कई बातें कीं, आत्मचिंतन करना चाहिए कि सन् 1998 में कितने लोगों को अनदेखी करके, वरिष्ठ लोगों की अनदेखी करके श्री अशोक गहलोत जी को राजस्थान का मुख्य मंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। क्या रिजल्ट आया लोक कल्याण का? पांच साल के बाद मात्र 56 विधायक आये, 100 कम हो गये। बहुत से विधायक कह रहे थे कि वसुन्धरा जी सदन में नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ...(व्यवधान) बहुत आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। विराजिए। आप सुनने की क्षमता रखिए।

2003 से 2008 तक राजस्थान में एकदम आकर सिंहासन पर विराजते थे। पांच साल तक उनको संगठन के रूप में काम में लिया और इनके जो जादूगर जी थे, वे कहीं नहीं दिखे और जादूगर जी फिर टपक कर राजस्थान के मुख्य मंत्री बन गये। 2008 से 2013 तक राजस्थान की रूह कांप गयी। इनको आत्म चिंतन करना चाहिए कि 1998 के बाद ये 100 की संख्या पार नहीं कर पाये हैं, फिर भी राजस्थान में नियम और मर्यादाओं की बात करते हैं। 2013 में मात्र 21 सदस्य आये। 2013 से 2018 में भारतीय जनता पार्टी की लोक कल्याणकारी सरकार ने काम किये।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं और सड़क के ऊपर अगर बात करें तो देश के पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ग्रामीण सड़क योजना हो, चाहे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो, दिल्ली-मुम्बई-अहमदाबाद, बम्बई से चेन्नई और चेन्नई से कोलकत्ता और कोलकत्ता से दिल्ली को स्वर्णिम चतुर्भुज से जोड़ने का काम किया है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। (व्यवधान)

(समय: 17.00 बजे)

राजस्थान पर भी बात कर रहा हूं। 2018 से 2023 तक आपकी सरकार थी। सड़कों के अन्दर मात्र 7 हजार करोड़ का वित्तीय बजट स्वीकृत

(श्री शत्रुघन गौतम)

करते हुए चुनावी वर्ष में 17 हजार करोड़ के टेंडर निकालने का काम आपकी सरकार ने किया। आपकी सरकार का एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी जिसको अच्छी तरह से जानते हैं, अपने इलाक़े में जो रिंग रोड थी उसको बदलकर, 30 बीघा जमीन खरीदकर अलाइनमेंट चेंज करने का काम आपकी सरकार के टाइम किया गया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा में इनकी पूरी सरकार गई, सरकार ने कहा कि कोटा की परियोजनाओं का मुख्य मंत्री जी उद्घाटन करेंगे। पूरे कैबिनेट के मंत्री चले गए और एक व्यक्ति ने एक प्रेस कान्फ्रेंस लेते हुए एक बात कही, जिसमें इनके मुख्य मंत्री जयपुर से कोटा नहीं जा पाये और उद्घाटन के सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिये। आज सदन में धारीवाल साहब नहीं हैं। फिर यहां से पांच दिन बाद गये। (व्यवधान) बता रहा हूं।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री शत्रुघन गौतम (केकड़ी): सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए ...(व्यवधान) आप विराजिए। सड़क पर अगर काम किया है तो राजस्थान की सरकार ने ...(व्यवधान) सभापति महोदय, इनकी सुनने की क्षमता नहीं है ...(व्यवधान) आप हमें संरक्षण प्रदान करें, जो ये सुन तो सकें। ये इस तरह से बात कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, सड़कों का पांच साल का रोड मैप बनाकर राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल जी ने राजस्थान की जनता को बता दिया है कि आने वाले पांच सालों में क्या करेंगे ...(व्यवधान) ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, कांग्रेस के नेता कभी सोच नहीं सकते कि यह कर सकते हैं। (व्यवधान) हमसे ही सीखकर आये हो, हमारी पार्टी की रीति-नीति में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया व्यवधान न डालें।

श्री शत्रुघन गौतम (केकड़ी): सड़कों के अन्दर 53 हजार किलोमीटर की 60 हजार करोड़ से अधिक 157 सड़कों की डी.पी.आर. बनाकर, पांच साल में क्रमबद्ध तरीके से सड़कों का निर्माण करने का काम हाथ में लिया है। (व्यवधान)

बजट में आप लोगों ने ज़िले बनाये थे, जब आपका 2023 का आखिरी बजट था। हिम्मत थी राजस्थान के मुख्य मंत्री की तो पहले बजट में जिला बनाते और फिर इनको एग्जीक्युट करते तो आज उधर नहीं इधर बैठते।

(श्री शत्रुघन गौतम)

(व्यवधान) मैं राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी जी को धन्यवाद दूंगा कि 157 सड़कों का सुदृढ़ीकरण करके स्टेट रोड को किस मद से करेंगे, इनको स्टेट हाईवे का दर्जा देने का काम किया है। 12 बाईपास सड़कें, 31 आर.ओ.बी., 16 शहरी क्षेत्र की सड़कें, 11 हाई लेवल ब्रिज, पहली बार प्रदेश के अन्दर पांच ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वेज को चिह्नित करके उसकी 30 करोड़ रुपये की डी.पी.आर.। डी.पी.आर. का टेंडर कर दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य बिजली पर बोल रहे थे। (व्यवधान) जूली साहब विराजो, अभी बहुत सारी बातें कहूंगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): बजट ही पास नहीं हुआ, टेंडर कहां से पास हो गया?

श्री शत्रुघन गौतम (केकड़ी): आप विराजिए। (व्यवधान)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): बजट ही पास नहीं हुआ, टेंडर कहां से हो गया? (व्यवधान)

श्री शत्रुघन गौतम (केकड़ी): बजट पर ही बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सिम्पल सी बात है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपकी बारी आएगी, उस समय आप बात को रख देना, अभी तो आप विराजें। (व्यवधान)

श्री शत्रुघन गौतम (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, बिजली पर बोल रहे थे...(व्यवधान)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): बजट पास ही नहीं हुआ है, बजट पास होगा, उसके बाद ही तो टेंडर होगा, उसके पहले कैसे करा दोगे, आप बताओ तो सही। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): इनका वक्तव्य पूरा हो जाने दो ...(व्यवधान) इनका वक्तव्य हो जाए, आपका अधिकार है कहने का। इनकी बात पूरी होने के बाद आप कह सकते हैं।

श्री सभापति: सदस्यों से निवेदन है कोई टोका-टाकी नहीं करे ...(व्यवधान) जब आपकी बारी आये तो आप उस विषय को बता दें, लेकिन बीच में टोका-टाकी न करें। बोलिए।

श्री शत्रुघन गौतम (केकड़ी): 1998 में राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था। इनकी सरकार बनी, पांच कम्पनियां बनाई गईं, उत्पादन निगम, विद्युत

(श्री शत्रुघन गौतम)

वितरण निगम, पांच साल में जब इनकी सरकार चली गई तो राजस्थान को कितने करोड़ का घाटा मिला? 2003 से 2008 तक वसुन्धरा जी की सरकार ने उस घाटे को पूरा करते हुए, 2008 में बहुत कम रेशो में वह घाटा था, 2008 से 2013 आया तो 75 हजार करोड़ का घाटा। जब 2013 में वसुन्धरा जी बनीं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: श्री गोविन्द प्रसाद।

श्री शत्रुघन गौतम (केकड़ी): 80 हजार करोड़ का कर्जा राजस्थान की सरकार ने वहन किया। फिर आते ही एक लाख करोड़ से अधिक का कर्जा। (व्यवधान) इनकी पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति के दामाद राजस्थान के सी.एम.डी. थे और अडानी का 1,500 करोड़ का पेमेंट इन्होंने किया।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री शत्रुघन गौतम (केकड़ी): उस अधिकारी का ट्रान्सफर इन्होंने पांच महीने के अन्दर किया। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। श्री गोविन्द प्रसाद।

श्री शत्रुघन गौतम (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। श्री गोविन्द प्रसाद।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): एक इधर से बुला लो।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन है, दो के लोगों को बुला रहे हो, बीच में हमको भी याद करो चार-चार इनके बुलाकर, नहीं तो हमारा नम्बर कब आएगा? (व्यवधान)

श्री सभापति: वही मैं निवेदन कर रहा हूं, वक्ता इतने हैं।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): दो के बाद, तीन के बाद तो हमारा नम्बर आए ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, पक्ष के 28 वक्ता हैं, विपक्ष के 14 वक्ता हैं और आप लोग पांच हो, वैसी ही व्यवस्था करके बुला रहे हैं।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ये ही बोलते रहेंगे, हमारा नम्बर कब आएगा? (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री गोविन्द प्रसाद।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): माननीय सभापति महोदय, मैं दो

(श्री गोविन्द प्रसाद)

मिनट एक्स्ट्रा टाइम लेना चाह रहा हूं। पक्ष और विपक्ष, आप सब यहां मौजूद हैं। यह सदन वह सदन है जिसमें जनता आपको चुनकर इस सदन में भेजती है। हमारा इस सदन की गरिमा बनाए रखने का पूरा दायित्व है। दायित्व के अनुसार, मैं सभी से यही निवेदन कर रहा हूं, पक्ष हो या विपक्ष हो, अपनी बात रखने का अधिकार है। (व्यवधान) इसके तहत मैं आप सभी से यही निवेदन कर रहा हूं कि हमसे जनता जवाब मांगेगी, हमें जनता को जवाब देना है। पूरे प्रदेश की जनता हम सबको देख रही है, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2024-25 के आय-व्ययक अनुमान पर बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधान मंत्री के मार्गदर्शन में हमारे माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, आधारभूत संरचना की विकास नीति निर्धारण की पहल तथा सबसे महत्वपूर्ण आम जन को राहत देने वाला बजट दिया है।

सभापति महोदय, उप मुख्य मंत्री महोदया ने विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना, जिला झालावाड़ में इतना कुछ दिया है कि जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सड़क के बारे में, बाईपास मनोहर थाना, एम.डी.आर. 176, साढ़े तीन किलोमीटर का बाईपास दिया है जो लम्बे समय से रुका हुआ था। परिवहन के क्षेत्र में मनोहर थाना में अत्याधुनिक सुविधायुक्त बस स्टैण्ड दिया गया। इस बारे में मैं पिछले पांच साल से गत सरकार को अवगत कराता रहा, परन्तु मेरी बात नहीं सुनी गई, क्योंकि कांग्रेस सरकार में भेदभाव की रीति नीति चलती आई है।

तीसरा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में सहायक अभियंता कार्यालय मनोहर थाना में खोला गया है। चौथा, लम्बे समय से कई पुलियाएं क्षतिग्रस्त थीं जो 2021-22 में अत्यधिक वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थीं, उन पुलियाओं का काम शुरू हो गया है और बहुत तेजी से चल रहा है।

गत सरकार में प्रदेश के पशुपालकों के लिए पशु बीमा योजना मात्र कागजी घोषणा की गई थी। अभी वर्तमान सरकार ने पशुपालकों के हितों का ध्यान रखते हुए चरणबद्ध रूप से दुधारू पशुओं के साथ-साथ अन्य पशुओं को सम्मिलित करते हुए मुख्य मंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारम्भ की गई है। कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने केन्द्र सरकार के

(श्री गोविन्द प्रसाद)

अनुरूप, ग्रेच्युटी की वर्तमान अधिकतम सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की घोषणा की। ओलावृष्टि से किसानों को 2024 तक का ख़रीफ़-रबी का मुआवजा एवं बीमा क्लेम बकाया तुरन्त प्रभाव से दिया जाएगा, इसकी भी घोषणा की है।

हमारी केन्द्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लागू कर देश में आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में क्रांतिकारी पहल की थी। उसी की तर्ज पर प्रदेश में मुख्य मंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना लागू करके कैंसर जैसी गम्भीर बीमारी से ग्रस्त रोगियों को और अधिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाते हुए आईपी.डी. के साथ डे-केयर पैकेज जोड़ने की व्यवस्था की गयी है। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में आयुष्मान मॉडल सी.एच.सी. स्थापित की जायेगी।

ई.आर.सी.पी. परियोजना को त्वरित गति से धरातल पर उतारने के लिए प्रथम चरण में रामगढ़, बारां, बीसलपुर बांध के वर्क आर्डर जारी किये जा चुके हैं। चम्बल बेसिन नदियों में बारां व झालावाड़ जिले में 14,350 हैक्टेयर भूमि सिंचाई हेतु उपलब्ध होगी।

माननीय सभापति महोदय, पेयजल परियोजना लगभग 1,240 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित की जायेगी। मिसिंग लिंक सड़कों को, जो कुछ गांव आज भी 250 की आबादी के गांव सड़कों से विहीन हैं उनको तुरन्त प्रभाव से सड़कों से जोड़ा जायेगा।

वर्ष 2024-25 के बजट में गुरु-शिष्य की परम्परा को अगर किसी ने जीवित किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों को कुलगुरु की पदवी से जाना जायेगा। बजट घोषणा में बेरोजगार एवं संविदा कर्मचारियों का ध्यान रखा गया है, क्योंकि चुनावी घोषणा पत्र में राज्य सरकार ने संविदाकर्मी, आंगनबाड़ी नियमितीकरण जैसे वादे किये थे, हर बेरोजगार एवं संविदाकर्मी को निराश नहीं किया गया।

माननीय सभापति महोदय, यह विकास का बजट है न कि कांग्रेस की तरह असत्य का पुलिंदा। सम्भागीय स्तर पर बालिका सैनिक स्कूल स्थापित करके वर्तमान सरकार ने सैनिकों के बच्चों का मान-सम्मान बढ़ाया है। इस तरह के इस बजट में प्रावधान किये गये हैं। आपने कई बजट देखे होंगे पर इस बजट में पेयजल, ऊर्जा, सड़क, पानी, सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नवाचार किये जायेंगे। ये हमारे मुख्य मंत्री भजन लालजी की सरकार की

(श्री गोविन्द प्रसाद)

उपलब्धियां हैं जो धरातल पर उतारकर उन्होंने जो बजट में ये लागू की हैं, धरातल से शुरू होकर इन पांच सालों के अन्दर ऐसे ऐतिहासिक काम किये जायेंगे जो कभी किसी सरकार ने नहीं किये हैं। जय हिन्द, जय भारत, जय-जय राजस्थान।

श्री सभापति: श्री अभिमन्यु।

श्री अभिमन्यु (संगरिया): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद कि आपने बजट पर बोलने का मौका दिया। राज्य सरकार ने जिस प्रकार किसान, युवाओं, महिला वर्ग को सुरक्षित रखने के लिए जो बजट दिया, उसमें कहीं न कहीं किसान, युवा और महिला वर्ग अपने आप में ठगा हुआ महसूस राज्य के अन्दर कर रहे हैं।

किसान वर्ग को लेकर 30 हजार करोड़ की इन्होंने कृषि जल ग्रिड मिशन योजना बनाई, उसमें पूरे राजस्थान के अन्दर हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़ जिला भी आता है जो पूरे राज्य का 50 प्रतिशत अन्न भण्डार है, उस अन्न भण्डार के होते हुए भी एक रुपया वहां पर, हरियाणा से ओटू हैड की तरफ से जो पानी आता है, हनुमानगढ़, गंगानगर जिले की सुरक्षा के लिए नहीं दिया गया। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह क्या इनके प्रोटेस्ट में पहना है?

श्री अभिमन्यु (संगरिया): यह छात्र संघ चुनाव को लेकर पहना है, सरकार को अगर एतराज नहीं है तो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): इनके प्रोटेस्ट में पहना है? (व्यवधान)

श्री अभिमन्यु (संगरिया): माननीय सभापति महोदय, मैं यह मांग करता हूं कि घग्घर साइफन जो हमारे ओटू हैड से राज्य के अन्दर आता है, उस बांध पर एक रुपये का बजट राज्य सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। अनेकों जिंदगियों को वहां से खतरा रहता है। वह राइस बैल्ट है, चावल का क्षेत्र है। दूसरी व्यवस्था, शिक्षा को लेकर राज्य के शिक्षा मंत्री और देश के शिक्षा मंत्री कहीं न कहीं, देश के शिक्षा मंत्री तो नीट को नहीं समझ पा रहे हैं और राज्य के शिक्षा मंत्री डी.एन.ए. टेस्ट में लगे हुए हैं, आदिवासियों के डी.एन.ए. टेस्ट के लिए लगे हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, जब से तहसीलें ऑनलाइन हुई हैं तब से

(श्री अभिमन्यु)

विवादित खातों की संख्या में नामांतरण नहीं हो पा रहा है तो सरकार से यह निवेदन है कि इस ओर ध्यान दें। 600 करोड़ रुपये में से जो खालों के लिए पिछली सरकार ने घोषणा की, पहली किश्त 150 करोड़ रुपये की आई, लेकिन इस बार इस सरकार ने मात्र 10 करोड़ रुपये खालों के निर्माण के लिए दिये, जिससे कि 15 या 20 खाले भी नहीं बन सकते।

दूसरी बात, फसल बीमा को लेकर, गुलाबी सुंडी फसल खराबे को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गयी। खाद्य सुरक्षा पोर्टल, जिसमें दस लाख किसानों ने अपना नामांकन किया, उसमें लघु किसान कैटेगरी आज भी होल्ड पर है, उसको चालू करने के लिए मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूं।

युवाओं को 2023 में जो बेरोजगारी भत्ता दिया गया, 4,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता युवाओं को मिलता था, लेकिन जनवरी के बाद, सरकार के आने के बाद आज तक वह बेरोजगारी भत्ता युवाओं को नहीं दिया गया। चार घंटे जो नौजवानों को, बेरोजगारों को इंटर्नशिप के लिए बुलाया जाता है तो आपसे यह निवेदन है कि उन बेरोजगारों को परीक्षा की तैयारी करने के लिए छूट दी जाए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, ग्रामीण लेवल पर जो मूलभूत सुविधाओं के लिए संस्थाएं हैं, उनमें आज सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद् में एस.एफ.सी.-15 की किश्त भी अभी तक नहीं आ पायी है। आपकी सरकार को सात माह हो चुके हैं। आज सरपंच हड़ताल कर रहे हैं। ग्रामीण विकास की पहली सीढ़ी गांव होता है। उसके बजट को भी एक हजार करोड़ रुपये कम कर दिया गया है।

डबल इंजन सरकार द्वारा जो राज्य सरकार का बजट पेश किया गया, पहली बात तो ऐसी क्या जल्दी थी कि आपने केन्द्र सरकार के बजट से पहले ही राज्य सरकार का बजट पेश किया और इस बजट में हनुमानगढ़, गंगानगर जिले को, संगरिया, पीलीबंगा, नोहर, अनूपगढ़ में बजट के नाम पर कुछ नहीं दिया गया।

संगरिया के अन्दर कानून-व्यवस्था आज इतनी बिगड़ी हुई है कि हत्याएं, चोरी, लूटपाट पंजाब और हरियाणा का बोर्डर होने के कारण से रोजाना हो रही हैं, लेकिन राज्य सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। मालारामपुरा चौकी, जो कि हरियाणा-पंजाब बोर्डर की चौकी है, उस पर मात्र दो मुलाज़िम हैं, उनके संसाधन की भी कोई व्यवस्था नहीं है। भा.ज.पा. का राज आने के बाद राज्य सुरक्षा की दृष्टि से किस ओर जा रहा है, यह इससे स्पष्ट होता दिख रहा है।

(श्री अभिमन्यु)

जिस प्रकार से मीरा शिक्षा समिति का सरकारीकरण 2013 में हुआ, फिर उसका 2014 के अन्दर नोटिफिकेशन आया, फिर उसको वापस 2020 के अन्दर सरकारीकरण किया गया, 2023 में सरकारीकरण किया और आज भी वहां के कर्मचारी 126 महीने से अपनी सैलेरी लेने के लिए दर-दर भटक रहे हैं, अभी तक कोई सुरक्षित महसूस नहीं हो पा रहा है तो निश्चित तौर पर यह राज्य सरकार का बजट दिखाता है।

चिकित्सा योजना में प्रत्येक जिले में, प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में आपने आयुष्मान सी.एच.सी. की घोषणा की, लेकिन उससे पहले जो वहां पर सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र बने हुए हैं न तो वहां पर डाक्टर है, न वहां पर हास्पिटल की व्यवस्थाएं हैं तो इन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कौन प्रयास करेगा?

राज्य सरकार से हम यह निवेदन भी करते हैं कि पूरे राज्य में छात्र संघ चुनाव बंद है, छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी है अतः हम निवेदन करते हैं कि राज्य के अन्दर छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। इसको लेकर हम सब लोग यह कहना चाहते हैं कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव हों, जिससे नये लोग चुनकर आएं। यह सबसे पहली मेरी मांग है कि छात्र संघ चुनाव राजस्थान में हों। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): बजट से क्या लेना-देना है इसका? (व्यवधान) अभी आपने कहा कि अनुशासन में रहिए। (व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री अभिमन्यु (संगरिया) द्वारा पोस्टर प्रदर्शन)

श्री सभापतिः यह सही नहीं है। आप नये सदस्य हैं। यह बिलकुल अनुकूल नहीं है। इनको आप नीचे रखें।

(कांग्रेस के कई माननीय सदस्यों द्वारा पोस्टर प्रदर्शन)

श्री अभिमन्यु (संगरिया): सर, यह हमारी मांग है। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह क्या है?

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री अभिमन्यु (संगरिया): सर, यह हमारी मांग है। यह हम टेबल करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री छगनसिंह राजपुरोहित। आप विराजिए।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह क्या बना रखा है आपने?

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: आपका यह तरीका ठीक नहीं है। आप अपने स्थान पर खड़े रहिए। आप पीछे जाइए। यह ठीक नहीं है ऐसे। आप अभी नये सदस्य हैं। अभी से आपको इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। आप विराजिए।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): विपक्ष के माननीय नेता, आप इनको यह बताएं कि यह चुनाव किसने कैंसिल किये थे। छात्र संघ चुनाव किसने रद्द किये थे, यह इनको जानकारी दें।

(माननीय सदस्य श्री अभिमन्यु (संगरिया) द्वारा स्लोगन युक्त चोला उतार कर प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा की टेबल पर रखा गया।)

श्री सभापति: आपकी बात आ गयी, पर यह क्या तरीका है? आप विराजिए। श्री छगनसिंहजी राजपुरोहित, प्रारम्भ करें।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): छात्र संघ चुनाव किसने रद्द किये थे, यह इनको जानकारी दे दो। (व्यवधान) माननीय विपक्ष के नेता, ये पिछली बार आये नहीं थे, अशोक गहलोतजी ने ही नहीं करवाये थे चुनाव। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिए, आप विराजिए... (व्यवधान) सुन लिया, समझ लिया, आपका एक बार आ गया विषय... (व्यवधान) बस ठीक है अब। छगनसिंह जी, प्रारम्भ करें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, इस विधान सभा में साबित हो रहा है कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता का एक भी सदस्य कहना नहीं मान रहा है। ये बार-बार रोक रहे हैं। इनका कोई कहना नहीं मान रहा। इन सबको लग रहा है कि इनको गलत बना दिया, गोविन्द जी को बनाना चाहिए था। इनके यह बात अभी निकल नहीं रही है। बार-बार टोकने के बावजूद भी इनका कहना नहीं मान रहे हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ऐसा है, गम्भीर विषय है, छात्र संघ चुनाव को लेकर इन्होंने अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया है। यहां भी नहीं कहेंगे तो कहां कहेंगे? (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): नियमों में आइए। प्रतिपक्ष कहता है तो नियमों में आइए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कहां कहेंगे? बैठ गये सारे लोग। इतने उत्तेजित मत हो ...(व्यवधान)

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आपने कराये थे क्या चुनाव?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आपने कराये क्या चुनाव... (व्यवधान)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप तो अब चुनाव करा दीजिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): तब लोग सो रहे थे क्या?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपने खुद ने बंद किये हैं। कांग्रेस सरकार ने बंद किये हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आपने खुद ने बंद किये हैं।

श्री सभापति: श्री छगनसिंह राजपुरोहित। विराजिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आपके टाइम पर ही चुनाव बंद किये हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हमारी सरकार ने बंद नहीं किये थे। एक साल के लिए पोस्टपोन किये थे ...(व्यवधान)

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप यह अशोक गहलोत जी के सामने खड़े होकर बोलिए कि चुनाव क्यों नहीं कराये?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): बंद आप लोग कर रहे हो।

श्री सभापति: माननीय विपक्ष के नेता यहां विराजमान हैं, कोई बात कहनी है तो उनकी परमिशन से कहें। आप पीछे से खड़े हो रहे हैं। आप कैसे बोल रहे हैं? (व्यवधान) सदन की गरिमा को बनाकर रखें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, आज डोटासरा जी होते तो यह स्थिति नहीं होती।

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कृपलानी जी को मंत्री बनवा दो, ताकि ये तो बंद हो जाएं कम से कम।

श्री सभापति: विराजें। विराजें। हां, छगनसिंह जी।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे परिवर्तित बजट 2024-25 में बोलने का अवसर दिया।

(श्री छगनसिंह राजपुरोहित)

माननीय सभापति महोदय, मैं जब परिवर्तित बजट को पढ़ रहा था तो मुझे 2019 के परिवर्तित बजट की भी याद आ गयी। मैंने दोनों की तुलना की। जो विपक्ष के माननीय सदस्य बोल रहे हैं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में कुछ नहीं दिया, किसी तरह का कोई विजन नहीं, तो एक बार आप 10 जुलाई, 2019 के बजट को भी पढ़ लेना। आपके पास कापी नहीं हो तो यह मेरे पास से लेकर के जाना। इसको अगर आप देखोगे तो इसमें क्या था? अगर कोई विजन हो तो बता देना। इसमें क्या दिया था? यहां तक कि जब हम लोग बाहर निकले थे, बजट के बाद में, तो सत्ता पक्ष के हमारे मित्रों ने कहा था कि गहलोत जी ने तो कुछ दिया ही नहीं। किसी को कुछ नहीं दिया। मुंह उतारकर बाहर निकले थे। एक बार ही नहीं, लगातार दो वर्षों तक कुछ नहीं दिया। फिर कोरोना का बहाना बनाया। चार वर्षों तक किसी को कुछ नहीं दिया। अंतिम वर्ष में सिर्फ घोषणाएं करने का काम किया।

श्री सभापति: प्लीज, बोलने दीजिए। देखिए, समय कम है। (व्यवधान)

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): बैठिए, बैठिए।

श्री सभापति: बहुत बढ़िया, सब व्यवस्था के अनुकूल है।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): रानीवाड़ा से आने वाले माननीय विधायक आये, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): कैसा एक्शन कर रहे हैं? अभी तो आपको ही नहीं मालूम कि कब बोलना चाहिए और कब नहीं बोलना चाहिए।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): जो हमारे माननीय साथी विधायक बैठे हैं, युवा हैं, अभी उनको यही लगता है कि हम कालेज में हैं। इसलिए कालेज की हरकतें करते हैं। इनको अभी तक यह पता नहीं कि हम विधायक बन चुके हैं। जो नियमों में आता है वह करना चाहिए। अब आप विधायक बन चुके हैं। आप विधायकों की तरह काम करें।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार ने, भजन लाल जी की सरकार ने, बी.जे.पी. की सरकार में माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा है।

अभी बायतू से आने वाले विधायक ने ई.डब्ल्यू.एस. में 150 करोड़ रुपये की चर्चा की। उन्होंने बजट पढ़ा नहीं, इसलिए उनको जानकारी नहीं है।

(श्री छगनसिंह राजपुरोहित)

इसमें मैं आपको 3-4 बातें बताना चाहूंगा। पैरा नम्बर 78 में एस.सी., एस.टी. सशक्तीकरण के लिए 1,500 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया है। 80 नम्बर पर अनुसूचित क्षेत्र, टी.एस.पी. को 75 करोड़ गुरु गोविन्द जनजाति क्षेत्रीय विकास के लिए किया है।

मैं कुछ बातें और बताना चाहूंगा जो कि शायद बायतू से आने वाले विधायक ने पढ़ी नहीं थीं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति सहित अन्य आवासीय विद्यालय छात्रावासों के रिपेयर एवं आवश्यक सामग्री के लिए 50 करोड़, जर्जर भवन के लिए, 15 छात्रावासों के लिए 45 करोड़, 17 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिए 77 करोड़, सुमेरपुर में घुमंतु जाति के लिए 28 करोड़, बालिका घरों के लिए, उसके बाद शेरगढ़ में अनुसूचित जाति छात्रावास, दौसा में अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास, डग में अनुसूचित जाति छात्रावास, कठूमर में बालिका छात्रावास, भटेर-सिरोही में, पोषाणा-जालौर में जनजाति बालिका छात्रावास, सिरोही जनजाति छात्रावास, इस प्रकार से कुछ बातें हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सभापति महोदय, जनजाति, एस.सी. के लिए जितनी घोषणाएं पहली बार भा.ज.पा. की सरकार ने की हैं, वे बातें बायतू के विधायक ने बताई नहीं और पढ़ी भी नहीं।

सभापति महोदय, मैं कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं। जिस प्रकार से मोदी जी की चर्चा कर रहे हैं, मोदी जी का तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है। उन्होंने आते ही सबसे पहले घोषणा की कि मैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पांच वर्षों में तीन करोड़ मकान बनाऊंगा। इस तरह की घोषणा की है और पिछले वर्षों में काम करके बताया है। मोदी जी हकीकत बुनते हैं, तभी तो मोदी को चुनते हैं। तीसरी बार चुना है। सपने नहीं हकीकत बुनते हैं। तभी तो लोग मोदी को चुनते हैं। यह बार-बार चुन रहे हैं और अगली बार भी चुनेंगे।

सभापति महोदय, मैं आपके मध्य कुछ बातें रखना चाहूंगा। अभी जल संसाधन मंत्री भी बैठे थे। मैं उनका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि जवाई पुनर्भरण की चर्चा हुई है। जवाई बांध के लिए पानी की चर्चा हुई है। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि यह तीन जिलों के लिए, जालौर, सिरोही और पाली के लिए वरदान साबित होने वाला है। बाड़मेर तक यह पानी जाता है। अगर राजस्थान जल नीति में डाउन स्ट्रीम में कुछ पानी का हिस्सा नदी में छोड़ा जाए तो अच्छा होगा।

मैं बार-बार कह रहा हूं कि जवाई बांध बनने के बाद में मेरे क्षेत्र के

(श्री छगनसिंह राजपुरोहित)

साथ-साथ जालौर, सिरोही और आसपास के कई जिलों में इसका प्रभाव पड़ा है। वहां नदी के किनारे बसे हुए जो गांव थे, उनमें जहां पहले हरियाली रहा करती थी, जहां कई तरह की फसलें हुआ करती थीं, बड़े-बड़े वृक्ष होते थे, आम के वृक्ष होते थे, अलग-अलग तरह के फल पैदा होते थे, आज उनके कुओं में सूखा हो गया है। इसका कारण जवाई बांध है। अगर यह जवाई पुनर्भरण योजना लागू होती है तो उसके बाद में कुछ हिस्सा जवाई से नदी में छोड़ने का प्रावधान करें। यह राजस्थान जल नीति भी बनी हुई है, जिसमें डाउन स्ट्रीम के लिए 15-20 परसेंट पानी छोड़ने का अगर प्रयास किया जाए तो उससे उस क्षेत्र के लोगों को वापस जीवनदान मिलेगा। यह मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे कई ऐसे काम थे, जिनको मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को बताया था। उन्होंने उसके लिए घोषणा की। इसके लिए मैं उनको इस मंच से धन्यवाद भी देना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने सभी विधान सभा क्षेत्रों में आम व्यक्ति के लिए लोक कल्याणकारी घोषणाएं कीं।

पाली से जो माननीय विधायक थे, जो विपक्ष में हैं, उन्होंने तो कल पूरा भाषण धन्यवाद देकर कहा। कम से कम 100 बार हम लोगों ने तालियां बजाईं। माननीय विपक्ष के नेता ने ट्विटर पर भी धन्यवाद दिया था। कई तरह के काम हुए हैं, लेकिन जो माननीय सदस्य हैं, वे यह बात खुले मन से कहना नहीं चाहते हैं। बहुत काम हुआ है। इसका कोई सानी नहीं है।

रानीवाड़ा से आने वाले माननीय विधायक ने यहां तक कह दिया कि क्या आप चुनाव में जा रहे हैं? यह पहली सरकार है जिसने पहले बजट में ही इस प्रकार की घोषणाएं की हैं। नहीं तो पांचवां बजट होता है तब जाकर के घोषणा करते हैं।

श्री सभापति: विराजें, माननीय सदस्य।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): यह भजनलाल जी की सरकार है, जिसने पहले बजट में इतनी बड़ी घोषणा की और काम करने का प्रयास किया। मैं भजन लाल जी और वित्त मंत्री को खूब-खूब धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री अशोक कोठारी।

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): सदन को नमन। माननीय

(श्री अशोक कुमार कोठारी)

सभापति महोदय, बजट सत्र पर अपनी बात रखने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद और आभार। बजट 2024-25 पेश हुआ। बजट अच्छा ही नहीं, बहुत ही अच्छा रहा। सभी वर्ग विशेष का पूरा ध्यान रखा गया। एक अच्छे बजट के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं उप मुख्य मंत्रीजी का हृदय से बहुत-बहुत आभार। बजट के पूर्व भी सरकार द्वारा प्रदेश के विकास और जनहित के लिए कई अच्छे कार्य और महत्वपूर्ण निर्णय लेकर उसमें ERCP की योजना तो प्रदेश के लिए एक वरदान साबित हुई। जल ही जीवन है और उसके बाद 20 हजार लोगों को रोजगार देना, यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं था।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ पेंशन और किसान निधि को बढ़ावा देना, यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, पर इन अच्छे निर्णयों के साथ, इन निर्णयों के बीच एक महत्वपूर्ण विषय छूट गया है। वह विषय है गौमाता का, जो कि अभी वर्तमान में बहुत ही गम्भीर विषय है। गौमाता की पीड़ा से सदन के सभी सदस्य परिचित हैं। हर शहर में सैकड़ों गौमाताएं सड़क पर भूखी-प्यासी खड़ी हैं। नन्दी बाबा उदास, निराश और थके हुए हैं और कोई देखने वाला नहीं है। क्या राजा का दायित्व नहीं है कि प्रजा के साथ पशु-पक्षी का भी ध्यान रखे। मानव के लिए लाखों-करोड़ों का बजट है और भूखी-प्यासी गौमाता के लिए कुछ नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, परसों उप मुख्य मंत्रीजी का तीन घंटे का बजट भाषण सुना और यह प्रतीक्षा करते रहे कि गौमाता पर कुछ बोलेंगी। हम सभी को समझना चाहिये, मानव चाहे कितने भी साधन-सुविधा जुटा ले, पर गौमाता पीड़ा में है तब तक मानव कभी सुखी नहीं हो सकता। धरती पर मां से बड़ी कोई उपमा नहीं है और मां की पदवी धरती माता एवं भारत माता को मिली है। इसके साथ ही गौमाता को मिली है। गौमाता हमारे लिए क्या है, इससे बड़ा इशारा या कोई संदेश नहीं हो सकता। आज इसी गौमाता की इतनी बड़ी दुर्दशा है। यह दुर्दशा देखकर आंखें भर आती हैं। क्या यही राम-कृष्ण, बुद्ध और महावीर का देश है? माननीय सभापति महोदय, आपसे व माननीय सदस्यों से निवेदन करते हैं कि हम और आप सभी मिलकर गौमाता पर कोई ठोस नीति बनाएं, जिससे उनकी पीड़ा का समाधान हो सके।

माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करेंगे कि बजट में गौशालाओं का अनुदान 9 माह से बढ़ाकर 12 माह कर दें। अभी जो बहुत ही जरूरी है, अभी जो अनुदान मिल रहा है, वह भी आधा ही मिलता है। जहां पर एक बड़ी

(श्री अशोक कुमार कोठारी)

गौमाता पर 80 रुपये और छोटी गौमाता पर 40 रुपये खर्च होता है, वहां 20 रुपये और 40 रुपये ही मिलता है। इसके अलावा भी केवल 9 माह का मिलता है। इसे बढ़ाकर 12 माह का बहुत ही जरूरी है। इसे 60 और 30 रुपये कर दें।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा मैं गौसंवर्धन नियम, 2016 की तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 2016 में गौ-सेस कर के नाम से एक नियम बना है, उसके तहत 2023 में गौ-सेस कर में 1,100 करोड़ रुपये आये हैं और 800 करोड़ ही इन 9 माह में गौशालाओं को बांटे गये हैं। 300 करोड़ से तीन माह का अनुदान तो पूरा दिया जा सकता है।

माननीय सभापति महोदय, अब हम हमारी विधान सभा क्षेत्र की बात करेंगे। बजट में बहुत कुछ देने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं उप मुख्य मंत्रीजी का हृदय से बहुत-बहुत आभार। आपने भीलवाड़ा को जो महत्वपूर्ण सौगात दी, जिसमें माही डैम का जल भीलवाड़ा के लिए एक वरदान साबित होगा। साथ ही, भीलवाड़ा नगर परिषद् को नगर निगम में क्रमोन्नत करना, यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इससे भीलवाड़ा के विकास के नये आयाम स्थापित होंगे।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही टेक्सटाइल पार्क सहित जयपुर-भीलवाड़ा का ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस हाईवे निर्माण और कई और घोषणाएं कीं, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। हम आपसे कहना चाहेंगे कि बजट में हमारी मुख्य मांग थी एक एलिवेटेड रोड और ROB, चूंकि भीलवाड़ा शहर बहुत बड़ा शहर है और दो भागों में विभाजित है पटरी के इस पार और पटरी के उस पार। आने के लिए मात्र एक पुलिया है और वहां पर भी भीड़ का इतना दबाव रहता है, पब्लिक इतनी दु:खी रहती है और आये दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। आपको हमारा निवेदन है, जाम से छुटकारा एवं आये दिन होने वाली दुर्घटना से बचाव हेतु आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप भीलवाड़ा के लिए एक एलिवेटेड रोड और एक ROB का निर्माण बजट में शामिल करें।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही भीलवाड़ा और राजस्थान रोडवेज डिपो की हालत भी अच्छी नहीं है। आपने आधुनिकीकरण करने में 10 जिलों को लिया है। उन जिलों में भीलवाड़ा का नाम जोड़ना भी बहुत जरूरी है। यहां प्रतिदिन 25 से 30 हजार यात्री आते हैं। उक्त दोनों मांगें पूरी करने पर भीलवाड़ा की जनता आपकी बहुत-बहुत आभारी रहेगी। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: विराजें, माननीय सदस्य। डॉ. विश्वनाथजी।

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): इसी के साथ मैं आपका ध्यान, अपराध को तत्काल रोकने के लिए हर जिले स्तर पर पी.सी.आर. वैन लगाएं, जो पांच किलोमीटर को कवर करेगी। यह पी.सी.आर. एक चलता-फिरता थाना होगा। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: डॉ. विश्वनाथजी।

डॉ. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): माननीय सभापति महोदय, परिवर्तित बजट 2024-25 के वाद-विवाद के अवसर पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर दिया हुआ बजट है। गांव्ढाणी और हर विधान सभा का इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। आम आदमी, युवा और किसानों का भी इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। ऐसे ऐतिहासिक बजट के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी का और वित्त मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय हमारे सामने बैठे हैं। आजकल इनको संविधान की बहुत याद आने लग गयी। ये खुद इनके सदस्य और इनके नेता हर समय संविधान की कापी साथ में लिए घूम रहे हैं। संविधान खतरे में है, की बात ये करते हैं। मैं तो समझता हूं कि पिछले दशक से संविधान खतरे में नहीं है, बल्कि कांग्रेस खतरे में है। संविधान नहीं, कांग्रेस खतरे में थी, इसलिए इनको संविधान की याद आयी है। बाबा साहब का अगर अपमान किया गया तो हमेशा कांग्रेस ने किया। बाबा साहब ने इतना स्ट्रांग संविधान दिया, इसका सम्मान इन्होंने कभी नहीं किया। आपने बाबा साहब को संसद में जाने से रोकने का काम किया। अगर बाबा साहब को किसी ने सम्मान दिया है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने दिया। भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी ने बाबा साहब को सम्मान दिया। आप लोग तो अभी जब आपकी 40 सीटें आयीं, पिछली बार 2014 में जब आपकी 52 सीटें आयीं 2019 में, तब जाकर आपको संविधान की याद आयी। चलो आपको संविधान तो याद आया, इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस मौके पर यह कहना चाहूंगा कि देश के यशस्वी प्रधान मंत्रीजी ने, कांग्रेस की सरकार पहले भी लगातार 10 साल रही, उसके बाद में देश में यशस्वी प्रधान मंत्री मोदीजी की सरकार रही। उन्होंने 10 साल में देश की अर्थव्यवस्था को पांचवें पायदान पर विश्व में पहुंचाया। आपके समय में भारत की अर्थव्यवस्था दसवें स्थान पर थी। बहुत

(डॉ. विश्वनाथ मेघवाल)

ही ऐतिहासिक काम देश के यशस्वी प्रधान मंत्री मोदीजी ने किया। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर आ जायेगी। आपकी सरकार के समय में भी घोषणाएं बहुत होती थीं। अभी आप कह रहे थे कि यह चुनावी बजट है। हम तो यह कह रहे हैं कि जब आप मानकर चल रहे हैं कि यह चुनावी बजट है तो पहले साल में अगर भजन लाल जी ने ऐसा बजट दिया है तो मैं समझता हूं कि पांच साल में, आने वाले समय में इससे बहुत अच्छा बजट आयेगा। आप देखते रहना। यह जितना भी बजट दिया है, इसका इम्प्लीमेंटेशन और इसको लागू करने की बात हमारी सरकार कर रही है। पूरे पांच साल में आपको अच्छा बजट मिलेगा। आप लोगों ने भी बजट की प्रशंसा की है। हर विधान सभा क्षेत्र में सबको कुछ न कुछ पूछकर दिया गया, तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अच्छा बजट है। आपके समय में भी बहुत सारी घोषणाएं होती थीं और सिर्फ थोथी घोषणाएं आप लोगों ने कीं।

माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ बीकानेर की बात करूंगा कि बीकानेर में आपने स्मार्ट सिटी की बात की थी, उसका क्या हुआ? बीकानेर के खाजूवाला में आपने कहा था कि सीवर लाइन डलवा देंगे, उसका क्या हुआ? सड़कों की बहुत सारी घोषणाएं की गयी थीं, आज तक वहां पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। 132 के.वी. जी.एस.एस. मेरे क्षेत्र में लगाने की आपने बात कही थी, उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। बिना बजट आपने रेवड़ियां बांटने की बात की। आजादी के बाद आज तक इतनी सरकारें आयीं लेकिन आज तक किसी भी मुख्य मंत्री ने 19 जिले नहीं बनाये। लेकिन आपने अपनी जीत के लिए, आपने कहा कि जैसे-तैसे वोट मिल जाएं, 19 जिले हम बना दें, लेकिन उसमें भी आप सफल नहीं हो पाये। उसमें भी आप 99 प्रतिशत विफल रहे। किसी भी प्रकार से आप उन जिलों में जीत हासिल नहीं कर पाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय भजन लाल जी की सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मोदीजी का जो संकल्प है 2047 तक विकसित भारत बनाने का, ऐसा बजट आपने पेश किया है। हमारी माननीय भजन लाल जी की सरकार ने जो हमारा घोषणा-पत्र और संकल्प पत्र था, उसको चरणबद्ध तरीके से पूरा भी कर रहे हैं।

जैसे महिलाओं के लिए, गरीब परिवार की महिलाओं के लिए 450 रुपये सिलेण्डर की बात की, उनकी घोषणा हमने पूरी की। प्रधानमंत्री किसान

(डॉ. विश्वनाथ मेघवाल)

सम्मान निधि की भी हमने बात की, उसको भी 6 हजार रुपये बढ़ाकर 8 हजार रुपये किया। इसी तरह गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएस.पी. पर 125 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस देने का काम भी हमारी सरकार ने किया। ई.आर.सी.पी. का जो हमारा बड़ा प्रोजेक्ट था, वसुन्धराजी के समय में जो प्रोजेक्ट हमने हाथ में लिया था, उसके लिए भी हमारी सरकार ने 45 हजार रुपये का प्रावधान किया है। 13 जिलों की जनता को इसका फायदा होगा। पेट्रोल-डीजल में भी पहली बार हमारी सरकार ने वैट कम करके आम आदमी को इसकी रिलीफ दिलाई। पेपर लीक के मामले में 100 से अधिक गिरफ्तारियां की हैं। एंटी गैंगस्टर फोर्स बनाकर भी राजस्थान में सभी को न्याय दिलाने की बात कही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं पेयजल के बारे में बात करूंगा। जे.जे.एम. बहुत ही अच्छा मिशन था। (व्यवधान) सर, दो मिनट के लिए।

श्री सभापति: एक मिनट के लिए। एक मिनट में अपनी बात को समाप्त करें माननीय सदस्य।

डॉ. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): 25 लाख ग्रामीण घरों के लिए 15 करोड़ रुपये की जो घोषणा की है, वह मैं समझता हूं कि हर घर को नल से जल मिलेगा। छह वृहद परियोजनाओं के लिए 20 हजार करोड़ रुपये की घोषणा की है। खाजूवाला के लिए भी इसमें बहुत ही अच्छा बजट दिया है 25 करोड़ रुपये का बजट खाजूवाला के लिए दिया है। पूगल के लिए साढ़े चार करोड़ रुपये का बजट दिया है। उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, विद्युत के क्षेत्र में पूर्ववर्ती हमारी वसुन्धराजी की सरकार थी, उस समय विद्युत निगम को घाटे से उबार कर 64 हजार करोड़ रुपये का ऋण चुकाया, जबकि आपकी सरकार ने इसमें वापस कर्ज में इस विद्युत कम्पनी को कर दिया है। मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति में राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में हर विधान सभा क्षेत्र में आयुष्मान मॉडल सी.एच.सी. स्थापित की जाएगी।

श्री सभापति: आप विराजें।

श्रीमती शिमला देवी।

डॉ. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): साथ में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि नरेन्द्र मोदीजी ने सुशासन के लिए, हमने माइंड सेट भी बदला है। (व्यवधान)

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2024-25 पर बोलने का का अवसर दिया।

डॉ. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): अब मैं कृषि पर बोलना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं हो।

डॉ. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): 000

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, सम्माननीय सदस्य को कहें, बैठें। मैं मेरा समय पूरा लूंगी। (व्यवधान) एक नारा था कि 'सबका साथ सबका विकास'। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें, एक मिनट।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय सभापति महोदय, मेरे को विपक्ष के सदस्यों ने एक पर्ची भेजी है, ये व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। लिखा है, पढ़ कर बताऊं आपको? (व्यवधान) बताऊं?

श्री सभापति: विराजें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अभी दी है इन्होंने पर्ची।

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): विराजूं काहे के लिए? आप इस पर कार्यवाही करें।

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, मुझे मेरा पूरा समय चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: बोलिए, अब आपका समय प्रारम्भ होता है।

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): मैं मेरी बात रखूंगी। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप सीनियर हैं, बैठिए, नहीं तो मेरा समय जितना लेंगे, मैं भी बीच में बोलूंगी और बैठूंगी भी नहीं और बोलने भी नहीं दूंगी आपको।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय सभापति महोदय, इस पर व्यवस्था दीजिए।

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): ..(व्यवधान) जिसने पर्ची दी है, उसका जवाब आप बाद में दे दीजिए। मैं आपको मना नहीं करती। आपको मना नहीं करती। (व्यवधान) आप बैठिए।

श्री सभापति: आप बोलें।

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, जो इस बार बजट पेश किया गया पूरे प्रदेश का 10 जुलाई को ..(व्यवधान) जो विशेष वर्ग है, चाहे कर्मचारी है या किसान है, महिला है, चाहे विद्यार्थी है, वे उस बजट को बहुत ध्यान से देखते हैं कि हमारे क्षेत्र के लिए सरकार ने क्या किया? अभी हमारे सम्माननीय सदस्य कह रहे थे कि बजट बिना भेदभाव दिया गया है, लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि जिस अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र से आती हूं वहां माननीय वित्त मंत्री महोदय ने क्या दिया? पिछली अशोक गहलोतजी की सरकार ने 19 नये जिले दिये थे, उनमें से अनूपगढ़ भी एक जिला है। लगभग साढ़े ग्यारह साल हमारी जनता धरने पर बैठी थी, जनता की भावना को देखते हुए भा.ज.पा. के विधायक थे, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री गहलोतजी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने जिला देकर हमारी जनता को बहुत बड़ी सौगात दी।

माननीय सभापति महोदय, अभी मेरे से पहले हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि रेवड़ियां बांटी हैं, जिले आनन-फानन में बांटे, तो मैं हमारे माननीय सदस्य, मेरे भाई को कहना चाहती हूं कि जिले का क्या महत्व है। वह भारत और पाक बोर्डर पर बसा हुआ विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ हमारा जिला मुख्यालय है, मैं बताती हूं कि जब 150 किलोमीटर, 175 किलोमीटर आप अपने घर से उठ जिला हैडक्वाटर जाते हो तो आपको वहां पर कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं मिलता है, लेकिन जब वापस आते हो तो गांव और ढाणी को जाने के लिए आपको साधन नहीं मिलता है। एक जिले की सौगात पूर्व मुख्य मंत्री, अशोकजी गहलोत ने दी थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि अभी भा.ज.पा. की सरकार ने, माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से और वित्त मंत्रीजी से निवेदन है, मैं जानना चाहती हूं कि क्या आप अनूपगढ़ को जिला मानते हो? अगर जिला मानते हो तो जो आधारभूत सुविधाएं हमारे अनूपगढ़ जिले को दी जानी चाहिए थीं वे क्यों नहीं दीं आपने? हमारे जिला मुख्यालय पर, जो मेरा हैडक्वार्टर है, ..(व्यवधान)... आप बैठिए, माननीय सदस्य, आपको बजट बहुत दे दिया गया है विश्वनाथजी, आपके लगता विधान सभा क्षेत्र है, आपसे कोई चीज छिपी हुई नहीं है।

(श्रीमती शिमला देवी)

मानननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जिला मुख्यालय पर हमारी जो सी.एच.सी. थी उसको जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने की मैं मांग करती हूं। इसके साथ-साथ परिवहन कार्यालय की मैं आपसे मांग करती हूं, क्योंकि हमें 150 किलोमीटर दूर वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए गंगानगर जाना पड़ता है। इसके साथ-साथ हमारा जो घड़साना क्षेत्र है, वहां पर 30 से 35 हजार की आबादी है, उसके अन्दर पंचायत समिति है, उप खण्ड कार्यालय है, ए.डी.जे. कोर्ट है, वहां पर हमारी बहुत बड़ी धान मण्डी है, मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप घड़साना, 3 एस.टी.आर., 2 एस.टी.आर., 1 एस.टी.आर., ये जो 4 पंचायतें लगती हैं, वहां पर नगरपालिका देकर, जो हमारी निकासी से सम्बन्धित समस्याएं हैं, और भी बहुत-सी समस्याएं हैं, उनसे निजात मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं आपसे निवेदन करती हूं कि मेरे विधान सभा के जो क्षेत्र हैं, आपने भी अपने भाषण में कहा था, नशा बहुत है। मेरा विधान सभा क्षेत्र अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर बसा हुआ है, पिछले छह महीने में लगभग 10 बार ड्रोन के माध्यम से ड्रग्स और हेरोइन गिराई गई थी। हमारे जो युवा हैं वे नशे की चपेट में हैं। चार से पांच दिन में हमारे एक युवा की मृत्यु नशे से हो रही है। मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि आप विशेष टास्क फोर्स से इस पर निगरानी कीजिए और अनूपगढ़ के अन्दर आप छोटे-छोटे उद्योग-धंधे स्थापित करके वहां के युवाओं को, वहां की जनता को रोजगार दीजिए। नहीं तो, माननीय सभापति महोदय, जैसे हम उड़ता पंजाब की बात करते थे वैसा अनूपगढ़ बनने में कोई दो राय नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं नशे पर लगाम लगाने के लिए आपसे निवेदन करना चाहती हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र कृषि प्रधान है। हम सिंचाई के लिए पानी पर निर्भर करते हैं, लेकिन किसानों के सम्बन्ध में आप कह रहे हो कि हमने बहुत कुछ दिया है लेकिन गेहूं के ऊपर आपके घोषणा पत्र में 2,700 रुपये प्रति क्विंटल आपने देने की बात कही थी, अभी 2,275 प्रति क्विंटल प्लस 125 रुपये आपने बोनस दिया तो मात्र 2,400 रुपये हो रहा है वहां पर। ज्वार और बाजरा पर एम.एस.पी. की बात की, उसका क्या हुआ? बताइए आप। 300 रुपये प्रति क्विंटल किसान को नुकसान हो रहा है इसके अन्दर, किसान के लिए आप क्या कहेंगे? 2022 के अन्दर सरसों की

(श्रीमती शिमला देवी)

फसल जो हमारे पाळे के कारण खराब हुई थी, उसका सरकार ने सर्वे करवाया, लेकिन आज तक उसका मुआवजा किसानों को नहीं दिया, लगभग 40 हजार हमारे किसान उसके लिए भटक रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा मेरे रावला का है। पिछली बार समर्थन मूल्य के ऊपर क्रय-विक्रय सहकारी समिति के द्वारा हमारी सरसों की खरीद की गई थी, लेकिन उसके अन्दर बहुत बड़ा घोटाला बताया गया। बार-बार जांचें हो गईं, 14 जनवरी, 2024 को जांच हुई, जिसमें किसान सही पाये गये, लेकिन आज तक उन किसानों का भुगतान नहीं किया गया। राजफैड और क्रय-विक्रय सहकारी समिति में जो कर्मचारी थे, जो दोषी कर्मचारी थे, उनके खिलाफ आप लोग क्या कार्यवाही करेंगे?

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ लाइट और ऊर्जा के सम्बन्ध में बात करना चाहती हूं। आठआठ, दस-दस घंटे लाइट नहीं आती है, लेकिन मेरा मानना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 459 ढाणियां आज भी लाइट से वंचित हैं। 5 ढाणियों का समूह बनाकर हम लाइट देते हैं, लेकिन एक ढाणी के सम्बन्ध में आप लाइट की व्यवस्था आप करेंगे कि नहीं करेंगे? इसके साथ-साथ पिछली सरकार ने 100 यूनिट घरेलू कनेक्शन पर लाइट फ्री दी थी, इस पर आपको क्या कहना है? किसानों को फ्री कृषि कनेक्शन दिया गया और 2000 यूनिट लाइट हमें फ्री दी गई, क्या सरकार उस योजना को चालू रखेगी? इसके साथ-साथ हमारी वित्त मंत्रीजी एक महिला होने के नाते मैं मांग करती हूं कि घड़साना के अन्दर जो मेरा ढाई लाख आबादी का विधान सभा क्षेत्र आता है, वहां पर कोई भी कन्या महाविद्यालय नहीं है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि 12वीं के बाद एक गरीब बच्ची को शिक्षा के लिए उसके अभिभावक अगर कहीं भेजना चाहें तो प्राइवेट कालेज और संस्थाओं में वे अध्ययन नहीं करवा पाते, तो वहां पर कन्या महाविद्यालय की मांग मैं आपके माध्यम से सरकार से करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मेरा आप सभी से निवेदन है कि घग्गर नदी, जो हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से निकलते हुए हमारे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से होते हुए पाकिस्तान को पानी जाता है, उस पानी को अगर डैम बनाकर संचित किया जाए और जब नहर बंदी आती है आई.जी.एन.पी. की, उस समय इस पानी को किसानों को दिया जा सकता है।

श्री सभापति: विराजें। श्री लक्ष्मण राम।

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): इसके साथ-साथ मेरा आपसे निवेदन है कि महिलाओं के ऊपर जो बात होती है, (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सर, एक मिनट।

श्री सभापति: एक मिनट नहीं है। बहुत समय हो जाता है एक मिनट।

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): एक बात मैं कहना चाहती हूं। महिलाओं के ऊपर इस तरह की बातें आती हैं। आप घटनाएं देखिए, जिले देखिए...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये आप प्लीज। अंकित नहीं होगा।

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): 000

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे के लिए, सात बजे तक बढ़ाया जाता है।

श्री लक्ष्मण राम।

आय-व्ययक

परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2024-25 पर

सामान्य वाद-विवाद

श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान के वर्ष 2024-25 के बजट पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के सर्वांगीण विकास और आदरणीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने जो विकसित भारत का सपना देखा, उसे साकार करने के लिए नये राजस्थान के शिल्पकार आदरणीय मुख्य मंत्री भजन लाल शर्मा साहब, आपको इस ऐतिहासिक बजट के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।

(श्री लक्ष्मण राम)

साथ ही, प्रदेश की यशस्वी उप मुख्य मंत्री दिया कुमारी जी, जिन्होंने वित्त मंत्री के रूप में राजस्थान की दशा और दिशा सुधारने के लिए अभूतपूर्व रोडमैप को सदन के पटल पर रखा, जिन्होंने पांच साल तक राजसमन्द लोक सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर दिल्ली तक हमारी मजबूत पैरवी की, इसी बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र मीरा नगरी, मेड़ता का विशेष ध्यान रखा।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, एक समावेशी और सर्वजन हितार्थ बजट पेश किया गया। जिन विकास कार्यों की घोषणा की गयी, उनके क्रियान्वयन हेतु सरकार ने प्रयास शुरू कर दिये हैं। मेड़ता आजादी से पूर्व एक जिला था। पूर्ववर्ती सरकार ने जिलों की बन्दरबांट कर दी, लेकिन मेड़ता को वंचित रखा। मेड़ता में विगत 20 वर्षों के बाद पहली बार इतनी सौगातें मिली हैं। इससे पूरे मेड़तावासी प्रसन्न हैं। क्षेत्रवासियों की ओर से मैं हमारी भा.ज.पा. सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में चिकित्सा से जुड़ी व्यापक समस्याएं हैं। मैंने विधान सभा चुनाव में हाथ फैलाकर मेरे क्षेत्र की जनता से वोट मांगे तो मेड़ता उप जिला अस्पताल खुलवाने का वादा किया था।

आपको धन्यवाद दूंगा कि मेड़ता की देवतुल्य जनता को आपने उप जिला अस्पताल की सौगात दी। माननीय चिकित्सा मंत्री बैठे हैं, इनका भी धन्यवाद देता हूं मैं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेड़ता की कृषि उपज मण्डी, जो विश्वभर में प्रसिद्ध है, उसके विस्तार हेतु बजट घोषणा की गयी। सभापति महोदय, मेड़ता मण्डी में नागौर, जोधपुर, पाली, अजमेर, बीकानेर से किसान मूंग व जीरा बेचने आते हैं। मण्डी में आवक ज्यादा और जगह कम होने से दूर-दराज से जब गरीब किसान मण्डी पहुंचता है, उसे बेमौसम बारिश का सामना करना पड़ता है। धरती का सीना चीरकर अन्न उपजाने वाले किसान को जब मैं कृषि मण्डी में समस्याओं का सामना करते हुए देखता था तो मैंने संकल्प किया कि मेरे किसान भाइयों की राहत के लिए कुछ करूं।

माननीय सभापति महोदय, सरकार ने जीरा प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की घोषणा बजट में की है। देश में गुजरात की ऊंझा मण्डी के बाद सर्वाधिक जीरे का व्यापार मेड़ता कृषि मण्डी में होता है। जीरा प्रोसेसिंग यूनिट से किसानों को ग्रेडिंग की सुविधा मिलेगी और उस जीरा फसल के मूल्य निर्धारण

(श्री लक्ष्मण राम)

में उन्हें बड़ा फायदा होगा। सभापति महोदय, बजट में मेड़ता के कस्बों और नगरपालिका की विभिन्न सड़कों की घोषणा की है। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। हमारे मंत्री महोदय विराजमान हैं, इनका भी धन्यवाद देता हूं। पूर्व मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी ने प्रदेश में पांच जगह तिलम संघ के प्लांट लगाये थे, जिनमें से एक प्लांट मेड़ता में लगाया था, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता से वह बंद हो गया। मेरी मांग है, तिलम संघ मेड़ता प्लांट को पुन: शुरू करें, ताकि किसानों को लाभ मिले और लोगों को रोजगार मिले।

माननीय सभापति महोदय, मेरी मेड़ता में तीन बड़े कस्बे - रेण, पादू कलां, जसनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित हैं। रेण कस्बे की जनसंख्या करीब 10 से 15 हजार व पादू कलां और जसनगर की जनसंख्या 7 हजार है। पड़ोस के 20-30 गांवों से सीधा जुड़ाव है। तीनों जगह ही प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र हैं। अत: इन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की मैं आपसे मांग करता हूं। कन्या महाविद्यालय खोलने की भी मैं मांग करता हूं। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार को अवगत कराना चाहूंगा, मेरे मेड़ता विधान सभा क्षेत्र में गांव तुकलिया, धनापा, बासनी, पूंदलू में काश्तकारों की सैकड़ों बीघा जमीन पर आर.एस.एम.एम. ने नोट लगा दिया, जिससे वे न तो भूमि पर खेती कर पाते हैं और न ही खनन कार्य कर सकते हैं। अत: किसानों के हित में निर्णय लेकर वह नोट हटाया जाए।

नेशनल हाईवे से जो रास्ता गुजरता है, वह संकरा होने और ज्यादा आबादी के कारण वहां घंटों जाम लग जाता है। जसनगर कस्बा, जहां से तीन फैक्टरियां हैं, सीमेंट फैक्टरी, बहुत बड़ा जाम लगता है, डेली तीन-चार घंटे जाम लगता है। अत: मैं आपसे मांग करता हूं कि जसनगर बाईपास बनाने की आप कृपा करें। मेड़ता में भीड़-भाड़ और काफी ट्रैफिक रहता है, वहां भी रिंग रोड बनाने का आप काम करें। माननीय सभापति महोदय, जो गाड़िया लोहार जाति, जो एम.बी.सी. में आते हैं, उनका रहने-खाने का कोई ठिकाना नहीं है। सर्दी, गर्मी और बारिश में वे बहुत परेशान होते हैं। उनके आवास भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। हमारी सरकार को इनके हितों का ध्यान रखते हुए गरीब गाड़िया लोहारों को आवास उपलब्ध कराने चाहिये।

एक समस्या इनकी और है। लोहार घुमन्तू जाति को एम.बी.सी. में लिया तो गया है, लेकिन उनके जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं, जिसकी वजह से आज इनके बच्चों को सरकारी नौकरियों सहित अनेक सरकारी

(श्री लक्ष्मण राम)

योजनाओं में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अत: उनके जाति प्रमाण पत्र बनाने का भी नोटिफिकेशन सरकार जारी करे। राजस्थान में एक बहुत छोटी जाति है, जिसे जंगलिया जाति कहते हैं। वे खेतों की रखवाली करते हैं और अपना जीवनयापन करते हैं। वे सबसे गरीब जातियों में से हैं, लेकिन वे ओ.बी.सी. में आते हैं। उन्हें कोई फायदा नहीं मिल रहा है। मैं पूरे सदन से, पक्ष से, विपक्ष से निवेदन करता हूं कि आप लोग इसकी ओर देखेंगे और गरीब लोगों को आप फायदा देंगे।

मेरे विपक्ष के साथी पिछले तीन-चार दिनों से बिजली पर बात कर रहे हैं कि बिजली नहीं मिल रही है। साथियों, हमारी सरकार बने छह महीने हुए हैं। मैं कहना चाहूंगा, क्या हमारी सरकार ने आपके खम्भे पाड़ लिए, क्या हमने ट्रांसफार्मर्स उखाड़ दिये? सारी गलती आपकी है। हम पर क्यों थोंप रहे हैं? हमने तो आते ही उस पर काम चालू कर दिया है। अत: आप अपनी करतूतों का दोष दूसरों को न दें। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत। जय भीम। जय संविधान।

श्री सभापति: श्री धर्मपाल।

श्री धर्मपाल (खेतड़ी): सभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपको साधुवाद। सर्वप्रथम, मैं बजट पर अपनी बात को इस शेर के माध्यम से कहना चाहता हूं-

"पीर हो गयी है पर्वत सी,
अब यह पिघलनी चाहिये,
हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिये,
जो आग मेरे दिल में है,
हर दिल में जलनी चाहिये,
हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,
मैं चाहता हूं कि मेरे इस प्रदेश की तस्वीर बदलनी चाहिये,
तकदीर बदलनी चाहिये।।"

तस्वीर और तकदीर बदलने का यह प्रयास हमारी सरकार ने किया है, भजन लाल जी ने किया है और वित्त मंत्री जी ने किया है, इस बजट के माध्यम से किया है। बजट सर्वांगीण विकास का बजट है। हर ग्रामीण का है, हर शहरी का है, हर गरीब का है, हर अमीर का है, हर युवा का है, हर बुजुर्ग

(श्री धर्मपाल)

का है, हर माता का है, हर बहन का है। सभी वर्गों को समर्पित यह बजट देने के लिए मैं पुन: एक बार भजन लाल जी की सरकार को और हमारी वित्त मंत्री महोदया को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। समय-सीमा की पाबन्दी रखते हुए मैं अपनी बात निश्चित रूप से पांच मिनट में समाप्त करने का प्रयास करूंगा। मैं इधर-उधर की बातें नहीं करके सीधा अपने मुद्दे पर आता हूं।

कुछ विषय मेरे विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी से जुड़े हैं। जो खेतड़ी ताम्र नगरी के रूप में जानी जाती है, जो विवेकानन्द की स्थली के रूप में जानी जाती है, विवेकानन्द नगरी के रूप में जानी जाती है, अरावली की पहाड़ियों और वादियों से जो घिरी हुई है, वहां पर जो बजट में दिया है, मैं समझता हूं, मैंने पूरा बजट पढ़ा है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 74.5 करोड़ की रोड देकर इस क्षेत्र में विकास को गतिमान बनाया गया है, उसके लिए पुन: मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। पीएच.सी. से सी.एच.सी. कन्वर्ट की गयी है। अन्य जो सुविधाएं दी गयी हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

विशेष रूप से मैं सदन का दो चीजों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यमुना जल का जो समझौता हमारी शेखावाटी में हुआ, निश्चित रूप से वह शेखावाटी के लिए वरदान है। इस वरदान के लिए मैं पूरा श्रेय सरकार को देना चाहता हूं, ई.आर.सी.पी. की परियोजना की तरह ही जो लम्बित थी, हमारी भी शेखावाटी की यमुना जल समझौते की जो एक योजना थी, उसका एम.ओ.यू. करके हमें जो एक सौगात प्रदान की है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। शेखावाटी का एरिया जो सबसे सूखा एरिया था, उसे पानी पिलाकर, वहां पानी का संरक्षण करके जो यमुना जल समझौता किया है, उसकी अगर डी.पी.आर. बने तो मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि उस डी.पी.आर. में खेतड़ी क्षेत्र में चार बांध बहुत बड़े हैं, हम नहीं कहते कि हमें नहर से पानी दीजिए, हम और ज्यादा मांग नहीं करते, सिर्फ हमारे चार बांध-अजीत सागर बांध, रवा बांध, इलाखर मोड़ी बांध और कालाबुझा बांध, इनमें अगर यमुना जल का पानी डाल दिया जाए तो मैं समझता हूं, यह हमारे खेतड़ी के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा।

(समय: 18.00 बजे)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी कैबिनेट की बैठक में नागरिक उड्डयन का हमारे एक फैसला हुआ है। मुझे आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि 555 गांवों की रियासत खेतड़ी, वहां पर राजा के समय से,

(श्री धर्मपाल)

रियासतकाल के समय से एक ग्राउंड आबंटित है, जो लगभग 54.39 हैक्टेयर है, हमारे मापदंड के अनुसार 500 बीघा का एक ग्राउंड है, जो जमाबन्दी में हवाई जहाज के मैदान के नाम से अंकित है और अभी हमारा फैसला हुआ है कि उसको या तो हरित में कन्वर्ट किया जाए या फिर मूलभूत सुविधाएं वहां पर दी जाएं।

मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे बबई के क्षेत्र में, जो प्रतापपुरा ग्राम के अन्दर आता है, इस हवाई पट्टी को विकसित किया जाए, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। खेतड़ी नगरपालिका रियासतकाल की नगरपालिका है, 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। आज तक यह 'डी' श्रेणी की कैटेगरी में आती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 'डी' श्रेणी की कैटेगरी को 'सी' श्रेणी में क्रमोन्नत कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि नगरपालिका की इन्कम और नगरपालिका का रुतबा, नगरपालिका का महत्व और खासियत बढ़ेगी। नागरिक उड्डयन का मैंने जिक्र किया है।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां शेखावाटी एक बहुत पढ़ा लिखा क्षेत्र है और यहां पर शिक्षा का प्रभाव, शायद, मैं समझता हूं कि पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा है। अगर हमारे खेतड़ी में महिला पॉलिटेक्निक कालेज खोला जाए तो मैं समझता हूं कि सरकार का बहुत बड़ा उपक्रम होगा।

(समय: 18.01 बजे)

(श्री फूल सिंह मीणा, सभापति, पदासीन)

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में सिर्फ तर्क-वितर्क करके एक दूसरे को बोलने से रोकने के लिए यह सदन चलता है तो मैं समझता हूं कि यह बहुत पीड़ा का विषय है। मैं हमारे सभी बन्धुओं से निवेदन करता हूं, पक्ष से भी निवेदन करता हूं, विपक्ष से भी निवेदन करता हूं कि सदन में गरिमामय बात या विकास की बात की जायेगी तो मैं समझता हूं कि सदन में हम लोगों का आना सार्थक है वरना एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करके सदन का समय जाया किया जाए तो मैं समझता हूं, मैं तो नया हूं, पहली बार चुनकर आया हूं, मैं इस सदन के बारे में इतना जानता भी नहीं हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं, पिछले कई दिनों से सिर्फ इसको एक हास्य का विषय बनाकर सदन का समय लिया जाता है। हो सकता है, मैं गलत होऊं, आपकी उपेक्षाओं की हिसाब से लेकिन मुझे विशेष रूप से पीड़ा होती है। आपको ढाई लाख और पांच लाख जनता चुनकर भेजती है और हम यहां आकर सदन का

(श्री धर्मपाल)

समय, जहां से राज्य का भाग्य लिखा जाता है, हर क्षेत्र का भाग्य लिखा जाता है, इसलिए आग्रह करता हूं कि इसको सीरियसली और गम्भीरता से लेंगे तो सदन का महत्व होगा और हमारा भी यहां आना सार्थक होगा।

मैं तो इतना ही कह सकता हूं विपक्ष के भाइयों से पुन: एक बार इसी गरिमा की बात करते हुए, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोगों ने भी राज किया है। राजस्थान की परम्परा भी एक बार हम और एक बार आपकी रही है, लेकिन इस बार जो हमने शुरुआत की है और इस बजट में जो शुरुआत की है, इस बजट को एक महत्वाकांक्षी बजट बनाया है, निश्चित रूप से मैं कठोर शब्दों में इस सदन के माध्यम से कह सकता हूं कि इस बार एक बार हम और एक बार तुम की परम्परा टूटेगी और अगली बार भी 2028 में भारतीय जनता पार्टी आयेगी, क्योंकि हमारी शुरुआत ही ऐसी है, हमारा आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। मैं यही निवेदन आप लोगों से करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ था।

टोका-टाकी हो और मुझे सभापति जी बैठने के लिए कहें, उससे पहले ही मैं अपनी बात समाप्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको राम-राम।

श्री सभापति: श्री पब्बाराम जी विश्नोई।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, सात मिनट का अल्प समय और अपने विषय के प्रति न्याय कर पाना किसी भी वक्ता के लिए कम समय होता है। फिर भी, मैं अपने समय के अन्दर अपनी पूरी बात करने की चेष्टा करूंगा।

विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की एन.डी.ए. सरकार, 65 वर्षों के बाद तीसरी बार पुन: सरकार बनाना, इस देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जायेगा। मैं इस सदन के पटल से माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूं।

प्रदेश के युवा और यशस्वी मुख्य मंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में यह पहला पूर्ण बजट है, जिसकी हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोगों के द्वारा प्रशंसा की जा रही है, यहां तक कि विपक्ष और आम जनता के द्वारा भी इसकी प्रशंसा की जा रही है। यह राज्य के समग्र विकास का एक तरह से रोड मैप है। हमारे घर के बजट को महिला ही संधारित करती है। महिला से ज्यादा कोई नहीं जानता कि बजट को किस प्रकार से समावेशी करना चाहिए।

(श्री पब्बाराम विश्नोई)

हमारे राज्य की वित्त मंत्री महिला हैं राजकुमारी दिया कुमारी जी और हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी भी महिला हैं। सबसे ज्यादा महिलाओं को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। इसके लिए मैं माननीय नरेन्द्र मोदी जी और भजन लाल जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

महिला सशक्तीकरण का यह अनुपम उदाहरण है, अद्वितीय उदाहरण है। मैं शानदार और विकासोन्मुखी बजट के लिए दिया कुमारी जी को और माननीय भजन लाल जी शर्मा, प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री को बधाई देता हूं। यह बजट ऐसी परिस्थिति में आया है जब हमें विरासत में खजाना खाली मिला है। मैं एक काव्य पंक्ति कहकर अपनी बात को शुरू करता हूं।

'कुछ तो फूल खिलाये हमने, कुछ तो फूल खिलाये हमने,
और कुछ फूल खिलाने हैं,
मुश्किल है ये, बाग़ में अब कांटे कई पुराने हैं, कांटे कई पुराने हैं।'

हम उन कांटों को निकालकर सहेजकर पुष्प खिलाने का काम करने जा रहे हैं। यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल जी के द्वारा किये गये बहुत सारे काम हैं, जिनकी सूची हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताई है, फिर भी मै कुछ कह देता हूं। जैसे, पेपर लीक माफियाओं पर एस.आई.टी. की कठोर कार्रवाई की। आइन्दा से कोई भी इस तरह का काम करते हुए थरथर कांपेगा। 450 रुपये में उज्ज्वला गैस सिलेंडर, आयुष्मान के अन्दर बड़ा लाभ, भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस, सी.बी.आई. को अनुमति दे देना। आप सी.बी.आई. को अनुमति नहीं दे रहे थे, हमने दे दी है।

महिला अपराध में थानागाजी जैसी घटना जिस प्रकार आपके समय में हुई, वह दुर्भाग्यपूर्ण था। आपके उस समय के मंत्री जी थे, जिन्होंने कहा कि यह मर्दों का प्रदेश है। इस प्रकार के वक्तव्य के द्वारा सम्पूर्ण महिला समाज में उनके बारे में आप लोगों ने सोच विकसित की, उस सोच की मैं निन्दा करता हूं।

जल जीवन मिशन के अन्दर आप लोगों ने जिस प्रकार के घोटाले किये, उन घोटालों को आज भी हम सहन कर रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इन्होंने तेरा और मेरा, अपने और पराये के हिसाब से सर्वे कराये हैं। उस सर्वे के हिसाब से आज भी जो-जो अधिकारी बैठे हैं, सर्वे में यह नाम आया, 20 से 25 परसेंट घर पानी से जोड़ने से छूट रहे हैं। यह हमारे लिए

(श्री पब्बाराम विश्नोई)

गली की हड्डी बन जायेगा। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि पुनः सर्वे करवाकर सभी को जोड़ा जाए, ताकि सभी के घर में नल से जल पहुंचे, जैसी हमारे प्रधान मंत्री जी की मंशा है।

अन्नपूर्णा रसोई में 450 ग्राम से लेकर 600 ग्राम किया, न तो भूखा रहता था और न पेट भरता था कांग्रेस शासन में। अब अन्नपूर्णा में 600 ग्राम भरपूर भोजन दिया जा रहा है। ई.आर.सी.पी. के साथ यमुना जल समझौता, आधा राजस्थान सरसब्ज हो जायेगा और पीने का पानी मिलेगा। 21 जिले वो और 4 जिले ये, आधा राजस्थान इस योजना के द्वारा सम्पन्न होगा। इसके अलावा फलौदी को जिस प्रकार की सौगातें पहली बार मिली हैं, मैं तीसरी बार सदन में हूं, पर पहली बार फलौदी को जितनी सौगातें दी हैं, मैं अभिभूत हूं, मैं प्रसन्न हूं, उद्वेलित हूं कि आपने किस प्रकार से हमारे फलौदी को नवाजा है।

हमारे जोधपुर जिले को जयपुर से जोधपुर और जयपुर से फलौदी के लिए दो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस हाईवे दिये, जिसमें फलौदी का 345 किलोमीटर का सीधा एक्सप्रेस हाईवे पूरे पांच साल में बनकर तैयार होगा। जिस प्रकार से हम कांडला से अमृतसर की तरफ जाते हैं, मेरे क्षेत्र में सांचोर के लिए लोहावट से जब चढ़ता हूं, पहले हमें साढ़े छह से सात घंटे लगते थे, आज ढाई घंटे में सांचोर पहुंचता हूं। इस प्रकार के हाईवे बनने वाले हैं बहुत बड़ी सौगात दी है। फलौदी में कन्या महाविद्यालय दे दिया। खीचन कंजर्वेशन, आप कुरजां देखने के लिए यहां पर आते हैं, जिस पर गीत बने हैं, 'कुरजांए म्हारो भंवर मिला दे', इस प्रकार से देखने के लिए आप आते हैं। चिमाणा में सहायक अभियन्ता, डिस्कॉम दे दिया। आयुष्मान मॉडल, सी.एच.सी., महिला थाना। किसानों के बहुत-बड़ा दिया है...

श्री सभापति: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, बस दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं।

165 करोड़ रुपये की लागत से जम्बेश्वर लिफ्ट और जयनारायण लिफ्ट में 30,250 हजार हैक्टेयर स्प्रिंकलर सिंचाई की सुविधा, जिला अस्पताल, फलौदी में अतिरिक्त बजट फलौदी, शेखासर, राणेरी बारू के लिए बीस करोड़ की लागत से। अभी-अभी कह रहे थे कि मिसिंग लिंक नहीं दे रहे हैं। मैं विपक्ष के माननीय शर्मा जी से भी निवेदन करूंगा कि आपने क्या

(श्री पब्बाराम विश्नोई)

किया, हमारे साथ में। आपके अभी के प्रदेशाध्यक्ष ने सदन में कहा था कि आपको मिसिंग लिंक काहे को दें और हमारी मिसिंग लिंक काट दी, फिर वही सास भी कभी बहू थी, आपके ऊपर भी यह लागू होता है। अगर हम यह कहें कि आपको मिसिंग लिंक काहे को दें, तो क्या गुजरेगी आपके ऊपर। आपको देखना चाहिये, सोचना चाहिये। इसी प्रकार से एक विषय पूरा कर दूं मैं। एक विषय को पूरा करके मैं बात पूरी करता हूं।

चलो, मैं बात को पूरा कर देता हूं चार लाइनें पढ़ करके इस बजट के बारे में। माननीय सभापति महोदय, मैं आधा मिनट में बात समाप्त करता हूं। प्लीज।

'इस मोड़ पर घबरा कर न थम जाइए आप,
जो बात नयी है उसे अपनाइये आप।
डरते हैं आप नयी राह पर चलने से क्यों,
हम आगे-आगे चलते हैं और आप पीछे-पीछे आ जाइए।'

धन्यवाद। जय भारत।

श्री सभापति: श्री मनोज कुमार (सादुलपुर)।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे परिवर्तित बजट 2024-25 पर बोलने का मौका दिया। मैं एक छोटे से दोहे के साथ अपनी बात को शुरू करता हूं।

'कर्म भूमि पर फल के लिए सबको श्रम करना पड़ता है,
रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है।'

वित्त मंत्री महोदया जी ने, माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी ने बजट में मेरे सादुलपुर का एक बार भी नाम न लिया हो चाहे, हमें तो हर लफ्ज में सादुलपुर-सादुलपुर रटना ही पड़ता है।

माननीय सभापति महोदय, फिर भी मैं मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री महोदया का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि न रहे मजबूरी में भी हमारा नाम, आपके मॉडल सी.एच.सी. के माध्यम से, आपके आंगनबाड़ी के माध्यम से, आपके पांच करोड़ रुपये सड़क के माध्यम से हमारे सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र में जो आया, उसके लिए आपका धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं लम्बी-चौड़ी बातें न करते हुए सीधा

(श्री मनोज कुमार)

मुद्दे पर आता हूं। इन्होंने बिजली पानी जो हमारे एक-एक आम सदस्य की गम्भीर समस्या है, ये भी नहीं बोल पा रहे हैं, ये बोलते हैं तो इनको विपक्ष की बात कहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक ये सरकारें आम मूलभूत सुविधा बिजली और पानी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है वे दोनों सरकारें 75 वर्षों में इस राजस्थान के आम नागरिक को देने में असफल रही हैं। जल जीवन मिशन जिस तरीके से भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा बना, उसकी जांच के लिए ये सरकारें कहती रही हैं, लेकिन ये आने के बाद उसकी जांच कराने में आज भी विफल रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, जल जीवन मिशन के माध्यम से धरातल की स्थिति यह है कि हर घर नल होगा, लेकिन हर घर जल नहीं होगा। इसको योजनाबद्ध तरीके से पूरे राजस्थान में, माननीय प्रधान मंत्री महोदय का जो मूल उद्देश्य और भाव है, जिस उद्देश्य से जनता को लाभ मिलना चाहिये था, इसकी मॉनिटरिंग करके सरकार हर घर तक जल पहुंचाने की प्लानिंग करे, जिससे जनता को लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरीके से बिजली में पिछली सरकार ने सौ यूनिट बिजली मुफ्त में देने की बात की। उस मुफ्त का परिणाम रहा कि बिजली तार से चली गई और परमानेन्ट मुफ्त हो गई। यह सरकार आने के बाद पिछले दो माह में, चाहे इधर के सदस्य रहे हों, चाहे उधर के सदस्य रहे हों, चाहे हम रहे हैं, सबने इन दो महीने में जो बिजली के लिए भुगता है, ऐसी व्यवस्था को सुचारु करें, जिससे जनता को बिजली मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना जो लागू की है, मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधान मंत्री जी और राजस्थान सरकार को, लेकिन उसको एक फ्लैगशिप योजना बनाकर हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए, तब जाकर इसका लाभ मिलेगा, नहीं तो कहीं न कहीं यह योजना, फिर कागजों के चक्कर में जनता घूमती रहेगी। ऑनलाइन के चक्कर में जनता घूमती रहेगी और कनेक्शन नहीं मिल पायेंगे। इसलिए अब विद्युतीकरण के लिए एक लाख पैंतालीस हजार किसानों को 31 मार्च, 2024 तक तो इन्होंने बजट में कहा है कि हम कनेक्शन देंगे।

माननीय सभापति महोदय, सरकार के हालात ये हैं कि पिछले दो साल से लोगों के घरेलू और किसानों के कनेक्शन आज भी पेंडिंग हैं, और सामान के अभाव के कारण उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए इनकी

(श्री मनोज कुमार)

व्यवस्था करें तभी दे पायेंगे, नहीं तो आपकी पेंडेंसी दो साल 31 मार्च, 2024 की जब तक आप पूरा करोगे, तब तक आपकी दो साल की पेंडेंसी, आज इनके कारण है, वह आपके कारण हो जायेगी।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा दूसरी बात, बहुत गम्भीर विषय है। गांव में आबादी विस्तार, गांव में बसता है हिन्दुस्तान और उसका आबादी विस्तार, पिछले पचास वर्ष में किसी भी सरकार ने इन गांवों के विस्तार के लिए विचार नहीं किया। लोग जाकर गोचर भूमि में निवास कर रहे हैं। सरकार की कोई भी योजना, विकास की जो आती है, पहली बाधा है गोचर भूमि में उन लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार गोचर भूमि में बसे हुए लोगों को, जो सरकारी सुविधाएं हैं, जब तक वे लोग बसे हुए हैं, तब तक उन लोगों को सुविधाएं देने का प्रयास करे और उनको सुविधा देने का काम करे।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ आबादी विस्तार करने के लिए सरकार गम्भीरता से विचार करे। गांव में अगर आबादी विस्तार नहीं होंगे तो गांव के लोग कहां बसेंगे, यह बहुत बड़ा विषय है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कह रहे थे कि तीन करोड़ लोगों को हम प्रधानमंत्री आवास देंगे। आप कैसे दोगे, जो लाभार्थी हैं, जिनके पास मकान नहीं हैं जिनके पास जमीन नहीं है, वो या तो गोचर में बसे हुए हैं, वो भूमिहीन लोग हैं, जिनको वास्तविक लाभ मिलना चाहिये, उनको नहीं मिल पायेगा। इसलिए सरकार इस प्रधानमंत्री आवास योजना में भूमि की व्यवस्था साथ-साथ करने का प्रयास करे।

माननीय सभापति महोदय, आजादी के बाद देश की जनसंख्या खूब बढ़ी है और जनसंख्या बढ़ने के कारण इनका विस्तार किया जाना अति आवश्यक है। इसलिए इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूं। इन्होंने घुमन्तू जातियों की एक बार चर्चा की, लेकिन कभी सरकार ने इस बात पर भी विचार किया कि घुमन्तू जातियों को आज तक स्थायीकरण करने के लिए, उनको बसाने के लिए, उनका ठहराव करने के लिए किसी भी सरकार ने विचार नहीं किया, इसलिए इन घुमन्तू जातियों के ठहराव के लिए पूर्ण रूप से...(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मेरी पार्टी से मैं अकेला बोलूंगा, दस मिनट का मेरा समय है। इसलिए मैं दस मिनट में मेरी बात पूरी करूंगा।

श्री सभापति: अठारह वक्ता और हैं, माननीय सदस्य।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): वो हैं, माननीय सभापति महोदय, मेरी पार्टी का मैं दस मिनट का समय लेना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं किसान की बात करना चाहता हूं। किसान के लिए किसान फसल बीमा एक बहुत बड़ी योजना है जिसका किसान को लाभ मिलना चाहिये था, लेकिन किसान के साथ अन्याय होना शुरू हो गया है। किसान के प्रीमियम की जब बात आती है तो सरकार एक तारीख निर्धारित करती है, एक दिन भी अगर देरी हो जाए तो किसान अपना बीमा नहीं करवा सकता। अगर देरी के कारण वह बीमा नहीं करवा सकता तो फिर किसान को क्लेम देते समय सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है। दो-दो वर्ष से मेरे विधान सभा क्षेत्र में खरीफ 2018, 2022, 2023 और रबी 2024 का क्लेम आज तक बीमा कम्पनी ने नहीं दिया और बीमा कम्पनी असत्य आपत्तियां लगाकर बीमा में देरी करने का प्रयास कर रही हैं। मैं मांग करता हूं सरकार से कि आप किसानों को जब भी जितनी देरी बीमा कम्पनी के कारण होती है, उतना ब्याज किसान को क्लेम के साथ दिलाने की कोई योजना बनाए।

सभापति महोदय, एम.एस.पी. की बात है। केन्द्र सरकार ने एम.एस.पी. की रेट बढ़ाई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सदन में। एमएस.पी. की रेट तो बढ़ा दी, लेकिन किसान जब एम.एस.पी. पर बेचने जाता है उस समय किसान के क्या हालात हैं, किसान को एम.एस.पी. का लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं कि किसान को पूरे बारह महीनों में कभी भी किसान अपनी उपज को जब बेचना चाहे उस समय किसान को एम.एस.पी. का लाभ मिलना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, एक-दो मैं मेरी मांग करना चाहता हूं आपके माध्यम से, एक तो नहर का मुद्दा जो दिया, मेरे वहां सिद्धमुख नहर की मुरब्बाबंदी और चकबंदी का बहुत बड़ा पुराना मुद्दा है। सरकार इस बजट का जब प्रतिउत्तर दे तो हमारी उस नहर से वंचित किसानों को लाभ देने के लिए मुरब्बाबंदी और चकबंदी की घोषणा करे। सरकार ने कल मेरे प्रश्न को सदन में स्थगित कर दिया। उस यमुना पाइप लाइन का जो एम.ओ.यू. हुआ..

श्री सभापति: श्री विनोद कुमार।

(आसन द्वारा संकेत से अंकित न करने के निर्देश)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): 000

श्री विनोद कुमार (पीलीबंगा): सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपकी बात हो गई। माननीय सदस्य, आपका समय चालू है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): 000

श्री विनोद कुमार (पीलीबंगा): ...(व्यवधान) सभापति महोदय, मैं खेतरपाल महाराज की नगरी से आता हूं। (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): 000

श्री विनोद कुमार (पीलीबंगा): सभापति महोदय, हमें तो फेसबुक पर पता चला कि हम पंजाब से सटे हुए, पाकिस्तान से सटे हुए हैं और बजट को देख कर लगा कि कहीं हमें पाकिस्तान या पंजाब में शामिल तो नहीं कर दिया गया। क्योंकि कालीबंगा सभ्यता की जब बात की गई, आई.ए.एस. का एग्जाम हो, बड़े-बड़े एग्जाम हों तो कहीं न कहीं कालीबंगा का जिक्र आता है। हमारे सुमित गोदारा जी प्रभारी मंत्री हैं, वह भी जाकर आयेंगे और आप सब भी कालीबंगा में आइए। इस कालीबंगा के लिए इसमें एक रुपये के बजट का भी प्रावधान नहीं किया गया। धार्मिक स्थलों के लिए बातें की गईं, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने राजस्थान के बहुत से धार्मिक स्थलों को बजट का आबंटन किया। मैं खेतरपाल महाराज की नगरी से आता हूं, हम चाह रहे थे कि आप वहां के लिए भी कुछ न कुछ प्रावधान करते तो हम भी आपका धन्यवाद करते। आपने डाक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बात की। इस बजट में कुछ पंक्तियां निदा फाजली जी की और मिर्जा इस्माइल जी का भी जिक्र किया और धार्मिक सद्भाव की भावना आपके इस बजट में देखने को मिली। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा।

हमारे स्वायत्त शासन मंत्री जी बैठे थे, नगरपालिकाओं की स्थिति पर विचार करने के लिए मैं मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा, क्योंकि ये बार-बार कहते हैं कि अगर कोई सही विचार होगा तो हम शामिल करेंगे। आज नगरपालिका के लिए जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट से पैसा आता है ...(व्यवधान) टी.वी. में मनोज कुमार की जगह विनोद कुमार (पीलीबंगा) करवा दो।

श्री सभापति: आपने यहां लिख कर दिया है। आपके नेता, प्रतिपक्ष जी ने लिख कर दिया है। (व्यवधान)

श्री विनोद कुमार (पीलीबंगा): टी.वी. पर मनोज कुमार आ रहा है।

(श्री विनोद कुमार)

सभापति महोदय, पूरे राजस्थान की 90-100 नगरपालिकाएं ऐसी हैं, जिनमें हमारी नगरपालिकाओं को टैक्स जमा करवाना था। उसमें कहीं न कहीं हमारे अधिकारियों की गलती रही, टैक्स जमा नहीं करवा पाने की वजह से, मैं पीलीबंगा का एक उदाहरण देना चाहूंगा कि 4-5 लाख रुपये जमा करवाने थे, लेकिन 4-5 करोड़ रुपये का नुकसान नगरपालिका को हुआ। पूरे राजस्थान को इसका नुकसान हुआ, इस पर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, पेयजल में, जे.जे.एम. और बहुत-सी पुरानी स्कीमें हैं, जैसे 22 आर.डब्ल्यू.डी. सुभाष चन्द बोस, नहरा वाली ढाणी, 22 आर.डब्ल्यू.डी. स्वामी विवेकानन्द स्कीम। ये स्कीमें पूर्व में ग्रामीणों द्वारा चलाई जा रही थीं, लेकिन अब उनकी वित्तीय हालत ऐसी नहीं है कि वे उसको चला सकें। इनको गवर्नमेंट अपने अंडर में लेकर जे.जे.एम. स्कीम से जोड़ें।

सिंचाई के लिए हमारी सरकार ने 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। हमारी एक ग्राम पंचायत में 5 या 7 चक आते हैं और 15-20 मुरब्बों का एक चक होता है। आपका जो 10 करोड़ का बजट है, इसमें 300 मुरब्बा खाला भी मुश्किल से बनेगा। साढ़े तीन लाख या चार लाख रुपये एक मुरब्बे खाले में लगते हैं। यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि इसको बढ़ाया जाए। हमारे यहां सेम ग्रस्त इलाका है। पीलीबंगा और रावतसर में खालों की हालत बहुत दयनीय स्थिति में है और किसान की हालत आप सब देख रहे हैं कि इन सालों में बहुत बुरी हुई है। इसलिए पीलीबंगा को भी इसमें शामिल किया जाए।

जिस तरह से सरकारें आईं-गईं, आती रहेंगी, ऊर्जा के क्षेत्र में अगर गरीब आदमी को आप तीन किलोवाट का मुफ्त सोलर सिस्टम दे दोगे, क्योंकि 78-80 हजार रुपये सेन्ट्रल गवर्नमेंट दे रही है, अगर राज्य सरकार भी इसमें कुछ अनुदान दे दे, क्योंकि 1 लाख 80 हजार रुपये भरने के बाद 78-80 हजार रुपये उसको अनुदान मिलते हैं, इतने रुपये उस व्यक्ति के पास होते नहीं और सोलर उसके लगता नहीं। अगर ऐसा प्रावधान राज्य सरकार करे तो मैं भी उसका स्वागत करूंगा। सरकार अगर किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए दिन में बिजली देने का विचार रखती है, तो दिन में बिजली दी जाए।

माननीय सभापति महोदय, सड़क की बातें करें तो हमारे 10-12 विधान सभा क्षेत्र जयपुर से लेकर लगते हैं। यह बड़ी सड़क है, इसको फोर लेन किया जाए, तो हमें भी जयपुर आने में आसानी होगी, नहीं तो जयपुर आने के

(श्री विनोद कुमार)

लिए बार-बार सोचना पड़ता है और एक्सीडेंट की सम्भावना भी बनी रहती है। इमरजेंसी में हमें बड़ी मुश्किल होती है, जयपुर के हास्पिटल की फैसेलिटी नहीं मिल पाती। पीलीबंगा में आर.ओ.बी. निर्माण की हमने हमेशा बात रखी है। पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र के गोलूवाला में भी रोडों की हालत बहुत खराब है उनको भी जल्द किया जाए। परमल धान की पंजाब-हरियाणा के एम.एस.पी. पर जब खरीद चालू होती है तो वह एक महीना लेट होती है, उसको भी आप समय पर चालू करावें और शुगर मिल स्थापित करने की बात करें। बहुतबहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री ताराचन्द जैन।

श्री ताराचन्द जैन (उदयपुर): माननीय सभापति महोदय, मुझे भजन लाल सरकार के 2024 के बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आभार। यह बजट सर्व समाज के सर्वांगीण विकास हेतु ऐतिहासिक बजट है। इस बजट के माध्यम से राजस्थान सरकार द्वारा समाज के प्रत्येक वर्ग, महिला, बालक, बेरोजगार, किसान, युवा, एस.सी., एस.टी., और पिछड़ा वर्ग, सभी समाज का उत्तरोत्तर विकास होगा, मैं ऐसी आशा करता हूं। राजस्थान सरकार द्वारा पेश बजट का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, उदयपुर में ट्रैफिक की सबसे बड़ी और पुरानी समस्या है। उदयपुर शहर एक फेमस ट्यूरिस्ट स्थान है, सम्भाग मुख्यालय है। यहां आये दिन परीक्षाएं होती हैं और हजारों छात्र आते हैं, उस समय घंटों ट्रैफिक जाम रहता है। मुख्य मंत्री जी ने उदयपुर में ट्रैफिक की बड़ी समस्या को ध्यान में रखते हुए जनता के हित में न केवल सिटी स्टेशन से लेकर रेलवे स्टेशन तक, उदयपुर कलेक्टर आवास तक एलिवेटेड रोड के प्रस्ताव को स्वीकार किया है, बल्कि हमारी इस बहुप्रतीक्षित मांग की पूर्ति के लिए बजट भी स्वीकृत किया है। उस बजट में उन्होंने डी.पी.आर. के लिए पांच करोड़ रुपये दिये हैं। मेरा मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह है, सरकार से आग्रह है कि डी.पी.आर. बन चुकी है, उसका खर्च हमारी नगर निगम ने कर दिया है और इसके साथ-साथ नगर निगम ने मुख्य मंत्री जी और सरकार को यह आश्वासन दिया है कि 75 करोड़ रुपये नगर निगम व्यय करेगा, 75 करोड़ रुपये यू.डी.ए. व्यय करेगा और शेष 58 करोड़ रुपये संशोधित बजट में स्वीकार करके इस बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करे, ऐसा मेरा निवेदन है।

इसी तरह से उदयपुर में प्रवेश करने के लिए छह रोड हैं। सभी छह

(श्री ताराचन्द जैन)

रोडों को 300 करोड़ रुपये से ऊपर की सौगात देकर उदयपुर को इस जाम से मुक्ति देकर जनता को बहुत बड़ी राहत दी है। उदयपुर में पारस चौराहे पर फ्लाईओवर के लिए 36 करोड़ रुपये स्वीकृत किये, इसके लिए बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

उसके साथ-साथ उदयपुर शहर में सबसे बड़ी समस्या एयरपोर्ट जाने की है। एयरपोर्ट से विश्व के बड़े-बड़े नेतागण और वी.आई.पी. आते हैं और इस जाम से 45 मिनट लग जाते हैं। देबारी चौराहे से प्रतापनगर एलिवेटेड रोड के लिए 125 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आगामी समय के अन्दर देबारी से लेकर अगर सेवाश्रम, जहां तक कि हमारा फ्लाईओवर है, वहां तक तीन-साढ़े तीन किलोमीटर का अगर एलिवेटेड रोड बन जायेगा तो मात्र 20 मिनट के अन्दर उदयपुर शहर से एयरपोर्ट तक पहुंचा जा सकेगा, ऐसा मेरा आग्रह है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि उदयपुर में जाडव नर्सरी कलड़वास, ये भी शहर के अन्दर प्रवेश का द्वार है, उसके लिए 14 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं। बड़गांव से कविता नेशनल हाईवे को जोड़ने के लिए 43 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं।

पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी। उस कांग्रेस की सरकार ने आज से ठीक 01 वर्ष पूर्व 10 जुलाई को घोषणा की थी कि हम शहर के अन्दर दो एलिवेटेड बनायेंगे। उसी दिन जनता ने इस बात को कहा था कि यह हवाई है। हवाई इसलिए कि न तो बजट का प्रावधान है, न लम्बाई का पता और दोनों एलिवेटेड रोड की, रामपुरा चौराहे से लेकर हाईवे तक, उसके साथ-साथ दूसरा फतेहपुरा चौराहे से पूला तक, लेकिन न तो उसका बजट में प्रावधान था, न डी.पी.आर. थी और न आज, एक वर्ष बाद भी उसका कोई नामोनिशान नहीं है। इसी तरह की घोषणाएं करके इस सरकार ने अपने आप को विदा कर दिया, जनता ने इनको विदा कर दिया। इसलिए मुझे यह कहते हुए बहुत हर्ष है कि उदयपुर में आगामी समय में.. सभापति महोदय, साथ ही मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कांग्रेस के पिछले पांच वर्षों का दंश इस उदयपुर सम्भाग ने झेला है। 400 के.वी.ए. का ग्रिड स्टेशन स्वीकृत था, उसको केवल पैसे देने पड़ेंगे, उस वजह से उसका काम चालू नहीं किया गया। 400 KVA जी.एस.एस. स्वीकृत, बजट में प्रावधान भी था, जमीन भी आबंटित, उसके साथ-साथ बाउंड्री बनाकर लोग कब्जे कर रहे हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं

(श्री ताराचन्द जैन)

कि अगर आप इस वर्ष से काम चालू नहीं करेंगे तो तीन वर्ष फिर कांग्रेस के दंश को आगामी समय में झेलना पड़ेगा। मेरा सरकार से आग्रह है कि उसको किसी न किसी रूप में कार्यादेश जारी करके, ये चालू करेंगे। सभापति महोदय, सरकार ने इतने काम किये हैं, जिसको बोलने के लिए मुझे 10 मिनट का समय माननीय सचेतक महोदय ने दिया है तो आप मेरे ऊपर तो कृपा करेंगे ही।

श्री सभापति: सदस्य महोदय, सभी का सात-सात मिनट का समय है।

श्री ताराचन्द जैन (उदयपुर): मुझे 10 मिनट दिये हैं। आबंटित हैं।

फतेहसागर झील के अन्दर जो नेहरू गार्डन है, उसके लिए 15 करोड़ रुपये दिये हैं। सुविधायुक्त बस स्टैण्ड के लिए 15 करोड़ रुपये दिये हैं। उदयपुर शहर के चारों तरफ कई धार्मिक स्थल हैं, उनके लिए 50 करोड़ रुपये दिये हैं। लोक कला मण्डल के लिए दिये हैं। मैं भजन लाल सरकार को धन्यवाद अर्पित करूंगा कि शहर का सबसे व्यस्ततम चौराहा दुर्गा नर्सरी, उस चौराहे के लिए तीन हजार फीट, कम से कम छह करोड़ की जमीन सरकार ने नि:शुल्क उपलब्ध कराकर उस चौराहे का विस्तार करके ट्रैफिक जाम से मुक्त किया है। मैं सरकार को धन्यवाद अर्पित करूंगा।

मैं एक गम्भीर बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं कि पिछले पांच वर्षों के अन्दर सरकार ने कहा कि जहां जिसका कब्जा है, भूमिहीन लोगों को राहत देने के लिए हम पट्टे दे रहे हैं। यू.डी.ए. ने जिन पट्टों को नगर निगम को हस्तांतरित किया, उन दोनों के बीच तीन सौ से ऊपर पट्टे कहां गायब हुए, आज तक पता नहीं है। उसकी जांच करायी, हमारा बोर्ड है। उसमें से 49 पट्टे रद्द किये हैं, जिनमें से कोई भी एक करोड़ से कम का नहीं है। एक पट्टा तीन दिन पहले निरस्त किया है, वह 12 हजार फीट का था। तात्कालिक आयुक्त, हिम्मत सिंह बारहठ ने 40 रुपये फीट के अन्दर 4 हजार फीट जमीन, डेढ़ करोड़ रुपये, कांग्रेस सरकार के इशारे से आबंटित की और हमारी सरकार ने, हमारे बोर्ड ने चार दिन पहले उसको निरस्त किया है। मैं आदरणीय मंत्री महोदय से और सरकार से आग्रह करूंगा और इस मुद्दे पर आगे विस्तार से चर्चा करूंगा। ताज्जुब है कि एस.ओ.जी. की जांच की, एफ.आई.आर. दर्ज हुई है, लेकिन एक पर कार्यवाही आज तक नहीं हुई है क्योंकि सरकार उस सम्बन्ध में काम नहीं करेगी, बड़े-बड़े घोटाले हैं। मेरा तो

(श्री ताराचन्द जैन)

आपसे आग्रह है। आप सोचेंगे कि सारी फाइल की कापियां मेरे पास कैसे हैं। यू.आई.टी. का रेलवे से तीस मीटर की दूरी पर सारा, जबकि नियम है कि तीस मीटर तक कोई स्वीकृति न दी जाए, बहुमंजिला इमारत खड़ी कर दी है। विभाग के सारे अधिकारियों ने उसके अन्दर लिखकर दिया है कि यहां स्वीकृत नहीं की जा सकती, यहां नहीं बनायी जा सकती। उस पट्टे को आज से चार दिन पहले रद्द किया है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि किसी न किसी रूप में, किसी स्वतंत्र बड़ी एजेंसी से जांच कराकर और अगर न्यायिक आयोग भी गठित करना पड़े तो यह कम होगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि निश्चित रूप से सरकार इसमें काम करेगी।

इसके साथ-साथ जब पिछले समय सरकार जाने वाली थी। इनको लग गया था, उदयपुर के अन्दर कम से कम अपने 60 चहेतों को मात्र 56 रुपये में भूमि बांट दी। (व्यवधान) आप अपने कारनामों की कथा तो सुनें। उधर ही बोल रहा हूं, आपको तो इसलिए कह रहा हूं कि आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। 56 रुपये फीट, जबकि उदयपुर में दो हजार रुपये फीट से कम की जगह नहीं है, सब पट्टे बांट दिये।

श्री सभापति: श्री बालमुकुन्दाचार्य जी।

श्री ताराचन्द जैन (उदयपुर): मैं अन्त में एक बात कह रहा हूं कि केन्द्र के विपक्ष के नेता, जिन्होंने इस हिन्दू समाज के लिए जो टिप्पणी की है, उसकी निन्दा करता हूं और मैं सदन से आग्रह करूंगा कि जिस हिन्दू समाज को हिंसक बताया है, उसके लिए यह सदन निन्दा प्रस्ताव पारित करे, इसकी मैं मांग करता हूं। आपने जो इस बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आभार।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति जी, हिन्दू समाज को नेता, प्रतिपक्ष महोदय ने हिंसात्मक नहीं बताया, कृपया इसको अंकित नहीं करें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): किसको बताया है? (व्यवधान)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): उन्होंने यह कहा.. आप उस चीज को घुमाओ मत। (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): नाम बता दीजिए, हमने एक-एक शब्द वीडियो पर सुना है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): किसको बताया है?

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): आपने मुझे परिवर्तित बजट 2024-25 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद है। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप बोलें...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): मानसिक विकृति हो गयी, इसका इलाज कराइए। (व्यवधान) आप निन्दा कीजिए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): बजट पर बोलें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): खुद तो आ रहे हैं, ...(व्यवधान) उपदेश देवें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): विधान सभा की गरिमा का ध्यान रखें, बजट पर बोलें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप भी गरिमा का ध्यान रखें। यह चोगा पहनना बंद कर दें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): जो कुछ राहुल गांधी ने कहा, वह हिन्दुओं के विपरीत नहीं है। केवल विपरीत यह है कि ये अपने आपको जो हिन्दुओं का प्रतिनिधि मानकर चल रहे हैं, इसका एतराज है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): हमें गर्व है कि हम हिन्दुओं के प्रतिनिधि हैं। (व्यवधान)

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): हम सनातनी हैं, हम हिन्दू हैं और हिन्दू सदा 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया' के माध्यम से चलता है। एकमात्र सनातनी, एक मात्र हिन्दू ऐसा है जो पूरी दुनिया की सुख शान्ति की कामना करता है। पूरी दुनिया को बिना भेदभाव के, वसुधैव कुटुम्बकम परिवार मानता है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बजट पर अपना भाषण दें, आपका समय चालू है।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): सभापति महोदय, धन्यवाद। आप विपक्ष को कह दीजिए कि कृपया कुछ देर सुनने का स्वभाव बनाएं।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): सभापति महोदय...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्यगण, आपके नेता, प्रतिपक्ष नोट कर रहे

(श्री सभापति)

हैं, ये सब जवाब देंगे। आप जरा उनको बोलने दें। नेता, प्रतिपक्ष सारे पाइंट नोट करें, आपकी बारी आए, तब आप बोलना।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, हिन्दू के बारे में अच्छी डेफिनेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं, सीनियर हैं, सीनियर कोई चीज बता रहे हैं, सुन भी लीजिए।

श्री सभापति: इनकी बात मानते हैं। हमारे सीनियर हैं।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आदरणीय प्रधान मंत्री, प्रधान सेवक नरेन्द्र जी मोदी एवं मुख्य मंत्री महोदय भजन लाल शर्मा साहब और उप मुख्य मंत्री दिया कुमारी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं, सम्पूर्ण राजस्थान के देवतुल्य मतदाता और जनता की ओर से। ऐतिहासिक बजट, अद्वितीय बजट और सम्पूर्ण राजस्थान का विकसित बजट इस बार जो पेश हुआ है, उस बजट को कहीं न कहीं विपक्ष सहन नहीं कर पा रहा है। इस वजह से कहीं न कहीं हाजमा भी खराब है। मुझे ऐसा लगता है कि अब तक,...(व्यवधान) बहन जी, सुन लीजिए, सुनने का स्वभाव भी बनाइए थोड़ा-सा। सभापति महोदय, अब तक जो सरकारों ने, पिछली कांग्रेस सरकार की बात करें तो बजट ऐसे समय में दिया था जो वही इनके स्वभाव में आ रहा है कि चुनावी बजट है। आप यह मानें और इस बात का धन्यवाद दें, सम्पूर्ण सोशल मीडिया, पत्र-पत्रिकाएं और राजस्थान के बजट की चर्चा भारतवर्ष में हो रही है कि ऐतिहासिक, अद्वितीय बजट इस बार मुख्य मंत्री महोदय भजन लाल शर्मा साहब और भा.ज.पा. की सरकार के द्वारा यहां हुआ है।

सम्पूर्ण राजस्थान में बधाई और धन्यवाद मिल रहे हैं। मैं जब यहां बजट के बाद बाहर गया था तो मेरे विधान सभा क्षेत्र के काफी संख्या में लोग यहां उपस्थित थे, इस धन्यवाद के लिए कि ऐतिहासिक बजट हमारे क्षेत्र को मिला है। पिछली बार भारी-भरकम मंत्री थे, भारी-भरकम डिपार्टमेंट थे और करोड़ों-करोड़ों रुपये केन्द्र सरकार से उनके हाथ में आये थे, उसके बाद भी हमारा क्षेत्र अछूता था। हमारा वॉल सिटी जयपुर, अपरा काशी, यह परकोटा पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस परकोटे को पूरी दुनिया का आदमी देखने व घूमने आता है। उसके बाद भी जयपुर शहर परकोटे में यह हाल है कि यहां लोग पलायन की ओर थे, परेशान थे, दुःखी थे, सुविधाओं का अभाव था और लोग क्षेत्र छोड़कर जाने को तैयार थे। हमने जो मांग की, उससे ज्यादा हमारी

(श्री बालमुकुन्दाचार्य)

सरकार ने मांगें पूरी की हैं। उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं हमारी क्षेत्र की सम्पूर्ण जनता की ओर से, सम्पूर्ण हमारे देवतुल्य मतदाताओं की ओर से कि आपने ऐतिहासिक बजट क्षेत्र को दिया।

मैं उस बात पर विश्वास करता हूं कि पिछला छोड़ो और आगे चलो। कांग्रेस ने जो किया, वह देख रही है और कुछ बात को मान रही है। हमारे बंधु यह बता भी रहे हैं कि हां, हम आज इसलिए यहां बैठे हैं। ये बात भी मान रही है कि बजट तो ऐतिहासिक है। आप इस बात को तो मानते हैं कि बजट ऐतिहासिक है, इस बात का धन्यवाद तो आप दे ही रहे हैं, लेकिन इस बात को मानें कि ये बजट जो दिया है, वह पूरा होगा। अभी तो यह शुरुआत है। आपको लग रहा है कि पांच साल, जब जाने लगी थी पिछली सरकार, एडवर्टाइजमेंट की सरकार, विज्ञापन की सरकार, फाइव स्टार होटल में रहकर समय बिताने वाली सरकार, अंत में देने लगी थी बजट, तो लग रहा था कि यह बजट हवा-हवाई है और वही सत्य हुआ कि खाली घोषणाएं हुईं काम हुआ नहीं। यहां पर आज शुरुआत में यह बजट दिया गया है और यह मानिए कि इस बजट का सारा काम होने वाला है।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। आपने पर्यटन और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हवामहल विधान सभा को 200 करोड़ रुपये का बजट दिया है। वॉल सिटी हैरिटेज डवलपमेंट के लिए, साज-सज्जा के लिए, सौन्दर्यीकरण के लिए, वहां की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, पर्यटन को बढ़ाने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए आपने 100 करोड़ रुपये का जो बजट दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। इसी के साथ हमारा जयसिंहपुरा खोर जो क्षेत्र है, यह काफी समय से बसा हुआ है, गरीब जनता यहां रहती है। कुछ किसान परिवार भी यहां रहते हैं। यहां की अनदेखी की जा रही थी। इस क्षेत्र की अनदेखी की वजह से विकास से कोसों दूर था और यहां के लोग बड़े परेशान थे। इस बार आपने जयसिंहपुरा खोर में एक खेल स्टेडियम की जो घोषणा की है, बजट दिया है, उसके लिए भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही, जयसिंहपुरा खोर में सी.एच.सी. स्वास्थ्य केन्द्र का, बड़े अस्पताल का जो प्रावधान रखा, उसके लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहूंगा।

इसी प्रकार से पांच आंगनबाड़ी और बढ़ाने का आपने काम किया, उसके लिए धन्यवाद एवं पांच करोड़ रुपये सड़क के लिए आपने दिये, ट्यूबवैल

(श्री बालमुकुन्दाचार्य)

10 दिये, जलमहल-आमेर से 20 करोड़ रुपये का कार्य कराने का, नाहरगढ़ जैविक उद्यान 20 करोड़ के काम कराने का, इसी तरह अनगिनत कई और जो हमारी कामनाएं थीं, उससे ज्यादा आपने पूर्ति की है, उन सबके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर उप मुख्य मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय, जितनी प्रशंसा की जाए (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) जितना धन्यवाद दिया जाए, उतना कम है। सभापति महोदय, मेरे समय में बीच-बीच में बोला गया था, मेरा आधा समय खराब हो गया, इसलिए मैं बोलूंगा। मेरा निवेदन है आपसे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समय हो गया।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): आदरणीय यशस्वी प्रधान मंत्री, प्रधान सेवक नरेन्द्र मोदी जी जिस प्रकार से 2014 में कमान संभाले थे, उससे पूर्व की मुझे अच्छे से स्मरण में है एक बात कि पूरे देश में एक वायुमंडल बना था। उस समय मैं कुंभ क्षेत्र में था और वहां एक बड़ी सभा थी धर्माचार्यों की और वहां सभा में चर्चा हुई थी कि अब देश की कमान किसको सम्भालनी चाहिए। पूरे देश से एक आवाज आयी थी कि जिस प्रकार से गुजरात मॉडल बना है और पूरे देश में गुजरात के विकास की चर्चा होती है, इसी प्रकार गुजरात के मुख्य मंत्री प्रधान मंत्री के रूप में पूरे देश का काम सम्भालें, यह कामना सबने की थी और वह काम पूरा हुआ। 2014 से जिस प्रकार देश प्रगति की ओर व उन्नति की ओर है और तीसरी बार मोदी जी की सरकार, एन.डी.ए. की सरकार फिर बनी है, मैं मानता हूं कि यह डबल इंजन की सरकार का जो नेतृत्व है, उसी नेतृत्व में हमारे मुख्य मंत्री महोदय, एक किसान पुत्र और गरीब की पीड़ा जानने वाले और लगातार कई वर्षों का 20-25 वर्षों का संगठन में काम करने का अनुभव...(व्यवधान)

श्री सभापति: श्री भगवाना राम जी सैनी।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): उसी अनुभव के आधार पर अनगिनत काम और योजनाएं, घोषणाएं, काम शुरू हुआ। आप सोचिए पिछले छह महीने में, तीन महीने चुनाव के गये और तीन महीने में ऐतिहासिक काम हुआ। आप सोचिए पांच वर्ष में काम होगा तो यह काम नजर आयेगा। (व्यवधान) पिछली सरकारों ने सिर्फ घोषणाएं की हैं, काम नहीं किये हैं।

श्री भगवाना राम सैनी (उदयपुरवाटी): धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया। (व्यवधान) मैं बजट के बारे में बोल रहा हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समय हो गया।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): मेरे क्षेत्र में ऐसी स्थिति है, तुष्टीकरण की राजनीति ऐसी हुई कि वहां आज भी आप सोचें..(व्यवधान) पुराना वॉल सिटी, हैरिटेज सिटी है। स्मार्ट सिटी से लेकर कई डिपार्टमेंटों का रुपया वहां आया, लेकिन वह एक रुपया लगा नहीं। हमारे यहां जो करोड़ों रुपया सेन्ट्रल गवर्नमेंट से आया था, अनगिनत डिपार्टमेंटों का आया था, उसकी जांच होनी चाहिए, ...(व्यवधान) वह पैसा कहां-कहां लगा, कैसे-कैसे लगा? भले ही चाहे पी.डब्ल्यू.डी. हो, चाहे स्मार्ट सिटी हो या कितने भी डिपार्टमेंट हों, उन सबकी जांच होनी चाहिए।

श्री भगवाना राम सैनी (उदयपुरवाटी): सभापति महोदय, ...(व्यवधान) बजट जो आया...

श्री सभापति: सदस्य, समय समाप्त हो गया। अंकित नहीं हो।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): 000

श्री भगवाना राम सैनी (उदयपुरवाटी): सभापति महोदय, पूरे प्रदेश को पता है कि छह महीने में सरकार जनता की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पायी, जिसका प्रमाण है कि लोक सभा चुनाव में इंडिया गंठबंधन को 11 सीटें मिलीं। भा.ज.पा. को नकार दिया। बजट से आस लगाये बैठी जनता को निराशा हाथ लगी है।

(समय: 18.47 बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

मेरे विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के साथ भेदभाव किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैंने बजट के सारे पन्ने पलट लिए, लेकिन उदयपुरवाटी का नाम कहीं भी नहीं मिला। विधान सभा के लोगों ने मुझे कहा कि उदयपुरवाटी के साथ कैसा भेदभाव? यह गलत है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पेयजल का गम्भीर संकट है। पीने के पानी में अत्यधिक फ्लोराइड है। कारण है कि बहुत गहराई पर पानी मिलता है। कोई नीतिगत फैसला नहीं है। पेयजल की शुद्धता पर उदयपुरवाटी के लोगों का अधिकार व हक है। इस सम्बन्ध में इस लोकतंत्र के मन्दिर में फैसला नहीं होना निराशाजनक है।

अध्यक्ष महोदय, पीने के पानी को लेकर सरकार गम्भीर है। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में 'हर घर नल' योजना का जिक्र किया गया। जल जीवन मिशन में उदयपुरवाटी में खोदे गये कुएं चलने से पहले सूख

(श्री भगवाना राम सैनी)

गये। इसी प्रकार से पी.एच.ई.डी. के भी सूख गये। यह डार्कजोन घोषित किया हुआ है। पहाड़ी क्षेत्र है हमारे विधान सभा क्षेत्र में। नीचे पानी नहीं मिल रहा है। बहुत गम्भीर समस्या है वहां पर। मैं निवेदन करता हूं कि जब तक बाहर से पानी नहीं आयेगा, तब तक पीने के पानी की समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए गहलोत सरकार ने कुम्भाराम लिफ्ट योजना के अंतर्गत 1,100 करोड़ रुपये दिये। टी.एस. हो गए, एफ.एस. हो गया, इवन देन टेंडर हो गये, केवल वर्क आर्डर जारी करना है। यह निवेदन करना है कि वहां जल्दी से जल्दी वर्क आर्डर जारी हो, जिससे हमारे इस क्षेत्र में पानी की समस्या भी हल हो सके और सरकार की मंशा भी पूरी हो सके। महोदय, छह महीने कैसे निकाले, यह मैं सोचता हूं। यह जरूर है कि वहां के प्रशासन ने मदद की। छह महीने निकालना बड़ा मुश्किल हो गया था।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया है। इस रिजर्व क्षेत्र में अरावली की पहाड़ी क्षेत्र है। मेरे क्षेत्र की बड़ी जनसंख्या की आजीविका इस पर निर्भर करती है। लकड़ी, पशु चराने की सुविधा इसमें उपलब्ध है। इस रिजर्व में बिना किसी नियोजन के लेपर्ड व अन्य जानवर छोड़ दिये गये हैं। जानवर रिजर्व क्षेत्र के आसपास ग्रामीण बस्ती, गांवों में आकर पालतू जानवरों का शिकार कर किसानों व आमजन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। माननीय, मेरे क्षेत्र में लोगों को इतना खौफ है कि जानवर पालना और पशु चराना ही छोड़ दिया है। अत: इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही योजना बनाई जाने का निवेदन है। इस बजट में निराशा हाथ लगी है, इस सम्बन्ध में कोई ठोस प्रावधान नहीं है। मेरे शहर की जनता की तरफ से मैं मांग करता हूं कि आप पूरक बजट में मेरे क्षेत्र का ध्यान रखें। कई पालतू जानवरों को मार दिया, फोरेस्ट डिपार्टमेंट में शिकायत भी दर्ज हुई है, उन लोगों को अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। उस मुआवाज़े के लिए भी आपसे निवेदन करता हूं।

महोदय, उदयपुरवाटी हैडक्वार्टर पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थापित किया जाए, ताकि कानून व्यवस्था में आमजन को राहत मिल सके। मेरे विधान सभा क्षेत्र में चवरा गांव, जो 10 पंचायतों का केन्द्र बिन्दु है, वहां शिक्षा का भी कोई ज्यादा नहीं है। पंचायत मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने से युवाओं को अध्ययन में सुविधा होगी। गहलोत साहब द्वारा स्वीकृत राजकीय महाविद्यालय, उदयपुरवाटी का नवीन भवन बनकर तैयार हो गया है, लेकिन अभी कालेज पुराने भवन में चल रहा है। मैं निवेदन

(श्री भगवाना राम सैनी)

करता हूं कि उस भवन में संचालित करने का आदेश प्रदान करें और अतिरिक्त विज्ञान संकाय खोलने के लिए आपको निवेदन कर रहा हूं।

फरवरी, 2023 को उदयपुरवाटी विधान सभा क्षेत्र में पाले से फसल खराब हो गई थी। गिरदावरी हुई, सारा काम हो गया, उसके बाद 40 परसेंट लोगों को उसमें मुआवजा मिल गया, लेकिन अभी 60 परसेंट लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। सरकार से निवेदन करता हूं कि बाकी बचे हुए लोगों को मुआवजा दिलाया जाए। उदयपुरवाटी उप खण्ड सिविल न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट न्यायालय था, वहीं सिविल न्यायाधीश का न्यायालय स्थापित है। उस स्थान पर ए.डी.जे. न्यायालय स्थापित कर दिया जाए तो पीड़ित लोगों को अधिक सुविधा मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, उदयपुरवाटी क्षेत्र में ट्रोमा सेन्टर, विभिन्न प्रकार की जांचों हेतु मशीनों का कोई बजट स्वीकृत नहीं है। आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि ट्रोमा सेन्टर बनकर तैयार हो गया है। उसमें जो भी संसाधन हैं, वे मिल जाएं तो उदयपुरवाटी को बड़ी सौगात मिल सकती है। मेरे यहां चार सी.एच.सी. हैं। उनमें बड़ागांव और पोख में अभी तक विशेषज्ञ डाक्टर नहीं हैं। मेरे यह संज्ञान में आया है कि मेरे पोख में डाक्टर महीने-महीने भर तक नहीं आते। पता नहीं कौन साइन करता है और तनख्वाह उठा रहा है? यह बड़ी विडम्बना है, यह जांच का विषय है। उदयपुरवाटी चिकित्सालय को उप जिला ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सात मिनट हैं आपके दल के। खतम करें।

श्री भगवाना राम सैनी (उदयपुरवाटी): क्रमोन्नत किया जाए।

श्री अध्यक्ष: खतम करें।

श्री भगवाना राम सैनी (उदयपुरवाटी): मगरसा एक गांव है, जहां 20 जगहों का सेन्टर है, वहां सी.एच.सी. खोलने के लिए लोगों की डिमाण्ड है, सरकार का इस तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे बढ़ाया जाता है।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (अनुपस्थित), श्री हंसराज मीना।

आय-व्ययक

परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2024-25 पर

सामान्य वाद-विवाद

श्री हंसराज मीना (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्य परिवर्तित बजट 2024-25 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। साथ ही मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारी उप मुख्य मंत्री व वित्त मंत्री जी ने ऐतिहासिक व अद्वितीय बजट पेश किया है। इस बजट में देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विकसित भारत संकल्प के अनुसार, प्रदेश के चहुंमुखी और समग्र विकास की मजबूत आधारभूत नींव रखी है, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीया वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट में विशेषकर मेरे ज़िले करौली के अन्दर हमने जो मांगें कीं, उन मांगों से भी बढ़कर हमें मिला है। विशेषकर मेरे विधान सभा क्षेत्र सपोटरा, सपोटरा का अधिकांश हिस्सा डांग क्षेत्र का दुर्गम इलाका आता है, उस दुर्गम इलाके में हमारी लम्बे समय से मांग थी कि सपोटरा सी.एच.सी. है, उसको उप जिला अस्पताल घोषित किया जाए। उसको उप जिला अस्पताल घोषित करने पर मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मंडरायल उप खण्ड में उप जिला अस्पताल है, उसके लिए भी इस बजट में स्वीकृति प्रदान की है, उसके लिए भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा।

मैं मेरी विधान सभा क्षेत्र के सभी वासियों की ओर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि सपोटरा के लिए रोडवेज बस स्टैण्ड, कुडगांव में 132 के.वी. जी.एस.एस. के साथ-साथ, कैलादेवी जो न केवल राजस्थान का, बल्कि देश का एक बड़ा आस्था का केन्द्र है, कैलादेवी मेले के समय पब्लिक का बड़ा जमावड़ा लगता है, उस आस्था धाम में बाईपास बनाने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा मेरे विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न सड़कों के लिए 40 करोड़

(श्री हंसराज मीना)

की घोषणा की गई है। उसके लिए मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की ओर से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सबका साथ सबका विकास की प्रेरणा के अनुसार, करौली और सपोटरा से हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, इनके अलावा हिण्डौन सिटी और टोडाभीम दोनों कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, इस बजट के अन्दर बहुत ही अच्छी घोषणा हमारे मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में की गई है, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि पूरे करौली ज़िले में इस प्रकार की घोषणाएं हुईं। मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहूंगा कि आने वाले समय में, इस बजट में हमें अतिरिक्त बजट देकर, क्योंकि सपोटरा, एक दुर्गम इलाका है, जिसका अधिकांश हिस्सा डांग क्षेत्र में आता है, उस डांग क्षेत्र में करणपुर उप तहसील है। उस उप तहसील की तहसील सपोटरा जो करीबन 70 किलोमीटर दूर है, तो करणपुर को तहसील बनाने की हमारी माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग है। इसके अलावा सपोटरा विधान सभा की विभिन्न सड़कें, डांग क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कें हैं, उनके लिए मैं आपके माध्यम से अतिरिक्त बजट की मांग करता हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि करौली ज़िले में मुख्य अस्पताल था, जिससे सात किलोमीटर दूरी पर अब जिला अस्पताल बनाया गया है, जो पुराना अस्पताल है उसको सैटेलाइट अस्पताल घोषित किया जाए, ऐसी मैं मांग करता हूं।

इस पूरे बजट में किसानों का, युवाओं का, एस.सी. व एस.टी. का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। पूर्ववर्ती सरकार में जिस तरह से पेपर लीक किये गये थे, हमें अच्छी तरह से याद है कि रीट की परीक्षा हुई थी, बहुत ज्यादा विद्यार्थी थे उस रीट परीक्षा में, पूरे प्रदेश में उस रीट परीक्षा को रीटोत्सव घोषित किया गया था। उसमें शायद मेरे साथी विधायकों ने भी बहुत तैयारी की होगी उन बच्चों के लिए जो परीक्षा देने आये थे। वे बच्चे जब परीक्षा देकर बाहर निकले तो वह रीटोत्सव चीटोत्सव में बदल गया। उसको ध्यान रखते हुए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने एस.आई.टी. गठित की और 100 से ज्यादा ऐसे लोगों को पकड़ा गया जिन्होंने उस परीक्षा में पेपर लीक किया।

युवा साथियों के लिए, इसी बजट में इसी वर्ष एक लाख से ज्यादा सरकारी भर्तियों का प्रस्ताव किया है और आने वाले पांच वर्षों में जो चार

(श्री हंसराज मीना)

लाख भर्तियां रखी गई हैं, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर मैं देख रहा हूं, काफी लम्बे से हम यहां बैठे हैं, आदिवासियों को लेकर बड़ा बवाल मच रहा है। मैं भी आदिवासी हूं। भारतीय जनता पार्टी ने, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई थी, अलग से आदिवासी मंत्रालय का गठन किया गया। उसके अलावा आदिवासियों के कल्याण के लिए अलग से बजट की घोषणा की। इस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को, आदिवासियों को जो सम्मान दिया, वह देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की वजह से सम्मान मिला। ये लम्बे समय तक सत्ता में रहे, लेकिन यदि आदिवासियों का साथ देते तो, भारतीय जनता पार्टी ने 1992 में, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की ओर से मेघालय के आदिवासी जॉर्ज गिल्बर्ट स्वेल को जब प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में, सामने प्रत्याशी के रूप में उतारा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नो, नो।

श्री हंसराज मीना (सपोटरा): आदिवासियों के बारे में ही बोल रहा हूं। आप लोग जो आदिवासियों का रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हो, आप लोग दूसरे के ख्यालात की जो तलाशी ले रहे हैं, उन ख्यालात में अपने गिरेबान में जाकर देखो कि आपने आदिवासियों को केवल चना, दाल और गेहूं तक ही सीमित रख दिया।

(समय: 19.00 बजे)

यह भारतीय जनता पार्टी थी, जिसने आदिवासियों को इस देश का सबसे बड़ा सम्मान दिया है। यह आदिवासियों की ही भारतीय जनता पार्टी थी। आप सब लोग केवल रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आदिवासियों के साथ में क्या हुआ है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके सामने मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट के अन्दर जिस तरह से, क्योंकि ये लोग कहते थे कि यह प्रदेश मर्दों का प्रदेश है। यह प्रदेश मर्दों का ही नहीं, बल्कि यह महिलाओं का भी प्रदेश है और महिला वित्त मंत्री के रूप में जिस तरह से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की विभिन्न

(श्री हंसराज मीना)

सड़कों, कैलादेवी से लेकर करौली सड़क मार्ग के लिए और बड़वासन से झाड़वाली के लिए एक हाई लेवल ब्रिज की मांग करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री गोरधन।

श्री गोरधन (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लालजी के नेतृत्व में और हमारी उप मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में सम्माननीय दिया कुमारीजी ने जिस प्रकार से इस राजस्थान का जो बजट पेश किया है, वह एक ऐतिहासिक बजट है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक विजन के रूप में काम करती है और हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री मोदीजी जब तीसरी बार प्रधान मंत्री बने हैं तो उनको तो हम बधाई देते हैं, लेकिन उन्होंने जो विजन रखा 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आयेगा, और उसी विजन को सार्थक बनाने के लिए यह राजस्थान का बजट भी एक ऐतिहासिक बजट है और एक नींव का बजट है। मैं सोचता हूं कि यह एक ऐतिहासिक बजट है और विकसित राजस्थान का विजन है, हमारा भी विकसित राजस्थान 2047 में बनेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से इस बजट में क्योंकि हमारे जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कहीं कि, साहब, इस बजट में कुछ नहीं है, यह नहीं दिया, वह नहीं दिया, लेकिन इन्हीं के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से यह बजट दिया गया है तो इससे यह लगता है कि चुनाव कल ही है, क्योंकि जिस प्रकार से इस बजट में जो प्रावधान किये गये हैं और जिस प्रकार से इस बजट में जो गरीब, असहाय, पीड़ित, मजदूर, किसान, युवा एवं महिलाओं सहित सभी वर्गों का जो ध्यान रखा गया है, तो मैं यह सोचता हूं कि यह हमारा जो बजट है यह वास्तव में एक नींव का पत्थर साबित होगा इस राजस्थान के विकास के रूप में।

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जिस प्रकार से आपने समय का निर्धारण कर रखा है तो मैं उसी के अनुरूप बोलते हुए, क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र धोद में जिस प्रकार से ऐतिहासिक हमें जो बजट दिया गया है, क्योंकि हमारा धोद विधान सभा क्षेत्र एक ऐसा विधान सभा क्षेत्र है जहां से

(श्री गोरधन)

लगातार बीस साल तक सी.पी.एम. का विधायक रहा है और उससे पहले लगभग 35 से 40 साल कांग्रेस का विधायक रहा है, मैं दूसरी बार वहां से विधायक बना हूं तो मैं धोद की जनता को धन्यवाद देता हूं और उनको यह बधाई भी देता हूं कि इस राजस्थान के ऐतिहासिक बजट में हमें जो दिया गया है, मैं यह सोचता हूं कि देश के आजाद होने के बाद में हमें यह पहली बार दिया गया है।

इसी प्रकार से हमारी जो लोसल नगरपालिका है, वह इस राजस्थान की सबसे पहली नगरपालिका थी, जो आज तक केवल 'डी' श्रेणी में ही थी तो उस नगरपालिका को विशिष्ट श्रेणी में क्रमोन्नत किया गया है। इसी प्रकार से हमारे उस लोसल में ही जो केवल सी.एच.सी. थी, उसको उप जिला अस्पताल घोषित किया गया है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं और मैं धन्यवाद इस बात का भी देता हूं कि हमारा जो विधान सभा क्षेत्र धोद है, उस धोद विधान सभा क्षेत्र को नगरपालिका में क्रमोन्नत किया गया है इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से किसानों के क्षेत्र में काम करते हुए हमारी सरकार आगे बढ़ रही है और इसी का कारण है कि हमारी पूर्व मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धराजी राजे द्वारा जो रसीदपुरा प्याज मंडी दी गयी थी, उस रसीदपुरा प्याज मंडी को विशिष्ट श्रेणी में अभी इस बजट में प्रावधान किया गया है, क्रमोन्नत किया गया है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। धोद मुख्यालय पर हमें बस डिपो भी दिया गया है, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का और उप मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र और सीकर जिले के लिए बहुत सारा इस बजट में प्रावधान किया गया है, क्योंकि हमने यह सोचा था कि इस बजट में, क्योंकि सीकर, चूरू और झुन्झुनूं में जिस प्रकार से जनता ने चुनावों में अभी जो निर्णय दिया था, यदि उसको देखें तो शायद हम यह सोच रहे थे कि पानी का प्रावधान नहीं होगा, लेकिन मैं यह धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी को और उप मुख्य मंत्रीजी को, क्योंकि उन्होंने दोनों योजनाएं, यमुना जल का पानी और इंदिरा गांधी नहर का पानी, दोनों के लिए हमें बजट दिया है तो इसके लिए भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से मोदीजी ने अयोध्या और काशी विश्वनाथ मन्दिर हो या अन्य धर्म-स्थलों का विकास किया है और जो

(श्री गोरधन)

विजन बनाया गया था, उसी प्रकार से पूरे हिन्दुस्तान में ही नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड में हमारे सीकर जिले का खाटू श्यामजी का फेमस मन्दिर है, उसे 100 करोड़ रुपये दिये हैं, इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जीणमाता मन्दिर, शाकम्भरी माता मन्दिर, इन सबका भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है, इनके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट का समय और लूंगा, क्योंकि मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बात को रख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट है आपका।

श्री गोरधन (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने यह कहा है कि, साहब, बाबा साहब का ये कभी नाम नहीं लेते थे और आज एस.सी. और एस.टी. या ओ.बी.सी. वर्ग के लिए यदि किसी ने सोचा है तो वह भारतीय जनता पार्टी ने ही सोचा है। सबसे पहले क्योंकि जिस प्रकार से आज हम यह कह सकते हैं कि बाबा साहब के पांचों स्थानों का तीर्थ स्थल के रूप में जीर्णोद्धार किया गया है तो वह माननीय मोदीजी द्वारा किया गया है और उसी प्रकार से आज बाबा साहब के नाम से एक आदर्श ग्राम विकास योजना की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है। इस राजस्थान के बजट में जिस प्रकार से एस.सी., एस.टी. और पिछड़ी जातियों के निगम के द्वारा 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है...। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक-दो बात और कहूंगा, क्योंकि नरेगा में एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और बी.पी.एल. परिवारों के लिए जिस प्रकार से फार्म पोंड, डिग्गी, पौधे, मेड़बंदी के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, तो मैं यह सोचता हूं कि यह बजट किसानों के लिए और गरीबों के उत्थान के लिए एक नींव का पत्थर साबित होगा। इसलिए मैं इसके लिए पुन: एक बार हमारे यशस्वी मुख्य मंत्रीजी का और उप मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द। वंदे मातरम्।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनीता जाटव।

श्रीमती अनीता जाटव (हिन्डौन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी विधान सभा क्षेत्र हिन्डौन की समस्याओं के सम्बन्ध में। मेरे हिन्डौन विधान सभा क्षेत्र में एक खारी नाला है, वह पटा हुआ है। वहां पर समस्याओं का बिलकुल भी समाधान नहीं होता है। आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनें। खारी नाले का जब से पटाव हुआ है तो शहर में

(श्रीमती अनीता जाटव)

बहुत सारा, जब बारिश भी नहीं हुई थी तो उससे पहले भी पानी का भराव रहता था। वहां पर सफाई नहीं होती है, गंदगी उसमें भरी हुई है, इससे व्यापारी और आम पब्लिक को परेशानी हो रही है। उसकी सफाई कराने के लिए मैं आपसे यह कहूंगी कि उसको तुड़वाया जाए। नाले का जो पटाव था, ऊपर से उसको हटवाया जाए, ताकि उसमें सफाई हो सके।

मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगी कि मैं उनके सम्भाग की, उधर की ही रहने वाली हूं। हमें बड़ी आशा थी। मुझसे पब्लिक पूछती है जबसे बजट पेश हुआ है, मेरे से उन्होंने पूछा कि, मैडम, मुख्य मंत्री जी तो आपके उधर के ही हैं, आपके भाई हैं, आपके लिए क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। यह तो मेरे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं दिया। अपनी बहन के लिए कुछ नहीं दिया तो लोगों के लिए क्या देंगे?

श्री अध्यक्ष: हां, आप बोलिए।

श्रीमती अनीता जाटव (हिन्डौन): मैं यह कहूंगी कि चुंगी नाका जो पांच नम्बर में है, मैन रोड पर वहां डाक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति है, उसके सामने महज 10 मीटर पर ही शराब का ठेका है। वह सुबह चार बजे से रात के 12 बजे तक खुला रहता है। वहां से शिकायतें भी आई हैं। वहां गुंडागर्दी भी होती है, लूटमार भी होती है। वहां कम से कम 100-200 महिलाओं ने धरना, प्रदर्शन भी किया था। मुझे इसकी सूचना भी आई थी। हमने कलेक्टर को भी बोला था, ए.डी.एम. को भी बोला था, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। आज तक वह ठेका नहीं हटा है। हमने कई बार कॉल भी कर दिया, लेकिन उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। पुलिस का बहुत गलत रवैया है। वह एक भी बात किसी की नहीं सुनती, बल्कि जो गरीब है उसको परेशान किया जा रहा है। वहां पर बजरी का भी धंधा हो रहा है, स्मैक का भी हो रहा है, गांजे का हो रहा है, लेकिन वहां की पुलिस बिलकुल ध्यान नहीं दे रही है।

डिम्पल मीणा की बात रही, उसमें भी हमने काफी जोर लगाया था। लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई है। बल्कि उनके पिताजी और माताजी को अरेस्ट कर लिया गया था। उनको टार्चर किया जा रहा था। उनको टार्चर करके उनके ऊपर ही केस लगाना चाह रहे थे। उसके लिए हमने पहले भी कहा था कि सी.आई.डी. जांच करवायी जाये। बड़े शर्म की बात है, आप कहते हो कि 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ', लेकिन इसमें बेटियां कहां बच रही हैं? आपकी

(श्रीमती अनीता जाटव)

सरकार होने के बावजूद भी आये दिन ये घटनाएं हो रही हैं। आये दिन इस तरह के कांड हो रहे हैं। बलात्कार हो रहे हैं। आपकी डबल इंजन की सरकार है, इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। डी.एन.ए. की जांच की जाए।

हमारे यहां बिजली की समस्या है। आये दिन रात के 12 बजे, एक बजे फोन आ रहे हैं कि लाइट नहीं आ रही है। मैडम, लाइट नहीं आ रही है। अब हम उनसे क्या कहें कि, भाइयों, डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद लाइट की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो क्या करें।

आप यह भी अच्छी तरह से मानते होंगे कि यह जो आप लोगों की सरकार बनी है, सिर्फ किरोड़ी लाल जी की वजह से बनी है। वे आज आप लोगों के बीच में नहीं हैं। यह बड़े ही शर्म की बात है।

मैं विधान सभा में पहली बार बोल रही हूं। अगर कोई भी गलत शब्द निकला हो तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। हिण्डौन विधान सभा क्षेत्र में 24 घंटे में से चार घंटे लाइट आती है। वह भी कट-कट कर आती है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगी कि कम से कम 15 घंटे लाइट हो। आप किसान भाइयों की बात करते हैं, किसान बहुत परेशान हैं। आप लोगों में से भी किसान भाइयों के बच्चे हैं। उन किसान भाइयों की तरफ ध्यान दिया जाए। दिन में भी लाइट दी जाए। सर्दियों के मौसम में रात को लाइट दी जाए।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत, राम-राम सा, जय भीम।

श्री अध्यक्ष: श्री हरिसिंह रावत।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे परिवर्तित बजट 2024-25 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

जब 10 जुलाई, 2024 को हमारे प्रदेश की वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी ने बजट पेश किया तो वह एक जानदार, शानदार और मालदार बजट था। आज उस बजट के पेश होने के बाद पूरे राजस्थान में वाहवाही हो रही है, जिससे हमारे विपक्षी भाई तो बड़े परेशान हैं कि क्या चुनाव आने वाले हैं? चुनाव नहीं आने वाला है, विकास का एक आयाम कायम होने वाला है।

हमारी सरकार का और हमारे देश के प्रधान मंत्री जी का यह सपना है कि हमारा भारतवर्ष एक विकसित भारत बने। विकसित भारत तभी बनेगा जब इस धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको शिक्षा,

(श्री हरिसिंह रावत)

सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, रोजगार उपलब्ध हो। उसी अनुरूप हमारी सरकार ने विजन बनाया है और यह विजनरी बजट पेश किया है। उस बजट के माध्यम से हमारी सरकार ने, मुख्य मंत्री जी ने एक सपना संजोया और उसके आधार पर प्रत्येक विधायक को, प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र को ऐसा बजट दिया। मैं समझता हूं कि इतिहास में ऐसा बजट पेश नहीं हुआ होगा।

अध्यक्ष महोदय, विपक्षी भाइयों का कहना है कि यह बजट तो खाली दिखावा है। कुछ होना, जाना नहीं है। होना, जाना तो तब नहीं होता जब लास्ट में बजट पेश होता। यह तो प्रथम बजट है, तो आप समझ लीजिए कि 100 परसेंट काम होने वाला है। हमारे प्रधान मंत्री जी का यह सपना है कि 2047 तक हमारा भारतवर्ष विकसित राष्ट्र बनकर एक महाशक्ति के रूप में उभरे। उसी अनुरूप हमारी सरकार ने यह बजट पेश किया है।

कहावत है कि शिक्षा विकास की जननी है। अगर हम, हमारा परिवार और परिवार का हर सदस्य शिक्षित नहीं होगा तो हमारा जो सपना है, मैं समझता हूं कि वह साकार नहीं हो पायेगा।

आज हमारे मुख्य मंत्री जी ने शिक्षा विभाग में 50 नये प्राथमिक विद्यालय खोले। 100 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया। 100 माध्यमिक विद्यालयों में नवीन विषय प्रारम्भ करना निश्चित किया। प्रदेश में कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में छात्रावासों की जो कमी थी, वह पूर्ण कर रहे हैं। पांच नेताजी सुभाष चन्द्र बोस छात्रावास तथा 138 भवन रहित विद्यालयों के भवन निर्माण कर रहे हैं। क्लास रूम, लैब, लाइब्रेरी, टायलेट्स निर्माण हेतु 300 करोड़ के बजट का प्रावधान रखा है। साथ ही 750 विद्यालयों के भवन मरम्मत हेतु 100 करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं। यह हमारी सरकार का विजन है। अगर पूर्ववर्ती सरकार ने यह सब किया होता तो इनको सामने बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन इन्होंने केवल सब्जबाग दिखाये, कोई काम नहीं किया।

बालिका सैनिक स्कूल खोलना बहुत ही सराहनीय कार्य है। जो हमारी पढ़ी-लिखी बच्चियां हैं, वे चाहती हैं कि हम भी कुछ करें। उसी अनुरूप स्कूल खोली है, जिसके लिए मैं उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। साथ ही भीम में जो पृथ्वीराज महाराज महाविद्यालय संचालित हो रहा है, उसमें मैंने मेरे मद से सवा तीन करोड़ रुपये से एक हॉस्टल बनाया है। मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार उस हॉस्टल का अधिग्रहण करे। वहां गरीब तबके की बच्चियां हैं। चाहे वे किसी भी समाज की हों, उनको वहां फ्री एजुकेशन मिले। उनके रहने की व्यवस्था हमारी सरकार पहले कर चुकी है, लेकिन अगर सरकार उसको

(श्री हरिसिंह रावत)

अधिग्रहण करके चलायेगी तो मैं समझता हूं कि गरीब बच्चों को बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा की बात करना चाहता हूं। सर्वप्रथम मैं हमारी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे देवगढ़ में उप जिला चिकित्सालय बनाया। उस उप जिला चिकित्सालय के साथ-साथ भीम में जो हमारा उप जिला चिकित्सालय है, अगर इसको जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करेंगे तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा संदेशजायेगा हमारी जनता को।

जो यह मेरा विधान सभा क्षेत्र है, नेशनल हाईवे नम्बर 8, करीब 165 किलोमीटर के दायरे में आता है। वहां पर आये दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं और कई दुर्घटनाएं होती हैं। अगर वह क्रमोन्नत होगा तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा। मेरा विधान सभा क्षेत्र चार विधान सभा क्षेत्रों की संगम स्थली है। एक तरफ ब्यावर है, दूसरी तरफ पाली है, तीसरी तरफ अजमेर है, चौथी तरफ भीलवाड़ा है और फिर राजसमन्द है। चार जिलों की संगम स्थली पर अगर यहां चिकित्सालय बनेगा तो मैं समझता हूं हमारे लिए बहुत अच्छा उपयोगी साबित होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश चिकित्सा सुविधा के विस्तार के लिए 27,660 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है, जो कि पूरे बजट का 8.26 प्रतिशत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए रखा है। मैं समझता हूं कि एक बहुत ही सराहनीय कदम है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार ने भी आयुष्मान योजना लागू कर देश में आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराकर एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। इसी क्रम में हमारे मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में प्रदेश में मुख्य मंत्री आयुष्मान योजना में कैंसर जैसी गम्भीर बीमारी से ग्रसित रोगियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, आई.पी.डी. के साथ डे-केयर पैकेज जोड़ने की भी व्यवस्था की है। यह भी एक बहुत अच्छी सराहना की बात है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मां योजना के माध्यम से एक अच्छी राहत मिली है। शिशु एवं छोटे बच्चों के इलाज के लिए पीडियाट्रिक पैकेज को जोड़ना, यह भी हमारे लिए बहुत अच्छी सुविधा है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ ही भीम उप जिला चिकित्सालय...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया। आज तो आठ बजे तक खत्म करना है। सात लोग और बोलने वाले हैं।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा विद्युत के बारे में कहूंगा कि 220 के.वी.ए. का जी.एस.एस. जो प्रावधान बनाया है हमारी सरकार ने, इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके साथ ही अब समय कम है तो मेरा आपसे एक अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष: आप टेबल कर दीजिए बाकी का।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): गत सरकार ने हमारे यहां केवल घोषणा की थी वहां पर नगरपालिका खोलने के लिए, लेकिन केवल थोथी घोषणा की थी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री गोपाल लाल शर्मा।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): उस घोषणा के अनुरूप वहां पर न ई.ओ. है, न जे.ईएन.है, कोई भी अधिकारी और कर्मचारी नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जो 10 करोड़ की घोषणा की है, वह मैं समझता हूं कि अपर्याप्त है। आप 10 करोड़ की जगह 50 करोड़ की घोषणा करेंगे तो मैं समझता हूं कि वहां पर जो भी कमी है वह पूर्ण होगी। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गोपाल लाल जी। पांच मिनट में पूरी बात समाप्त करें।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024-25 के बजट की चर्चा में आपने मुझे विचार रखने का समय प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं सर्वप्रथम आभार प्रकट करना चाहता हूं हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा और उप मुख्य मंत्रीजी दिया कुमारी जी का, जिन्होंने भीलवाड़ा की नगर परिषद् को नगर निगम बनाने की घोषणा की है। अब तक सम्भागीय मुख्यालय पर ही नगर निगम थे, पर अब पाली व भीलवाड़ा जिला मुख्यालयों पर भी नगर निगम होगा। यह निर्णय भीलवाड़ावासियों के लिए प्रसन्नता का है। मेरी ओर से व भीलवाडा जिले की जनता की ओर से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी व उप मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र जी मोदी द्वारा दी गई दिशा, 'विकसित भारत 2047' व 'मोदी की गारंटी' की दिशा में आगे बढ़ते हुए जनता की आशाओं व आकांक्षाओं को पूरा करने की

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

दृढ़ इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति है। यह बजट देश व प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इस बजट में वर्णित दस संकल्पों ने बजट को सर्वस्पर्शी बनाया है। बजट में समाज के हर वर्ग के उत्थान व राहत देने की मंशा स्पष्ट प्रकट होती है। 5 वर्ष में 4 लाख नौकरियां देने का संकल्प है। प्रदेश के 35 लाख किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा मार्च, 2025 तक 1.45 लाख विद्युत के कृषि कनेक्शन व दो लाख घरों को नये विद्युत कनेक्शन देने की घोषणा, निर्धन परिवारों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की व्यवस्था हो या सी.एन.जी. पर 4.5 प्रतिशत वैट घटाने की पहल, डीजल या पेट्रोल में जो रेट कम की, वह आपके सामने है। पेंशनरों की आउटडोर चिकित्सा व्यय राशि 50 हजार करने की घोषणा और RGHS में माता-पिता व सास-ससुर को शामिल करने का निर्णय सरकार के सामाजिक सरोकारों के प्रति संवेदनशीलता का प्रमाण है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह भा.ज.पा. की सरकार है, जो कहती है वह करती भी है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस देश व प्रदेश में ऐसे दलों ने शासन किया है कि जो असत्य वादे और असत्य नारे देकर सत्ता में आ गये। गरीबी हटाओ का नारा दिया, 100 दिन में महंगाई घटाने का नारा दिया, 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करने का नारा दिया और अभी का जो चुनाव था, जो आपके सामने है। बैंक में खटाखट-खटाखट रुपये देने की जो घोषणा आपके सामने हो रही है। जनता ने इसी घोषणा को इस बार नकार दिया है। यही कारण है कि जनता ने राजस्थान में 2023 में पूर्ण बहुमत के साथ भा.ज.पा. को सत्ता सौंपी और केन्द्र में लगातार तीसरी बार माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने जनता का प्रबल विश्वास जीता। हमारी नीतियों, सिद्धांतों, कार्यक्रमों व योजनाओं पर भी जनता की मोहर लगी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बात करूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ की जनता 37 साल से इंतजार कर रही है। पहले दो बार कांग्रेस की सरकार में शिवचरण जी माथुर रहे थे, उसके बावजूद वहां पर कोई विकास नाम का काम नहीं हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा व उप मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री दिया कुमारी जी को कि इस भा.ज.पा. की सरकार ने पहले ही बजट में मेरी मांगों को, माण्डलगढ़ में बहुप्रतीक्षित मांग, सामुदायिक अस्पताल व बिजौलियां शहर

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

के सामुदायिक अस्पताल को जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया व बिजौलिया शहर को नगरपालिका की घोषणा करके माण्डलगढ़ की जनता का मान बढ़ाया है। माण्डलगढ़ में विद्युत विभाग का अधीक्षण अभियंता कार्यालय खोला है। इसकी बहुत दिनों से मांग थी। पहले की सरकार में भी मैंने बारबार मांग की थी। मेरे क्षेत्र में जो क्षतिग्रस्त सड़कें थीं, उनकी भी घोषणा की। मैं माण्डलगढ़ विधान सभा की जनता की तरफ से यशस्वी मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा व उप मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री दिया कुमारी जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद व आभार प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष: हो गया पूरा।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): एक मिनट और।

सरकार ने बहुत कुछ दिया, परन्तु कुछ और जरूरी कार्य मेरे यहां के बाकी रह गये। पूरक बजट में इसकी घोषणा करें। माण्डलगढ़ में जो अस्थायी ए.डी.जे. कोर्ट संचालित है, उसके लिए स्थायी कोर्ट की घोषणा करें। मेरे यहां बडलियास अस्पताल है, उसके लिए सी.एच.सी. की घोषणा करें। बडलियास उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने की घोषणा करें। मेरे विधान सभा में बड़ी पंचायतें हैं, जिनमें सब सेन्टर और पी.एच.सी. खोलने की घोषणा करें। इसमें ककरोलिमा घाटी, किशनगढ़, सुराणा, जोजवा थल, मांगढला आदि बड़ी पंचायतें हैं। इनमें पी.एच.सी. की घोषणा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में बांध बहुत हैं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट और। मेरे क्षेत्र में बांध बहुत बने हुए हैं परन्तुउनकी नहरें क्षतिग्रस्त हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। उनका नवीनीकरण करने के लिए भी बजट में घोषणा की जाए। मेरे यहां 13 पंचायतें हैं, जिनमें नया जिला बनाया। कहां माण्डलगढ़ क्षेत्र और कहां शाहपुरा, उसमें मिला दी गयीं तो मैं मांग करता हूं कि मेरी पंचायतों को उससे बाहर निकाला जाए। मेरे माण्ड्लगढ़ का ऐतिहासिक धरोहर का किला है और वहां पर नीचे जालेश्वर तालाब है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

साहब, एक मिनट और लूंगा।

श्री अध्यक्ष: श्री कालूराम। दो मिनट हो गये।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): एक मिनट। जालेश्वर तालाब है उसको वापस सुरम्य और पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: डिमांड हो जब और बोल लेना। श्री कालूराम जी, आपका टाइम शुरू हो गया। आपका टाइम कम हो जायेगा।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): मैं एक पंक्ति को कहकर बात को खतम कर रहा हूं।

"कुछ कर गुजरने के लिए, मौसम नहीं मन चाहिए।
साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए।।"

और प्रदेश के विकास का यह संकल्प इस बजट में हमारी सरकार ने व्यक्त किया है, यह साकार होगा। बहुत-बहुत आभार।

श्री कालूराम (डग): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बजट 2024-25 के आय-व्ययक अनुमान पर बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: पांच-पांच मिनट हैं।

श्री कालूराम (डग): मैं सम्माननीय देश के यशस्वी प्रधान मंत्रीजी का धन्यवाद देना चाहता हूं, तीसरी बार जनता का विश्वास जीतकर सबका साथ, सबका प्रयास करके माननीय प्रधान मंत्रीजी ने इस देश की सत्ता प्राप्त की है, और हमारी भजन लाल जी की सरकार ने प्रदेश में जो कार्यभार सम्भाला है, इन्होंने बहुत अच्छा कार्यभार सम्भाला है। बजट 2024-25 में जो लाया गया, यह आम जनता के हित में बजट है। बहुत अच्छा बजट आप लाये हैं और इस बजट के माध्यम से आपने कई नये आयाम खोले हैं। गरीब परिवारों को 450 रुपये में LPG सिलेण्डर दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 8 हजार रुपये किया है और MSP के तहत 125 रुपये का बोनस बढ़ाया है। ऐसी कई जनकल्याणकारी योजनाएं सम्माननीय भजन लाल जी की सरकार ने बनायी हैं।

वृक्षारोपण के ऊपर सम्माननीय प्रधान मंत्रीजी ने बहुत जोर दिया है। 'एक पौधा मां के नाम' अभियान के तहत करीब 7 करोड़ पौधे राजस्थान में लगाए जाएंगे। पौधरोपण का बहुत बड़ा काम हमारे राजस्थान में हो रहा है। हमारे राजस्थान में सबसे बड़ी, एक बड़ी घोषणा सम्माननीय उप मुख्य मंत्री महोदया ने की है, 10 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में बाबा साहब अम्बेडकर आदर्श गांव घोषित किया जाएगा, जिनमें सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री महोदय और मंत्रिमण्डल के सभी माननीय सदस्यों का,

(श्री कालूराम)

जिन्होंने महाविद्यालय खोला है डग में, जिसमें महाविद्यालय के साथ-साथ डग में उप जिला चिकित्सालय व भवानी मण्डी में कई दिनों से दूषित पानी की दिक्कत आ रही थी, वहां से हमारे पीपलाद से दूषित पानी आता था, तो राजगढ़ पेयजल योजना के माध्यम से राजगढ़ को पेयजल परियोजना से जोड़कर भवानी मण्डी और उसके आसपास के 14 गांवों को पानी मिलेगा, इसलिए उस क्षेत्र में हमें बहुत बड़ी सुविधा मिली है।

डग में उप जिला चिकित्सालय खोला है, जबकि डग जिला मुख्यालय चिकित्सालय से 105 किलोमीटर की दूरी पर था, वहां पर जाने में आसपास की जनता काफी दु:खी रहती थी और वहां पर इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं सरकार को धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आपने उप जिला अस्पताल वहां पर चालू किया है, इससे वहां की जनता को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बीलवाड़ी में बनाने के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी योजना लागू की है।

ऊर्जा के मामले में हमारे कई साथी बता रहे थे कि हमारे लाइट नहीं मिलती थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार में आठ-आठ घंटे बिजली नहीं मिली और अभी जो बिजली मिल रही है, बहुत अच्छी बिजली मिल रही है और सौर ऊर्जा के माध्यम से जो सम्माननीय प्रधान मंत्रीजी ने पी.एम. सौर ऊर्जा के माध्यम से हर आदमी, हर किसान अपने खेत में 2 से 3 मेगावाट का प्लांट लगा सकता है। आने वाले दो साल में हमारा राजस्थान आत्म निर्भर बन जाएगा ऊर्जा के क्षेत्र में, इसलिए बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ई.आर.सी.पी. योजना के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में चम्बल नदी निकलती है उसमें काफी पानी है, ई.आर.सी.पी. योजना से उसको जोड़ा जाए। काली सिंध नदी या चाचरणी नदी पर एक बांध बनाया जाए, ताकि उस क्षेत्र की जनता को फायदा मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि समय बहुत कम है आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री कंवरलाल।

श्री कंवरलाल (अंता): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान परिवर्तित बजट 2024-25, सम्माननीय दिया कुमारी जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। समय बहुत कम है।

(श्री कंवरलाल)

यह जो बजट है पृष्ठ एक से पृष्ठ 125 तक इसको पूरा का पूरा मेरी तरफ से पढ़ा हुआ मान लिया जाए। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र अंता में मॉडल सी.एच.सी. घोषित की गयी, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। 8.26 प्रतिशत हिस्सा 27,600 करोड़ रुपये का प्रावधान पूरे राजस्थान में रखा है। मैं इस बात को नहीं दोहराता हुआ, मेरा सुझाव है कि जो मा योजना है उसमें माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी होती है और उसमें आपरेशन नहीं कर सकते, डिलीवरी का पैसा नहीं मिलता है, डिलीवरी सरकारी अस्पताल में होती है और बच्चा एन.आई.सी.यू., निकू-पिकू में प्राइवेट अस्पताल में चला जाता है, तो मां-बच्चे का दूर होना, यह अच्छी बात नहीं है। माननीय वसुन्धराजी की सरकार के समय में यह काम फ्री में होता था, आप भी इस प्रावधान को लागू करें। आपने पैकेजेज को बढ़ाने की जो बात की है, उससे जनता को, गरीब लोगों को, किसानों को इसमें फायदा होगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे यह भी चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार ने मुख्य मंत्री चिरंजीवी योजना के नाम से, अभी मेरे विपक्ष के साथी बार-बार कह रहे थे कि उसमें 25 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज होता था। मैं कहता हूं कि सारे कोड़ आप डाल लो, सारे टी.आई.डी. जनरेट कर दो, फिर भी 25 लाख रुपये नहीं हो सकता, क्योंकि एकमात्र 125 करोड़, आपने एड लगाकर इसको रटाने का और प्रचार करने का काम किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मांगरोल की रोड और पानी के लिए जो पैसा आपने दिया है, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी मांग है कि रक्षपुरिया पुलिया टूटी हुई है, उसको माननीय मंत्री महोदय के माध्यम से बजट आबंटित करने की मांग करता हूं। ईआर.सी.पी. योजना, संशोधित चम्बल-कालीसिंध परियोजना के अंतर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र से नदियां निकलेंगी, महलपुर बांध बनना है और हमारी जनता के सामने पानी बहकर निकल जाएगा तो जनता के दिल में अच्छा नहीं गुजरेगा। लिफ्ट सिंचाई परियोजना इसमें जोड़कर हमारे क्षेत्र में पानी देने की बात करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अंता विधान सभा क्षेत्र बारां से आता हूं। इस क्षेत्र में बजरी का खनन माननीय प्रमोद जैन, पूर्व मंत्री के समय अताह हुआ है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप नाम नहीं लेंगे। (व्यवधान)

श्री कंवरलाल (अंता): अताह हुआ है अताह, **+++** है। इसलिए आप चिढ़ो मत, **+++** का विधान सभा क्षेत्र रहा है मेरा विधान सभा क्षेत्र। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेश मोदी। (व्यवधान)

श्री कंवरलाल (अंता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष: आप बैठो, माननीय सदस्य, हो गया। (व्यवधान) आप शुरू कीजिए।

श्री कंवरलाल (अंता): आपके मिर्ची क्यों लग रही है? वो **+++** है और आप उनके सरदार हो। (व्यवधान) उसके बारे में बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेश मोदी। पांच मिनट हैं आपके।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट पर वाद-विवाद के लिए मुझे समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। डबल इंजन की सरकार का पहला बजट, जिसमें नीम का थाना का एक बार भी नाम नहीं लिया गया। मैं तो योग में जैसे ध्यान लगाकर आदमी बैठता है, वैसे बैठा था तीन घण्टे तक, सोच रहा था, अब नीम का थाना का नाम आएगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मंत्री महोदया...।

श्री गोरधन (धोद): नीम का थाना का नाम आया है।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): वह मैं बता दूंगा। जो आया है वह बता दूंगा आपको।

श्री गोरधन (धोद): बजट पढ़ो अच्छे से।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): हां, सब पढ़ा है मैंने अच्छे से। आपसे ज्यादा पढ़ा-लिखा हूं मैं।

श्री अध्यक्ष: बोलिए आप तो।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ग्रीन एक्सप्रेस कॉरिडोर निकलेगा आपके यहां से। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): अजी विराज जाओ, विराज जाओ। आपके छह-सात माह के कार्यकाल में आपने जो काम किये हैं, चिरंजीवी

(श्री सुरेश मोदी)

योजना का गला घोंटने का काम आपने किया है, अन्नपूर्णा योजना खतम करने का काम आपने किया है, इंदिरा रसोई का बजट कम करने का काम आपने किया है। (व्यवधान) नये जिलों पर तलवार लटका कर उनका विकास रोकने का काम आपने किया है। आपकी नीयत जिले के ढांचे को तैयार करने और उसमें अन्य कार्यालय खोलकर उनमें बजट देने की नहीं है। इसलिए आपने जांच के नाम पर इन जिलों के विकास को रोका है। आपने गरीब के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ने का जो सपना था, उसे पूरा करने में रुकावट डालने का काम किया है। आपने गर्मी के मौसम में बढ़-चढ़कर बिजली की कटौती की, जिससे आमजन बहुत त्रस्त हुआ। मेरे क्षेत्र में 10-12 घण्टे की बिजली प्रतिदिन काटी जाती थी। पिछली सरकार के कार्यकाल में शायद कभी एक-आध घण्टे बिजली काटी होगी ..(व्यवधान) लेकिन बिजली लगातार आती रही। आज बिजली निगम के दफ्तरों के पास मरम्मत करने का सामान, ट्रांसफार्मर, डी.पी., केबल कंडक्टर, पोल आदि किसी भी दफ्तर में नहीं हैं। वित्त मंत्रीजी ने अपने भाषण में कहा कि हम किसानों को दिन में बिजली देंगे। मंत्री महोदय, यह काम कांग्रेस सरकार पहले ही कर चुकी है। आप असत्य वाहवाही लूटने का काम न करें। गर्मी के मौसम में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था न कर जनता को प्यासा मारने का काम और जनता को भगवान भरोसे छोड़ देने का काम किया है। हर साल गर्मियों के मौसम में सरकार द्वारा पानी के टैंकरों की समुचित व्यवस्था की जाती रही है और जनता की परेशानियों को कम करने का काम किया जाता रहा है। उक्त व्यवस्था इस साल बिलकुल फेल और ठप रही है। ट्यूबवैल व हैंडपम्प रिपेयरिंग का कोई भी सामान आपके किसी भी कार्यालय में जैसे मोटर, स्टार्टर, केबल, पाइप आदि एवं मरम्मत का बजट किसी भी कार्यालय में उपलब्ध नहीं था। और तो और, लम्बे समय तक रिपेयरिंग के ठेके भी नहीं दिये गये। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: श्री देवी सिंह।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष: मैं तीसरी बार घण्टी बजा रहा हूं।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): पर मेरा समय कितना है, यह तो बता दें आप।

श्री अध्यक्ष: आठ बजने में चार लोग और हैं।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): आप एक तरफ किसी आदमी को दस मिनट बोलने के लिए ही नहीं टोक रहे और दो मिनट में ही मेरा समय काट रहे हैं।

श्री देवी सिंह शेखावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज परिवर्तित बजट 2023-24 पर बोलने देने के लिए आपने जो मुझे समय दिया, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): मुझे पूरा तो करने दें, साहब। अध्यक्ष जी, मुझे पूरा तो करने दें। अपनी विधान सभा के काम तो बताऊं मैं।

श्री अध्यक्ष: टेबल कर दें।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए मेडिकल कालेज और नर्सिंग कॉलेज खोले जाने की मांग करता हूं।

(माननीय सदस्य श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना) के सदन पटल पर रखे गये शेष वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट देखें।)

श्री अध्यक्ष: आप बोलें, कन्टीन्यू करें।

श्री देवी सिंह शेखावत (बानसूर): राजस्थान सरकार के बजट में हमारे गांव, गरीब, ढाणी की चिन्ता करते हुए मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश की जनता का ध्यान रखा है। दिया कुमारी जी ने जो बजट रखा, उसकी जितनी तारीफ की जाए, वह कम है। माननीय, इस बजट में हमारे पूर्वी राजस्थान के 21 जिले, 04 शेखावाटी के जिले, 25 जिलों की, यानी 50 प्रतिशत आबादी के पानी की चिन्ता की गयी। मुख्य मंत्री जी ने किसानों का जीवन सुगम बनाने का प्रयास किया। मुख्य मंत्री जी गांव-ढाणियों की पगडण्डियों से होते हुए किसान परिवार से आते हैं। अत: उन्होंने किसान की चिन्ता करते हुए ई.आर.सी.पी. और चम्बल परियोजना को धरती पर उतारा। यमुना लिंक का समझौता भी उन्होंने किया।

बेरोजगारों की चिन्ता करते हुए एक लाख नौकरियां केवल एक साल में देने का वादा किया और पांच साल में चार लाख नौकरियों की व्यवस्था की। मुख्य मंत्री जी ने एस.आई.टी. के माध्यम से नकल पर रोकथाम लगाने के प्रयास में जो सफलता हासिल की है, मैं उसके लिए उन्हें बहुत बधाई देता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी, यहां हमारी जो कांग्रेस की सरकार रही, उसकी कथनी

(श्री देवी सिंह शेखावत)

और करनी में इतना अन्तर रहा कि जो उन्होंने बजट घोषणाएं कीं, वे उन्हें पूरा भी नहीं कर सके। मेरे विधान सभा क्षेत्र में निमुचाणा खोरी में उद्योग के लिए बोर्ड लगाये गये, लेकिन कागज पर कोई भी कार्य नहीं हुआ, धरातल पर कुछ नहीं उतरा।

इसके साथ कानून-व्यवस्था इतनी बिगड़ी, थानागाजी मेरा निकट क्षेत्र है, भूपसेड़ा सुनीता हत्याकाण्ड का मैंने पहले भी जिक्र किया और उसकी जांच की मांग आपके माध्यम से की और आज भी कर रहा हूं। रहस्यमय हत्याकाण्ड हुए, सरकार उदासीन बनी रही। महिलाओं का जीवन कठिन हो गया था। आज उन अपराधों में कमी आयी है और कानून-व्यवस्था बहुत ही दुरुस्त हुई है। माननीय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि एक बात जो कांग्रेस और बी.जे.पी. में साझा हुई, जिस पर आप भी और हम भी सहमत हैं कि इतना कार्य करने के बावजूद हमें यह लगता था कि यहां लोक सभा में 25 सीटें मिलेंगी, लेकिन हमें यह अचम्भा है कि 11 सीटें गईं कैसे। कांग्रेस को यह अचम्भा है कि 11 सीटें आईं कैसे। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय, मोदी जी इस देश को जातिवाद, भ्रष्टाचार और परिवार की राजनीति से बाहर लेकर आये, इसके लिए उनका जितना आभार व्यक्त किया जाए, वह कम है। माननीय, बेरोजगारों के लिए जो योजना बनी, वह सराहनीय है। माननीय, मैं यह आपके सामने कहना चाहता हूं, यह कार्य इतनी अच्छी नीति, नीयत और विजन से हुआ है कि भजन लाल जी ने 53 परसेंट संकल्प पत्र को आज तक पूरा कर दिया और कर रहे हैं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

"तुलसी जसि भवतब्यता तैसी मिलइ सहाइ।
आपुनु आवइ ताहि पहिं ताहि तहां लै जाइ॥"

अध्यक्ष जी, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि सभी को समय थोड़ा-थोड़ा ज्यादा दिया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेश गुर्जर।

श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट 2024-25 के सामान्य वाद-विवाद में मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। 10 जुलाई को राज्य की वित्त मंत्री साहिबा ने बजट पेश किया। बजट घोषणा से पहले राजस्थान की 8 करोड़ जनता उम्मीद लगाकर बैठी थी कि जिन सपनों को दिखाकर भा.ज.पा. सत्ता में आयी, उन चुनावी वादों को पूरा करके ठोस काम करेंगे, कुछ नयी पहल करेंगे, मगर

(श्री सुरेश गुर्जर)

अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बजट में किसी भी वर्ग को कुछ नहीं मिला, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे मजदूर हों, चाहे नौजवान हों, चाहे महिलाएं हों। किसी को कोरी बातों के अलावा कुछ नहीं मिला। इस बजट भाषण में सबसे विशेष बात क्या नजर आयी, जिस प्रकार से दिल्ली की पर्ची से मुख्य मंत्री जी बनाये गये, उसी प्रकार से बजट भी दिल्ली दरबार के इशारों पर लिखा हुआ नजर आया।

इस बजट में राजस्थान के विकास के एजेंडे में चेहरा देखकर भेदभाव दिख रहा है। जितनी उपेक्षा कांग्रेस के विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों की इस बजट में की गयी है, ऐसा राजस्थान में पहले कभी नहीं हुआ। कांग्रेस के शासन में भेदभाव की परम्परा नहीं रही है। इस पक्षपात के लिए राजस्थान की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदया ने 125 पेज का बजट भाषण पढ़ा। इसमें खानपुर विधान सभा क्षेत्र का एक बार भी नाम नहीं आना वहां के लोगों के साथ अन्याय है। इस बजट घोषणा में खानपुर विधान सभा क्षेत्र के लिए कोई नयी घोषणा नहीं की गयी। पूरी विधान सभा क्षेत्र के लोग इस उपेक्षा से निराशा में हैं। मैं आपके माध्यम से खानपुर विधान सभा क्षेत्र के लाखों लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि इस बजट में मैं बिजली की बात करूं तो इसमें ऊर्जा प्रबन्धन के लिए बड़ी-बड़ी बातें की गईं, जबकि हकीकत यह है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र खानपुर सहित झालावाड़ के साथ पूरे राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में बिजली के हालात बहुत खराब हैं। ग्रामीण इलाकों में 24 घंटे में से मात्र 5-7 घण्टे ही बिजली मिल पा रही है। कभी आपकी सरकार मेंटिनेंस के नाम पर बिजली कटौती करती है, कभी किसी और चीज के नाम पर बिजली कटौती करती है। शाम को छह बजते ही पूरी रात के लिए बिजली गुल हो जाती है। अभी इस समय मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो धान की रोपाई चल रही है। पूरे खानपुर विधान सभा क्षेत्र में जले हुए ट्रांसफार्मर्स 15-15 दिन तक आपकी सरकार नहीं दे रही है।

सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर्स भी गांव के लोगों को नहीं मिल रहे हैं। मेरी मांग है कि किसानों के जले हुए ट्रांसफार्मर्स जल्दी से बदले जाएं ताकि किसानों की फसलें प्रभावित न हों। अध्यक्ष महोदय, बजट भाषण में प्रदेश की सड़कों और पुलियाओं के लिए 9 हजार करोड़ की राशि खर्च करने की घोषणा

(श्री सुरेश गुर्जर)

की गयी, किन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है, खानपुर विधान सभा क्षेत्र में एक भी सड़क, एक भी पुलिया को बजट भाषण में सम्मिलित नहीं किया गया, जबकि पिछले वर्ष बारिश के चलते हमारे यहां पर भीमसागर डैम के गेट खोले गये थे, जो खानपुर विधान सभा क्षेत्र की कई सड़कें, पुलियाएं फ्लड में बह गयी थीं, उनके पुनर्निर्माण के लिए भी बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, यदि सरकार सड़क बनाने में असमर्थ है तो मेरी मांग है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे हैं, उन पर पैच वर्क कर दे, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। झालावाड़ जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यहां कई नदी-नाले बारिश के समय बंद हो जाते हैं। इसके लिए लम्बे समय से कुछ उच्च स्तरीय पुलियाओं की मांग की जा रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में खेरया से पीपलियानग्गा, घांडरवाला से भराना, घांडरवाला से मुरला, मराइता, फादन्या से देहकलां के बीच उच्च स्तरीय पुलियाओं का निर्माण किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, नगरीय विकास की मैं बात करूं तो मैं झालावाड़, खानपुर से चुनकर आता हूं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र राजस्थान के उन विधान सभा क्षेत्रों में से है, जहां पर एक भी नगरपालिका नहीं है। खानपुर ग्राम पंचायत प्रदेश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायतों में से एक है। फिर भी आज तक वहां नगरपालिका नहीं बनायी गयी। खानपुर विधान सभा क्षेत्र के कई व्यापारियों, राजनीतिक संगठनों द्वारा कई बार नगरपालिका की मांग की गयी। खानपुर और बकानी में पंचायत को नगरपालिका बनाये जाने के सभी मापदण्ड पूरे कर दिये हैं। अत: मैं मांग करता हूं कि सरकार वहां पर जल्दी ही नगरपालिका की घोषणा करे। शिक्षा के क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में बकानी में एक कालेज खोला जाए। धन्यवाद। राम-राम सा।

श्री अध्यक्ष: श्री राधेश्याम बैरवा।

श्री राधेश्याम बैरवा (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपके द्वारा बजट पर बोलने का मौका दिया गया। मैं आदरणीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा एवं उप मुख्य मंत्री दिया कुमारी जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि बजट में आपके द्वारा प्रदेश के प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा गया है। आप द्वारा इस बजट में खेती,

(श्री राधेश्याम बैरवा)

किसानों, युवाओं, रोजगार, महिला सशक्तीकरण, महिला सुरक्षा, देवस्थानों के जीर्णोद्धार के साथ ही आम जनता की रोजमर्रा की आवश्यकता बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा पर भी फोकस करते हुए काफी बेहतर बजट सदन में पेश किया है।

देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सोच सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास को साकार करने वाला यह बजट बनाया गया है। इस बजट में, आप द्वारा अन्नपूर्णा नगरी बारां क्षेत्र को अनेक सौगातें प्रदान की गई हैं। बारां में नलका फाटक पर आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य, जनता को अपने गंतव्य स्थान पर जाने हेतु काफी लम्बा चक्कर लगाना पड़ता है अथवा रेलवे फाटक पर काफी देरी तक इन्तजार करने से अव्यवस्था रहती है। इस आर.ओ.बी. के निर्माण कार्य से मेडिकल कालेज एवं कृषि उपज मंडी में आने-जाने में व्यापारियों एवं किसानों को काफी राहत मिलेगी। साथ ही, स्थानीय लोगों को बार-बार लगने वाले जाम की स्थिति से राहत मिलेगी।

बारां के हनुतिया गांव में नदी पर पुलिया निर्माण का कार्य, इस पुलिया के अभाव में बरसात के दिनों में हनुतिया गांव एक टापू बन जाता था, आवागमन का रास्ता पूर्ण रूप से बंद हो जाता था, जिसके चलते आपातकालीन स्थिति में गांव से बाहर जाना असम्भव कार्य था। इस पुलिया के निर्माण से गांव से सम्पर्क निरन्तर बना रहेगा। किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होने पर भी रोक लग सकेगी। बारां में श्रीराम स्टेडियम को विकसित कर अत्याधुनिक बनाने का कार्य, वर्तमान में स्थानीय खिलाड़ियों को अभ्यास कार्य एवं खेलकूद के दौरान अथवा किसी टूर्नामेंट के आयोजन हेतु अन्यत्र जिले में जाना पड़ता है। किसी भी जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन कराने के लिए काफी परेशानियों को सामना करना पड़ता है। उक्त श्रीराम स्टेडियम को विकसित कर अत्याधुनिक बनाने से क्षेत्र के बच्चों के हुनर को बढ़ावा मिलेगा। बारां में ऊर्जा उत्पादन क्षमता केन्द्र की स्वीकृति निश्चित ही इस केन्द्र के माध्यम से प्रदेश में नये आयाम स्थापित होंगे, साथ ही स्थानीय लोगों के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

बारां में मसाले की प्रोसेसिंग यूनिट की स्वीकृति, इस कार्य से क्षेत्रीय लोगों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बारां के गजनपुरा स्थित छात्रावास का नवीनीकरण एवं स्वीकृति, छात्रावास के मरम्मत एवं नवीनीकरण के कार्य से पढ़ाई के दौरान रहने वाले छात्रों को अन्यत्र स्थान पर किराये के आवास से

(श्री राधेश्याम बैरवा)

मुक्ति प्राप्त होगी, जिससे और अधिक छात्रों को पढ़ाई का माहौल मिल सकेगा। बारां में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक एक्ट के तहत न्यायालय की स्वीकृति से विभागीय स्तर की पैंडेंसी समय रहते समाप्त हो सकेगी। बारां के शेरगढ़ में ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु विकसित करने की स्वीकृति, इस स्वीकृति से पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, जिससे स्थानीय लोगों के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

माननीय, मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत एक श्रीपेरेराम जी मन्दिर स्थित है, जो कि अति प्राचीन मन्दिर है। यह मन्दिर अपनी अमिट छाप रखता है, परन्तु देवस्थान विभाग द्वारा इसकी सुध नहीं लिए जाने के कारण यह मन्दिर खंडहर इमारत में तब्दील होता जा रहा है। मैं आपका इस ओर ध्यान इंगित करना चाहता हूं कि इस मन्दिर से हजारों श्रद्धालुओं की भावना जुड़ी हुई है। हर वर्ष लाखों की संख्या में भक्तगण आते हैं। मैं श्रीमान से निवेदन करता हूं कि इसका जीर्णोद्धार किया जाए।

वर्तमान में अटरू तहसील में स्थानीय लोगों को विभागीय कार्य हेतु विभिन्न सरकारी कार्यालयों में जाना होता है। इसके लिए मैं माननीय महोदय से निवेदन करता हूं कि अटरू में मिनी सचिवालय बनाया जाए और अटरू में बस स्टैण्ड बनाया जाए। साथ ही, बारां शहर और अटरू में 24 घंटे जलापूर्ति करने हेतु जल संशोधन संयंत्र स्थापित होता है तो स्थानीय लोगों की पेयजल सम्बन्धी समस्या का निराकरण होगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सुशीला देवी।

श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी (नोखा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में परिवर्तित बजट के बारे में बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं नोखा की जनता और आपकी बहुत-बहुत आभारी हूं और धन्यवाद देती हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र नोखा में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए कुछ भी नहीं दिया। इसके लिए मुझे खेद है और वित्त मंत्री को भी इससे मैं अवगत कराना चाहती हूं कि आगे इसको ध्यान में रखकर हमें विकास की ओर उठाएं। राजस्थान के बजट में युवाओं और महिलाओं को बहुत आस होती है कि हमारा आज बजट तैयार होगा। हमारे विकास होगा, लेकिन उस विकास की तरफ

(श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी)

ध्यान नहीं दिया गया और जनता निराश हुई। इससे हम सबको नुकसान है। बजट में विशेष तौर पर विकास की बातें ही होती हैं। हमने पूछा तो कहा कि अगली बार दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह पहला अवसर है। मैं उस विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई हूं बीकानेर के अन्तिम छोर पर स्थित है, रेतीला क्षेत्र है, जिस पर माननीय मुख्य मंत्री जी को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उस क्षेत्र में विकास की अधिक आवश्यकता है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र नोखा को कुछ नहीं दिया गया है जबकि बजट से पूर्व विधान सभा क्षेत्र नोखा के लिए यथा समय माननीय वित्त मंत्री महोदय को प्रस्ताव भेजा था।

अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण में मिथ्या कथन किया गया है, जिसमें अधिकतर थोथी घोषणाएं शामिल हैं। मैं आपका ध्यान बजट में इस तरफ दिलाना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पूर्व में कांग्रेस सरकार के द्वारा जिला अस्पताल स्वीकृत हुआ था। उसी जिला अस्पताल को वापस बीजेपी सरकार ने स्वीकृत कराकर हमें यह दिखा दिया कि ये आपके स्वीकृत हुए हैं लेकिन वह हमारी कांग्रेस सरकार में स्वीकृत हो चुका था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र नोखा की ओर आकर्षित कराना चाहती हूं कि वह भी राजस्थान का ही हिस्सा है। वहां पर विकास की बहुत आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आशा करती हूं और नम्र निवेदन करती हूं कि आगे हमारे इस क्षेत्र को पीछे नहीं रखा जाए और विकास के काम दिये जाएं। कांग्रेस के जो सदस्य हैं, उन सबको काम नहीं दिये हैं। हम हाथ जोड़कर मुख्य मंत्री जी से और वित्त मंत्री से विनती करते हैं कि हमें काम दिया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: हो गया? श्री थावर चन्द। दो-तीन मिनट ही हैं, आठ बजे खतम करना है।

श्री थावर चन्द (धरियावद): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय माननीय सदस्य का भाषण समाप्त होने तक बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

बस पांच मिनट हैं।

आय-व्ययक

परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2024-25 पर

सामान्य वाद-विवाद

श्री थावर चन्द (धरियावद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अन्तिम वक्ता हूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि पक्ष और विपक्ष दोनों थोड़ा वक्त लेकर सुनेंगे। साहब, जब बजट पेश हो रहा था, हम नये सदस्य भी हैं और कम उम्र के भी हैं, बड़ी उम्मीद के साथ इस बजट के लिए आये थे, लेकिन जब पूरा बजट ध्यान से सुना, धरियावद विधान सभा क्षेत्र का जिक्र तक नहीं हो रहा था। तब काफी मन व्याकुल था, फिर सोचा कि किरदार तो बदलते गये, पर नाटक वही पुराना चल रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट में जिक्र था पानी, बिजली, सड़क, विकास। इस बार जो ये गर्मी के दिन निकले, मेरे विधान सभा क्षेत्र में इस तरह के हालात बने हुए हैं, कहीं-कहीं ऐसा इलाका है, जहां एक-एक, दो-दो किलोमीटर दूर-दूर तक तरसना पड़ता है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। साथ में, बिजली की बात करें तो बिजली का आलम यह है कि क्षेत्र के अन्दर, न सिर्फ पूरे राजस्थान का यह हाल है, कब बिजली जा रही है, कब आ रही है, कोई पता नहीं है। शहरों के अन्दर दिन में बिजली 24 घंटे भी देते हैं, लेकिन गांव के अन्दर पता नहीं इंसान रहते भी हैं या नहीं? इसलिए गांवों के अन्दर बिजली नहीं देते हैं, दो से तीन घंटे बिजली मिलती है। इतनी परेशानी है, दो-दो महीने का, चार-चार महीने का बच्चा पूरी रात रोता है, उसकी मां को कहता

(श्री थावर चन्द)

है। मां-बाप सो नहीं पाते हैं। किसान रोता है, खेत तक जाते हैं और पीछे से वापस बिजली कट जाती है, यह आलम बिजली का है।

(समय: 20.00 बजे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सड़क की बात करूं तो हमारे साथ इस तरह का धोखा हुआ है कि आजादी के आज 75-76 वर्षों बाद भी मेरे विधान सभा क्षेत्र के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आज भी रोड नसीब नहीं हैं उन लोगों को और आज इस बजट में हमारे इस तरह का कोई नाम तक नहीं आया। सड़क की बात करें तो बारिश के टाइम पर बहुत सारे गांव ऐसे इलाकों में बसते हैं जहां पर अगर पानी आ जाता है, नाला भरा रहता है और अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको इंतजार करना पड़ता है कि उस नाले को पार करूं, पानी नीचे जायेगा तब। ये हालात बने हुए हैं और विकास के नाम पर आदिवासियों के साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बजट के बारे में बड़ी उम्मीदें लेकर बैठा था। न सड़क के लिए, न बिजली के लिए, न पानी के लिए कोई बड़ी व्यवस्था हुई। साथ में मैं कहना चाहूंगा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी, यह बहुत बड़ा जिम्मेदारी वाला पद होता है और उन्होंने बड़ी शान से यह कहा कि आदिवासी इनके बाप की औलाद हैं कि इनके डी.एन.ए. की जांच करनी चाहिये। मैं यह कहना चाहूंगा..।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह बजट का पार्ट नहीं है।

श्री अध्यक्ष: यह बजट का पार्ट नहीं है। बजट पर बोलिए। माननीय सदस्य, बजट पर बोलिए।

श्री थावर चन्द (धरियावद): मैं बजट पर ही आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: यह बजट पर नहीं है। बजट पर आ जाइए, तीन मिनट ही हैं आपके पास।

श्री थावर चन्द (धरियावद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जिम्मेदारी वाले पद पर उनको आदिवासी अंचल के अन्दर शिक्षा की व्यवस्था कैसी है, उस व्यवस्था की तरफ झांकना चाहिये था। हम लोगों ने मांग की थी कि 45-50 किलोमीटर दूर-दूर तक मेरे भाई, मेरे जैसे नौजवान, मेरी बहनें, जिनके लिए महाविद्यालय नहीं है, उस क्षेत्र में 45-50 किलोमीटर दूर-दूर तक महाविद्यालय के लिए जाना पड़ता है। एक महाविद्यालय है जिसके अन्दर अस्सी सीटें हैं उनको बढ़ाने के लिए मैंने पी.जी. के लिए बात रखी थी, नहीं कर पाये। आज यह आलम है कि हम लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं।

(श्री थावर चन्द)

माननीय अध्यक्ष महोदय, पढ़ने वाला नौजवान प्राइवेट स्कूलों की फीस भरने के लिए अहमदाबाद, मुम्बई, गुजरात तक मजदूरी करने जाता है तो ऐसी स्थिति में हमने कॉलेज की मांग की थी, बालिका महाविद्यालय की मांग की थी। हमने नर्सिंग कॉलेज की मांग की थी। हमारे क्षेत्र में बहुत सारे किसान हैं, जिनके पास नॉलेज अच्छी है, लेकिन कृषि महाविद्यालय नहीं है। आज हम लोग इसीलिए कहना चाहते हैं कि आदिवासी को गाली देना आसान है, लेकिन उनकी समस्या समझने को कोई तैयार नहीं है। आदिवासी इलाके में सरकार ने सौ स्कूलें क्रमोन्नत और पचास विद्यालय नये खोलने की बात कही है। मेरे वहां पर ऐसे कई महाविद्यालय हैं, जिनकी स्थिति यह है कि भवन जर्जर हो रहे हैं। जिन्दगी हाथ में लेकर बच्चे स्कूल में बैठते हैं, कोई पेड़ के नीचे पढ़ाई कर रहा है और इस स्थिति में हम यह सोचते हैं, उम्मीद थी कि इस बार नये स्कूल क्रमोन्नत भी होंगे और हमको नये भवन भी मिलेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो देश का निर्माण करने वाला बच्चा है, आने वाला भविष्य है उसके लिए शिक्षा की आज कोई व्यवस्था नहीं है। इस तरीके से हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय और धोखा होता जा रहा है। बजट से हमें बहुत बड़ी उम्मीदें थीं। साथ में जो खादबीज की बात किसानों के साथ की जाती है, अभी हाल ही में बीज दिया गया था। ऐसी स्थिति थी कि 30 प्रतिशत लोगों को बीज बांटा गया, 70 प्रतिशत को नहीं मिला। आपस में गांव में लोग लड़ते रह गये और जन-प्रतिनिधियों के साथ गाली-गलौज करने पर उतर गये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हर साल किसानों के साथ कालाबाजारी होती है खाद के नाम पर, और हर साल खाद के नाम पर कालाबाजारी के अन्दर ये जो कम्पनियां हैं इन कम्पनियों के मार्फत किसानों को, जो नहीं चाहिये वो भी जबरन थोपा जाता है साथ-साथ में। इस तरह की कम्पनियों पर भी कार्यवाही होनी चाहिये। हमारे क्षेत्र में दो बार किसानों ने बड़े आन्दोलन इसी वजह से किये थे और कई किसानों पर मुकदमे हुए थे। हाल ही में एक हमारी ग्राम पंचायत सियाड़ थी, वहां पर लोगों को लगा कि यह नि:शुल्क है बांटने के लिए लाया गया है तो लोग चढ़ गये और लेकर चले गये। स्थिति ऐसी पैदा हो गई कि सब पर मुकदमे लगे लूटमार के, तो यह स्थिति ऐसी पैदा होती है तो हमको सोचना पड़ेगा कि वह किसान जो अन्न उगा कर पेट भरता है पूरे देश का, उस किसान के साथ में ऐसी दुर्गति होती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्राइबल क्षेत्र में शिक्षा की हम बात करें तो हमारे इलाके में 11वीं और 12वीं कक्षा में व्याख्याताओं की कमी है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है। जो संविदा पर लगे हुए थे उनको भी बाहर निकाल दिया।

(श्री थावर चन्द)

थोड़ी-बहुत जानकारी देते थे और बाहर निकाला तो ठीक है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा।

मैं यही कहना चाहूंगा कि संविधान में पांचवीं अनुसूची है, उस पांचवीं अनुसूची का जिक्र सदन में होना चाहिये। पांचवीं अनुसूची के अन्तर्गत अनुच्छेद 244(1)क और 13(3)क के अन्दर 'न लोक सभा न विधान सभा सबसे ऊंची ग्राम सभा।' यह उसके अन्दर लिखा गया है, लेकिन आज उसका अनुपालन नहीं किया जाता है। हमारे वहां पर अभी आमूलवा, राठड़ी, डगोचा वहां पर सोने की खान है, यों करके आदिवासियों की जमीनें लूटने का कार्य किया जा रहा है। (व्यवधान) (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: सबके लिए समान है।

श्री थावर चन्द (धरियावद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा दो मिनट का और समय चाहिये मुझे। महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम के अन्दर लेबर को जो पेमेन्ट दिया जाता है, वह कम है। दाल, मिर्ची और सारी चीजें महंगी होती जा रही हैं तो इनके लेबर का पेमेन्ट बढ़ाया जाए और नरेगा के जो मैट हैं उनके लिए स्थायी... (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं लास्ट दो लाइनें कहकर समाप्त कर रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि

'जनता की आवाज सुनो, जनता है नाराज सुनो।
कल तक जो खामोशी थी, चीख रही है आज सुनो।
क्रान्ति का आगाज सुनो, गिरने वाली गाज सुनो।
सहा बहुत है अब तक हमने, बदल रहा अन्दाज सुनो।
जनता का है राज सुनो, जनता ही सरताज सुनो।
बने रहोगे तब तक हमारे, जनता की आवाज सुनो।'

मैं इतना ही कहूंगा। मैं यह कहूंगा कि जब शिक्षा मंत्री डीएन.ए. की बात करते हैं तो इस देश के अन्दर हम यह कहना चाहेंगे कि हम हमारे डी.एन.ए. ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हो गया।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 15 जुलाई 2024 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.05 बजे सोमवार, दिनांक 15 जुलाई 2024 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

पीपल्दा की परिवहन सुविधा से वंचित ग्राम पंचायतें

54. श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा की ग्राम पंचायत अयाना, लुहावद, लक्ष्मीपुरा, अयानी, दुजनपुरा में परिवहन की सुविधा नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त में परिवहन सुविधा कब तक प्रारम्भ करने का विचार रखती हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा की अयाना ग्राम पंचायत में 08 सेवाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसकी सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

निगम के पास पर्याप्त संसाधन एवं यात्रीभार होने पर अन्य उल्लेखिक पंचायतों में भी वाहन संचालन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी निजी वाहन स्वामी द्वारा उक्त मार्ग पर वाहन संचालन हेतु आवेदन किया जाता है तो सम्बन्धित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी द्वारा परमिट जारी कर दिया जाएगा।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

किशनगढ़ के राजस्व गांवों में पेयजल आपूर्ति

55. श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के समस्त राजस्व गांवों में पेयजल आपूर्ति के स्रोत क्या हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत कुल कितने गांवों का चयन घर-घर नल कनेक्शन योजना में किया गया है? क्या सरकार उक्त योजना में शेष रहे गांवों को भी जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में विगत पांच वर्षों में जल जीवन मिशन योजना के तहत कितना बजट स्वीकृत किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में समस्त 148 गांवों में पेयजल का मुख्य स्रोत बीसलपुर बांध है। इसके अतिरिक्त 21 नलकूप, 26 खुले कुएं एवं 3,347 हैण्डपंप भी पेयजल के स्त्रोत हैं। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के 148 गांवों में से 145 गांवों का चयन जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर-घर जल कनेक्शन हेतु किया गया है। शेष दो गांव चकबीड़ एवं सूरतपुरा मे वर्ष 2011 की जनसंख्या क्रमशः दो व्यक्ति, 12 व्यक्ति एवं छितरी आबादी होने से राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशानुसार अनुमत नहीं है। 01 गांव ढाणी राठोरान की भूमि का अधिग्रहण एयरपोर्ट ऑथोरिटी के द्वारा होने के कारण आबादी विस्थापित हो गई है। इस प्रकार शेष उक्त 145 गांवों में से 74 गांव दो वृहद् परियोजनाओं में एवं 71 गांव लघु योजनाओं (ओ.टी.एम.पी.) में स्वीकृत हैं। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में विगत 5 वर्षों (2019-20 से 2023-24) में जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत राशि रुपये 28.09 करोड़ का बजट ओ.टी.एम.पी. में स्वीकृत किया गया है। 74 ग्रामों में स्वीकृत दो वृहद् परियोजनाओं के स्रोत बीसलपुर बांध पर इन्टेक वैल निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रक्रियाधीन होने से उक्त परियोजनाओं के कार्य की नवीन निविदा आमंत्रित नहीं हुई है। इन परियोजनाओं के कार्य प्रारम्भ होने पर बजट राशि आबंटित की जा सकेगी। विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जमवारामगढ़ बांध में अतिक्रमण रोकने की कार्ययोजना

56. श्री महेन्द्र पाल मीना (जमवारामगढ़): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ स्थित जमवारामगढ़ बांध में अतिक्रमण हो रहा है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जमवारामगढ़ बांध के भराव क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण को रोकने हेतु कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जयपुर जिले में स्थित रामगढ बांध के बहाव क्षेत्र में

(जल संसाधन मंत्री)

वर्तमान में किसी प्रकार का अतिक्रमण चिन्हित नहीं है। पूर्व में हटाये गये अतिक्रमणों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) रामगढ बांध के बहाव क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अतिक्रमण के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना में राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश दिनांक 30.07.2012 द्वारा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसके द्वारा नदी-नालों एवं जल स्रोतों में अतिक्रमण के चिन्हीकरण एवं उनको नियमानुसार कार्यवाही कर हटाने की कार्यवाही की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

लाडपुरा में पंजीकृत पेंशनधारी

57. श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में विधवा एवं वृद्धावस्था के कितने पेंशनधारी पंजीकृत हैं? ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त पेंशनधारियों को समय पर पेंशन का भुगतान किया जा रहा है? यदि नहीं, तो कितनों को पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वंचित पेंशनधारियों को पेंशन का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में (विधवा एकल नारी) पेंशन योजनान्तर्गत कुल 11,180 लाभान्वित हैं तथा वृद्धजन (वृद्धावस्था) पेंशन योजनान्तर्गत कुल 26,522 लाभान्वित हैं। पेंशन लाभार्थियों का पंचायतवार विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-अ)

(2) हां। सभी श्रेणियों के पात्र पेंशन लाभार्थियो को यथा समय पर किया जा रहा है। पेंशन लाभार्थियों के जन आधार में प्रविष्ट बैक खाता विवरण एवं आई.एफ.एस.सी की त्रुटि के कारण विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में कुल 740 लाभार्थियों का भुगतान खाता बंद होने, विधवा पुनर्विवाह सत्यापन में मृत्यु प्रदर्शित होने के कारण With held है तथा कुल 26 लाभार्थियों की पेंशन राशि के एरियर बिलों का उनके बैंक खातो में ई.सी.एस. (हस्तांतरण) किया जाना प्रक्रियाधीन है। विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-ब)

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(3) हां। सरकार पेंशन लाभार्थियों को देय राशि का भुगतान नियमित रूप से करती है। विधान सभा लाडपुरा के विभिन्न श्रेणियो के पेंशन लाभार्थियों के भुगतान का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-स)

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नि:शुल्क फूड पैकेट का वितरण

58. श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि खाद्य सुरक्षा योजना में नये लोगों के नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार अब उक्त योजना में नाम जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त लोगों को दिये जा रहे नि:शुल्क फूड पैकेट का वितरण बंद कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार पुन: नि:शुल्क फूड पैकेट का वितरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रदेश की वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थियों को चयनित करने की सीलिंग 4.46 करोड की गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानानुसार सुसंगत प्रकाशित जनसंख्या अनुसार सीलिंग तय है राज्य के कवरेज में कोई भी संशोधन अगली जनगणना के जनसंख्या अनुमान आंकड़े प्रकाशित होने के बाद सम्भव हो सकेगा

(2) माह दिसम्बर, 2023 से जिलों में वित्त विभाग के अ.शा. टीप दिनांक 22.12.2023 की अनुपालना में कार्यादेश जारी नहीं किया गया। इस बिन्दु पर सक्षम स्तर पर निर्णय लम्बित है।

सूरसागर में पर्यटकों से प्राप्त आय

59. श्री देवेन्द्र जोशी (सूरसागर): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सूरसागर स्थित माचिया सफारी पार्क, जोधपुर में प्रतिमाह हजारों देशी-विदेशी पर्यटक आते हैं? यदि हां, तो वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक पर्यटकों से प्राप्त आय का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री देवेन्द्र जोशी)

(2) उक्त सफारी पार्क कितने क्षेत्र में विस्तारित है तथा पर्यटकों के लिए कितने स्थानों पर शुद्ध पेयजल, छाया, महिला व पुरुष शौचालय की सुविधा कब से उपलब्ध हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त पार्क के उन्नयन, पर्यटक सुविधा व विकास हेतु विशेष राशि का प्रावधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक सरकार को प्राप्त आय का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) माचिया जैविक उद्यान, जोधपुर का क्षेत्रफल 41 हैक्टेयर है जो कि माचिया वन खण्ड में कायलाना झील के पास विस्तारित है। सफारी पार्क में पर्यटकों के लिए शुद्ध पेयजल, छाया, महिला व पुरुष शौचालय की सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। 10 वर्ष के लिए स्वीकृत नई (JICA वित्त पोषित) परियोजना CRESEP के अन्तर्गत कुल राशि 12.26 करोड़ रुपये माचिया जैविक उद्यान के विकास कार्य के लिए प्रस्तावित है, जिसका विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

बिलाड़ा में संचालित ग्राम सेवा सहकारी समितियां

60. **श्री अर्जुन लाल** (बिलाड़ा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के कौन-कौनसे ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समिति कब-कब से संचालित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा वर्ष 2019 से 2023 में ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्वीकृति दी गई थी? यदि हां, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र में कहां-कहां पर स्वीकृति दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियां खोलने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के 65 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में से

(सहकारिता मंत्री)

38 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियां स्थित है। वांछित विवरण सहित सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। प्रदेश में वर्ष 2019 से 2023 में ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्वीकृति दी गई है। उक्त समयावधि में विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में कुल 9 ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्वीकृति दी गई। सूची परिशिष्ट -2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। उक्त विधान सभा क्षेत्र में जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंषा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों की गठन की स्वीकृति दी जायेगी।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

जैसलमेर में पार्कों के विकास की योजना

61. श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जैसलमेर शहर में विभिन्न कालोनियों में वर्तमान में कितने पार्क हैं एवं उनकी स्थिति क्या है? पार्कवार, कालोनीवार, आबंटित भूमि के रकबे सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समस्त पार्कों में किन-किन योजनाओं में कितनी धन राशि व्यय की गई? फर्मवार, कार्यवार एवं राशिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जैसलमेर नगर परिषद् क्षेत्र में ऐसे कितने पार्क हैं, जिसमें कोई विकास कार्य नहीं हुआ है? क्या सरकार विकास से वंचित ऐसे पार्कों का विकास करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जैसलमेर शहर में विभिन्न कालोनियों में कुल 159 पार्क हैं, जिनमें 38 पार्क विकसित, 44 पार्क अर्द्ध विकसित एवं 77 पार्क अविकसित हैं।

पार्कवार, कालोनीवार, आबंटित भूमि के रकबे सहित विवरण परिशिष्ट -अ पर संलग्न है।

(2) उक्त पार्कों में व्यय की गई धनराशि का फर्मवार कार्यवार एवं राशिवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। जैसलमेर नगर परिषद् क्षेत्र में कम जनसंख्या घनत्व होने के कारण ऐसी कालोनियों के 77 पार्क ऐसे हैं, जिनमें विकास कार्य नहीं करवाया गया है। विकास से वंचित पार्कों के विकास का कार्य बजट उपलब्धता के अनुसार करवाया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कालेज शिक्षकों द्वारा निजी कोचिंग में अध्यापन

45. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा निजी कोचिंग में अध्यापन, ऑनलाइन या ट्यूशन कराना अनुमत है? यदि हां, तो नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त शिक्षकों से भौतिक या ऑनलाइन रूप से निजी अध्यापन नहीं करने के सम्बन्ध में शिक्षकों से कोई शपथ-पत्र लिया जाता है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों में उक्त के संबंध में महाविद्यालयों से कोई जानकारी मांगी गई है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार को राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा प्राइवेट कोचिंग की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं तथा उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। इस सम्बन्ध में राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1971 के नियम-18 में प्रावधान विहित है।

(3) जी नहीं।

(4) इस सम्बन्ध में डॉ. किशनाराम महिया, सहायक आचार्य संस्कृत के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत निराधार पाये जाने पर आदेश दिनांक 23.07.2021 द्वारा निस्तारित कर दी गई है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

पंजीकृत होम्योपैथिक चिकित्सक

46. श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री हाकम अली खां)

(1) प्रदेश में पंजीकृत होम्योपैथिक चिकित्सकों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में विगत पांच वर्षों में कितने होम्योपैथिक चिकित्सकों की भर्ती की गई? वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में उक्त पंजीकृत होम्योपैथिक चिकित्सकों में से कितने चिकित्सकों को संविदा पर रखा गया? वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सी.एच.ओ. भर्ती में आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सकों को सम्मिलित किया गया तथा होम्योपैथिक चिकित्सकों को बाहर रखा गया है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

(5) क्या सरकार भविष्य में सी.एच.ओ. भर्ती में होम्योपैथी चिकित्सकों को भी सम्मिलित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश मे कुल 9,989 होम्योपैथी चिकित्सक पंजीकृत हैं।

(2) वर्ष 2023 में विज्ञप्ति संख्या 03/2023 द्वारा 358 होम्योपैथी चिकित्सकों के पदों हेतु स्थाई भर्ती निकाली गई, जिनमें से 350 होम्योपैथी चिकित्सकों को नियुक्ति दी गयी।

(3) होम्योपैथी चिकित्सा विभाग में एक भी होम्योपैथी चिकित्सक संविदा पर कार्यरत नहीं है।

(4) सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सी.एच.ओ.) की भर्ती आयुर्वेद विभाग द्वारा नहीं की गई। आयुर्वेद विभाग द्वारा स्थाई चिकित्साधिकारी को ही सी.एच.ओ. का कार्यभार दिया गया है।

(5) बिन्दु संख्या 4 के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सी.एच.ओ.) की भर्ती आयुर्वेद विभाग द्वारा नहीं की गई है।

जहाजपुर में बसों का संचालन

47. श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गोपीचन्द मीणा)

(1) क्या यह सही है कि विगत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के विभिन्न मार्गों पर निगम की बसों का संचालन बंद कर दिया गया है? यदि हां, तो किन-किन मार्गों पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में बंद परिवहन सेवाओं को पुन: प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा पिछले 5 वर्षों के दौरान विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के विभिन्न मार्गों पर बंद की गई बसों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) निगम के सीमित संसाधनों के कारण बंद कर दी गई परिवहन बस सेवाओं को पुन: संचालित किये जाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आसीन्द के राजकीय महाविद्यालय में रिक्त पद

48. श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजकीय महाविद्यालय, आसीन्द में कितने पदों पर व्याख्याता प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त महाविद्यालय में कितने पद स्वीकृत हैं, उनमें से कितने रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय, आसीन्द में 01 शिक्षक कार्य व्यवस्थार्थ कार्यरत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र आसींद में संचालित राजकीय महाविद्यालय आसीन्द में पदों की स्थिति:-

(उच्च शिक्षा मंत्री)

क्र.सं.	विषय/पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
01	अर्थशास्त्र	01	01	00
02	अंग्रेजी	01	00	01
03	भूगोल	01	00	01
04	हिन्दी	01	00	01
05	इतिहास	01	01	00
06	राजनीति विज्ञान	01	00	01
07	समाजशास्त्र	01	01	00
08	अशैक्षणिक	10	04	06

नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

डूंगरपुर में खराब हैण्डपम्प व नलकूप

49. श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के विभिन्न गांवों व ढाणियों में वर्ष 2020 से माह दिसम्बर, 2023 तक कितने हैण्डपम्प व नलकूप खराब होने की शिकायतें प्राप्त हुईं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा प्राप्त शिकायतों के आधार पर कितने हैण्डपम्प व नलकूप ठीक किये गये तथा शेष खराब व बंद पड़े हुए हैण्डपम्प व नलकूपों को कब तक ठीक करवा दिया जायेगा? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में नवीन हैण्डपम्प लगवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के विभिन्न गांवों व ढाणियों में वर्ष 2020 से वर्ष 2023 दिसम्बर तक 4,824 हैण्डपम्प एवं 03 नलकूप खराब होने की शिकायत प्राप्त हुई। प्राप्त शिकायतों का ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

(2) जी हां। सरकार द्वारा उक्त प्राप्त शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता से समयबद्ध रूप से किया गया है। वर्ष 2020 से वर्ष 2023 तक प्राप्त समस्त शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है।

(3) जी हां। नवीन हैण्डपम्पों की स्वीकृति का कार्य आवश्यकतानुसार, तकनीकी उपादेयता एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जावेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शेरगढ़ में नवीन हैण्डपम्पों की स्वीकृति

50. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में अगस्त, 2018 में 100 नवीन हैण्डपम्पों की स्वीकृति जारी की गई थी? यदि हां, तो उक्त में से कितने हैण्डपम्प स्थापित कर दिये गये व कितने शेष हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार शेष हैण्डपम्पों की संशोधित स्वीकृति जारी कर हैण्डपम्प स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में अगस्त 2018 में 100 नग हैण्डपम्पों की स्वीकृति जारी की गई थी। उक्त स्वीकृत हैण्डपम्पों में से 59 हैण्डपम्पों का निर्माण कार्य पूर्ण कर चालू कर दिये गये हैं एवं 41 हैण्डपम्पों के निर्माण कार्य शेष हैं। हैण्डपम्प वार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) वित्त विभाग के आदेश दिनांक 22.12.2023 द्वारा 15.12.2023 से पूर्व के स्वीकृत कार्यों को क्रियान्वित नहीं किये जाने के निर्देशों के दृष्टिगत उक्त शेष रहे 41 हैण्डपम्पों के कार्य प्रारम्भ नहीं हुए हैं। दिनांक 15.12.2023 से पूर्व के स्वीकृत कार्यों को प्रारम्भ करने के लिए राज्य सरकार स्तर से समीक्षा की जाकर योजना कार्य की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता का आकलन करते हुए उचित निर्णय लिया जाकर तदानुसार हैण्डपम्प निर्माण कार्य किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खाजूवाला में जल जीवन मिशन योजना के तहत स्वीकृत कार्य

51. डॉ. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में विगत तीन वर्षों में जल जीवन मिशन योजना के तहत कुल कितने कार्य स्वीकृत हुए तथा कुल कितने बजट का प्रावधान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वर्षों में स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कितने कार्य शेष हैं? शेष को कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में स्थित कुल 210 ग्रामों में विगत 3 वर्षों में जल जीवन मिशन के तहत एक वृहद् पेयजल परियोजना "वृहद् पेयजल परियोजना खाजूवाला" के अंतर्गत 134 ग्रामों की स्वीकृति जारी की गई। शेष 76 ग्रामों हेतु अन्य 30 योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृति जारी की गई। इसका विवरण परिशिष्ट अ पर उपलब्ध है। विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला के अंतर्गत जल जीवन मिशन के तहत विगत तीन वर्षों में राशि रुपये 230.69 करोड़ का आबंटन किया गया, जिसका तद्नुसार व्यय किया गया। विवरण परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(2) जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत योजनाओं के अंतर्गत 19 ग्रामों में कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं शेष 191 ग्रामों में कार्य प्रगति पर है, जिसका विवरण परिशिष्ट-अ में सम्मिलित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

ब्यावर में जल जीवन मिशन के निर्धारित लक्ष्य

52. श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कितने पेयजल कनेक्शन दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित था तथा अब तक कितने कनेक्शन दिये गये? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना के अन्तर्गत पेयजल कनेक्शन देने में लापरवाही के कारण कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री शंकरसिंह रावत)

(3) क्या सरकार समय पर पेयजल कनेक्शन उपलब्ध देने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के कुल 222 ग्रामों हेतु जल जीवन मिशन के तहत दो वृहद् पेयजल परियोजनाओं की स्वीकृति एस.एल.एस.एस.सी. की क्रमशः बैठक संख्या 19वीं दिनांक 26.12.2019 के अंतर्गत 62 ग्राम तथा 25वीं बैठक दिनांक 16.07.2021 के अंतर्गत 160 ग्राम की परियोजना की स्वीकृति जारी की गई है।

जल जीवन मिशन के तहत जारी स्वीकृतियों के अनुसार कुल 38,748 क्रियाशील घरेलू जल सम्बन्धों के लक्ष्य के विरुद्ध 29,009 जल सम्बन्ध जारी किये गये हैं एवं शेष का कार्य प्रगति पर है। ग्राम पंचायतवार जारी किये गये जल सम्बन्धों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। 62 ग्राम की वृहद् पेयजल परियोजना का कार्य पूर्ण कर लक्षित 16695 जल सम्बन्धों के विरुद्ध 16,556 जल सम्बन्ध जारी किये गये हैं।

160 ग्राम की वृहद् पेयजल परियोजना का कार्य प्रगतिरत है। उक्त योजनान्तर्गत 12,453 जल सम्बन्ध जारी किये गए हैं। उक्त योजना के शेष कार्य पूर्ण करते हुए दिसम्बर, 2024 तक शेष जल संबंध जारी किया जाना लक्षित है।

(3) हां। परियोजना का शेष कार्य माह दिसम्बर, 2024 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

माउण्ट आबू में सालगांव बांध की स्वीकृति

53. श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

माउण्ट आबू में सालगांव बांध के कार्य हेतु स्वीकृति कब जारी की गई तथा उक्त बांध का कार्य कब प्रारम्भ हुआ? स्वीकृत आदेश मय कार्य के आदिनांक तक हुई प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

माउण्ट आबू में सालगांव बांध के कार्य हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 06.10.2022 को राशि

(जल संसाधन मंत्री)

रुपये 250.54 करोड़ की जारी की गई। कार्यादेश, राशि रुपये 111.11 करोड़ का दिनांक 16.05.2023 को जारी किया गया, जिसके अनुसार कार्य की प्रारम्भ एवं पूर्णता तिथि क्रमश: 26.05.2023 एवं 25.11.2026 निर्धारित है।

बांध की प्रारम्भिक ड्राइंग एवं डिजाइन, कन्सल्टेन्ट आई.आई.टी. रूड़की के स्तर पर परिक्षणाधीन है।

परियोजना में बांध निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र वन विभाग से प्राप्त नहीं होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है।

वर्तमान में भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 15 के तहत कार्यवाही एवं बांध निर्माण से प्रभावित होने वाले परिवारों के पुर्नवास की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

स्वीकृति आदेश परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अकावद परवन वृहद सिंचाई परियोजना (बारां-अटरू) में अवाप्त भूमि का मुआवजा

54. श्री राधेश्याम बैरवा (बारां-अटरू): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अकावद परवन वृहद सिंचाई परियोजना कब स्वीकृत हुई तथा इसकी लागत कितनी है एवं उक्त परियोजना को कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया था? उक्त की वर्तमान कार्य प्रगति क्या है? कार्य में विलम्ब के क्या कारण रहे हैं? सरकार द्वारा उक्त का निर्माण कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त परियोजना से किन-किन जिलों के किस-किस आबादी क्षेत्रों को पेयजल एवं किन-किन गांवों को सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अटरू क्षेत्र में उक्त परियोजना के लिए अवाप्त की गई किसानों की भूमि का मुआवजा अटरू नगरपालिका की डी.एल.सी. दर से भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) परवन वृहद सिंचाई परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार के पत्रांक 3050, दिनांक 30.08.2013 द्वारा जारी की गई है। परियोजना की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रु. 7,355.23 करोड़ है। परियोजना को पूर्ण करने का लक्ष्य मई, 2022 निर्धारित किया गया था।

परियोजना के अन्तर्गत माह जून, 2024 तक बांध एवं टनल निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति 83.00 प्रतिशत, प्रथम चरण (1.31 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र) कार्य की भौतिक प्रगति 43.00 प्रतिशत एवं द्वितीय चरण (0.70 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र) कार्य की भौतिक प्रगति 77.00 प्रतिशत की जा चुकी है।

परियोजना के कार्य में विलम्ब के मुख्यतः कारण कोविड महामारी-2019, बांध की नीव में फाल्ट लाइन, अन्य विभागों द्वारा एन.ओ.सी. जारी करने में विलम्ब, बांध स्थल के अपस्ट्रीम में स्थित मोहनपुरा बांध (मध्य प्रदेश) से जल प्रवाह करने व भूमि अवाप्ति में देरी है।

परियोजना को जुलाई, 2025 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(2) परवन अकावद वृहद पेयजल परियोजना से कोटा सम्भाग के जिला बारां के 907 ग्राम, जिला झालावाड़ के 311 ग्राम एवं जिला कोटा के 184 ग्रामों को लाभांवित करने का प्रावधान लिया गया है। प्रस्तावित तहसीलवार ग्रामों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

परियोजना के अन्तर्गत जिला झालावाड़, कोटा एवं बारां के कुल 637 गांवों को सिंचाई से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) अवाप्त भूमि के मुआवजे का निर्धारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 26(1)(क) के अनुसार उस क्षेत्र में, जहां भूमि स्थित है, यथास्थिति, विक्रय विलेखों या विक्रय के करारों के रजिस्ट्रीकरण के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में विनिर्दिष्ट बाजार मूल्य के आधार पर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की अधिसूचना जारी होने की दिनांक को प्रचलित डी.एल.सी. दर अनुसार मुआवजा निर्धारित करने का प्रावधान है, अर्थात् जिस ग्राम की भूमि अवाप्त की जा रही है उस ग्राम की धारा 11 की दिनांक को लागू डी.एल.सी. दर के आधार पर मुआवजे की

(जल संसाधन मंत्री)

गणना करने का प्रावधान है। तदनुसार मुआवजा निर्धारण किया गया है। नगरपालिका अटरू की डी.एल.सी. दर से भुगतान करने सम्बन्धी प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जामडोली (जयपुर) के मानसिक विमंदित पुनर्वास केन्द्र में निवासरत बालक-बालिकाएं

55. श्री भीम राज भाटी (पाली): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) मानसिक विमंदित पुनर्वास केन्द्र, जामडोली, जयपुर में वर्तमान में रह रहे कितने बालक-बालिकाएं किस प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त है,? आयु वर्ग व विकलांगता की श्रेणी 0-6, 6-14, 14-18 व 18 से अधिक के अनुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत चार वर्षों में उक्त केन्द्र पर कितने नये बच्चों की भर्ती की गई तथा कितनों की मृत्यु हुई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह, जामडोली, जयपुर में 156 बालक तथा 204 बालिकाएं, कुल 360 बालक/बालिकाएं आवासरत हैं। आयुवर्ग व विकलांगता की श्रेणी के अनुसार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) गत चार वर्षों में मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह जामडोली, जयपुर में नये बच्चों की भर्ती तथा मृत्यु का विवरण नाम व पते सहित परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

.(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

विशेष योग्यजनों की पेंशन राशि में वृद्धि की कार्ययोजना

56. श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) उप खण्ड पदमपुर एवं करणपुर, जिला श्रीगंगानगर में विशेष योग्यजनों (दिव्यांग) की जनसंख्या कितनी है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर)

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त सभी विशेष योग्यजनों (दिव्यांग) को पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विशेष योग्यजनों (दिव्यांगजनों) को सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र करणपुर में विगत पांच वर्षों में कितने विशेष योग्यजनों (दिव्यांगजनों) को स्कूटी का लाभ दिया गया है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त की पेंशन राशि बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उप खण्ड पदमपुर एवं श्रीकरणपुर में जिन विशेष योग्यजनों द्वारा Specially Abled Person (SAP) पोर्टल पर यू.डी.आई.डी. कार्ड एवं विकलांगता प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन किया है, उनमें से पात्र विशेष योग्यजनों को विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं यू.डी.आई.डी. कार्ड जारी किये गये हैं, जिनमें उप खण्ड पदमपुर में 2,067 एवं उपखण्ड श्रीकरणपुर में 1,762 (कुल 3,829) विशेष योग्यजन हैं, जिनकी ग्रामवार एवं वार्डवार सूची परिशिष्ट अ संलग्न है।

(2) उप खण्ड पदमपुर एवं श्रीकरणपुर में विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजनान्तर्गत जिन विशेष योग्यजनों द्वारा ई-मित्र/फेस आर.डी. एप के माध्यम से आनलाइन आवेदन किया है, उनकी पात्रता/नियमानुसार पेंशन स्वीकृत कर लाभ प्रदान किया जा रहा है। विशेष योग्यजन पेंशनर्स की संख्या उप खण्ड पदमपुर में 1,842 एवं उपखण्ड श्रीकरणपुर में 1,648 (कुल 3,490) हैं, जिनकी ग्रामवार एवं वार्डवार सूची परिशिष्ट-ब संलग्न है।

(3) राज्य सरकार द्वारा विशेष योग्यजनों के लिए संचालित निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत सुविधाएं उपलब्ध करवायी जा रही हैं-

मुख्यमंत्री स्वरोजगार लोन योजना।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्कूटी योजना।

सुखद दाम्पत्य योजना।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना।

संयुक्त सहायता योजना।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

पालनहार योजना।

विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति योजना।

उक्त योजनाओं में पात्रतानुसार एवं नियमानुसार आवेदन के पश्चात् लाभ प्रदान किया जा रहा है।

(4) उप खण्ड पदमपुर में 22 एवं श्रीकरणपुर में 33 (कुल 55) विशेष योग्यजनों को आदिनांक तक विशेष योग्यजन स्कूटी योजना का लाभ दिया जा चुका है, जिनकी उप खण्डवार सूची परिशिष्ट-स संलग्न है।

(5) राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम, 2023 के अध्याय 4 (7)(2) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में आधार दर पर 15 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में विशेष योग्यजनों (दिव्यांगजनों) की मासिक पेंशन की अधिवृद्वित राशि रुपये 1,000/- से 1,150/- रुपये प्रतिमाह दिनांक 01.04.2024 से प्रभावी है। विभागीय आदेश परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत गेहूं का आबंटन

57. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत विगत छह माह में जिलों को कब-कब और कितना-कितना गेहूं का आबंटन किया गया? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के अंतर्गत डिपो से आबंटन होने के उपरांत कितने दिनों में गेहूं का उठाव होना आवश्यक है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश में उक्त अवधि में डिपो से नियत समय पर गेहूं का उठाव नहीं होने के कारण लैप्स हुआ है? यदि हां, तो कहां-कहां? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त अवधि में डिपो से गेहूं के उठाव के पश्चात् लाभार्थियों को गेहूं वितरित नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत माह जनवरी, 2024 से जून, 2024 तक आबंटित गेहूं का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(2) खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आबंटित गेंहूं का उठाव सम्बन्धित माह के पूर्व माह की प्रथम तारीख से अंतिम तारीख तक किया जाता है।

(3) जी नहीं। माह जनवरी, 2024 से जून, 2024 तक आबंटित गेहूं का नियत समय पर उठाव नहीं होने के कारण लैप्स हुए गेहूं की मात्रा शून्य है।

(4) जी नहीं। डिपो से गेहूं के उठाव के पश्चात् लाभार्थियों को गेहूं वितरित किया गया है। खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत गेहूं उठाव के पश्चात् चयनित पात्र लाभार्थियों को उचित मूल्य दुकान पर गेहूं प्राप्ति हेतु जाने पर निर्धारित प्रावधानानुसार पोस मशीन के माध्यम से बायोमैट्रिक सत्यापन पश्चात् गेहूं का वितरण किया जाता है।

माह जनवरी, 2024 से जून, 2024 तक गेहूं के आबंटन उठाव, वितरण आदि मात्रा का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बूंदी में खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित परिवार

58. श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बूंदी में खाद्य सुरक्षा योजना में कुल कितने पात्र परिवार हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाले सभी परिवार खाद्य सुरक्षा योजना में पंजीकृत हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त सभी परिवारों को उक्त योजना में जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बूंदी में खाद्य सुरक्षा योजना हेतु कुल 67,915 पात्र परिवार हैं।

(2) खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत समावेशन निष्कासन निर्धारित मापदण्ड अधिसूचना दिनांक 27.09.2018 प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न के अनुसार चयन की प्राथमिकता श्रेणियों में बिन्दु संख्या 5 के उप बिन्दु

A. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना

B. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

C. मुख्यमंत्री एकल नारी योजना

D. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

E. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना

F. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना

उक्त श्रेणियों में चयनित लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारक मानते हुए उनके परिवारों को आवेदन उपरान्त निष्कासन श्रेणी में नहीं होने पर, पात्र पाये जाने की दशा में खाद्य सुरक्षा का लाभ प्रदान करवाया जाता है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी विशेष योग्यजनों की श्रेणी को खाद्य सुरक्षा में स्वत: समावेशन हेतु अधिसूचना दिनांक 13.03.2023 को जारी की जा चुकी है। प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी विशेष योग्यजनों को खाद्य सुरक्षा योजना में स्वत: समावेशन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मेड़ता में संचालित उचित मूल्य की दुकानें

59. श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में उचित मूल्य की कितनी दुकानें संचालित हैं तथा उक्त पर विगत तीन वर्षों में क्या-क्या एवं कितनी मात्रा में सामग्री उपलब्ध कराई गई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने बी.पी.एल. कार्डधारक हैं तथा कितनों ने आवेदन कर रखा है? क्या सरकार सभी पात्र आवेदकों के बी.पी.एल. कार्ड जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में कितने राशन डीलर किन कारणों से निलम्बित हैं? उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में कुल 166 राशन की दुकानें संचालित हैं। उक्त उचित मूल्य दुकानों पर विगत तीन वर्षों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत ऑनलाइन दर्ज राशन कार्डों में अन्त्योदय अन्न योजना श्रेणी के

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

राशन कार्डों पर 35 किलोग्राम प्रति कार्ड प्रति माह एवं अन्य चयनित खाद्य सुरक्षा पात्र परिवारों के कार्डों पर 05 किलोग्राम प्रति यूनिट प्रति माह खाद्यान्न गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र परिवारों को प्रति यूनिट 05 किलोग्राम खाद्यान्न गेहूं माह अप्रैल, 2021 से माह दिसम्बर, 2022 तक 05 किलोग्राम प्रति यूनिट खाद्यान्न गेहूं उपलब्ध करवाया गया।

माह अगस्त, 2023 से माह नवम्बर, 2023 तक मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के अन्तर्गत प्रति परिवार फूड पैकेट एवं आयल पैकेट का वितरण करवाया गया।

(2) विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में कुल 4,571 बी.पी.एल. राशन कार्ड धारक हैं तथा बी.पी.एल. के लम्बित आवेदनों की संख्या शून्य है।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में राशन सामग्री वितरण में अनियमितता किये जाने के कारण दो उचित मूल्य दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी कर प्राधिकार पत्र निलम्बित किये गये हैं। नोटिस का जवाब प्राप्त होने पर प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

नागौर, डीडवाना-कुचामन में खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी

60. श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला नागौर, डीडवाना-कुचामन में कितनी उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं तथा वर्ष 2023 से माह मई, 2024 तक कितनी मात्रा में क्या-क्या सामग्री उपलब्ध करवाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिलों में कितने बीपीएल कार्डधारक हैं तथा कितनों ने नए आवेदन कर रखे हैं? क्या सरकार सभी पात्र आवेदकों के कार्ड बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला नागौर व डीडवाना-कुचामन में कितने कार्डधारक हैं जिनको राशन सामग्री नहीं मिल रही है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री जाकिर हुसैन गैसावत)

(4) क्या सरकार खाद्य सुरक्षा में नये नाम जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला नागौर, डीडवाना-कुचामन में कुल 1,288 राशन की दुकानें संचालित हैं। वर्ष 2023 से माह मई 2024 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत ऑनलाइन दर्ज राशन कार्डों में अन्त्योदय अन्न योजना श्रेणी के राशन कार्डों पर 35 किलोग्राम प्रति कार्ड प्रति माह एवं अन्य चयनित खाद्य सुरक्षा पात्र परिवारों के राशनकार्डों पर 05 किलोग्राम प्रति यूनिट प्रति माह खाधान्न गेहूं निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।

माह अगस्त 2023 से माह नवम्बर, 2023 तक मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के अन्तर्गत प्रति परिवार फूड पैकेट एवं ऑयल पैकेट का वितरण करवाया गया।

(2) उक्त जिलों में कुल 63450 बी.पी.एल. राशनकार्ड धारक हैं तथा बी.पी.एल. का कोई आवेदन लम्बित नहीं है।

(3) उक्त जिलो में 4,81,133 परिवार नॉन एन.एफ.एस.ए. राशनकार्डधारक है।

(4) वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रदेश की वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थियों को चयनित करने की सीलिंग 4.46 करोड़ की गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानानुसार सुसंगत प्रकाशित जनसंख्या अनुसार सीलिंग तय है राज्य के कवरेज में कोई भी संशोधन अगली जनगणना के जनसंख्या अनुमान आंकडे प्रकाशित होने के बाद सम्भव हो सकेगा।

राजस्थान फॉरेस्ट्री एण्ड बायो-डाइवर्सिटी डवलपमेंट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कार्य

61. श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

प्रदेश में वर्ष 2021 से माह मई, 2024 तक राजस्थान फॉरेस्ट्री एण्ड बॉयो डायवर्सिटी डवलपमेंट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत वृक्षारोपण, ओरण विकास, पौधे वितरण व आजीविका के संवर्द्धन हेतु कहां-कहां पर क्या-क्या कार्य कितनी राशि के करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना (RFBDP) के अन्तर्गत ऋण की प्रथम किस्त माह अगस्त, 2023 में प्राप्त हुई। परियोजना के वित्तीय वर्ष 2023-24 से मई 2024 तक कराये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-अ के अनुसार हैं।

वार्षिक कार्ययोजना के प्रथम वर्ष में ओरण विकास, पौध वितरण व आजीविका संवर्द्धन के कार्य सम्मिलित नहीं होने से उक्त कार्य सम्पादित नहीं किये गये।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कपासन के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर सहकारी समितियों की स्थापना

62. **श्री अर्जुन लाल जीनगर** (कपासन): क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर सहकारी समितियां खोलने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो अब तक कितनी सहकारी समितियां खोली गईं? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र कपासन की सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर सहकारी समितियां खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में भवन व गोदाम विहीन सहकारी समितियों में नये भवन व गोदाम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2022-23 में ग्राम सेवा सहकारी समिति से वंचित सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन की घोषणा की गई थी।

उक्त घोषणा की अनुपालना में अब तक 1,283 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, सहकारिता)

(2) जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर कपासन विधान सभा क्षेत्र में ग्राम सेवा सहकारी समिति से वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किया जायेगा।

(3) गोदाम विहीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पास गोदाम निर्माण हेतु वैध स्वामित्व की भूमि उपलब्ध होने तथा सम्बन्धित केन्द्रीय सहकारी बैंक की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर तत्समय उपलब्ध बजट के आधार पर गोदाम निर्माण की स्वीकृति दी जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बारां में नवीन सहकारी समितियों का गठन

63. श्री ललित मीना (किशनगंज): क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बारां में वर्ष 2019 से माह मई, 2024 तक कितनी नवीन सहकारी समितियों का गठन किया गया? वर्तमान में कितनी सहकारी समितियां संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त जिले में संचालित सहकारी समितियों का विगत वर्ष में कितनी बार निरीक्षण किया गया? निरीक्षण के दौरान कितनी समितियां अधिनियम के तहत सही पाई गईं तथा अधिनियम के तहत संचालित नहीं होने वाली समितियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बारां में वर्ष 2019 से माह मई, 2024 तक 52 नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की स्वीकृति जारी की गई, जिनमें से वर्तमान में 37 ग्राम सेवा सहकारी समितियां संचालित हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जिला बारां में केन्द्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से विगत वित्तीय वर्ष में 29 ग्राम सेवा सहकारी समितियों का निरीक्षण किया गया है। सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। निरीक्षण के दौरान सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियां सहकारी अधिनियम के तहत कार्य करते पायी गईं।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं।)

किशनपोल में नगर निगम हेरिटेज द्वारा स्वीकृत कार्य

64. श्री अमीन कागजी (किशनपोल): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बजट वर्ष 2022-23 में नगर निगम हेरिटेज, जयपुर हेतु स्वीकृत कार्य चारदीवारी स्थित गलियों का सुदृढ़ीकरण एवं सफाई के लिए राशि 25 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये थे? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में दिनांक 31 मई, 2024 तक कितना कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कितना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्य हेतु किस एजेंसी को टेंडर दिया गया? टेंडर की शर्तें प्राप्त निविदाओं सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्य करने वाली कार्यकारी एजेंसी को कितना भुगतान किया जा चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार शेष गलियों का सुदृढ़ीकरण एवं सफाई कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि सरकार द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में नगर निगम जयपुर-हेरिटेज के किशनपोल, आदर्शनगर एवं हवामहल विधान सभा क्षेत्रों में चारदीवारी स्थित गंदी गलियों के सुदृढ़ीकरण एवं सफाई के लिए राशि रुपये 25 करोड़ स्वीकृत किये गये थे। (कार्यादेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।)

किशनपोल विधान सभा क्षेत्र में उक्त निविदा के तहत लगभग 70 प्रतिशत गंदी गलियों में सफाई का एवं सात प्रतिशत गंदी गलियों में मरम्मत कार्य करवाया गया है।

(2) उक्त कार्य हेतु मैसर्स Sharma Detective & Security Services, Bharatpur को टेण्डर दिया गया है। (निविदा एवं शर्ते परिशिष्ट-ब पर संलग्न हैं।)

(3) उक्त कार्य करने वाली कार्यकारी एजेन्सी को राशि रुपये 2.07 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।

(4) जी हां। शेष रही गंदी गलियों के सुदृढ़ीकरण एवं सफाई कार्य हेतु क्रमशः राशि रुपये 293.04 लाख एवं राशि रुपये 483.57 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है, निविदा प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जाकर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा। (प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रति परिशिष्ट-स पर सलग्न है।)

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट

परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2024-25 पर सामान्य वाद-विवाद के समय सदन पटल पर रखा गया लिखित वक्तव्य

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना)

महोदय, डबल इंजन की सरकार के बजट में नीम का थाना का एक बार भी नाम नहीं लिया गया और आपके 6-7 माह में कार्यकाल में आपने चिरंजीवी योजना का गला घोटने का काम किया है। अन्नपूर्णा योजना खतम कर दी गई है। इंदिरा रसोई का बजट कम कर दिया गया है। आपने नये जिलों पर तलवार लटका कर उनका विकास रोक दिया है। आपकी नीयत वहां जिले के ढांचे के लिए एवं सभी कार्यालय खोलने के लिए बजट देने की नहीं है। आपने गरीब के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने का सपना पूरा करने में रुकावट डालने का काम किया है।

आपने गर्मी के मौसम में बढ़ चढ़कर बिजली की कटौती की है, जिससे आम जन त्रस्त है। मेरे क्षेत्र में 10-12 घंटे की बिजली कटौती की गई है। आज बिजली निगमों के पास मरम्मत करने का समान, जैसे ट्रासफार्मर, डी.पी, केबल, कण्डक्टर, पोल आदि भी नहीं हैं। वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण में कहा कि हम किसानों को दिन में बिजली देंगे। मंत्री महोदया, यह काम कांग्रेस सरकार द्वारा पहले ही किया जा चुका है। आप असत्य वाहवाही लूटने का कार्य न करें।

आपने गर्मी के मौसम में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था न कर जनता को प्यासा मारने का कार्य तथा जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। हर साल गर्मियों के मौसम में सरकार द्वारा पानी के टैंकरों की समुचित व्यवस्था कर जनता की परेशानी कम करने का कार्य भली भांति किया जाता है। उक्त व्यवस्था इस साल बिलकुल फेल हो गई है। ट्यूबवैल व हैडपम्प रिपेयरिंग का कोई भी सामान, जैसे मोटर, स्टार्टर, केबल, पाइप इत्यादि सामान एवं उचित बजट पी.एच.ई.डी के पास ही नहीं है। और तो और, लम्बे समय तक रिपेयरिंग के ठेके भी नहीं दिये गये हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में आपने बड़े पैमाने पर पम्प चालकों को एवं अन्य कर्मचारियों को बड़ी संख्या में ट्रांसफर कर अपनी हार की खीझ उतारी है।

जनता ने 2018 में 12,500 मतों से एवं 2023 में 33,500 मतों से

पटखनी खाये नेता जनता को धमकियां दे रहे थे कि ये तो ट्रैलर है, फिल्म तो अभी शेष है। जनता ने सांसद को भी पटकनी देकर उन्हें फिल्म दिखाई है एवं पंचायत समिति के उप चुनाव में 550 मतों से जीती हुई सीट छीनकर जनता ने पुनः अपनी ताकत दिखाई।

एक और कार्य आपके 6-7 माह के कार्यकाल में हुआ है, भ्रष्टाचार, जो कि चरम सीमा पर पहुंच गया है। अधिकारी बेलगाम होकर जनता को लूट रहे हैं।

अब मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की प्रमुख आवश्यकताओं को इस सदन के माध्यम से रखना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की प्रमुख मांग पीने का पानी है, जिसके लिए इंदिरा गांधी नहर आधारित वृहद पेयजल परियोजना हेतु 2022-23 की घोषणा संख्या 259 द्वारा 7,800 करोड़ की गई थी, पुनः क्रम संख्या (6) परिवर्तित बजट 2024-25 के क्रम संख्या (5) द्वारा 7,582 करोड़ की दी गई है। मेरा सरकार से निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में पीने के पानी की भंयकर समस्या को दृष्टिगत रखते हुए उक्त पर युद्ध स्तर पर कार्य किया जावे।

इसी प्रकार परिवर्तित बजट 2024-25 के बिन्दु संख्या 113 के III यमुना जल सम्बन्धित कार्य में 17.02.2024 को हुए एमओ.यू. के तहत बनने वाली डी.पी.आर. में नीम का थाना विधान सभा क्षेत्र को शामिल किया जावे एवं भूमिगत पाइप लाइन के जरिये पानी लाकर यहां के बांधों में डाला जावे, ताकि जलस्तर में सुधार हो एवं सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की स्थिति बहुत दयनीय है। अब यह जिला भी बन गया है। अतः इसे सड़कों के लिए अधिक बजट दिया जावे।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार हेतु कॉलेज एवं नर्सिंग कालेज खोले जावें। यहां जिला अस्पताल स्वीकृत है एवं उसका निर्माण कार्य चल रहा है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के सिरोही ग्राम में पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत किया जावे। यह मेरे क्षेत्र की सबसे बड़ी पंचायत है एवं यहां पर सीमेन्ट फैक्टरी भी स्थित है। यहां की ओ.पी.डी. 25 हजार से ऊपर एवं आई.पी.डी. 7500 से उपर है। यहां पर भवन भी दानदाता द्वारा बहुत अच्छा एवं बड़ा निर्मित है जिसमें सी.एच.सी. आराम से चल सकती है।

मेरे यहां पशुपालन एवं कृषि ही आजिविका के प्रमुख साधन हैं। अतः यहां वेटनरी का मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल खोला जाना अति आवश्यक है।

गुहाला पंचायत को नगरपालिका में क्रमोन्नत करने की महती आवश्यकता है।

चला में सहायक अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. का कार्यालय जनता की सुविधा हेतु खोला जाना आवश्यक है।

मेरा विधान सभा क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से काफी बड़ा है एवं यहां आवागमन के साधन बहुत कम हैं। अतः यहां नवीन बसों का बड़ी मात्रा में संचालन आरम्भकिया जावे।

पाटन में चल रहे राजकीय महाविद्यालय को पी.जी. में क्रमोन्नत किये जाने से वहां के गरीब छात्रों को आगे पढ़ने की बहुत सुविधा मिलेगी | अतः इसे क्रमोन्नत किया जावे एवं डाबला में नया राजकीय महाविद्यालय खोला जावे।